



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 1, 2009/श्रावण 10, 1931

No. 438]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 1, 2009/SRAVANA 10, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 560(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम उन सभी व्यक्तियों को जो अधिनियम के अधीन हैं लागू होंगे।

परंतु उसके अध्याय 4 के उपबंधों अखिल भारतीय सेवा के व्यक्तियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को, जो सशस्त्र सीमा बल में प्रतिनियुक्ति पर है, लागू नहीं होंगे।

परंतु यह और कि प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को यह विकल्प होगा कि वे अपना विचारण या जांच इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन और नियम या अपने-अपने सेवा अधिनियम के उपबंधों तथा विशिष्ट प्रकृति के नियमों के अधीन कराएं।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) अभिप्रेत है;

(ख) “परिशिष्ट” से इन नियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट अभिप्रेत है ;

(ग) “नियुक्ति” से किसी व्यक्ति की बल में नियुक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अभ्यावेशन भी है ;

(घ) “कमांडेंट” से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 5 के अधीन बल में कमांडेंट के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ङ) “न्यायालय” से अधिनियम की धारा 76 के अधीन बल न्यायालय अभिप्रेत है ;

(च) “टुकड़ी” के अंतर्गत बल के किसी बटालियन या यूनिट का कोई ऐसा भाग, जिससे मुख्यालय से दूर ड्यूटी की अपेक्षा की गई है या आदेश दिया गया है ;

- (छ) “बल प्राधिकारी” से जब इसका प्रयोग किसी शक्ति कर्तव्य कार्य या विषय के संबंध में किया जाए ऐसा बल प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इन नियमों के अनुसरण में उस शक्ति का प्रयोग करता है या कर्तव्य का पालन करता है या उस विषय से संबद्ध है;
- (ज) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (झ) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. रिपोर्ट और आवेदन—ऐसी कोई रिपोर्ट या आवेदन जो इन नियमों के अधीन किसी वरिष्ठ प्राधिकारी या किसी बल प्राधिकारी को किया जाना अपेक्षित है जब तक कि उक्त प्राधिकारी सेवा की आवश्यकताओं के कारण या अन्यथा उसके लिखित में किए जाने से छूट न दे उचित माध्यम से लिखित रूप में किया जाएगा।

4. परिशिष्टों में प्रारूप—(1) परिशिष्टों में उपवर्णित प्रारूप ऐसे परिवर्तनों के साथ जो प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हों उनमें उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं और यदि उनका प्रयोग किया जाता है तो वे पर्याप्त होंगे किन्तु इन प्रारूपों से विचलन किसी आरोप वारन्ट आदेश कार्यवाही या इन नियमों से सुसंगत किसी अन्य दस्तावेज को केवल विचलन के कारण अविधिमाम्य नहीं बनाएगा।

(2) ऐसे किसी प्रारूप का कोई लोप किसी कार्य या बात को केवल ऐसे लोप के कारण ही अविधिमाम्य नहीं बनाएगा।

(3) प्रारूप के टिप्पणों और अनुदेशों में दिए गए निदेशों का ऐसे सभी मामलों में जिनसे वे संबंधित सम्यक् रूप से अनुपालन किया जाएगा किन्तु टिप्पणों या अनुदेशों में दिए गए ऐसे किसी निदेश के अनुपालन में कोई लोप किसी कार्य या बात को मात्र ऐसे लोप के कारण अविधिमाम्य नहीं बनाएगा।

5. बल के किसी पद के धारक में निहित शक्ति का प्रयोग किया जाना—बल में कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के प्रति या उसके समक्ष किसी कार्य या बात को करने के लिए दी गई किसी शक्ति या अधिकारिता का इन नियमों के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा जो तत्समय सशस्त्र सीमा बल के नियमों और पद्धति के अनुसार उस पद के कृत्यों का पालन कर रहा हो।

6. मामले जिनके लिए उपबंध नहीं किया गया हो—किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसके लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सक्षम प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी बात या ऐसी कार्यवाई करे जो मामले की वह आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे।

अध्याय 2

संगठन

7. बल का गठन—(1) सशस्त्र सीमा बल सशस्त्र सीमा बल (नियमित) से मिलकर बनेगा।

(2) सशस्त्र सीमा बल (नियमित) में नियुक्त या अभ्यावेशित आफिसर अधीनस्थ आफिसर और अभ्यावेशित व्यक्ति अपने अभ्यावेशन, प्रारूप नियुक्ति पत्र या इस निमित्त बनाए गए नियमों में उल्लिखित अवधि तक निरंतर सेवा करने के दायित्व के अधीन होंगे।

8. रैंक—(1) बल के आफिसर और अन्य सदस्य उनकी रैंक के अनुसार निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) आफिसर

(i) महानिदेशक

(ii) अपर महानिदेशक

(iii) महानिरीक्षक

(iv) उपमहानिरीक्षक

(v) कमांडेंट

(vi) द्वितीय कमान अधिकारी

(vii) उप कमांडेंट

(viii) सहायक कमांडेंट

(ख) अधीनस्थ आफिसर

- (i) सूबेदार मेजर
- (ii) निरीक्षक
- (iii) उपनिरीक्षक
- (iv) सहायक उपनिरीक्षक
- (ग) अंडर आफिसर
- (i) हैड कांस्टेबल
- (ii) नायक
- (viii) लांस नायक
- (घ) अन्य आफिसरों से भिन्न अभ्यावेशित व्यक्ति
- (i) कांस्टेबल
- (ii) अभ्यावेशित फोलोअर्स

(2) उसी रैंक के व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता से संबंधित मामले ऐसे नियमों के अनुसार जो इस निमित्त बनाए जाएं अवधारित किए जाएंगे।

(3) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक जहां भी उसके द्वारा बल के अच्छे कार्यकरण के हित में आवश्यक समझा जाए इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टिकरण के अधीन रहते हुए बल के किसी आफिसर या निरीक्षक को उपनियम (1) के खंड (क) में वर्णित रैंक स्थानीय रैंक के रूप में अनुदत्त कर सकेगा।

(4) स्थानीय रैंक धारण करने वाला बल का कोई आफिसर या निरीक्षक —

- (क) कमान और रैंक को धारण करने वाले किसी आफिसर में निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा
- (ख) उस रैंक को धारण नहीं करेगा, यदि ऐसे रैंक का अनुदत्त किया जाना केन्द्रीय सरकार द्वारा एक मास, के भीतर उसकी पुष्टि नहीं की जाती है या जहां महानिदेशक द्वारा ऐसा आदेश दिया जाए या उस पद को धारण नहीं करे जो रैंक उसे अनुदत्त की गई थी ;
- (ग) ऐसे रैंक धारण करने के लिए किसी अतिरिक्त वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा ; और
- (घ) बल के अन्य आफिसरों पर ऐसे रैंक धारण करने के कारण ज्येष्ठता का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

9. बल का कार्य और उसका समादेश और नियंत्रण.—(1) धारा 4 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए बल,—

- (i) भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करेगा।
- (ii) सीमा के आस-पास अपराधों, तस्करी, और किसी जन्म अवैध क्रियाकलाप को रोकेंगे।
- (iii) भारत राज्य क्षेत्र में और भारत राज्य क्षेत्र से अप्राधिकृत प्रवेश को रोकेंगे।
- (iv) जिम्मेदारी के क्षेत्र में नागरिक कार्यवाही कार्यक्रम करेगा।
- (v) केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन कृत्यों के निर्वहन में, समादेश, अनुशासन, प्रशासन, मनोबल और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी का विस्तार।

- (क) अपर महानिदेशक की दशा में उन सभी बटालियनों, मुख्यालयों, स्थापनों और बल कार्मिकों तक होगा जो इसके अधीन रखे गए हैं और उसे सौंपे गए क्षेत्र के भीतर है ;
- (ख) महानिदेशक की दशा में, उन सभी बटालियनों, यूनिटों, मुख्यालयों, स्थापनों और बल कार्मिकों तक होगा जो उसके अधीन रखे गए हैं और उसे सौंपे गए क्षेत्र के भीतर हैं ;
- (ग) उपमहानिरीक्षक या अपर महानिरीक्षक की दशा में, उसके अधीन रखे गए उन सभी बटालियनों, यूनिटों और अन्य कार्मिकों तक होगा जो उसके अधीन रखे गए हैं और उसे सौंपे गए क्षेत्र के भीतर है ;
- (घ) कमांडेंट की दशा में, उस बटालियन या यूनिट तक होगा जो उसके अधीन रखा गया है और उसे सौंपे गए क्षेत्र के भीतर है।
- (3) संघर्षों के दौरान अपर महानिदेशक महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक और कमांडेंट ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हें उनसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे जाए।

(4) उप महानिरीक्षक, या किसी महानिरीक्षक के अधीन न रखी गई बटालियनों, यूनिटों और स्थापनाओं के कमान अनुशासन, प्रशासन, मनोबल और प्रशिक्षण का निष्पादन ऐसे आफिसर द्वारा और ऐसी रीति से किया जाएगा जो महानिदेशक समय-समय पर अधिकथित करे ।

(5) बल का कोई सदस्य उल्लिखित उपनियम (1) में कथित बल के कार्य के संबंध में किसी भी कर्तव्य का पालन करने, बल के प्रशासन, अनुशासन, प्रशिक्षण और कल्याण तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करने का दायी होगा, जिनकी उसमें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार पालन करने की अपेक्षा की जाए । किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा इस निमित्त दिया गया कोई आदेश अधिनियम के प्रयोजन के लिए विधिपूर्ण समादेश होगा ।

10. कमान—(1) कमान के लिए नियुक्त किसी आफिसर को, उसके कमान के अधीन रखे गए सभी आफिसरों और व्यक्तियों पर ज्येष्ठता को ध्यान में लाए बिना, कमान की शक्ति होगी ।

(2) (क) ऐसी आकस्मिकता में जिसमें कोई आफिसर किसी कारणवश उस कमान का, जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है, प्रयोग करने में असमर्थ है, कमान द्वितीय कमान के आफिसर को न्यागत हो जाएगी यदि उसे इस प्रकार नियुक्त किया गया है ।

(ख) यदि द्वितीय कमान आफिसर की नियुक्ति नहीं की गई है तो वह उस आफिसर को न्यागत हो जाएगा जिस कमान का प्रयोग करने में असमर्थ आफिसर के अव्यवहित वरिष्ठ आफिसर द्वारा स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाए ।

(ग) यदि इस प्रकार किसी आफिसर की नियुक्ति नहीं की गई तो कमान उपस्थित ज्येष्ठतम आफिसर को न्यागत हो जाएगी ।

(घ) किसी आफिसर द्वारा कमान के प्रयोग की असमर्थता की ओर इन उपनियम के अनुसार किसी अन्य आफिसर द्वारा उसका भार ग्रहण किए जाने की रिपोर्ट ऐसे आफिसर द्वारा जिसने कमान का भार ग्रहण किया है अगले उच्चतर आफिसर को तुरन्त की जाएगी ।

(3) यदि विभिन्न बटालियनों और यूनिटों के व्यक्ति—

(i) किसी ऐसे विनिर्दिष्ट कार्य के लिए जिसके लिए वे नियोजित किए गए हैं एक साथ कार्य कर रहे हैं तो कमान करने के लिए नियुक्त किया गया आफिसर या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित ज्येष्ठतम आफिसर ऐसे सभी व्यक्तियों को कमान करेगा ।

(ii) अन्य सभी मामलों में प्रत्येक बटालियन या यूनिट का ज्येष्ठ आफिसर यथास्थिति अपनी बटालियन या यूनिट के व्यक्तियों को कमान करेगा ।

(4) जब बल के आफिसर और अन्य व्यक्ति शत्रु द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं तब वरिष्ठ और अधीनस्थ के विद्यमान संबंध और कर्तव्य की आज्ञाकारिता अपरिवर्तित रहेगी और इस निमित्त अनुशासनहीनता या अवज्ञा का दोषी व्यक्ति अपनी नियुक्ति के पश्चात् दंड का भागी होगा ।

(5) ऐसे व्यक्ति पर जो अधिनियम के अधीन है अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस बटालियन या यूनिट के जिसका वह व्यक्ति है, कमांडेंट से अन्यून पंक्ति के आफिसर द्वारा या उस आफिसर द्वारा जिस पर उपनियम (2) के अनुसार कमान न्यागत हुई है, किया जाएगा ।

(6) जहां ऐसा व्यक्ति टुकड़ी संबंधी ड्यूटी कर रहा है, जिस के अंतर्गत शिक्षण पाठ्यक्रम पर उपस्थित होना भी है ऐसे यूनिट सेंटर या स्थापन के कमांडेंट से अन्यून पंक्ति के आफिसर को जिसके साथ वह ऐसी ड्यूटी कर रहा है, कमांडेंट की सभी अनुशासनिक शक्तियां भी प्राप्त होंगी ।

(7) महानिदेशक, अपर महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और कर्मचारीवृंद के एक या अधिक आफिसरों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो, ऐसे व्यक्तियों की बाबत जो अपने-अपने मुख्यालयों के हैं या अपने-अपने मुख्यालयों में टुकड़ी ड्यूटी कर रहे हैं, किसी कमांडेंट की अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

(8) महानिदेशक, ऐसे आफिसरों को भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्तियों की बाबत जो अपने मुख्यालयों के हैं या उनमें टुकड़ी ड्यूटी कर रहे हैं क्रमशः महानिरीक्षक और उपमहानिरीक्षक की अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

(9) कोई महानिरीक्षक किसी ऐसे आफिसर को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो ऐसे व्यक्तियों की बाबत जो उसके मुख्यालय के हैं या उसमें टुकड़ी ड्यूटी कर रहे हैं, किसी उपमहानिरीक्षक की अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

स्पष्टीकरण : उपनियम (2) में “आफिसर” शब्द के अंतर्गत अधीनस्थ आफिसर और अवर आफिसर भी होंगे ।

अध्याय 3

भर्ती

11. अपात्रता—(1) वह व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या जो पति या पत्नी के जीवित होते हुए ऐसी किसी दशा में विवाह करता है, जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवित रहने के दौरान किया जाता है बल में नियुक्ति, अभ्यावेदन या नियोजन का पात्र नहीं होगा।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है अपने पहले पति या पत्नी के जीवित रहने के दौरान, दूसरा विवाह करता है, अपने आपको सेवा में रखे जाने के लिए अपात्र बनाएगा और अनुपयुक्तता के आधार पर उसे सेवा से पदच्युत किया जा सकता है, हटाया जा सकता है या निवृत्त किया जा सकता है :—

परंतु केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

12. अन्य देशियों की अपात्रता.—कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार की लिखित रूप में संज्ञापित सम्मति के सिवाय बल में नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा :

13. आफिसरों की नियुक्ति.—केन्द्रीय सरकार ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को, जिन्हें वह आफिसर के रूप में उपयुक्त समझता है, बल में निम्नलिखित रीति से नियुक्त कर सकेगी और उनकी सेवा की शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों में उपबंधित की जाएं :

(क) सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों, संघ के अन्य सशस्त्र बलों, राज्य पुलिस केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग या स्वशासी निकायों से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ;

(ग) प्रोन्नति द्वारा जैसा समय-समय पर विहित किया जाए ;

(घ) स्थानान्तरण द्वारा ;

(ङ) पुनर्नियोजन द्वारा ।

14. अधीनस्थ आफिसरों और अभ्यावेशित व्यक्तियों की नियुक्ति :—सूबेदार, मेजर या निरीक्षकों के पदों पर महानिरीक्षक द्वारा, उपनिरीक्षक या सहायक उपनिरीक्षक के पदों पर, उप महानिदेशक द्वारा और अंडर आफिसर अभ्यावेशित व्यक्तियों के पदों पर कमांडेंट या बल के किसी ऐसे अन्य आफिसर, जिसे महानिदेशक ने अभ्यावेशन आफिसर के रूप में नियुक्त किया हो, द्वारा नियुक्तियां की जा सकेंगी, जिन्हें क्रमशः निम्नलिखित रूप में नियुक्ति की जा सकेंगी और उनकी सेवा की शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों में उपबंधित की जाएं;

(क) सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) रक्षा बलों, संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल, राज्य पुलिस, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग या स्वशासी निकायों से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा;

(ग) प्रोन्नति द्वारा जैसा समय-समय पर विहित किया जाए;

(घ) स्थानान्तरण द्वारा;

(ङ) पुनर्नियोजन द्वारा ।

15. परिवीक्षा.—(1) सीधी भर्ती द्वारा, नियुक्त किया या कोई आफिसर, अधीनस्थ आफिसर या अभ्यावेशित व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, आफिसरों की दशा में और नियम 14 में विहित प्राधिकारी अधीनस्थ आफिसरों और अभ्यावेशित व्यक्तियों की दशा में, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, परिवीक्षा की अवधि या अवधियों के लिए जो दो वर्ष से अधिक नहीं हो बढ़ा सकेगा या परिवीक्षा की अवधि के दौरान कोई कारण बताए बिना उनकी सेवाओं को समाप्त कर सकेगा।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबंध किसी व्यक्ति को उसकी आफिसर के रूप में प्रारंभिक प्रोन्नति पर भी लागू होंगे। जो व्यक्ति परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरी नहीं करते वे अपने पूर्व रैंक में प्रत्यावर्तन के दायी होंगे।

16. अभ्यावेदन की प्रक्रिया, अभ्यावेदन का ढंग और उससे संबंधित अन्य विषय.—(1) किसी व्यक्ति के बल के सदस्य के रूप में अभ्यावेशन से पहले किसी यूनिट का कमांडेंट या ऐसा अन्य आफिसर जिसे महानिदेशक द्वारा अभ्यावेशन

आफिसर नियुक्त किया जाए उसे उस पद की जिस पर उसका अभ्यावेशन किया जाना है, सेवा की शर्तें उसकी उपस्थिति में पढ़ेगा या पढ़वाएगा और उसके समक्ष स्पष्ट करेगा या स्पष्ट करवाएगा और उससे परिशिष्ट में दिए गए अभ्यावेशन प्रारूप में अंतर्विष्ट प्रश्न करेगा और उसको इस बात की चेतावनी देने के पश्चात् कि यदि वह ऐसे किसी प्रश्न का मिथ्या उत्तर देगा तो वह अधिनियम के अधीन दंड का दायी होगा, ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर उसके उत्तर को अभिलिखित करेगा या अभिलिखित करवाएगा।

(2) यदि उपनियम (1) के उपबंधों का और ऐसे अन्य निदेशों का जो महानिदेशक द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए जाएं, अनुपालन करने के पश्चात् अभ्यावेशन आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि अभ्यावेशन किए जाने के लिए इच्छुक व्यक्ति, उन प्रश्नों को पूर्णतः समझता है जो उससे पूछे गए हैं और सेवा की शर्तों के लिए, सहमति देता है और यदि उक्त आफिसर का समाधान हो जाता है कि कोई अड़चन नहीं है तो वह अभ्यावेशन प्रारूप पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे व्यक्ति के उस पर हस्ताक्षर कराएगा और तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति अभ्यावेशन किया गया समझा जाएगा।

(3) (क) उपनियम (2) के अधीन बल के सदस्य के रूप में अभ्यावेशित प्रत्येक व्यक्ति को परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रारूप पर शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा।

(ख) शपथ या प्रतिज्ञान यथासंभव कमांडेंट के अन्यून पंक्ति के आफिसर द्वारा या कमांडेंट द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत आफिसर द्वारा दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा।

(ग) सत्यापित किए जाने वाले व्यक्ति को शपथ तभी दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान तभी कराया जाएगा जब उसने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो।

17. सेवा के लिए दायित्व.—(1) सभी आफिसर, केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल में सेवा करने के दायित्व के अधीन हैं। ऐसी सेवा के लिए आफिसरों के चयन में स्वयंसेवकों को अधिमानता दी जाएगी किंतु यदि आवश्यक संख्या में उपयुक्त स्वयंसेवक उपलब्ध नहीं है तो आफिसर केन्द्रीय सरकार द्वारा जैसा वह आवश्यक समझे प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर भेजे जा सकेंगे या अन्यथा नियुक्त किए जा सकेंगे।

(2) इस नियम के उपबंध अधीनस्थ आफिसरों और अभ्यावेशित व्यक्तियों को या उनके संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे बल के किसी आफिसर को या उनके संबंध में लागू होते हैं और उपनियम (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग महानिदेशक द्वारा किया जाएगा।

अध्याय 4

सेवा समाप्ति

18. सेवा समाप्ति.—नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 3 से स्तंभ 6 तक के शीर्षकों में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, स्तंभों में विनिर्दिष्ट बल के किसी सदस्य को, स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में दिए गए आधारों पर इस अध्याय में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पदच्युत करने, हटाने, सेवान्मुक्त करने, सेवानिवृत्त करने, सेवानिवृत्त करने या निर्मुक्ति करने के लिए सक्षम होगा। इस नियम या इस अध्याय के किसी उपबंध द्वारा पूर्वोक्त किसी भी प्राधिकारी की प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग उससे वरिष्ठ किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा :

परंतु इस अध्याय के उपबंध उन व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे जो बल में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

सारणी

क्र.सं.	कारण, जिसके आधार पर सेवा समाप्त की जा सकती है	केन्द्रीय सरकार	महानिरीक्षक	उप महानिरीक्षक	कमांडेंट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i)	अवधार	आफिसर	सूबेदार मेजर और निरीक्षक	उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक	अंडर आफिसर/ अभ्यावेशित व्यक्ति
(ii)	अनुपयुक्तता	आफिसर	सूबेदार मेजर और निरीक्षक	उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक	अंडर आफिसर/ अभ्यावेशित व्यक्ति
(iii)	प्रशिक्षण में असंतोषप्रद प्रगति	आफिसर	सूबेदार मेजर और निरीक्षक	उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक	अंडर आफिसर/ अभ्यावेशित व्यक्ति

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(iv)	नियुक्ति के समय मिथ्या गलत सूचना देना	आफिसर	सूबेदार मेजर और निरीक्षक	उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक	अंडर आफिसर/अभ्यावेशित व्यक्ति
(v)	शारीरिक अयोग्यता	आफिसर	सूबेदार मेजर और निरीक्षक	उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक	अंडर आफिसर/अभ्यावेशित व्यक्ति
(vi)	स्वयं आग्रह करने पर	आफिसर	सूबेदार मेजर और निरीक्षक	उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक	अंडर आफिसर/अभ्यावेशित व्यक्ति

19. अवचार के कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा आफिसरों की सेवा समाप्ति.—(1) जब धारा 10 के अधीन, किसी आफिसर की सेवा को उसके अवचार के कारण समाप्त किए जाने का प्रस्ताव हो, तब उसको उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर दिया जाएगा।

परंतु यह उप-नियम वहां लागू नहीं होगा—

(क) जहां सेवा, ऐसे आचरण के आधार पर समाप्त की जाती है, जिसके लिए दंड न्यायालय या बल न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्ध किया गया है, या

(ख) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, आफिसर को हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर दिया जाना समीचीन या युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है।

(2) जब केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक का, किसी आफिसर के अवचार की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि बल न्यायालय द्वारा आफिसर का विचारण असमीचीन या असाध्य है किंतु उसकी यह राय है कि उक्त आफिसर को सेवा में और बने रहने दिया जाना अवांछनीय है, तब महानिदेशक, आफिसर को उन मामलों में जहां अभिकथनों का अन्वेषण किया गया है, अभिकथनों की विशिष्टियाँ और अन्वेषण की रिपोर्ट सहित (जिसके अंतर्गत साक्षियों का अभिलिखित कथन और दस्तावेजों की प्रतियाँ, यदि कोई हों, जिनका उसके विरुद्ध उपयोग किया जाना आशयित है, भी शामिल हैं) ऐसी सूचना देगा और उसे अपना स्पष्टीकरण और प्रतिवाद लिखित में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा:

परंतु महानिदेशक ऐसी किसी रिपोर्ट या उसके भाग के प्रकटन को रोक सकेगा, यदि उसकी राय में उसका प्रकटन राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है।

(3) यदि महानिदेशक आफिसर के स्पष्टीकरण को असमाधानप्रद समझता है या जब केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा निदेश दिया जाता है, तब मामले को आफिसर के प्रतिवाद सहित और उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट रीति से आफिसर की सेवा की समाप्ति के संबंध में महानिदेशक की सिफारिश के साथ केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार को मामले को प्रस्तुत करते समय महानिदेशक इस बात की अपनी सिफारिश करेगा कि क्या आफिसर की सेवा समाप्त की जानी चाहिए और यदि ऐसा हो तो क्या आफिसर को—

(क) सेवा से पदच्युत किया जाना चाहिए; या

(ख) सेवा से हटा दिया जाना चाहिए; या

(ग) सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए; या

(घ) त्यागपत्र देने के लिए कहा जाना चाहिए।

(5) केन्द्रीय सरकार यथास्थिति रिपोर्टों और आफिसरों के प्रतिवाद पर, यदि कोई हो, या दंड न्यायालय के और महानिदेशक सिफारिश पर विचार करने के पूर्व आफिसर को सेवा से हटा सकेगी या पदच्युत कर या सेवानिवृत्त कर सकेगी या सेवा से उसका त्यागपत्र प्राप्त कर सकेगी और उसे ऐसा करने से इंकार करने आफिसर को अनिवार्यतः सेवानिवृत्त या सेवा से हटा सकेगी।

20. अनुपयुक्तता के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा आफिसरों की सेवा समाप्ति.—(1) जब महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि किसी आफिसर को सेवा में बनाए रखे जाना अनुपयुक्त है तो, आफिसर को—

(क) ऐसी सूचना दी जाएगी;

(ख) उसके प्रतिकूल सभी विषयों की विशिष्टियाँ दी जाएंगी; और

(ग) किन्हीं ऐसे कारणों को प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा जिन्हें वह सेवा में अपने को बनाए रखे जाने के पक्ष में सामने रखने की इच्छा प्रकट करे :

परंतु खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) लागू नहीं होंगे, यदि केन्द्रीय सरकार का, ऐसे कारणों को लेखबद्ध किए जाएं, यह समाधान हो जाता है कि इन उपबंधों का अनुपालन किया जाना समीचीन या युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है :

परंतु यह और कि, महानिदेशक उस आफिसर को ऐसी कोई सामग्री नहीं देगा जो उसके प्रतिकूल हो, उसकी राय में ऐसा करना राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है ।

(2) यदि महानिदेशक स्पष्टीकरण को असमाधानप्रद समझता है तो मामले को केन्द्रीय सरकार को आफिसर स्पष्टीकरण और महानिदेशक की सिफारिश के साथ केन्द्रीय सरकार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार रिपोर्टों, आफिसर के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हों, और महानिदेशक की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् आफिसर से सेवानिवृत्त होने, त्यागपत्र देने की अपेक्षा कर सकेगा और उसके ऐसा करने से इंकार करने पर आफिसर को सेवानिवृत्त किया जा सकेगा ।

21. आफिसरों से भिन्न व्यक्तियों की अवचार के कारण सेवा-समाप्ति.—(1) जब किसी आफिसर से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति की, जो अधिनियम के अधीन है, सेवा समाप्ति का प्रस्ताव है तब उसको पदच्युत या हटाए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसी कार्यवाई के विरुद्ध उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से हेतुक दर्शित करने का अवसर दिया जाएगा :

परंतु यह उप-नियम वहां लागू नहीं होगा :

(क) जहां ऐसे आचरण के आधार पर समाप्त की जाती है, जिसके लिए किसी दंड न्यायालय या बल न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्ध किया गया है; या

(ख) जहां नियम 18 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखबद्ध किया जाए, संबंधित व्यक्ति को हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर दिया जाना समीचीन या युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है ।

(2) जब संबंधित व्यक्ति के अवचार से संबंधित रिपोर्टों पर विचार किए जाने के पश्चात्, नियम 18 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति का बल न्यायालय द्वारा विचारण असमीचीन या असाध्य है किंतु उसकी यह राय है कि उसे सेवा में और बनाए रखना अवांछनीय है तो वह उसे उसके प्रतिकूल सभी रिपोर्टों सहित सूचित करेगा और उससे लिखित में अपना स्पष्टीकरण और प्रतिवाद प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा :

परंतु नियम 18 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी किसी रिपोर्ट या उसके भाग के प्रकटन को रोक सकेगा, यदि उसकी राय में उसका प्रकटन राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है ।

(3) नियम 18 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, यथास्थिति, उसके स्पष्टीकरण तथा प्रतिवाद यदि कोई है तो, या दंड न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के पश्चात् उसको सेना से पदच्युत या हटा सकेगा ।

(4) इस नियम के अधीन पदच्युत किए जाने या हटाए जाने के सभी मामलों की रिपोर्ट महानिदेशक को दी जाएगी ।

22. प्रशिक्षण में असंतोषप्रद प्रगति के आधार पर सेवा से निर्मुक्ति.—(1) जब किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस नियम के अधीन है, प्रशिक्षण में असंतोष प्रगति के कारण सेवा से निर्मुक्त किए जाने का प्रस्ताव हो उस प्रशिक्षण स्थापन का कमान आफिसर, जहां वह व्यक्ति प्रशिक्षणरत है, उस बटालियन यूनिट के कमान आफिसर को, जिससे वह व्यक्ति संबद्ध है, उसकी सेवा से निर्मुक्ति के लिए उपयुक्त कार्यवाई करने की सिफारिश करेगा ।

(2) किसी व्यक्ति के सेवा से निर्मुक्ति के लिए सिफारिश किए गए सभी मामलों में, प्रशिक्षण स्थापन का कमान आफिसर इस तथ्य को स्पष्टतः स्थापित करेगा कि व्यक्ति की प्रगति दर्शाने के लिए उपयुक्त चेतावनी और पर्याप्त समय दिया गया है, इस संबंध में सिफारिश के साथ दस्तावेजी साक्ष्य दिए जाएंगे ।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार का नियम 18 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, उप-नियम (1) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को सेवा से निर्मुक्ति या सेवान्मुक्त कर सकेगा ।

23. नियुक्ति के समय मिथ्या/गलत सूचना देने के आधार पर सेवा-समाप्ति.—यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या नियम 17 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा जो अधिनियम के अधीन है, उस व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति के समय मिथ्या/गलत सूचना देने के आधार पर समाप्त की जा सकती है । व्यक्ति-विशेष को उसकी सेवा समाप्ति से पूर्व हेतुक दर्शित करने के लिए एक मास का समय देते हुए सूचना जारी की जाएगी ।

24. शारीरिक अयोग्यता के आधार पर आफिसरों को सेवानिवृत्ति/निर्मुक्ति/सेवान्मुक्ति.—(1) जहां उपमहानिरीक्षक से अन्यून पंक्ति का कोई आफिसर यह समझता है कि बल का कोई आफिसर अपनी शारीरिक अवस्था के कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के अयोग्य है तो आफिसर को किसी चिकित्सीय बोर्ड के संमक्ष लाया जाएगा ।

(2) चिकित्सीय बोर्ड में ऐसे आफिसर होंगे और उसका गठन ऐसी रीति से किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जाएं ।

(3) जहां चिकित्सीय बोर्ड, आफिसर को सेवा के अयोग्य समझता है वहां केन्द्रीय सरकार, यदि वह चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष से सहमत होती है, तो उक्त आफिसर को चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष को संसूचित करेगी और तब आफिसर ऐसी संसूचना से तीस दिन की अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार को उसके विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकेगा जिसमें चिकित्सीय बोर्ड द्वारा व्यक्त राय में निर्णय की त्रुटियों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य भी होना चाहिए । ऐसा साक्ष्य सिविल सर्जन से अन्यून प्रास्थिति के सरकारी चिकित्सक द्वारा दिया जाना चाहिए और उसमें इसका विशिष्ट उल्लेख होना चाहिए कि उसने अपना मत प्रकट करने से पूर्व चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष को ध्यान में रखा है ।

(4) केन्द्रीय सरकार आफिसर से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस प्रयोजन के लिए गठित किसी नए चिकित्सीय बोर्ड को, मामले का पुनर्विलोकन किए जाने के लिए निर्देश कर सकेगी और यदि नए चिकित्सीय बोर्ड का विनिश्चय उसके अप्रतिकूल है तो उक्त आफिसर की सेवानिवृत्ति/निर्मुक्ति/सेवानुक्ति का आदेश कर सकेगी ।

25. नियम 18 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा अनुपयुक्तता के आधार पर अधीनस्थ आफिसरों की सेवा की समाप्ति.—

(1) जहां कमांडेंट से अन्यून पंक्ति के किसी कमान आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि किसी अधीनस्थ आफिसर को सेवा में बनाए रखे जाना अनुपयुक्त है तो अधीनस्थ आफिसर को :

(क) तदनुसार सूचित किया जाएगा;

(ख) उसके प्रतिकूल मामलों की विशिष्टियां दी जाएंगी; और

(ग) किन्हीं ऐसे कारणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा जिन्हें वह सेवा में अपने को बनाए रखे जाने के पक्ष में सामने रखे जाने की इच्छा प्रकट करे ।

परंतु खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) लागू नहीं होंगे, यदि नियम 18 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, यह समाधान हो जाता है कि उसके उपबंधों का अनुपालन किया जाना समीचीन या युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है :

परंतु यह और कि, वह सक्षम प्राधिकारी अधीनस्थ आफिसर को, ऐसी कोई सामग्री नहीं देगा जो उसके प्रतिकूल हो, यदि उसकी राय में ऐसा करना राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है ।

(2) कमांडेंट से अन्यून पंक्ति के कमान आफिसर द्वारा स्पष्टीकरण को संतोषप्रद समझे जाने की दशा में मामला अधीनस्थ आफिसर के स्पष्टीकरण तथा कमान आफिसर को सिफारिशों सहित आदेश के लिए नियम 18 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) नियम 18 में विनिर्दिष्ट, प्राधिकारी अधीनस्थ आफिसर की रिपोर्ट और स्पष्टीकरण यदि कोई हो, और जो कमांडेंट से अन्यून पंक्ति के कमान आफिसर की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् अधीनस्थ आफिसर को सेवानिवृत्त होने के लिए या त्यागपत्र देने के लिए कह सकेगा और उसके ऐसा करने से इंकार करने पर अधीनस्थ आफिसर को अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया जा सकेगा या सेवा से निर्मुक्त किया जा सकेगा ।

26. अभ्यावेशित व्यक्तियों की अनुपयुक्तता के आधार पर सेवा समाप्ति.—(1) जहां कमांडेंट से अन्यून पंक्ति के कमान आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि अभ्यावेशित व्यक्ति बल में बनाए रखने के लिए अनुपयुक्त है तो उस अभ्यावेशित व्यक्ति को—

(क) तदनुसार सूचित किया जाएगा;

(ख) उसके प्रतिकूल मामलों की विशिष्टियां दी जाएं; और

(ग) किन्हीं ऐसे कारणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा जिन्हें वह सेवा में अपने को बनाए रखे जाने के पक्ष में सामने रखे जाने की इच्छा प्रकट करे ।

परंतु खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) लागू नहीं होंगे, यदि कमांडेंट से अन्यून आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किया जाए, उसके उपबंधों का अनुपालन किया जाना समीचीन या युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है :

परंतु यह और कि, वह सक्षम प्राधिकारी अभ्यावेशित आफिसर को, ऐसी कोई सामग्री नहीं देगा जो उसके प्रतिकूल हो, यदि उसकी राय में ऐसा करना राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है ।

(2) कमांडेंट से अन्यून पंक्ति का कमान आफिसर स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् अभ्यावेशित व्यक्ति से सेवानिवृत्त होने के लिए या त्यागपत्र देने के लिए कह सकेगा और उसके ऐसा करने से इंकार करने पर अभ्यावेशित व्यक्ति की सेवासय से अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति या निर्मुक्ति की जा सकेगी ।

27. शारीरिक अयोग्यता के आधार पर अधीनस्थ आफिसरों और अभ्यावेशित व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति, नियुक्ति.—(1) जहां कमांडेंट से अन्यून पंक्ति के कमान आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि कोई अधीनस्थ आफिसर या कोई अधीनस्थ व्यक्ति किसी शारीरिक निःशक्तता के कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है वहां वह यह निदेश दे सकेगा कि यथास्थिति उक्त अधीनस्थ अधिकारी या अभ्यावेशित व्यक्ति को किसी चिकित्सीय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए ।

(2) चिकित्सीय बोर्ड में ऐसे आफिसर होंगे और उसका गठन ऐसी रीति से किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जाए ।

(3) जहां उक्त अधीनस्थ आफिसर या अभ्यावेशित व्यक्ति को चिकित्सीय बोर्ड द्वारा बल में आगे सेवा के लिए अयोग्य पाया जाता है वहां नियम 18 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी यदि वह चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष से सहमत होता है तो वह संबंधित व्यक्ति को चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष सूचित करेगा तब वह व्यक्ति ऐसी संसूचना से 30 दिन की अवधि के भीतर उसके विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन कर सकेगा जिसमें चिकित्सीय बोर्ड द्वारा व्यक्त राय में निर्णय की त्रुटियों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य भी होना चाहिए । ऐसा साक्ष्य सिविल सर्जन से अन्यून प्रास्थिति के सरकारी चिकित्सक द्वारा दिया जाना चाहिए कि उसने अपना मत प्रकट करने से पूर्व चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष को ध्यान में रखा है ।

(4) जहां और सेवा के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति, उपनियम (3) के अधीन कोई अभ्यावेदन करता है वहां उसे अगले वरिष्ठ अधिकारी के पास अग्रेषित किया जाएगा जो मामले को किसी नए चिकित्सीय बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन के लिए निर्दिष्ट कराएगा । बोर्ड का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जाए ।

वरिष्ठ अधिकारी नए चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे ।

(5) जहां उपनियम (3) के अधीन चिकित्सीय बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन नहीं किया जाता है वहां नियम 18 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी यथास्थिति, (यदि वह चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्षों से सहमत है) बल में और सेवा के लिए उस अयोग्य घोषित व्यक्ति की सेवानिवृत्ति निर्भुक्ति का आदेश कर सकेगा ।

28. त्यागपत्र.—(1) केन्द्रीय सरकार किसी मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बल के किसी आफिसर को अपनी वचनबद्ध अवधि को पूर्ण करने से पूर्व त्यागपत्र देने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा :

परंतु ऐसी अनुज्ञा देने से पूर्व केन्द्रीय सरकार उस आफिसर से उसके द्वारा आहरित तीन मास के वेतन और भत्ते या उसे दिए गए प्रशिक्षण की लागत का, इनमें से जो भी अधिक हो, प्रतिदाय करने की अपेक्षा कर सकेगी :

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के अधीन काम स्वीकार करने के लिए त्यागपत्र देने वाला बल का कोई अधिकारी जिसे उसी के लिए काडर निर्वाधन मंजूर किया जा चुका है के पश्चात् या जिसने दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तो उससे उपरोक्त यथा उपबंधित राशि का प्रतिदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार उपनियम (1) के अधीन उस तारीख से जिसे वह समीचीन समझे त्यागपत्र स्वीकार कर सकेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार किसी आफिसर को त्यागपत्र देने की अनुज्ञा से इंकार कर सकेगी,—

(क) यदि देश में आंतरिक उपद्रव या बाह्य आक्रमण के कारण आपात की उद्घोषणा की गई है; या

(ख) यदि वह बल के अनुशासन के हित में ऐसा किया जाना असमीचीन समझती है; या

(ग) यदि आफिसर से विशेष रूप से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सेवा करने के लिए वचनबद्ध किया है और ऐसी अवधि समाप्त नहीं हुई है ।

(4) इस नियम के उपबंध अधीनस्थ आफिसरों और अभ्यावेशित व्यक्तियों को और उनके संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे बल के किसी भी आफिसर को या उसके संबंध में लागू होते हैं और उपनियम (1) और (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग सूबेदार मेजर और सूबेदार/या निरीक्षक की दशा में किसी महानिरीक्षक द्वारा, उपनिरीक्षक की दशा में अपर उपमहानिरीक्षक से अन्यून पंक्ति के किसी आफिसर द्वारा तथा अभ्यावेशित व्यक्ति की दशा में किसी कमांडेंट द्वारा किया जाएगा ।

29. पदच्युति, हटाए जाने या सेवानिवृत्ति के आदेशों के विरुद्ध अपील.—(1) यदि आफिसर से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति को जो अधिनियम के अधीन है सेवा से पदच्युत किया गया है, या हटाया गया है या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया गया है तो उसे अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध सेवा समाप्ति का आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी से उच्चतर किसी प्राधिकारी को सेवा समाप्त किए जाने के नब्बे दिन के भीतर अपील करने का अधिकार होगा ।

(2) आफिसरों की दशा में अपील केन्द्रीय सरकार को की जाएगी और ऐसी अपील सेवा की समाप्ति के नब्बे दिन के भीतर फाइल की जाएगी ।

(3) जहां अपील प्राधिकारी इस नियम के अधीन पदच्युति हटाए जाने या सेवानिवृत्ति के आदेश को अपास्त करता है वह ऐसा प्राधिकारी ऐसे आदेश पारित करेगा जो ऐसे व्यक्ति की जिसकी पदच्युति, हटाया जाना या सेवानिवृत्ति अपास्त की गई है, ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि की बाबत आवश्यक हो ।

30. पदच्युति, हटाए जाने, उन्मोचन, सेवा निवृत्ति की तारीख पदच्युत, हटाए जाने, उन्मोचन या सेवा निवृत्ति की :-

- (क) वह तारीख होगी जो पदच्युति या हटाए जाने या सेवोन्मुक्त किए जाने या सेवानिवृत्ति के आदेश में उल्लिखित हो, या
- (ख) यदि ऐसी कोई तारीख उल्लिखित नहीं की गई है तो वह तारीख होगी जिसको संबंधित व्यक्ति को ड्यूटी से मुक्त किया गया है ।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति की जो इस अधिनियम के अधीन है पदच्युति, हटाया जाना, सेवोन्मुक्त किया जाना, या सेवानिवृत्ति भूतलक्षी प्रभाव से नहीं होगी ।

अध्याय 5

गिरफ्तारी और निलंबन

31. गिरफ्तारी के रूप.—(1) गिरफ्तारी या तो खुली गिरफ्तारी हो सकेगी या बंद गिरफ्तारी ।

(2) गिरफ्तारी से, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, खुली गिरफ्तारी अभिप्रेत है ।

(3) गिरफ्तारी अधिरोपित करने वाला आदेश गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से संसूचित किया जा सकेगा ।

32. गिरफ्तारी का आदेश करने वाला प्राधिकारी - (1) इस अधिनियम के अध्याधीन किसी व्यक्ति की, अधिनियम के अधीन किसी आरोप पर गिरफ्तारी उस पर समादेश की शक्ति रखने वाले वरिष्ठ आफिसर के आदेश के अधीन और उसके अनुसार ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन है, किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा गिरफ्तार किया जा सकेगा -

- (क) यदि वह ऐसे वरिष्ठ आफिसर के विरुद्ध कोई अपराध करता है, या
- (ख) यदि वह ऐसे वरिष्ठ आफिसर के सामने कोई अपराध करता है या
- (ग) यदि वह विच्छृंखल रीति से आचरण करता है और उक्त वरिष्ठ आफिसर ऐसे विच्छृंखल व्यवहार को रोकने की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक समझता है ।

(3) उपनियम (2) के अधीन गिरफ्तारी करने वाला वरिष्ठ आफिसर यथासम्भव शीघ्र और किसी भी दशा में ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर उस बटालियन या यूनिट के जिसका गिरफ्तार किया गया व्यक्ति सदस्य है कमान आफिसर को और कमांडेंट को या उससे ऊपर की पंक्ति के किसी आफिसर को गिरफ्तारी की दशा में उसके अव्यवहित वरिष्ठ आफिसर को एक रिपोर्ट भेजेगा ।

33. गिरफ्तारी अधिरोपित करने की रीति—(अ) बंद गिरफ्तारी—(1)(क) बंद गिरफ्तारी अभ्यावेशित व्यक्तियों की दशा में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को सूचित करके और यह आदेश देकर की जाएगी कि उसे या उससे वरिष्ठ पंक्ति के व्यक्ति के अनुस्क्षण में परिरोध स्थल को ले जाया जाए,

(ख) जहां ऐसा कोई अनुस्क्षक उपलब्ध न हो वहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्वार्टर गार्ड या अन्य परिरोध स्थल पर तुरंत रिपोर्ट करने का आदेश दिया जाएगा ।

(2)(क) बंद गिरफ्तारी आफिसरों, अधीनस्थ आफिसरों और अवर आफिसरों की दशा में, ऐसे आफिसर, अधीनस्थ आफिसर या अवर आफिसर को उसी या उससे वरिष्ठ पंक्ति के किसी दूसरे व्यक्ति की अभिरक्षा में रख कर की जाएगी और जहां कहीं आवश्यक समझा जाए वहां ऐसा आफिसर, अधीनस्थ आफिसर या अवर आफिसर किसी गार्ड के प्रभाव के अधीन परिरक्षित किया जा सकेगा,

(ख) गिरफ्तार व्यक्ति अपने कमान आफिसर या अधीनस्थ आफिसर द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी वरिष्ठ अधिकारी की अनुज्ञा के बिना अपने परिरोध के स्थल को नहीं छोड़ेगा ।

(आ) खुली गिरफ्तारी.—(3)(क) खुली गिरफ्तारी गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को यह सूचित करके की जाएगी कि वह खुली गिरफ्तारी के अधीन है और वह स्वयं को उन सीमाओं के भीतर विरुद्ध परिरुद्ध रखेगा जो गिरफ्तारी करने वाले संबंधित वरिष्ठ आफिसर द्वारा निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(ख) कमान आफिसर ऊपर खंड (क) में निर्दिष्ट सीमा में समय समय पर परिवर्तन कर सकेगा ।

34. अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी से निर्मुक्ति—नियम 32 के अधीन गिरफ्तार किसी व्यक्ति को आफिसर के आदेश के अधीन गिरफ्तारी से निर्मुक्त किया जा सकेगा ।

परंतु ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी आफिसर द्वारा गिरफ्तार किया गया है उसे गिरफ्तारी का आदेश करके आफिसर से वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के अधीन गिरफ्तारी से निर्मुक्त किया जाएगा ।

35. पुनः गिरफ्तारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्मुक्ति—अन्वेषण पूरा होने तक या न्यायालय संयोजित जाने तक, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसके कमान आफिसर द्वारा या उसके कमान आफिसर से वरिष्ठ किसी आफिसर द्वारा, पुनः गिरफ्तारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्मुक्त किया जा सकेगा ।

36. गिरफ्तारी कब की जाएगी—(1) किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर निम्नलिखित का आरोप है :—

- (i) धारा 16 या धारा 18 के खंड (क) या खंड (ख) या धारा 19 या धारा 22 या धारा 23 या उप-धारा (1) के अधीन किसी अपराध का,
 - (ii) मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय सिविल अपराध का,
 - (iii) अधिनियम के अधीन किसी अन्य अपराध :
- (क) यदि अनुशासन के हित में ऐसा अपेक्षित हो
 - (ख) यदि संबद्ध व्यक्ति जानबूझ कर अनुशासन भंग करता हो, या
 - (ग) यदि संबद्ध व्यक्ति हिंसात्मक स्वभाव का हो
 - (घ) यदि विचारण से बचने की दृष्टि से संबद्ध व्यक्ति के अनुपस्थित होने की संभावना है, या
 - (ङ) यदि संबद्ध व्यक्ति से साक्षियों में बाधा और साक्ष्य में गड़बड़ करने की संभावना हो,

गिरफ्तार किया जाएगा ।

(2) जहां कोई गिरफ्तार व्यक्ति बीमार दिखाई देता है वहां उसे चिकित्सीय सहायता दी जाएगी ।

37. मत्त व्यक्ति की गिरफ्तारी की दशा में विशेष उपबंध—(1) जहां कोई मत्त व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, या वहां उसे यथासंभव अलग ही परिरुद्ध किया जाएगा और ड्यूटी आफिसर या ड्यूटी अधीनस्थ आफिसर या ड्यूटी अवर आफिसर या गारद का भारसाधक अवर आफिसर हर दो घंटे बाद उसके पास एक बार जाएगा ।

(2) किसी मत्त व्यक्ति को उसके मामले के अन्वेषण के लिए किसी वरिष्ठ आफिसर के समक्ष तब तक नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि वह स्वस्थचित नहीं हो जाता है ।

38. उन व्यक्तियों की दशा में गिरफ्तारी जिनके विचारण के लिए आदेश दिए गए हैं—(1) जब तक संयोजन आफिसर ने अन्यथा निदेश नहीं दिया हो तब तक किसी व्यक्ति का न्यायालय द्वारा विचारण प्रारंभ होने पर उक्त व्यक्ति को उसके कमान आफिसर द्वारा गिरफ्तारी में रखा जाएगा और विचारण के दौरान वह गिरफ्तार रहेगा ।

(2) जहां किसी न्यायालय द्वारा कारावास से कम दंडादेश पारित किया जाता है, वहां गिरफ्तार व्यक्ति को उसके कमान आफिसर द्वारा तब तक के लिए निर्मुक्त किया जा सकेगा जब तक कि निष्कर्ष और दंडादेश की पुष्टि नहीं हो जाती है :

परंतु संयोजन आफिसर कमान आफिसर द्वारा उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन पारित किए गए आदेश को विखंडित, परिवर्तित या उपांतरित कर सकेगा और जहां ऐसा कोई आदेश कमान आफिसर द्वारा पारित नहीं किया गया है, वहां संयोजन आफिसर ऐसा आदेश, जो वह उचित समझे पारित कर सकेगा ।

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे पदच्युत किए जाने का दंडादेश दिया गया है, उस दशा में सिवाय जब वह सक्रिय ड्यूटी पर है, किसी ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा ।

39. विलंब रिपोर्टें—(1)(क) धारा 71 के अधीन यथा अपेक्षित विलंब के कारणों के संबंध में रिपोर्ट परिशिष्ट 2 में दिए गए प्रारूप में होगी और यह कमान आफिसर द्वारा उस उपमहानिरीक्षक या अपर उपमहानिरीक्षक को भेजी जाएगी जिसके अधीन अभियुक्त सेवा कर रहा है ।

(ख) आठवीं विलंब रिपोर्ट और उसके पश्चात् वाली प्रत्येक रिपोर्ट की एक प्रति उस महानिरीक्षक को भी भेजी जाएगी जिसके अधीन अभियुक्त सेवा कर रहा है ।

(2) जहाँ अभियुक्त को विचारण के समक्ष लाए बिना तीन मास से अधिक की अवधि के लिए गिरफ्तार रखा जाता है, वहाँ की गई कार्रवाई और विलंब के कारणों के बारे में विशेष रिपोर्ट कमान-आफिसर द्वारा महानिदेशक को और उसकी एक-एक प्रति संबंधित उपमहानिरीक्षक या अपर उपमहानिरीक्षक और महानिरीक्षक को भेजी जाएगी।

40. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार.—(1) (क) गिरफ्तार करने वाला आफिसर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय उसके विरुद्ध आरोपों की लिखित विशिष्टियां देगा।

(ख) उक्त विशिष्टियों को साधारण भाषा में प्रस्तुत किया जाएगा और उन्हें अभियुक्त को भी बताया जाएगा।

(ग) खंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ अन्वेषण के दौरान अभियुक्त द्वारा किए गए अन्य अपराधों का पता चलता है, वहाँ उन अपराधों से ऐसे व्यक्ति का आरोपित करना विधिपूर्ण होगा।

(2) (क) ड्यूटी आफिसर या ड्यूटी अधीनस्थ आफिसर गिरफ्तार व्यक्ति को प्रतिदिन जाकर देखेगा और गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा किए गए निवेदन या अभ्यावेदन पर कमान आफिसर से आदेश प्राप्त करेगा,

(ख) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा किया गया निवेदन या अभ्यावेदन परिशिष्ट 3 में उपवर्णित प्रारूप में प्रविष्ट किया जाएगा।

41. निलंबन.—(1) इतने नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा राष्ट्रपति द्वारा उस निमित्त सशक्त है अपने अधीन सेवा कर रहे किसी व्यक्ति को स्वविवेकानुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में निलंबित कर सकेगा, अर्थात्

(i) जहाँ उसके विरुद्ध अधिनियम के अधीन कोई अनुशासनिक कार्रवाई करने का विचार है या अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है या

(ii) जहाँ वह पूर्वोक्त प्राधिकारी की राय में ऐसे क्रियाकलापों में लगा हुआ है जिनसे राज्य के हित या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या

(iii) जहाँ किसी सिविल अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण जांच या विचारण के अधीन है।

परंतु महानिदेशक, उप कमांडेंट के रैंक तक के आफिसरों के संबंध में निलंबन की शक्ति का प्रयोग कर सकेगा :

परंतु यह और कि महानिदेशक प्रत्येक मामले के तथ्यों की रिपोर्ट शीघ्र ही केन्द्रीय सरकार को देगा और निलंबन के ऐसे सभी आदेश आरंभ से ही शून्य होंगे जब तक इस तथ्य को ध्यान दिए बिना कि उस अवधि के भीतर उक्त अधिकारी द्वारा निलंबन को प्रतिसंहत किया गया है, उक्त आदेशों की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती।

(2) अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति का—

(i) यदि वह सिविल पुलिस द्वारा किसी आपराधिक आरोप पर या अन्यथा 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए निरोध में रखा जाता है तो उसके ऐसे निरोध की तारीख से

(ii) यदि वह दंड न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक आरोप पर 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है तो उस न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि की तारीख से, नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा

निलम्बित समझा जाएगा।

(3) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलंबन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि वह ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपांतरित नहीं कर दिया जाता या वापस नहीं ले लिया जाता।

(4) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलंबन आदेश किसी भी समय किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसने आदेश किया था या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसके कि वह प्राधिकारी अधीनस्थ है, उपांतरित या वापस लिया जा सकेगा।

(5) निलंबन की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति में निहित शक्तियां प्रास्थगित रहेंगी किंतु वह उन जिम्मेदारियों, अनुशासन, शास्तियों और अन्य सेवा-शर्तों के अध्यधीन रहेगा जिनका वह ड्यूटी पर रहने के दौरान अध्यधीन रहता तथा वह बिना पूर्व अनुमति के सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा।

(6) जब कोई व्यक्ति नब्बे दिन से अधिक के लिए निलंबित रहता है तब ऐसी रिपोर्ट, जिसमें उसके मामले को अंतिम रूप देने में देरी होने के कारण दिए गए हों, अभियुक्त के कमान आफिसर द्वारा महानिदेशक को भेजी जाएगी और उसके बाद पश्चात्पूर्ती रिपोर्ट मामले को अंतिम रूप दिए जाने तक या निलंबन आदेश को वापस लिए जाने तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रत्येक मास भेजी जाएगी।

अध्याय 6

बल न्यायालय और दंड न्यायालय में से किसी एक की अधिकारिता का चयन

42. बल न्यायालय द्वारा या दंड न्यायालय द्वारा मामलों का विचारण.—(1) जहां कोई अपराध, दंड न्यायालय और बल न्यायालय, दोनों द्वारा विचारणीय है, वहां धारा 92 में निर्दिष्ट कोई आफिसर—

- (i) (क) जहां अपराध अभियुक्त द्वारा बल के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य के अनुपालन के दौरान किया गया है; या
- (ख) जहां अपराध सरकार या बल या अधिनियम के अध्यक्षीन किसी व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में किया गया है; या
- (ग) जहां अपराध अधिनियम के अध्यक्षीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति का जो अधिनियम के अधीन है और जिसके बारे में यह अभिकथित है कि उसने ऐसा अपराध किया है, विचारण किसी बल न्यायालय द्वारा किया जाए; और

(ii) किसी अन्य मामले में, यह विनिश्चय कर सकेगा कि किसी ऐसे व्यक्ति का, जो अधिनियम के अध्यक्षीन है और जिसके बारे में यह अभिकथित है कि उसने ऐसा अपराध किया है, बल न्यायालय द्वारा विचारण के लिए दावा करना अनुशासन के हित में आवश्यक होगा या नहीं।

(2) किसी अपराधी के बल न्यायालय द्वारा विचारण के लिए दावे का विनिश्चय करने में, धारा 92 में निर्दिष्ट कोई आफिसर, निम्नलिखित सब बातों का या उनमें से किसी का ध्यान रखेगा; अर्थात् :—

- (क) अपराधी सक्रिय ड्यूटी पर है या सक्रिय ड्यूटी के लिए उसे चेतावनी दी गई है और ऐसा लगता है कि वह ऐसी ड्यूटी से बचने का प्रयत्न कर रहा है;
- (ख) अपराधी एक ऐसा नवयुवक है जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और अपराध गंभीर नहीं है और अपराधी कर दंड न्यायालय द्वारा विचारण उसके प्रशिक्षण पर तात्त्विक रूप से प्रभाव डालेगा;
- (ग) मामले की प्रकृति को देखते हुए अपराधी के बारे में अधिनियम के अधीन संक्षेपतः कार्रवाई की जा सकती है।

43. वे मामले जिनका बल न्यायालय द्वारा विचारण नहीं किया जाना है.—नियम 42 के उप-नियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी अपराधी के बारे में किसी बल न्यायालय द्वारा विचारण के लिए सामान्यतः दावा वहां नहीं किया जा सकेगा :—

- (क) जहां अपराध उसके द्वारा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर किया जाता है जो अधिनियम के अध्यक्षीन नहीं है और जिसकी पहचान ज्ञात है; या
- (ख) जहां उसके द्वारा अपराध छुट्टी पर रहने के दौरान या छुट्टी के बिना अनुपस्थिति के दौरान किया जाता है;
- (ग) जहां अपराध उसके बारे में कारित किया जाता है जिससे उसकी ड्यूटी के पालन से कोई संबंध नहीं है।

अध्याय 7

अन्वेषण और संक्षिप्त निपटारा

44. अभिकथनों का विवरण.—जहां यह अभिकथन किया गया है कि अधिनियम के अध्यक्षीन किसी व्यक्ति ने अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है वहां अभिकथन को हैड कांस्टेबल के उससे नीचे की शक्ति के व्यक्तियों की दशा में परिशिष्ट-4 में उपवर्णित प्रारूप में और आफिसरों और अधीनस्थ आफिसरों की दशा में परिशिष्ट 5 में उपवर्णित प्रारूप में लिखा जाएगा।

45. ऐसे आफिसर द्वारा सुनवाई जो सहायक कमांडेंट की शक्ति से नीचे का न हो.—(1) (क) आफिसर या अधीनस्थ आफिसर से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अधिनियम के अध्यक्षीन है मामले की सुनवाई प्रथमतः किसी ऐसे आफिसर द्वारा की जाएगी जो सहायक कमांडेंट की शक्ति से नीचे का न हो।

(ख) साक्षियों की सुनवाई अभियुक्त की उपस्थिति में, जिसे उनकी प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा, की जाएगी।

(ग) अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा के लिए साक्षियों को बुलाने और कथन करने का अधिकार होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अभियुक्त की सुनवाई के पश्चात् वह आफिसर ऐसा दण्ड दे सकेगा जिसके देने के लिए वह सशक्त है या जब आरोप साबित नहीं होता है तो उसे खारिज कर सकेगा या मामले को कमान आफिसर द्वारा निपटाए जाने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

परन्तु वह ऐसे मामले का निपटारा नहीं करेगा जिसे कमान आफिसर द्वारा स्वयं निपटाए जाने के लिए आरक्षित रखा गया है या यदि अभियुक्त बंद गिरफ्तारी के अधीन है।

46 कमान आफिसर द्वारा सुनवाई .—(1) कमाण्डेंट या उससे ऊपर की पंक्ति का कमान आफिसर नियम 45 के उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसार अपनी कमान के अधीन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप की सुनवाई कर सकेगा; और

- (i) ऐसा कोई दंड दे सकेगा जिसके लिए किसी हैंड कांस्टेबल के या उससे नीचे पंक्ति के व्यक्तियों की बाबत, देने के लिए वह सशक्त है, या
- (ii) आरोप को खारिज कर सकेगा, या
- (iii) अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य का अभिलेख या साक्ष्य की संक्षिप्ति तैयार करने के लिए मामले को प्रतिप्रेषित कर सकेगा, या
- (iv) हैंड कांस्टेबल के या उससे नीचे की पंक्ति के किसी अभियुक्त की दशा में, अभियुक्त को समरी बल न्यायालय द्वारा विचारण के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा :

परन्तु -

- (क) किसी आफिसर के मामले में, साक्षियों के साक्ष्य को, यदि वह ऐसा मांग करे, तो लिखा जाएगा;
- (ख) कमान आफिसर आरोप को खारिज कर देगा, यदि उनकी राय में, आरोप साबित नहीं होता है या उसे खारिज कर सकेगा यदि वह समझता है कि अभियुक्त के पिछले चरित्र और उससे विरुद्ध आरोप की प्रकृति के कारण इस पर और आगे विचार करना उपयुक्त नहीं है किसी आफिसर के मामले में, आरोप खारिज करने के कारणों को वह अभिलिखित करेगा;
- (ग) जहां किसी आफिसर की बाबत कोई मामला अनुशासनिक कार्यवाई आरंभ करने के किसी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कमान आफिसर को निर्दिष्ट किया गया है, वहां कमान आफिसर ऐसे आरोप को ऐसे प्राधिकारी को निर्देश किए बिना खारिज नहीं करेगा।

(घ) मृत्यु से दंडनीय सभी अपराधों के मामले में, साक्ष्य का अभिलेख तैयार किया जाएगा।

(2) जहां कमान आफिसर की राय यह है कि किसी आफिसर या अधीनस्थ आफिसर के विरुद्ध आरोप गंभीर प्रकृति का है वहां वह उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसार आरोप की सुनवाई किए बिना मामले में साक्ष्य के अभिलेख के लिए या साक्ष्य की संक्षिप्ति तैयार किए जाने के लिए सीधा आदेश दे सकेगा।

(3) जहां कमान आफिसर की राय यह है कि किसी आफिसर या अधीनस्थ आफिसर के विरुद्ध आरोप खारिज किए जाने योग्य नहीं है और आरोप इतना गंभीर भी नहीं है कि उसका विचारण बल न्यायालय द्वारा किया जाए, वहां वह अधीनस्थ आफिसर की दशा में या तो स्वयं मामले का निपटारा कर सकेगा या धारा 58 के उपबंधों के अधीन निपटारे के लिए किसी समुचित प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा। किसी आफिसर की दशा में, वह मामले को धारा 58 के उपबंधों के अधीन संक्षिप्त निपटारे के लिए समुचित प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा।

(4) जहां किसी बटालियन या यूनिट या मुख्यालय के कमान आफिसर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जानी आशयित है वहां ऐसे आफिसर को, यथास्थिति उस बटालियन या यूनिट या मुख्यालय के कमान से हटा दिया जाएगा और उस प्रयोजन के लिए इस प्रकार सम्बद्ध या तैनात किए जाने वाले आफिसर से वरिष्ठ आफिसर की कमान के अधीन बटालियन या यूनिट या मुख्यालय में उसे सम्बद्ध या तैनात किया जाएगा।

47. आफिसरों के विरुद्ध आरोपों के संक्षिप्त निपटारे की प्रक्रिया.—(1) जहां किसी आफिसर को, उसके विरुद्ध आरोप के संक्षिप्त निपटारे के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है वहां उसको आरोप पत्र के साथ उसके विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य का सार या अभिलेख की एक प्रति या साक्ष्य की संक्षिप्ति, यदि तैयार की गयी हो तो, यथा साध्य शीघ्र और किसी भी दशा में कार्यवाही आरंभ होने के चौबीस घंटे पहले की जाएगी।

(2) धारा 58 के अधीन मामले पर कार्यवाई करने वाला आफिसर जब तक कि अभियुक्त के साक्षियों की उपस्थिति को अभियुक्ति की लिखित रूप में सम्मति नहीं दी हो, अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य की सुनवाई करेगा जिसे साक्षियों की प्रतिष्ठा करने का अधिकार होगा। अभियुक्त को किसी साक्षी को बुलाने और अपनी प्रतिष्ठा में कथन करने का अधिकार होगा।

(3) कार्यवाहियों को, यथासाध्य, परिशिष्ट 14 के प्रारूप के अनुसार अभिलिखित किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें दण्ड अधिनिर्णीत किया जाए, यथास्थिति, साक्ष्य के सार या अभिलेख या साक्ष्य का संक्षिप्ति के साथ कार्यवाही अगले उच्चतर प्राधिकारी को जज महान्यायवादी या उसके द्वारा किसी ऐसे आफिसर के माध्यम से भेजा जाएगा जो यदि उसे

अधिनिर्णीत किया गया दण्ड अवैध, अन्यायपूर्ण अत्यधिक या अपर्याप्त प्रतीत होता है तो दण्ड में परिवर्तन कर सकेगा या छूट दे सकेगा या कार्यवाही को अपास्त कर सकेगा या दण्ड को बढ़ा सकेगा या ऐसा अन्य निदेश दे सकेगा जो मामले को परिस्थितियों में समुचित हो :

परन्तु दण्ड में वृद्धि करने से पूर्व अभियुक्त, को यह हेतुक दर्शित करने का अवसर दिया जाएगा कि उसके दण्ड में वृद्धि क्यों न की जाए ।

(4) यदि कोई आफिसर इस नियम के अधीन किए गए किसी विनिश्चय से अपने आप को व्यथित समझता है तो वह अपने कमान आफिसर के माध्यम से एक याचिका मामले के निपटारे के एक मास के भीतर महानिदेशक को प्रस्तुत कर सकेगा जो ऐसा आदेश या निदेश पारित कर सकेगा जो मामले की परिस्थितियों में समुचित हो ।

48. अधीनस्थ आफिसर के विरुद्ध आरोपों का संक्षिप्त निपटारा.—(1) जहां किसी अधीनस्थ आफिसर को अधिनियम के अधीन किसी अपराध से आरोपित किया गया है वहां उसके विरुद्ध धारा 58 के अधीन सशक्त प्राधिकारी द्वारा नियम 47 में यथा उपबन्धित के अनुसार लगभग उसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जो परिस्थितियां स्वीकार करें ।

(2) कार्यवाहियों की यथासाध्य परिशिष्ट 14 के प्रारूप के अनुसार अभिलिखित किया जायेगा और ऐसे प्रत्येक मामलों में, जिसमें दण्ड अधिनिर्णीत किया जाए, यथास्थिति साक्ष्य के सार या अभिलेख या साक्ष्य की संक्षिप्ति के साथ कार्यवाही अगले उच्चतर प्राधिकारी को जज महान्यायावादी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे आफिसर के माध्यम से भेजी जाएगी, जो यदि उसे अधिनिर्णीत किया गया दण्ड अवैध, अन्यायपूर्ण, अत्यधिक या अपर्याप्त प्रतीत होता है तो दण्ड में परिवर्तन कर सकेगा या छूट दे सकेगा या कार्यवाहियों को अपास्त कर सकेगा या दण्ड बढ़ा सकेगा या ऐसे अन्य निदेश दे सकेगा जो मामले की परिस्थितियों में समुचित हो :

परन्तु दण्ड में वृद्धि करने से पूर्व, अभियुक्त को यह हेतुक दर्शित करने का अवसर दिया जाएगा कि उसके दंड में वृद्धि क्यों न की जाए ।

(3) यदि कोई अधीनस्थ आफिसर इन नियम के अधीन किए गए विनिश्चय कि अपने आप को व्यथित समझता है तो वह अपने कमान आफिसर के माध्यम से एक याचिका मामले के निपटारे के एक मास के भीतर दण्ड अधिनिर्णीत करने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी ऐसा आदेश या निदेश पारित कर सकेगा जो मामले की परिस्थिति में समुचित हो ।

49. किसी दूसरी यूनिट से सम्बद्धता.—कमान आफिसर किसी मामले में कार्यवाही नहीं करेगा :—

- (i) जिसमें वह अपराध, जिसका अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है, स्वयं कमान आफिसर के विरुद्ध है, या
- (ii) जहां कमान आफिसर अभियुक्त के विरुद्ध मामलों में स्वयं साक्षी है, या
- (iii) जहां कमान आफिसर मामले में व्यक्तिगत रूप से अन्यथा हितबद्ध है ।

वहां अभियुक्त को सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन मामले के निपटारे के लिए किसी दूसरे बटालियन या यूनिट या मुख्यालय से सम्बद्ध किया जाएगा :

परन्तु कमान आफिसर केवल इस कारण आरोप को सुनवाई करने से निरहित नहीं होगा कि अपराध बल की उस में, बैंड या संस्था की, जिसका कमान आफिसर सदस्य या न्यासी है, संपत्ति के विरुद्ध किया गया था या कि अपराध ऐसे कमान आफिसर के आदेशों की अवज्ञा का अपराध है ।

50. वे आरोप जिन पर संक्षिप्ततः कार्यवाही नहीं की जानी है.—धारा 16 या 18 के खण्ड (क) और खण्ड (ख) या धारा 19 या धारा 20 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या धारा 22 के खण्ड (क) या धारा 27 खण्ड (क) या धारा 49 के अधीन साधारणतः उपहति या चोरी से भिन्न किसी अपराध के आरोप या इन अपराधों में से किसी के दुष्प्रेरणा करने या दुष्प्रेरणा करने के प्रयत्न के आरोप पर संक्षिप्ततः कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

51. साक्ष्य का अभिलेख.—(1) कमान आफिसर या तो स्वयं साक्ष्य के अभिलेख तैयार कर सकेगा या वह किसी दूसरे आफिसर को ऐसा करने के लिए तैयार कर सकेगा ।

(2) साक्षी अपना साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में देंगे और अभियुक्त को उन सब साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा जो उसके विरुद्ध साक्ष्य देते हैं :

परन्तु जहां किसी जांच न्यायालय में किसी साक्षी का कथन उपलब्ध है, वहां ऐसे साक्षी की परीक्षा अभियुक्त की जाएगी और उक्त कथन की मूल प्रति अभिलेख पर ली जाएगी और उसकी प्रति अभियुक्त को दी जाएगी तथा उसको यदि जांच न्यायालय में साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर नहीं दिया गया था तो उसे प्रति परीक्षा करने का अधिकार होगा :

परंतु यह और कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के अध्याधीन धारा 16, धारा 17, धारा 19 और धारा 20 और अधिनियम की धारा 49 के अधीन दंडनीय 'हत्या' के अपराध के पश्चात् फरार हो जाता है या अभित्यजन करता है और उसके पकड़े जाने की तुरंत कोई संभावना नहीं है तो साक्ष्य का अभिलेख तैयार करने के लिए ब्यौरा रखने वाला अधिकारी अभियुक्त के अभाव में साक्षियों की परीक्षा करेगा तथा ऐसा साक्ष्य ऐसे अभियुक्त के संदेह व्यक्त करने पर सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा विचारण पर उसके विरुद्ध दी जाएगी चाहे ऐसे साक्षी की मृत्यु हो गई हो या साक्ष्य देने में असमर्थ हो या जिसे खोजा नहीं जा सकता हो या उसकी उपस्थिति अविलंब, ऐसे खर्चों या असुविधा के बिना जो मामले की परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त नहीं हो, उपाप्त नहीं की जा सकती हो ।

(3) अभियुक्त के विरुद्ध सभी साक्षियों की परीक्षा कर लिए जाने के पश्चात् अभियुक्त को निम्नलिखित रूप से सतर्क किया जाएगा । "यदि आप कोई कथन करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप कथन करने के लिए बाध्य नहीं हैं और आप जो कुछ कहेंगे वह लिखा जाएगा और उसका साक्ष्य में प्रयोग किया जा सकेगा" । पूर्वोक्त रीति से सतर्क किए जाने के पश्चात् अभियुक्त जो कथन करता है वह लिखा लिया जाएगा ।

(4) अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा में साक्षी बुला सकेगा और साक्ष्य अभिलिखित करने वाला आफिसर कोई भी ऐसा प्रश्न पूछ सकेगा जो ऐसे साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो ।

(5) सभी साक्षी शपथ या प्रतिशत पर साक्ष्य देंगे :

परन्तु अभियुक्त से कोई शपथ या प्रतिज्ञान नहीं कराया जाएगा और न ही उसकी प्रतिपरीक्षा की जाएगी ।

(6) (क) साक्षियों द्वारा दिए गए कथन सामान्यतः वृत्ति के रूप में अभिलिखित किए जाएंगे और साक्ष्य अभिलिखित करने वाला आफिसर अभियुक्त के निवेदन पर, साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में अभिलिखित करने की अनुज्ञा दे सकेगा,

(ख) साक्षियों को उनके कथन पढ़कर सुनाए जाने और स्पष्ट किए जाने के पश्चात् साक्षी उन पर हस्ताक्षर करेंगे ।

(7) धारा 101 के उपबंध साक्ष्य का अभिलेख तैयार करने वाले आफिसर के समक्ष साक्षियों को हाजिर कराने के लिए लागू होंगे । साक्षियों को परिशिष्ट 15 में दिए गए प्रारूप के अनुसार समन किया जाएगा ।

(8) जहां किसी साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है या वह उपलब्ध नहीं है या उसे समय या धन के अनुचित व्यय के बिना हाजिर नहीं कराया जा सकता और जहां साक्ष्य अभिलिखित करने वाले आफिसर द्वारा इस निमित्त प्रमाण-पत्र दिए जाने के पश्चात् वह ऐसे साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित कथन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जा सकेगा और वह साक्ष्य के अभिलेख में सम्मिलित किया जा सकेगा ।

(9) साक्ष्य का अभिलेखन पूरा करने के पश्चात् साक्ष्य अभिलिखित करने वाला आफिसर निम्नलिखित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र देगा :—

"प्रमाणित किया जाता है कि द्वारा आदिष्ट साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति और सुनवाई में लेखबद्ध किया गया था और नियम 51 के उपबंधों का पालन किया गया है ।"

(10) किसी काउन्सेल या विधि व्यवसायी को साक्ष्य अभिलिखित करने वाले आफिसर के समक्ष उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

52. साक्ष्य का सार.—(1) साक्ष्य का सार या तो कमान आफिसर या उसके द्वारा तैयार किसी आफिसर द्वारा तैयार किया जाएगा ।

(2) (क) साक्ष्य के साथ में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(i) साक्षियों के हस्ताक्षरित कथन जहां कहीं उपलब्ध हों या उसके सारांश, और

(ii) विचारण में पेश की जाने के लिए आशयित सभी दस्तावेजों की प्रतियां ।

(ख) जहां किन्हीं साक्षियों के हस्ताक्षरित कथन उपलब्ध न हों, वहां साक्षियों द्वारा दिए जाने वाले संभावित साक्ष्य का सारांश सम्मिलित होगा ।

(3) साक्ष्य का सार तैयार करने वाले आफिसर द्वारा साक्ष्य के सार की एक प्रति अभियुक्त को दी जाएगी और अभियुक्त को, यदि वह चाहता है तो उसे नियम 51 के उप-नियम (3) में अधिकथित रीति से सतर्क करने के पश्चात् कथन करने का अवसर दिया जाएगा :

परन्तु अभियुक्त को अपना कथन करने के लिए उतना समय दिया जाएगा जो परिस्थितियों में युक्तियुक्त हो किंतु किसी भी दशा में उसे साक्ष्य के सार की प्राप्ति के पश्चात् चौबीस घंटे से कम समय नहीं दिया जाएगा ।

53. पुलिस द्वारा मामलों का अन्वेषण— जहां कमान आफिसर ऐसा करना आवश्यक समझता है, वहां वह किसी मामले के अन्वेषण के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा।

54. साक्ष्य के अभिलेख या सार के पश्चात् कमान आफिसर द्वारा मामले का निपटारा :—(1) जहां साक्ष्य का अभिलेख तैयार करने का उसका सार बनाने का कार्य किसी आफिसर को सौंपा गया हो, वहां वह उसे कमान आफिसर को भेजेगा।

(2) कमान आफिसर स्वयं अपने या किसी दूसरे आफिसर द्वारा तैयार किए गए, साक्ष्य के अभिलेख या सार के अवलोकन के पश्चात् :-

- (i) यदि अपेक्षित हो, मामले की अतिरिक्त साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा, या
- (ii) आरोप खारिज कर सकेगा परन्तु जहां वरिष्ठ प्राधिकारी के निर्देश पर किसी आफिसर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरम्भ की गई है, वहां ऐसे प्राधिकारी को निर्देश किए बिना आरोप खारिज नहीं किया जाएगा, या
- (iii) आरोप की पुनः सुनवाई कर सकेगा और समरी/लघु खंड में से कोई दंड अधिनिर्णीत कर सकेगा, या
- (iv) धारा 56 के अधीन अभियुक्त का समरी विचारण कर सकेगा या समरी बल न्यायालय द्वारा विचारण कर सकेगा जहां वह ऐसा करने के लिए सशक्त है, या
- (v) किसी आफिसर या अधीनस्थ आफिसर की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संक्षिप्त निपटारे के लिए मामले को प्रतिप्रेषित कर सकेगा, या
- (vi) अभियुक्त के विचारण के लिए न्यायालय संयोजित करने के लिए सक्षम आफिसर या प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

55. न्यायालय के लिए आवेदन :—न्यायालय के लिए आवेदन यथासंभव परिशिष्ट 6 में दिए गए प्रारूप में कमान आफिसर द्वारा किया जाएगा और उसके साथ साक्ष्य के अभिलेख या सार और आरोप-पत्र की पांच प्रतियां और ऐसे अन्य दस्तावेज होंगे जिनका उस आवेदन के प्रारूप में उल्लेख किया गया है।

अध्याय 8

आरोप और विचारण की पूर्वगामी बातें

56. आरोप पत्र :— (1) आरोप पत्र में संपूर्ण विवादक या एक ही समय में विचारणीय सभी विवादक होंगे और यदि आरोप उन्हीं तथ्यों पर आधारित है अथवा उसी या वैसे ही स्वरूप के अपराधों की श्रृंखला के भाग रूप है तो आरोप-पत्र में एक से अधिक आरोप हो सकेंगे :-

परन्तु धारा 20, धारा 21, धारा 32 और धारा 35 के अधीन कोई आरोप किसी आरोप-पत्र में इस बात को होते हुए भी सम्मिलित किया जा सकेगा कि उस आरोप-पत्र में अन्य आरोप उन्हीं तथ्यों पर आधारित नहीं हैं अथवा उसी या वैसे ही स्वरूप के अपराधों की श्रृंखला के भागरूप नहीं हैं।

(2) प्रत्येक आरोप—पत्र यथासंभव परिशिष्ट 5 में दिए गए प्रारूप के अनुसार तैयार किया जाएगा।

57. आरोप :—(1) प्रत्येक अपराध के लिए पृथक आरोप होगा।

(2) (क) यदि कोई एक कार्य या कार्यों की श्रृंखला ऐसी प्रकृति की है कि यह संदेहास्पद है कि उन तथ्यों से जो सिद्ध किए जा सकते हैं, कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनेगा तो अभियुक्त पर ऐसे सब अपराधों या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा और किसी भी संख्या में ऐसे आरोपों का एक साथ तुरंत विचारण किया जा सकेगा, या उस पर उक्त अपराधों में से कोई अपराध करने का अनुकल्पित आरोप लगाया जा सकेगा।

(ख) अधिक गम्भीर अपराध के आरोप का उल्लेख उससे कम गम्भीर अपराध के आरोप के पहले किया जाएगा।

(3) प्रत्येक आरोप के दो भाग होंगे, अर्थात् :—

(क) अपराध का कथन, और

(ख) अपराध की विशिष्टियां।

(4) यदि अपराध सिविल अपराध नहीं है तो उसका कथन यथासाध्य अधिनियम के निकटतम शब्दों में किया जाएगा और यदि अपराध सिविल अपराध है तो उसका कथन ऐसे शब्दों में किया जाएगा जो उस अपराध का पूर्वाप्त रूप से वर्णन करते हैं।

(5) (क) विशिष्टियों में अभिकथित अपराध के समय और स्थान का और उन व्यक्ति का (यदि कोई हो) जिसके विरुद्ध अथवा उस वस्तु का (यदि कोई हो) जिसके विषय में वह अपराध किया गया है कथन होगा और ये विशिष्टियां अभियुक्त की

उस बात की जिसका उस पर आरोप है, सूचना देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

(ख) यदि ऐसी विशिष्टियाँ अभियुक्त को उस बात की, जिसका उस पर आरोप है, सूचना देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो उस रीति की, जिससे अपराध किया गया था, ऐसी विशिष्टियाँ भी जो उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं, आरोप में अंतर्विष्ट होंगी।

58. संयुक्त आरोप :— (1) किसी भी संख्या में अभियुक्तों पर किसी ऐसे अपराध का जिसके बारे में यह प्रकटित है कि वह उन्होंने संयुक्त रूप से किया है, संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा।

(2) कितनी भी संख्या में अभियुक्तों का ऐसे अपराध के लिए, जिसके बारे में यह प्रकटित है कि वह उनमें से एक या अधिक द्वारा किया गया है और दूसरे या दूसरों द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है, एक साथ विचारण भी किया जा सकेगा भले ही उस पर संयुक्त रूप से आरोप नहीं लगाया गया है।

(3) जहाँ अभियुक्तों पर उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन इस प्रकार आरोप लगाया जाता है वहाँ उनमें से एक या अधिक पर किसी अन्य अपराध का, जिसका उन पर नियम 56 के उप-नियम (1) के अधीन आरोप लगाया जा सकता था, आरोप लगाया जा सकेगा।

59. आरोप पत्र की विधिमाम्यता.—आरोप-पत्र केवल इस तथ्य के कारण अविधिमाम्य नहीं होगा कि उसमें अभियुक्त के नामों या वर्णन में कोई भूल है और आरोप-पत्र का अर्थ लगाने में, ऐसी प्रत्येक प्रतिपादन की, जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह उपधारणा की जा सकती है कि वह उनमें व्यक्त न होते हुए भी विवक्षित रूप से उनमें सम्मिलित है, उसका समर्थन करने के पत्र में उपधारणा की जाएगी और अपराध का कथन तथा अपराध की विशिष्टियाँ एक साथ पढ़ी जाएंगी और उनका एक साथ अर्थ लगाया जाएगा।

60. बल न्यायालय द्वारा आरोप-पत्र का संशोधन :—(1) विचारण के दौरान यदि किसी समय न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि आरोप-पत्र में—

(क) अभियुक्त के नाम या वर्णन में कोई भूल है, या

(ख) कोई ऐसी भूल है तो लेखन गलती या लोप के कारण हुई मानी जा सकती है तो न्यायालय उस भूल को सुधारने के लिए आरोप-पत्र का संशोधन कर सकेगा।

(2) यदि विचारण के दौरान जिसमें जज अटर्नी है, किसी समय न्यायालय को अपने निष्कर्षों पर विचार-विमर्श की समाप्ति से पूर्व यह प्रतीत होता है कि किसी आरोप में कोई परिवर्तन, उससे लोप या उसमें परिवर्तन जो इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन नहीं किया जा सकता, करना न्याय के हित में वांछनीय है तो वह उस दशा में जब ऐसा परिवर्तन, लोप या परिवर्तन अभियुक्त के प्रति अन्वृत्ता के बिना किया जा सकता है, जज अटर्नी की सहमति से आरोप-पत्र का इस प्रकार संशोधन कर सकेगा।

(3) यदि विचारण के दौरान, जिसमें कोई जज अटर्नी नहीं है, किसी समय न्यायालय को अपने निष्कर्षों पर विचार-विमर्श की समाप्ति से पूर्व यह प्रतीत होता है कि किसी आरोप में कोई परिवर्तन, उसमें लोप या उसमें परिवर्तन, जो इन नियम के उप-नियम (1) के अधीन नहीं किया जा सकता, करना न्याय के हित में वांछनीय है तो वह स्थगित कर सकेगा और संयोजक आफिसर को अपनी राय की रिपोर्ट भेज सकेगा और संयोजक आफिसर :

(क) यदि इस नियम के अधीन अनुज्ञेय है, तो आरोप का संशोधन कर सकेगा और अभियुक्त को संशोधन की सम्यक सूचना देने के पश्चात् संशोधित रूप में उसका विचारण करने के लिए न्यायालय को निदेश दे सकेगा; या

(ख) इसको संशोधन किए बिना उसका विचारण अग्रसर करने के लिए न्यायालय को निर्देश दे सकेगा या

(ग) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय संयोजित कर सकेगा।

61. संयोजक आफिसर द्वारा आरोप का संशोधन :—जब कोई बल न्यायालय नियम 60 या नियम 76 के अधीन संयोजक आफिसर को रिपोर्ट भेजता है, तब वह उस आरोप का, जिसकी बाबत न्यायालय ने रिपोर्ट भेजी है, ऐसे परिवर्तन, लोप या परिवर्तन द्वारा संशोधन कर सकेगा जो उसकी राय में न्याय के हित में वांछनीय है और जिसके बारे में उसका यह समाधान हो गया है कि वह अभियुक्त के प्रति अनुचित के बिना किया जा सकता है।

62. न्यायालय संयोजित करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कार्यवाई—(1) जैसे ही वरिष्ठ आफिसर न्यायालय संयोजित करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त करता है, वह, जहाँ आवश्यक हो वहाँ, जज अटर्नी जनरल या ऐसे आफिसर के साथ जिसे जज अटर्नी जनरल द्वारा इस प्रयोजन के लिए लगाया गया है, के परामर्श से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप और साक्ष्य की संवीक्षा करेगा और वह,

- (i) जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य अपर्याप्त है और अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहाँ कमान आफिसर को आरोप खारिज करने के लिए निदेश देगा और यदि वह विचारण प्रारंभ करना उपयुक्त नहीं समझता है तो आरोप खारिज करने के लिए निदेश दे सकेगा; या
- (ii) समरी बल न्यायालय द्वारा विचारण के लिए या संक्षेपतः कार्रवाई करने के लिए मामला कमान आफिसर को उस दशा में वापस कर सकेगा जब उसका विचार है कि उसका इस प्रकार पर्याप्त रूप से विचारण किया जा सकता है या कार्रवाई की जा सकती है; या
- (iii) मामले का प्रशासनिक रूप से निपटारा कर सकेगा और यदि वह ऐसा करने को सक्षम नहीं है तो अपनी सिफारिशों के साथ उच्चतर प्राधिकारी के पास मामले को भेज सकेगा; या
- (iv) अतिरिक्त साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए मामला उस दशा में वापस कर सकेगा जब उसका विचार है कि अभिलिखित साक्ष्य अपर्याप्त है किन्तु अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध हो सकेगा ।

(2) (क) किसी अन्य मामलें में वह या तो न्यायालय का संयोजन स्वयं कर सकेगा या यदि उसका यह विचार है कि उच्चतर किस्म के न्यायालय का संयोजन किया जाना चाहिए और वह ऐसा न्यायालय संयोजक करने के लिए सशक्त नहीं है तो वह इस सिफारिश के साथ कि ऐसे न्यायालय का संयोजन किया जाए, मामला उच्चतर प्राधिकारी को भेज सकेगा ।

(ख) उच्चतर प्राधिकारी, मामला प्राप्त होने पर, इस नियम के उप नियम (1) में दी गई शक्तियों में से किसी का प्रयोग कर सकेगा :

परन्तु वरिष्ठ आफिसर या उच्चतर प्राधिकारी, जनरल बल न्यायालय या पैटी बल न्यायालय का संयोजन करने से पूर्व जज अटर्नी जनरल या ऐसे आफिसर की जिसे जज अटर्नी जनरल द्वारा इस प्रयोजन के लिए लगाया गया है, सलाह लेगा ।

परन्तु यह और कि वरिष्ठ आफिसर या उच्चतर प्राधिकारी न्यायालय का संयोजन करते समय, ऐसा आरोप पत्र पुनः विरचित कर सकेगा जिस पर अभियुक्त का विवरण किया जाना है ।

63. जनरल और पैटी बल न्यायालय में सेवा करने से आफिसरों की निरहर्ता :— कोई आफिसर, न्यायालय में सेवा करने के लिए निरहर्त होगा यदि :—

- (i) वह ऐसा आफिसर है जिसने न्यायालय को संयोजित किया है, या
- (ii) वह अभियोजक है या अभियोजन का साक्षी या
- (iii) उसने मामले के अन्वेषण में ऐसा भाग लिया है जिसके कारण उसे साक्ष्य के किसी भाग पर या मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग लगाना आवश्यक हो गया था, या
- (iv) वह अभियुक्त का कमान आफिसर या उपमहानिरीक्षक या अपर उपमहानिरीक्षक है जिसके कमान के अधीन वह यूनिट भी है जिसमें अभियुक्त द्वारा अधिकथित अपराध किया गया था, सेवारत था ।
- (v) उसका मामले में कोई व्यक्तिगत हित है ।

64. जनरल और पैटी बल न्यायालयों का गठन.—(1) न्यायालय, यथासाध्य, विभिन्न यूनिटों के आफिसरों से मिलकर गठित होगा ।

(2) किसी आफिसर के विचारण के लिए न्यायालय के सदस्य उस आफिसर के रैंक से निम्नतर रैंक के नहीं होंगे जब तक संयोजन आफिसर की राय में, ऐसे रैंक के आफिसर लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं का सम्यक ध्यान रखते हुए, उपलब्ध नहीं है, ऐसी राय संयोजन आदेश में अभिलिखित की जाएगी ।

65. न्यायालयों का संयोजन करते समय संयोजक आफिसर के कर्तव्य — जब कोई आफिसर किसी न्यायालय का संयोजन करता है, तब वह —

- (क) परिशिष्ट 7 में दिए गए समुचित प्ररूप में संयोजन आदेश जारी करेगा,
- (ख) यह निदेश देगा कि अभियुक्त का किन आरोपों पर विचारण किया जाना है और यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त का इन आरोपों पर न्यायालय द्वारा विचारण के लिए उसके कमान आफिसर द्वारा प्रतिप्रेषण कर दिया गया है,
- (ग) यदि उसकी यह राय है कि आरोप पृथक आरोप पत्र से सम्मिलित किए जाएं, तो ऐसा निदेश देगा और यह निदेश भी देगा कि उनका विचारण किस क्रम से किया जाना है ।
- (घ) यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं तो यह निदेश देगा कि अभियुक्तों का विचारण संयुक्ततः किया जाना है या पृथकतः;

- (ख) न्यायालय के सदस्यों और किन्ही प्रतीक्षा सदस्यों की नियुक्ति करेगा;
- (च) यदि जनरल बल न्यायालय का या पैटी बल न्यायालय का जिसके बारे में वह समझता है कि उसमें जज अटर्नी को हाजिर होना चाहिए, संयोजन करता है, तो जज अटर्नी जनरल द्वारा या उसकी ओर से जज अटर्नी की नियुक्ति कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और ऐसे आफिसर को भी नियुक्त कर सकेगा जो विचारण के समय उसके अनुदेश के अधीन रहे,
- (छ) अभियोजन करने के लिए अधिनियम के अधीन या ऐसे आफिसर या ऐसे आफिसर द्वारा सहायता प्राप्त किसी काउंसिल की नियुक्ति करेगा;

परंतु यदि संयोजक आफिसर ठीक समझता है तो वह अभियोजन करने के लिए एक से अधिक ऐसे आफिसर या काउंसिल नियुक्त कर सकेगा,

- (ज) जहां कहीं आवश्यक हो तो एक दुभाषिए की नियुक्ति करेगा,
- (झ) ज्येष्ठ सदस्य को आरोप पत्र, संयोजन आदेश और अभिलेख या साक्ष्य के सार की एक प्रति भेजेगा जिसमें से वह साक्ष्य निकाल दिया गया है, जिसके बारे में उसकी राय है कि वह विचारण में अग्राह्य होगा,
- (ञ) न्यायालय के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक प्रतीक्षा सदस्य को आरोप पत्र और संयोजन आदेश की एक प्रति भेजेगा,
- (ट) अभियोजन को आरोप पत्र और संयोजन आदेश की प्रतियां और मूल अभिलेख या साक्ष्य का सार उसकी अशोधित प्रति के साथ भेजेगा जिसमें वे लेखांश (यदि कोई है) दर्शित होंगे जो ज्येष्ठ सदस्य को भेजी गई प्रति में से निकाल दिए गए हैं ।
- (ठ) जज अटर्नी को (यदि कोई है) आरोप पत्र और संयोजन आदेश की प्रतियां और अभिलेख या साक्ष्य के सार की संशोधित प्रति भेजेगा, जिसमें वे लेखांश (यदि कोई है) दर्शित होंगे जो ज्येष्ठ सदस्य को भेजी गई प्रति में से निकाल दिए गए हैं ।
- (ड) यह सुनिश्चित करेगा कि कमान आफिसर ने सब अभियोजन साक्षियों को और ऐसे प्रतिरक्षा साक्षियों को समन किया है जिन्हें समन करने के लिए अभियुक्त के नियम 67 के अधीन निवेदन किया हो ।

66. अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा की तैयारी—(1) ऐसे अभियुक्त को, जिसको विचारण के लिए प्रतिप्रेषित किया गया है, अपनी प्रतिरक्षा तैयार करने का समुचित अवसर दिया जाएगा और उसे अपने प्रतिरक्षा आफिसर या काउंसिल के साथ और अपने साक्षियों के साथ उचित संपर्क करने दिया जाएगा ।

(2) किसी ऐसे अभियुक्त की, जिसको विचारण के लिए प्रतिप्रेषित किया गया है, प्रतिरक्षा के लिए यथासंभव अभियुक्त की इच्छानुसार प्रतिरक्षा आफिसर की नियुक्ति की जाएगी जब तक कि अभियुक्त लिखित में यह कथित नहीं करता कि वह ऐसी नियुक्त किए जाने का इच्छुक नहीं है ।

(3) यदि अभियोजन, वैध रूप से अर्हित आफिसर या काउंसिल द्वारा किया जाना है, तो अभियुक्त को पर्याप्त समय पहले यह तथ्य सूचित किया जाएगा जिसमें कि यदि वह चाहे तो अपनी प्रतिरक्षा के लिए वैध रूप से अर्हित आफिसर या काउंसिल की व्यवस्था कर सके ।

(4) अभियुक्त का विचारण करने को विनिश्चय करने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र और किसी भी दशा में उसके विचारण से कम से कम चार दिन पूर्व उसे—

- (क) आरोप पत्र की एक प्रति दी जाएगी,
 - (ख) अभिलेख या साक्ष्य के सार की एक अशोधित प्रति दी जाएगी जिसमें वे लेखांश (यदि कोई है) दर्शित होंगे जो ज्येष्ठ सदस्य को भेजी गई प्रति में से निकाल दिए गए हैं ।
 - (ग) ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की सूचना दी जाएगी जो अभियोजन देना चाहता है, और
 - (घ) यदि अभियुक्त ऐसी अपेक्षा करता है तो उन सदस्यों के जिन से मिलकर न्यायालय का गठन होगा, और प्रतीक्षा सदस्यों के बैंक, नाम और युनिट की सूची दी जाएगी ।
- (5) जब किसी अभियुक्त को इस नियम के अनुसार आरोप पत्र की और अभिलेख या साक्ष्य के सार की प्रति दी जाए

तब,—

- (क) वह आरोप को स्पष्ट कराएगा, और

(ख) उसे सूचित किया जाएगा कि उसके विचारण से कम से कम चौबीस घंटे पूर्व कमान आफिसर को उसके द्वारा लिखित आवेदन किए जाने पर जिसमें (अभियोजन के साक्षी से भिन्न) किसी ऐसे साक्षी को, जिसे वह अपनी प्रतिरक्षा में बुलाना चाहता है) ऐसे साक्षी का उसके द्वारा नाम दिया जाएगा उसके विचारण में हाजिरी की अपेक्षा की गई हो, उसके विचारण में साक्षी को हाजिर कराने के लिए इन नियमों के अनुसार व्यक्तिगत कदम उठाए जाएंगे।

(6) उप-नियम (2) और उप-नियम (3) के उपबंध समरी बल न्यायालय के समक्ष विचारण के संबंध में लागू नहीं होंगे और ऐसे विचारण के संबंध में चार दिन की उस अवधि का अर्थ, जो उप-नियम (1) में निर्दिष्ट है, चौबीस घंटे लगाया जाएगा।

67. प्रतिरक्षा साक्षियों का समन करना.—(1) उप-नियम (2) और उप-नियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कमान आफिसर अभियुक्त द्वारा इस निमित्त निवेदन किए जाने पर उन साक्षियों को समन करेगा जो अभियुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) जहां कमान आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि किसी साक्षी द्वारा दिए जाने वाले साक्ष्य से विचारण में कोई तात्त्विक सहायता मिलने की संभावना नहीं है, वहां वह ऐसे साक्षी का समन करने से इंकार कर सकेगा। और ऐसा करते समय वह साक्षियों को नहीं बुलाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(3) कमान आफिसर किसी साक्षी को समन करने से पूर्व अभियुक्त से ऐसे साक्षी की हाजिरी के व्यय को पूरा करने का या पूरा कराने का जिम्मा लेने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि अभियुक्त पूर्वोक्त व्यय को पूरा करने से या पूरा कराने का जिम्मा लेने से इंकार करता है तो कमान-आफिसर उस साक्षी को हाजिर कराने से इंकार कर सकेगा।

(4) जहां कमान आफिसर ने साक्षी को समन करने से उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन इंकार कर दिया है, वहां अभियुक्त ऐसे साक्षी को समन करने के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकेगा और न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में ऐसा करना समीचीन समझता है, तो ऐसे साक्षी को समन करने का आदेश दे सकेगा और यदि आवश्यक हो तो ऐसे साक्षी की हाजिरी के लिए कार्रवाई स्थगित कर सकेगा। साक्षियों को समन करने के लिए परिशिष्ट 15 में दिए प्रारूप के अनुसार समन जारी किए जाएंगे।

अध्याय—9

साधारण और पैटी बल न्यायालयों के लिए प्रक्रिया

68. न्यायालय को समवेत होना और शपथ लेना.—(1) बल न्यायालय के समवेत होने पर न्यायालय विचारण आरंभ करने से पूर्व बल न्यायालय में अपना समाधान करेगा कि—

(क) न्यायालय अधिनियम और इन नियमों के अनुसार संयोजित किया गया है ;

(ख) न्यायालय जिन आफिसरों से मिल कर बना है उनकी संख्या विधि द्वारा अपेक्षित आफिसरों की न्यूनतम संख्या से कम नहीं है।

(ग) सदस्य अपेक्षित रैंक के हैं ;

(घ) सदस्यों की सम्यक रूप से नियुक्ति की गई है और वे अधिनियम के अधीन निरर्हित नहीं हैं ;

(ङ) यदि कोई जज अटर्नी है तो उसकी नियुक्ति सम्यक रूप से की गई है ;

(च) आरोप-पत्र से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त अधिनियम के अध्यक्षीन है और न्यायालय की अधिकारिता के अधीन है ; और

(छ) प्रत्येक आरोप विधि की दृष्टि से सही है और इन नियमों के अनुसार विरचित किया गया है।

(2) (क) जहां कोई रिक्ति, न्यायालय के किसी सदस्य के अधिनियम के अधीन निरर्हित होने या न्यायालय के समवेत होने पर उसके अनुपस्थित रहने के कारण होती है वहां पीठासीन आफिसर उस रिक्ति को भरने के लिए सम्यकतः अर्हित प्रतीक्षा सदस्य को नियुक्त कर सकेगा।

(ख) जहां कोई रिक्ति यथा अपेक्षित सदस्य से हो तो, संयोजक आफिसर द्वारा, नियुक्ति किसी सदस्य के स्थान पर सम्यकतः अर्हित प्रतीक्षा सदस्य को प्रतिस्थापित कर हो सकेगी।

(3) यदि न्यायालय का उप-नियम (1) में उल्लिखित विषयों में से किसी के संबंध में समाधान नहीं होता है और अधिनियम या इन नियमों के अधीन ऐसे विषयों का वह स्वयं परिशोधन करने के लिए सक्षम नहीं है तो वह विचारण प्रारंभ करने से पूर्व उस संबंध में संयोजक आफिसर को रिपोर्ट भेजेगा।

(4) जब न्यायालय ने इस नियम का अनुपालन कर लिया है और विचारण प्रारंभ करने के लिए तैयार है, तब पीठासीन आफिसर न्यायालय की कार्यवाही आरंभ करेगा और विचारण आरंभ होगा।

69. विचारण का प्रारंभ—(1) न्यायालय संयोजित करने का आदेश और अभियुक्त का विचारण करने के लिए नियुक्त आफिसरों के नाम अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाएंगे, जिसे उन आफिसरों में से किसी पर अधिनियम की धारा 96 के उपबंधों के अनुसार आक्षेप करने का अवसर दिया जाएगा।

(2) जब न्यायालय को एक से अधिक अभियुक्तों का पृथकतः या संयुक्ततः विचारण करना है तब प्रत्येक अभियुक्त को न्यायालयसीन किसी आफिसर के बारे में उपनियम (1) के अनुसार आक्षेप करने का अवसर दिया जाएगा और उनसे अलग-अलग पूछा जाएगा कि क्या वे कोई ऐसा आक्षेप करते हैं।

(3) अभियुक्त, किसी आक्षेप के निपटाए जाने के पूर्व उन सब आफिसरों के नाम बताएगा जिनके बारे में वह आक्षेप करता है।

(4) यदि एक से अधिक आफिसरों के बारे में आक्षेप किया जाता है तो प्रत्येक आफिसर के बारे में आक्षेप पृथक रूप से निपटाया जाएगा और सबसे छोटे रैंक वाले आफिसर के बारे में आक्षेप को सबसे पहले निपटाया जाएगा।

(5) अभियुक्त कोई कथन कर सकेगा और अपने आक्षेप के समर्थन में कथन करने के लिए किसी व्यक्ति को बुला सकेगा।

(6) ऐसा कोई आफिसर जिसके बारे में अभियुक्त ने आक्षेप किया है वह अभियुक्त के आक्षेप से सुसंगत किसी बात का कथन बल न्यायालय में, चाहे वह उसके समर्थन में हो या उसके खंडन में, कर सकेगा।

(7) किसी आफिसर के बारे में आक्षेप पर विचार न्यायालयासीन सभी अन्य आफिसरों द्वारा बंद न्यायालय में किया जाएगा और वह आफिसर जिसके बारे में आक्षेप किया गया है उस समय उपस्थित नहीं रहेगा।

(8) जब किसी आफिसर के बारे में कोई आक्षेप धारा 96 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात किया जाता है तब वह आफिसर तत्काल नियुक्त हो जाएगा और कार्यवाहियों में आगे कोई भाग नहीं लेगा।

(9) जब कोई आक्षेपित आफिसर निवृत्त हो जाता है और सम्यक्तः अर्हित प्रतीक्षा सदस्य हाजिर है तब पीठासीन आफिसर उस आफिसर का, जो निवृत्त हो गया है, स्थान ग्रहण करने के लिए उसकी तत्काल नियुक्ति करेगा।

(10) न्यायालय अपना यह समाधान करेगा कि ऐसा कोई प्रतीक्षा सदस्य जो न्यायालय के सदस्य का स्थान ग्रहण करता है, अपेक्षित रैंक का है और अधिनियम के अधीन निरहित नहीं है तो अभियुक्त को उसके बारे में आक्षेप करने का अवसर देगा और ऐसे किसी आक्षेप के संबंध में अधिनियम और इन नियमों के अनुसार कार्यवाई करेगा।

(11) यदि किसी सदस्य के बारे में कोई आक्षेप अनुज्ञात किए जाने के परिणामस्वरूप, अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में न्यायालय का गठन करने के लिए आफिसर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो न्यायालय आगे विचारण के लिए अप्रसर हुए बिना संयोजक आफिसर को रिपोर्ट करेगा और संयोजक आफिसर या तो उस शक्ति को भरने के लिए किसी आफिसर का सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगा या अभियुक्त के विचारण के लिए न्यायालय संयोजित कर सकेगा।

70. सदस्यों का शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना—जैसे हो न्यायालय समुचित संख्या में ऐसे आफिसरों से, जिन पर आक्षेप नहीं किया गया है या जिनके बारे में आक्षेप नामंजूर कर दिए गए हैं, गठित हो जाता है वैसे ही प्रत्येक सदस्य को अभियुक्त को उपस्थिति में निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक में या समान आशय के ऐसे अन्य प्रश्न में जैसा न्यायालय उस सदस्य के धर्म के अनुसार या अन्यथा उसके अतःकरण पर आबद्ध कर अभिनिश्चित करता है, शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा।

शपथ का प्रारूप

“..... सर्व शक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं न्यायालय के समक्ष अभियुक्त (या अभियुक्तों) का साक्ष्य के अनुसार भलीभांति और सच्चाई से विचारण करूँगा और मैं पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से न्याय करूँगा और मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से, किसी भी समय, इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं करूँगा या उसका पता नहीं लगाऊँगा।”

प्रतिज्ञान का प्रारूप

“ मैं सत्यनिष्ठा, सदभाव और सच्चाई से घोषणा करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं न्यायालय के समक्ष अभियुक्त (या अभियुक्तों) का साक्ष्य के अनुसार भलीभांति और सच्चाई से विचारण करूँगा और मैं पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से न्याय करूँगा और मैं सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा सदभाव और सच्चाई से यह घोषणा और प्रतिज्ञान भी करता हूँ कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से, किसी भी समय, इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं करूँगा या उसका पता नहीं लगाऊँगा । ”

71. जज अटर्नी और अन्य आफिसरों का शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना—न्यायालय के सभी सदस्यों को शपथ दिलाए जाने या प्रतिज्ञान कराए जाने के पश्चात् निम्नलिखित व्यक्तियों की या उनमें से जो न्यायालय में उपस्थित हैं निम्नलिखित प्रारूपों में से ऐसे प्रारूप में जो उचित हों या समान आशय के ऐसे अन्य अन्य प्रारूप में जैसा न्यायालय शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने वाले व्यक्ति के धर्म के अनुसार या अन्यथा उसके अंतः करण पर आबद्धकर अभिनिश्चित करता है, शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा ।

(क) जज अटर्नी**शपथ का प्रारूप**

“ मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी सर्वोत्तम योग्यता से सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार और पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना जज अटर्नी के कर्तव्यों का पालन करूँगा और मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से किसी भी समय, किसी विषय पर इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं करूँगा या उसका पता नहीं लगाऊँगा । ”

प्रतिज्ञान का प्रारूप

“ मैं सत्यनिष्ठा, सदभाव और सच्चाई से घोषणा करता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं अपनी सर्वोत्तम योग्यता से सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार और पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना जज अटर्नी के कर्तव्यों का पालन करूँगा और मैं सत्यनिष्ठा, सदभाव और सच्चाई से यह घोषणा और प्रतिज्ञान भी करता हूँ कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से किसी भी समय किसी विषय पर इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं करूँगा या उसका पता नहीं लगाऊँगा । ”

(ख) अनुदेश के प्रयोजन के लिए हाजिर रहने वाला आफिसर**शपथ का प्रारूप**

“ मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से, किसी भी समय, इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं करूँगा या उसका पता नहीं लगाऊँगा । ”

प्रतिज्ञान का प्रारूप

“ मैं सत्यनिष्ठा, सदभाव और सच्चाई से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक किसी भी कारण से, किसी भी समय, इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं करूँगा या उसका पता नहीं लगाऊँगा । ”

(ग) आशुलिपिक**शपथ का प्रारूप**

“ मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि अपनी सर्वोत्तम शक्ति से इस न्यायालय के समक्ष लिए जाने वाले साक्ष्य और किसी ऐसी अन्य बातों को, जिन्हें लिखने की मुझसे अपेक्षा की जाए, सच्चाई से लिखूँगा और जब अपेक्षा की जाए न्यायालय को उसकी सच्ची अनुलिपि दूँगा । ”

प्रतिज्ञान का प्रारूप

“ मैं सत्यनिष्ठा, सदभाव और सच्चाई से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं अपनी सर्वोत्तम शक्ति से इस न्यायालय के समक्ष दिए जाने वाले साक्ष्य और ऐसी अन्य बातों को जिन्हें लिखने को मुझसे अपेक्षा की जाए, सच्चाई से लिखूंगा और जब अपेक्षा की जाए, न्यायालय का उसकी सच्ची अनुलिपि दूंगा । ”

(घ) दुभाषिया**शपथ का प्रारूप**

“ मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं इस न्यायालय के समक्ष मामले से संबंधित ऐसी किसी बात का, जिसका भाषांतर और अनुवाद करने की मुझसे अपेक्षा की जाए, निष्ठापूर्वक भाषांतर और अनुवाद करूंगा । ”

प्रतिज्ञान का प्रारूप

“ मैं सत्यनिष्ठा, सदभाव और सच्चाई से घोषणा करता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं इस न्यायालय के समक्ष मामले से संबंधित ऐसी किसी बात का, जिसका भाषांतर और अनुवाद करने की मुझसे अपेक्षा की जाए, निष्ठापूर्वक भाषांतर और निर्वचन करूंगा । ”

72. दुभाषिए या आशुलिपिक के बारे में आक्षेप.— यदि किसी व्यक्ति के बारे में अभियुक्ति द्वारा कोई आक्षेप किया जाता है तो उसे दुभाषिए या आशुलिपिक के रूप में तब तक शपथ नहीं दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान नहीं कराया जाएगा जब तक कि न्यायालय अभियुक्त और अभियोजक की सुनवाई के पश्चात् ऐसे आक्षेप को अभियुक्त के रूप में नामंजूर नहीं कर देता है ।

73. जज अटर्नी और अभियोजक के बारे में आक्षेप.— अभियुक्त को जज अटर्नी या अभियोजक के बारे में कोई आक्षेप करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

74. दोषारोपण.—(1) जब न्यायालय और जज अटर्नी (यदि कोई है) को शपथ दिला दी गई हो या अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वह आरोप या आरोपों को दोषी होने का अभिवाक करता है या दोषी न होने का अभिवाक करता है ।

(2) यदि अभियुक्त के विरुद्ध एक से अधिक आरोप है तो उससे प्रत्येक आरोप के बारे में पृथक्कृत अभिवाक करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(3) यदि अभियुक्त के विरुद्ध एक से अधिक आरोप-पत्र न्यायालय के समक्ष है जो वह ऐसे आरोप पत्रों में से पहले आरोप पत्र के आरोपों के संबंध में कार्यवाही करेगा और उस पर अपने निष्कर्ष सुनाएगा और यदि अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन किया है तो वह किसी पश्चातवर्ती आरोप पत्र के आरोपों पर उसका दोषारोपण करने से पूर्व नियम 81 का अनुपालन करेगा ।

75. अधिकारिता के संबंध में अभिवाक.—(1) अभियुक्त आरोप के संबंध में अभिवचन करने से पूर्व न्यायालय की अधिकारिता के बारे में अभिवचन कर सकेगा और ऐसी दशा में:—

(क) अभियुक्त अभिवचन के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा और अभियोजक उसके उत्तर में साक्ष्य पेश कर सकेगा; और

(ख) अभियोजक अभिवचन के उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजन के संबोधन का उत्तर दे सकेगा ।

(2) यदि न्यायालय अभिवचन अनुज्ञात करता है, तो वह स्थगित हो जाएगी और संयोजक आफिसर को रिपोर्ट भेजेगा ।

(3) जब न्यायालय इस नियम के अधीन संयोजन आफिसर को रिपोर्ट करता है तब संयोजक आफिसर :—

(क) यदि वह अभिवचन अनुज्ञात करने के न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन करता है तो न्यायालय का विघटन कर देगा ।

(ख) यदि वह न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन नहीं है तो वह या तो:—

(i) मामला न्यायालय को वापस निर्देशित करेगा और उसे विचारण के लिए अग्रसर होने का निदेश करेगा; या

(ii) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय संयोजित करेगा;

76. आरोप के बारे में आक्षेप.—(1) कोई अभियुक्त आरोप पर अभिवचन करने से पूर्व उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप पर इस आधार पर आक्षेप कर सकेगा कि वह विधि की दृष्टि से सही नहीं है या उसकी विरचना इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नहीं की गई है। यदि वह ऐसा करता है तो अभियोजक आक्षेप के उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा।

(2) यदि न्यायालय आक्षेप को कायम रखता है तो वह या तो आरोप पत्र का नियम 60 के उपबंधों के अनुसार संशोधन करेगा या सुनवाई स्थगित करेगा और संयोजन आफिसर को रिपोर्ट भेजेगा :

परंतु यदि न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या दूसरा आरोप पत्र है तो न्यायालय स्थगित करने से पूर्व, अभियुक्त के विरुद्ध ऐसे अन्य आरोप या आरोप पत्र के विचार के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(3) जब न्यायालय उप-नियम (2) के अधीन संयोजक आफिसर को रिपोर्ट भेजता है तो तब संयोजन अधिकारी

(क) यदि वह आक्षेप अनुज्ञात करने के न्यायालय विनिश्चय का अनुमोदन करता है; तो

(i) न्यायालय का विघटन कर देगा ;

(ii) जहां न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या दूसरा आरोप पत्र है जिसके संबंध में अभिवचन नहीं है और जिसका न्यायालय ने विचारण नहीं किया है वहां वह केवल ऐसे आरोप या आरोप पत्र के विचारण के लिए अग्रिम होने के लिए न्यायालय को निदेश देगा; या

(iii) ऐसे आरोप को, जिससे आक्षेप का संबंध है नियम 61 के उपबंधों के अनुसार संशोधन करेगा तदनुसार अभियुक्त के विचारण करने के न्यायालय को निदेश देगा ; या

(ख) यदि वह न्यायालय के आक्षेप अनुज्ञात करने के विनिश्चय का अनुमोदन कर देता है, तो

(i) आरोप पर अभियुक्त के विचारण के लिए न्यायालय को निदेश देगा; या

(ii) जहां न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या दूसरा आरोप पत्र है या जिसके संबंध में आक्षेप नहीं है और जिसका न्यायालय ने विचारण नहीं किया है, वहां वह केवल ऐसे अन्य आरोप या आरोप-पत्र पर अभियुक्त के विचारण के लिए अग्रसर होने के लिए न्यायालय को निदेश देगा; या

(iii) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय संयोजित करेगा।

77. विचारण के वर्जन का अभिवचन.—(1) कोई अभियुक्त आरोप पर अभिवचन करने से पूर्व यह अभिवचन कर सकेगा कि विचारण धारा 87 या धारा 88 के अधीन वर्जित है। यदि वह ऐसा करता है, तो

(क) अभियुक्त अभिवचन के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा और अभियोजक उसके उत्तर में साक्ष्य पेश कर सकेगा, और

(ख) अभियोजक अभिवचन के उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा।

(2) यदि न्यायालय अभिवचन अनुज्ञात करता है तो वह स्थगित हो जाएगा और संयोजक आफिसर को रिपोर्ट करेगा :

परंतु यदि न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या दूसरा आरोप पत्र है तो न्यायालय सुनवाई स्थगित करने से पूर्व ऐसे अन्य आरोप या आरोप पत्र पर अभियुक्त के विचारण के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(3) जब न्यायालय इस नियम के अधीन संयोजक आफिसर को रिपोर्ट भेजता है, तब संयोजक आफिसर—

(क) यदि वह अभिवचन अनुज्ञात करने के न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन करता है तो

(i) न्यायालय का विघटन कर देगा, या

(ii) जहां न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या दूसरा आरोप-पत्र है, वहां वह केवल ऐसे अन्य आरोप या आरोप पत्र पर अभियुक्त के विचारण के लिए अग्रसर होने के लिए न्यायालय को निदेश देगा।

(ख) यदि वह अभिवचन मंजूर करने के न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन कर देता है तो

(i) आरोप पर अभियुक्त के विचारण के लिए न्यायालय को निदेश देगा; या

(ii) जहां न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या दूसरा आरोप-पत्र है जिसके संबंध में अभिवचन नहीं है और जिसका न्यायालय ने विचारण नहीं किया है, वहां वह केवल ऐसे अन्य आरोप या आरोप-पत्र पर अभियुक्त के विचारण के लिए अग्रसर होने के लिए न्यायालय को निदेश देगा; या

(iii) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय संयोजित करेगा ।

78. पृथक विचारण के लिए आवेदन—(1) जहां दो या दो से अधिक अभियुक्तों को संयुक्ततः आरोपित किया जाता है, वहां अभियुक्त आरोपों पर अभिवचन करने से पूर्व, इस आधार पर उस आरोप-पत्र के किसी आरोप पर पृथक रूप से विचारण किए जाने के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि यदि उसका उस आरोप पर पृथकतः विचारण किए जाने के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि यदि उसका उस आरोप पर पृथकतः विचारण नहीं किया गया तो उस की प्रतिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(2) जहां अभियुक्त ऐसा कोई आवेदन करता है, वहां अभियोजक उसके उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा ।

(3) जहां न्यायालय की यह राय है कि न्याय के हित में ऐसा करना अपेक्षित है, वहां वह आवेदन मंजूर करेगा और अभियुक्त का उस आरोप पर जिससे उसका संबंध है, इस प्रकार पृथक रूप से विचारण करेगा मानो वह आरोप किसी पृथक आरोप-पत्र में विरचित किया गया है ।

79. पृथक आरोप-पत्र विचारण के लिए आवेदन—(1) जहां किसी आरोप-पत्र में एक से अधिक आरोप हैं, वहां अभियुक्त आरोपों पर अभिवचन करने से पूर्व, इस आधार पर उस आरोप-पत्र के किसी आरोप पर पृथक रूप से विचारण किए जाने के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि यदि उसका उस आरोप पर पृथकतः विचारण नहीं किया गया तो उस की प्रतिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(2) जहां अभियुक्त ऐसा कोई आवेदन करता है, वहां अभियोजक उसके उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा ।

(3) जहां न्यायालय की यह राय है कि न्याय के हित में ऐसा करना अपेक्षित है, वहां वह आवेदन मंजूर करेगा और अभियुक्त का उस आरोप पर जिससे उसका संबंध है, इस प्रकार पृथक रूप से विचारण करेगा मानो वह आरोप किसी पृथक आरोप-पत्र में विरचित किया गया है ।

80. आरोप पर अभिवचन करना—(1) नियम 75 और नियम 77 के अधीन किसी अभिवचन, नियम 75 के अधीन किसी आक्षेप और नियम 78 और नियम 79 के अधीन किसी आवेदन के संबंध में कार्रवाई किए जाने के पश्चात् अभियुक्त से उप-नियम (2) के अधीन रहते हुए ऐसे प्रत्येक आरोप का, जिसका उस पर दोषारोपण किया गया है, दोषी होने या दोषी का अभिवचन करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(2) जहां कोई न्यायालय, अभियुक्त पर आरोपित अपराध से भिन्न अपराध के लिए उसे दोषी ठहराने के लिए या अपराध के ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें कम मात्रा में दंड अंतर्वलित है, किए जाने का दोषी ठहराने के लिए धारा 105 द्वारा सशक्त है या जहां वह साक्ष्य सुनने के पश्चात् नियम 101 के अनुसार अपवाद या परिवर्तन के अधीन रहते हुए, दोषी होने का विशेष निष्कर्ष निकाल सकता था, वहां अभियुक्त ऐसे अन्य अपराध का या आरोपित अपराध के ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें कम मात्रा में दंड अंतर्वलित है, किए जाने का या ऐसे अपवाद या परिवर्तन के अधीन रहते हुए आरोपित अपराध का दोषी होने का अभिवचन कर सकेगा ।

81. दोषी होने का अभिवचन स्वीकार करना—(1) जहां कोई अभियुक्त नियम 80 के उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन किसी अपराध को दोषी होने का अभिवचन करता है, वहां पीठासीन आफिसर या जज अटर्नी, न्यायालय द्वारा अभिवचन स्वीकार करने का विनिश्चय किए जाने से पूर्व, आरोप की प्रकृति और उसके अभिवचन का साधारण प्रभाव और विशिष्टियां अभियुक्त के दोषी होने के अभिवचन के कारण प्रक्रिया का अंतर अभियुक्त को स्पष्ट करेगा ।

(2) न्यायालय तब अभियोजक के साक्ष्य का अभिलेख या सार न्यायालय में पढ़कर सुनवाएगा या न्यायालय को उसमें दिए गए तथ्यों को सूचित करेगा :

परंतु यदि साक्ष्य के अभिलेख या सार की कोई परिशोधित प्रति पीठासीन आफिसर को भेजी गई तो अभियोजक न्यायालय को साक्ष्य के अभिलेख या सार के ऐसे भाग को पढ़कर नहीं सुनाएगा जिसका परिशोधन किया गया है या उन भागों में दिए गए तथ्यों को न्यायालय को सूचित नहीं करेगा और न्यायालय को साक्ष्य का मूल अभिलेख या सार तब तक नहीं देगा जब तक कि विचारण समाप्त नहीं हो जाता । जहां कोई अभिलेख या साक्ष्य का सार नहीं है वहां न्यायालय इन नियमों के अनुसार दंड का अवधारण करने में अपने को समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य अभिलिखित करेगा ।

(3) न्यायालय नियम 83 के उप-नियम (1) के अधीन दोषी होने का अभिवचन उस दशा में स्वीकार नहीं करेगा यदि :—

(क) न्यायालय का यह समाधान नहीं होता है कि अभियुक्त आरोप की प्रकृति या वह अपने अभिवचन का प्रभाव समझता है, या

(ख) पीठासीन आफिसर का साक्ष्य के अभिलेख में अंतर्विष्ट साक्ष्य या साक्ष्य के सार और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह विचार हो कि अभियुक्त को दोषी न होने का अभिवचन करना चाहिए, या

(ग) अभियुक्त दोष सिद्ध होने पर मृत्यु दंड का भागी है।

(4) (क) नियम 82 के अधीन दोषी होने के अभिवचन की दशा में न्यायालय अभिवचन तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक संयोजक आफिसर सहमत नहीं होता है और ऐसी कार्यवाही के न्यायोचित होने के बारे में उसको समाधान नहीं हो जाता है;

(ख) संयोजक आफिसर की सहमति अभियोजक द्वारा संज्ञापित की जा सकेगी।

(5) जब दोषी होने का अभिवचन नियम 80 के उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है या अभियुक्त आरोप पर अभिवचन करने से इंकार करता है या वह उस पर स्पष्ट रूप में अभिवचन नहीं करता है तो न्यायालय दोषी न होने का अभिवचन करेगा।

(6) जब न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वह नियम 80 के उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन दोषी होने का अभिवचन उचित रूप से स्वीकार कर सकता है तो वह उसकी बाबत दोषी होने का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(7) न्यायालय अपने निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात् वह अभियुक्त को चरित्र का साक्ष्य पेश करने के लिए और दंड को कम करने के संबंध में कथन करने का अवसर देगा।

(8) यदि अभियुक्त द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और उप-नियम (7) के अधीन दिए गए उसके कथन से न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अभियुक्त ने दोषी होने के अभिवचन के प्रभाव को नहीं समझा था तो उसे अभिलेख में परिवर्तन करना चाहिए और दोषी होने के अभिवचन की प्रविष्टि करनी चाहिए तथा तदनुसार विचारण के लिए अग्रसर होना चाहिए।

(9) उप-नियम (7) का अनुपालन करने और न्यायालय द्वारा दोषी होने के अभिवचन को स्वीकार करने का विनिश्चय करने के पश्चात् न्यायालय नियम 103 के निर्देशानुसार अग्रसर होगा।

82. आनुकल्पिक आरोप पर अभिवचन.—(1) जब अभियुक्त दो या अधिक आनुकल्पिक आरोपों में से प्रथम की बाबत दोषी होने का अभिवचन करता है तब न्यायालय, यदि वह अभियुक्त का दोषी होने का अभिवचन स्वीकार करता है, प्रथम आरोप की बाबत दोषी होने का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, और अभियोजक उस पर अभियुक्त को दोषारोपित किए जाने से पूर्व किसी आनुकल्पिक आरोप को वापस ले लेगा।

(2) जब अभियुक्त ऐसे दो या अधिक आरोपों में से, जो आनुकल्पिक के रूप में अधिकथित किए गए हैं, ऐसे आरोपों के प्रथम से भिन्न किसी एक आरोप की बाबत दोषी होने का अभिवचन करता है तब न्यायालय :—

(क) इस प्रकार अग्रसर हो सकेगा मानो अभियुक्त ने सब आरोपों की बाबत, दोषी नहीं होने का अभिवचन किया है; या

(ख) (i) संयोजक आफिसर की सहमति से (जो अभियोजक द्वारा संज्ञापित की जा सकेगी) उस आरोप की बाबत, जिसका अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन किया है, दोषी होने का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा और किसी आनुकल्पिक आरोप की बाबत जो आरोप-पत्र में इसके पूर्व है, दोषी न होने का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा;

(ii) जहां न्यायालय ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित करता है, वहां अभियोजक उस पर अभियुक्त को दोषारोपित किए जाने से पूर्व किसी ऐसे आक्षेप को वापस ले लेगा जो आरोप का अनुकल्पी है जिसके लिए न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया है और जो आरोप-पत्र में उसके पश्चात् है।

83. दोषी होने के अभिवचन की दशा में विचारण का आदेश.—(1) दोषी होने का निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात् न्यायालय यदि उसी आरोपपत्र में ऐसा अन्य आरोप नहीं है जिसकी बाबत अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवचन किया है और कोई ऐसा अभियुक्त नहीं है जिसने उस आरोप-पत्र के किसी आरोप की बाबत दोषी न होने को अभिवचन किया है तो, यह नियम 81 के निर्देशानुसार विचारण के लिए अग्रसर होगा।

(2) जहां आरोप-पत्र में ऐसा अन्य आरोप है जिसकी बाबत अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवचन किया है या ऐसा अन्य अभियुक्त है जिसने उस आरोप-पत्र में किसी आरोप की बाबत दोषी न होने का अभिवचन किया है वहां न्यायालय नियम 81 का तब तक अनुपालन नहीं करेगा जब तक उसने ऐसे अन्य आरोप की बाबत कार्रवाई नहीं कर ली है या उसने ऐसे अन्य अभियुक्त का विचारण नहीं कर लिया है और उसकी बाबत अपना निष्कर्ष घोषित और अभिलिखित नहीं कर दिया है।

84. अभिवचन का परिवर्तन—(1) दोषी न होने का अभिवचन करने वाला अभियुक्त न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष पर विचार-विमर्श समाप्त किए जाने से पूर्व किसी भी समय दोषी न होने के अपने अभिवचन की वापस ले सकेगा और उसके स्थान पर दोषी होने का अभिवचन (जिसके अंतर्गत नियम 82 के अधीन दोषी होने का अभिवचन भी है) कर सकेगा और ऐसी दशा में न्यायालय यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि वह अभियुक्त के परिवर्तित अभिवचन के अनुसार निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और जहां तक आवश्यक हो नियम 81 के निर्देशानुसार अग्रसर होगा ।

(2) जहां विचारण के दौरान किसी भी समय न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह अभियुक्त जिसने दोषी होने का अभिवचन किया है, अपने अभिवचन के प्रभाव को या आरोप की प्रकृति को नहीं समझता है तो न्यायालय दोषी न होने के अभिवचन की प्रविष्टि करेगा और तदनुसार विचारण के लिए अग्रसर होगा ।

(3) जब न्यायालय उपनियम (2) के अधीन किसी आरोप की बाबत दोषी न होने का अभिवचन अभिलिखित करता है तब वह यदि उसके अनुकूल्य के रूप में कोई ऐसा आरोप अभिकथित था जिसे अभियोजक ने नियम 82 के अधीन वापस ले लिया था तो ऐसे आनुकूल्यिक आरोप की पुनः स्थापित करेगा, उस पर अभियुक्त को दोषारोपित करेगा और विचारण के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह कभी भी वापस नहीं लिया गया था ।

85. दोषी न होने के अभिवचन पर प्रक्रिया—किसी आरोप की बाबत दोषी न होने का अभिवचन अभिलिखित किए जाने के पश्चात :—

(i) न्यायालय अभियुक्त से पूछेगा कि क्या वह इस आधार पर कि विचारण के पूर्व की प्रक्रिया से संबंधित उन नियमों में से किसी का अनुपालन नहीं किया गया है और इसका उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इस आधार पर कि उसे अपनी प्रतिरक्षा को तैयार करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिला है ;

(ii) जहां अभियुक्त रथगन के लिए आवेदन करता है,—

(क) अभियुक्त अपने आवेदन के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा

(ख) अभियोजक आवेदन के उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा ।

(iii) यदि न्यायालय समझता है कि न्याय के हित में ऐसा करना अपेक्षित है तो वह रथगन मंजूर कर सकेगा ।

86. आरंभिक संबोधन—(1) अभियोजक, यदि वह चाहे और यदि न्यायालय द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए तो आरंभिक संबोधन कर सकेगा, जिसमें वह आरोप और उस साक्ष्य की प्रकृति और साधारण प्रभाव को स्पष्ट करेगा जो वह पेश करने की प्रस्थापना करता है ।

(2) तब अभियोजन के लिए साक्षियों को उनके साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाएगा ।

87. अतिरिक्त साक्षी—जहां अभियोजक ऐसा साक्ष्य पेश करने का आशय रखता है, जो अभियुक्त को दिए गए साक्ष्य के किसी अभिलेख या सार में सम्मिलित नहीं है, वहां साक्ष्य की विशिष्टियों सहित, ऐसे आशय की सूचना, जब साक्ष्य हो, अभियुक्त को साक्ष्य पेश करने से उचित समय पूर्व दी जाएगी । यदि ऐसा साक्ष्य, ऐसी सूचना या विशिष्टियां दिए बिना पेश किया जाता है तो न्यायालय यदि अभियुक्त चाहे तो, साक्ष्य लेने के पश्चात् या तो, स्थगित कर सकेगा या उस साक्ष्य से उद्भूत को सूचित करेगा कि उसे ऐसे रथगन या मुत्तवी के लिए आवेदन करने का अधिकार है ।

88. साक्षियों को छोड़ना—अभियोजक, अभियुक्त के विरुद्ध उन सब साक्षियों को, जिनका साक्ष्य, साक्ष्य के अभिलेख या सार में है, बुलाने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही वह किसी ऐसे साक्षी को बुलाने के लिए बाध्य होगा जब वह अभियुक्त को यह सूचित कर चुका है कि वह नियम 86 के अधीन बुलाने का आशय रखता है और अभियुक्त को उससे पत्र-व्यवहार और, यदि वह चाहे तो उसे प्रतिरक्षा की ओर से साक्षी के रूप में बुलाने की अनुज्ञा दी जाएगी ।

89. साक्षियों का वापस लिया जाना—विचारण के दौरान, अभियोजक या अभियुक्त को छोड़कर, कोई साक्षी न्यायालय की इजाजत के बिना न्यायालय में तब नहीं रहेगा जब उसकी परीक्षा नहीं चल रही है और यदि उसकी परीक्षा चलने के दौरान उसकी परीक्षा की बाबत कोई प्रश्न अनुज्ञात करने या न करने के बारे में कोई विचार-विमर्श होता है, तो न्यायालय ऐसे विचार-विमर्श होता है तो न्यायालय ऐसे विचार विमर्श के दौरान साक्षी को वापस जाने के लिए निर्देश दे सकेगा ।

90. साक्षियों की परीक्षा—(1) किसी साक्षी की परीक्षा उसे बुलाने वाले व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी और कार्यवाही के दौरान विरोधी पक्षकार द्वारा उसकी प्रति-परीक्षा की जा सकेगी और ऐसी प्रति-परीक्षा की समाप्ति पर, प्रति-परीक्षा से उद्भूत विषयों के संबंध में उसकी उस व्यक्ति द्वारा पुनः परीक्षा की जा सकेगी जिसने उसे बुलाया है ।

(2) (क) किसी साक्षी की परीक्षा करने वाला व्यक्ति साक्षी से प्रश्न मौखिक तौर पर पूछेगा और जब तक कि साक्षी, न्यायालय जज अटर्नी, अभियोजक या अभियुक्त द्वारा कोई आक्षेप नहीं किया जाता, साक्षी तत्काल उत्तर देगा।

(ख) जहां ऐसा आक्षेप किया जाता है, वहां साक्षी तब तक उत्तर नहीं देगा जब तक आक्षेप निपटा नहीं दिया जाता है।

(3) न्यायालय साक्षी की प्रति-परीक्षा या पुनःपरीक्षा का मुक्तवी किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा।

(4) साक्षी की परीक्षा करने से पूर्व उसे निम्नलिखित प्ररूप में या समान आशय के ऐसे अन्य प्ररूप में, जैसा न्यायालय उसके धर्म के अनुसार या अन्यथा जो उसके अंतःकरण पर आबद्धकर हो, अभिनिश्चित करे, शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञात कराया जाएगा।

शपथ का प्रारूप

मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, पूर्ण सत्य कहूंगा और सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा।

प्रतिज्ञान का प्रारूप

मैं सत्यनिष्ठा सद्भाव और सच्चाई से घोषणा करता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा, सत्य कहूंगा, पूर्ण सत्य कहूंगा, और सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा।

91. न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछा जाना—(1) पीठासीन आफिसर, जज अटर्नी और न्यायालय का कोई सदस्य साक्षी से प्रश्न पूछ सकेगा।

(2) ऐसे प्रश्न का उत्तर दिए जाने पर, अभियोजक और अभियुक्त साक्षी से उस उत्तर से उद्भूत, जो वह दे चुका है ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें न्यायालय उचित समझे।

92. साक्ष्य का पढ़कर सुनाया जाना—(1)(क) साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य का अभिलेख उसे, उसके न्यायालय छोड़ने से पूर्व, पढ़कर सुनाया जाएगा और ऐसा किए जाने पर वह अभिलेख को शुद्ध करने के लिए कह सकेगा या उस साक्ष्य को स्पष्ट करें सकेगा जो उसने दिया है

(ख) जहां कोई ऐसी शुद्धि की जाती है या स्पष्टीकरण दिया जाता है, वहां अभियोजक और अभियुक्त उस साक्षी में शुद्धि या स्पष्टीकरण के बारे में ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे।

(2) जब आशुलिपिक-लेखक नियोजित किया जाए तब उपनियम (1) का अनुपालन करना आवश्यक नहीं होगा, यदि न्यायालय और जज अटर्नी (यदि कोई है) की राय में ऐसा करना अनावश्यक है :

परंतु यदि कोई साक्षी ऐसी मांग करता है तो उपनियम (1) का अनुपालन किया जाएगा।

93. न्यायालय द्वारा साक्षियों को बुलाया जाना या पुनःबुलाया जाना — (1) (क) न्यायालय अपने निष्कर्ष पर विचार-विमर्श की समाप्ति से पूर्व या यदि कोई जज अटर्नी साक्षी उपसंहार प्रारंभ किए जाने की दशा में पूर्व बुला सकेगा या पुनः बुला सकेगा जब न्यायालय की राय में ऐसा करना न्याय के हित में है,

(ख) जहां न्यायालय इस नियम के अधीन किसी साक्षी को बुलाता है या पुनः बुलाता है वहां अभियोजक और अभियुक्त साक्षी में ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे।

(2) अभियोजक और अभियुक्त, न्यायालय द्वारा निष्कर्ष पर विचार-विमर्श की समाप्ति से पूर्व या यदि कोई जज अटर्नी है तो उसके द्वारा उपसंहार प्रारंभ किए जाने से पूर्व किसी समय, किसी साक्षी को न्यायालय की इजाजत से पुनः बुला सकेंगे और अभियोजक तथा अभियुक्त उस साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे।

94. उत्तर के लिए कोई मामला प्रस्तुत करना और मामलों को रोकना.—(1) (क) अभियोजन पक्ष के लिए मामलों की समाप्ति पर अभियुक्त किसी आरोप की बाबत न्यायालय से यह निवेदन कर सकेगा कि अभियोजना पक्ष प्रथम दृष्टया ऐसा मामला सिद्ध करने में असफल रहा है जिसका उसके द्वारा उत्तर दिया जाए और उस आरोप पर उसे अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

(ख) जहां अभियुक्त ऐसा निवेदन करता है वहां अभियोजक उसके उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा।

(2) न्यायालय निवेदन को तब तक मंजूर नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि :—

(क) अभियोजन ने अधिकथित आरोप की बाबत प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध नहीं किया है, और

(ख) उसे साक्ष्य पर या तो धारा 105 या नियम 101 के उपनियम (4) के अधीन विशेष निष्कर्ष निकालने की छूट नहीं है।

(3) (क) जहां न्यायालय निवेदन को अनुज्ञात करता है वहां वह अभियुक्त को उस आरोप की बाबत जिसके संबंध में वह है, दोषी नहीं ठहराएगा और निष्कर्ष पुष्टि के अधीन रहते हुए, खुले न्यायालय में तत्काल सुनाया जाएगा।

(ख) जहां न्यायालय निवेदन को अनुज्ञात नहीं करता है वहां वह आरोपित रूप में अपराध के विचारण के लिए अग्रसर होगा।

(4) न्यायालय अभियोजन पक्ष के मामले की सुनवाई की समाप्ति के पश्चात और अभियोजक को सुनने के पश्चात स्वप्रेरणा से, अभियुक्त को आरोप की बाबत निर्दोष ठहरा सकेगा और निष्कर्ष को, पुष्टि के अधीन रहते हुए खुले न्यायालय में तत्काल सुनाया जाएगा।

95. प्रतिरक्षा के लिए मामला :— (1) अभियोजन पक्ष के लिए मामले की समाप्ति पर, पीठासीन आफिसर या जज अटर्नी (यदि कोई हो) अभियुक्त को यह स्पष्ट करेगा कि :—

(क) यदि वह चाहे तो साक्षी के रूप में शपथ पर साक्ष्य दे सकता है या शपथ लिए बिना कथन कर सकता है किंतु वह इनमें से कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है,

(ख) यदि वह शपथ पर साक्ष्य देता है तो अभियोजक द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी और न्यायालय द्वारा उससे प्रश्न पूछे जा सकेंगे।

(2) अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्ष्य के प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों को स्पष्ट करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, न्यायालय विचारण के किसी प्रक्रम पर अभियुक्त को पूर्व चेतावनी दिए बिना उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें न्यायालय आवश्यक समझे और अभियोजन के साक्षियों की परीक्षा के पश्चात और अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा के लिए बुलाने के पूर्व पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसमें मामले के संबंध में साधारणतः प्रश्न पूछेगा।

(3) अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करने के कारण या उनके मिथ्या उत्तर देने के कारण दण्ड का भागी नहीं होगा।

(4) अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों पर ऐसे विचारण में विचार किया जा सकेगा और ऐसे उत्तर किसी अन्य अपराध की, जो ऐसे उत्तरों से यह दर्शित हो कि उसने किया है, किसी अन्य जांच में या उसके विचारण में उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध साक्ष्य में रखे जा सकेंगे।

(5) यदि अभियुक्त मामले के तथ्यों के लिए अपने से भिन्न कोई साक्षी बुलाना चाहता है तो वह प्रतिरक्षा के लिए साक्ष्य दिए जाने से पूर्व प्रतिरक्षा के मामले की रूपरेखा बनाते हुए आरंभिक संबोधन कर सकेगा।

96. प्रतिरक्षा के लिए साक्षी :- (1) नियम 95 का अनुपालन किए जाने के पश्चात, प्रतिरक्षा के लिए साक्षियों को (यदि कोई है) अपना साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाएगा।

(2) नियम 90, 91 और 92 के उपबंध प्रतिरक्षा के लिए साक्षियों को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे अभियोजन के लिए साक्षियों के साक्ष्य को लागू होते हैं।

97. उत्तर में साक्षी :- प्रतिरक्षा के लिए साक्षियों द्वारा अपना साक्ष्य दिए जाने के पश्चात अभियोजक, अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में उठाए गए किसी ऐसे विषय पर, जिसे अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा प्रकट किए जाने से पूर्व न्यायालय को उचित रूप से वर्णित नहीं कर सका या जिसकी अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त रूप से पूर्व कल्पना नहीं कर सकता था, साक्ष्य देने के लिए किसी साक्षी को न्यायालय की इजाजत से बुला सकेगा या पुनः बुला सकेगा।

98. संबोधनों का समापन :- (1) सभी साक्ष्य दिए जाने के पश्चात अभियोजक और अभियुक्त में से प्रत्येक न्यायालय को समापन संबोधन कर सकेगा।

(2) अभियुक्त, अभियोजक द्वारा समापन संबोधन किए जाने के पश्चात अपना समापन संबोधन करने का हकदार होगा जब तक कि अभियुक्त ने तथ्यों के लिए अपने से भिन्न कोई अन्य साक्षी नहीं बुलाया है और ऐसे मामले में अभियोजक, उपनियम (3) और उपनियम (4) के अधीन रहते हुए, अभियुक्त द्वारा समापन संबोधन किए जाने के पश्चात अपना समापन संबोधन करने का हकदार होगा।

(3) जहां दो या अधिक अभियुक्तों का एक साथ विचारण किया जाता है, वहां उनमें से कोई एक, जिसने कोई साक्षी नहीं बुलाया है, अभियोजक के समापन संबोधन के पश्चात अपना समापन संबोधन करने का हकदार होगा।

(4) (क) जहां दो या अधिक अभियुक्तों का एक ही प्रतिरक्षा आफिसर या काउंसल प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहां वह केवल एक समापन संबोधन कर सकेगा।

(ख) जहां किसी अभियुक्त ने, जिसके लिए वह उपस्थित होता है, तथ्यों के लिए अपने से भिन्न कोई साक्षी नहीं बुलाया है, वहां ऐसा प्रतिरक्षा आफिसर या काउंसल अभियोजक द्वारा समापन संबोधन किए जाने के पश्चात अपना समापन संबोधन करने का हकदार होगा।

99. जज अटर्नी द्वारा उपसंहार.—समापन संबोधन के पश्चात यदि जज अटर्नी है तो वह खुले न्यायालय में साक्ष्य का उपसंहार करेगा और मामले से संबंधित विधि पर न्यायालय को सलाह देगा।

100. निष्कर्ष पर विचार-विमर्श.—(1) न्यायालय जज अटर्नी की उपस्थिति में बंद न्यायालय में अपने निष्कर्ष पर विचार-विमर्श करेगा।

(2) न्यायालय का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष के बारे में अपनी राय मौखिक रूप में, कनिष्ठतम रैंक से प्रारंभ करके, पृथक रूप से देगा।

101. निष्कर्ष का अभिलेख और सुनाया जाना.—(1) प्रत्येक आरोप पर, जिस पर अभियुक्त को दोषारोपित किया जाता है, निष्कर्ष अभिलिखित किया जाएगा और इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय "दोषी होने" या "दोषी न होने" के निष्कर्ष के रूप में ही अभिलिखित किया जाएगा;

परंतु न्यायालय ऐसे निष्कर्षों के लिए संक्षिप्त कारणों को अभिलिखित करेगा जिसे पीठासीन आफिसर और जज अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा, यदि कोई हो।

(2) जहां किसी आरोप की बाबत न्यायालय की राय है कि साबित किए गए तथ्यों से आरोपित अपराध या ऐसा कोई अपराध प्रकट नहीं होता है जिससे वह लगाए गए आरोप पर अधिनियम के अधीन वैध रूप से दोषी ठहराया जा सके, वहां न्यायालय अभियुक्त को उस आरोप से दोषमुक्त कर देगा।

(3) यदि न्यायालय को किसी आरोप के बारे में ऐसा संदेह है कि साबित किए गए तथ्यों से यह दर्शित होता है या नहीं कि अभियुक्त लगाए गए आरोप का दोषी है, तो वह उस आरोप पर निष्कर्ष अभिलिखित करने से पूर्व, उन तथ्यों का उपवर्णित करते हुए जिसके बारे में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वे साबित हो गए हैं, पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को उसकी राय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो उस प्रयोजन के लिए स्थगित कर सकेगा।

(4) जहां किसी आरोप के बारे में न्यायालय की राय है कि वे लक्ष्य, जिनके बारे में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वे साक्ष्य से साबित हो रहे हैं, आरोप की विशिष्टियों के कथन में अभिकथित तथ्यों से तात्त्विक रूप से भिन्न है, कि ऐसा होने पर भी वे आरोप में कथित अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है और भिन्नता इतनी तात्त्विक नहीं है, जिससे कि अभियुक्त पर उसकी प्रतिरक्षा में उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, वहां वह "दोषी न होने" के निष्कर्ष के बजाय विशेष निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(5) विशेष निष्कर्ष से अभियुक्त को, उसमें विनिर्दिष्ट अपवादों या परिवर्तनों के अधीन रहते हुए, किसी आरोप का दोषी ठहराया जा सकेगा।

(6) जहां अनुकल्पिक आरोप है और साबित तथ्यों से न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उसे अनुकल्पिक आरोपों में से किसी में अपराध नहीं बनता है, वहां न्यायालय उस आरोप पर "दोषी न होने" का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(7) यदि एक आरोप पर दोषसिद्धि से आवश्यक रूप से अनुकल्पी आरोप या आरोपों का दोषी होने का संकेत मिलता हो तो भी न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि अभियुक्त अनुकल्पतः अधिकथित दो या अधिक आरोपों में से एक से अधिक का दोषी है।

(8) यदि न्यायालय का विचार है कि साबित तथ्यों से कोई ऐसा अपराध बनता है जो दो या अधिक अनुकल्पी आरोपों में कथित अपराधों में से एक है किंतु उसे संदेह है कि उन तथ्यों से विधि की दृष्टि में कौन सा अपराध बनता है, तो वह उन आरोपों पर निष्कर्ष अभिलिखित करने से पूर्व उन तथ्यों को, जिनके बारे में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वे साबित हो गए हैं, उपवर्णित करते हुए और यह कथित करते हुए कि उसे संदेह है कि विधि की दृष्टि उन तथ्यों से ऐसे एक या अन्य आरोपों में कथित अपराध बनता है या नहीं, पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को उसकी राय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो उस प्रयोजन के लिए स्थगित कर सकेगा।

(9) प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष, पुष्टि किए जाने के अधीन रहते हुए, खुले न्यायालय में तत्काल सुनाया जाएगा।

102. दोषमुक्त किए जाने पर प्रक्रिया.—यदि सभी आरोपों की बाबत “दोषी न होने” का निष्कर्ष है तो पीठासीन आफिसर निष्कर्ष पर तारीख डालकर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे हस्ताक्षर से संपूर्ण कार्यवाही अधिप्रमाणित हो जाएगी और जज अटर्नी (यदि कोई है) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर कार्यवाहियां पुष्टि के लिए तुरंत पारेषित कर दी जाएंगी।

103. दोषसिद्धि पर प्रक्रिया.—(1) यदि किसी आरोप की बाबत “दोषी होने” का निष्कर्ष है तो न्यायालय, आरोप के लिए दण्डादेश अवधारित करने में अपने मार्गदर्शन के लिए और दण्डादेश पर विचार करने के लिए पुष्टिकर्ता प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए, दण्डादेश पर विचार विमर्श करने से पूर्व, अभियुक्त के साधारण चरित्र, आय, सेवा, रैंक और शौर्य के किन्हीं मान्यताप्राप्त कार्यों का या उसके विशिष्ट आचरण का और बल न्यायालय दंड न्यायालय द्वारा अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धियों का, यथास्थिति, धारा 56, या धारा 58 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी आफिसर द्वारा उसके बारे में अधिनिर्णित किए गए किन्हीं पूर्व दंडों या, उस अवधि का जिसमें वह किसी पूर्व दंड के कारण गिरफ्तार या परिरुद्ध रहा है, और किसी अलंकरण या इनाम का, जो उसके कब्जे में है या जिसका वह हकदार है, जब कभी संभव हो लेगा और उसे अभिलिखित करेगा।

(2) उपर्युक्त मामलों पर साक्ष्य किसी साक्षी द्वारा ऐसा कथन, जिसमें अभियुक्त की बाबत सेवा पुस्तिका की प्रविष्टियों की संक्षिप्ति होंगी, सत्यापित करके और अभियुक्त की उस संक्षिप्ति में निर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में पहचान करके दिया जा सकेगा।

(3) अभियुक्त किसी ऐसे साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर सकेगा और ऐसे साक्ष्य का खंडन करने के लिए साक्षियों को बुला सकेगा और यदि अभियुक्त ऐसा निवेदन करता है तो सेवा पुस्तिका या उनमें की तात्त्विक प्रविष्टियों की सम्यक्तः प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जाएगी और यदि अभियुक्त यह अभिकथित करता है कि संक्षिप्ति यथास्थिति, सेवा पुस्तिका या ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार नहीं है, तो न्यायालय संक्षिप्ति का मिलान सेवा पुस्तिका या तात्त्विक प्रविष्टियों की प्रतिलिपि से करेगा और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संक्षिप्ति उनके अनुसार नहीं है तो वह संक्षिप्ति को शुद्ध कराएगा या अभियुक्त का आक्षेप अभिलिखित कराएगा।

(4) जब उपर्युक्त मामलों पर सभी साक्ष्य दे दिया गया हो तो अभियुक्त उसके बारे में और दंड कम करने के बारे में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा।

104. दंडादेश.—न्यायालय उन सब अपराधों की बाबत, जिनका अभियुक्त को दोषी पाया जाता है, एक दंडादेश अधिनिर्णित करेगा और ऐसा दंडादेश उनकी बाबत जिनकी बाबत वह वैध रूप से दिया जा सकता है अधिनिर्णीत किया गया समझा जाएगा और जिनकी बाबत वह वैध रूप से नहीं दिया जा सकता है, अधिनिर्णीत किया गया नहीं समझा जाएगा।

105. दया की सिफारिश.—(1) जहां न्यायालय दया की सिफारिश करता है वहां वह अपनी ऐसी सिफारिश के कारण देगा।

(2) इस नियम में उल्लिखित दया या उससे संबंधित किसी अन्य प्रश्न के बारे में सिफारिश करने वाले न्यायालय के सदस्यों की संख्या कार्यवाहियों में की जा सकेगी।

106. दंडादेश सुनाया जाना और कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर और उनका पारेषण.—(1) दया की सिफारिश और ऐसी सिफारिश के कारणों के साथ दण्डादेश खुले न्यायालय में तत्काल सुनाया जाएगा। दण्डादेश पुष्टि किए जाने के अधीन रहते हुए सुनाया जाएगा।

(2) न्यायालय द्वारा दण्डादेश अधिनिर्णीत किए जाने पर पीठासीन आफिसर दण्डादेश पर तारीख डालकर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे हस्ताक्षरों से संपूर्ण कार्यवाही अधिप्रमाणित हो जाएगी और कार्यवाहियां जज अटर्नी (यदि कोई है) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर तुरंत पुष्टि के लिए पारेषित की जाएंगी।

107. पुनरीक्षण.—(1) (क) जहां निष्कर्ष धारा 127 के अधीन पुनरीक्षण के लिए वापस भेजा जाता है, वहां न्यायालय खुले न्यायालय में पुनः समवेत होगा, पुनरीक्षण आदेश पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि न्यायालय को नए सिरे से साक्ष्य लेने का निदेश है तो, ऐसा साक्ष्य खुले न्यायालय में लिया जाएगा,

(ख) जहां ऐसा नया साक्ष्य अभियुक्त की प्रेरणा से अन्यथा अभिलिखित किया जाता है, वहां अभियुक्त को ऐसे नए साक्ष्य में लाए गए विषयों की बाबत साक्ष्य पेश करने के लिए और अवसर दिया जाएगा,

(ग) अभियोजक और अभियुक्त को पेश किए गए नए साक्ष्य की बाबत न्यायालय को संबोधित करने के लिए और अवसर दिया जाएगा,

- (घ) जज अटर्नी भी और उपसंहार कर सकेगा ।
- (2) जहां निष्कर्ष के पुनरीक्षण में नया साक्ष्य का लिया जाना अंतर्वलित नहीं है, वहां अभियुक्त को पुनरीक्षण आदेश में उठाए गए विषय की बाबत न्यायालय को संबोधित करने का अवसर दिया जाएगा ।
- (3) (क) तब न्यायालय अपने निष्कर्ष पर बंद न्यायालय में विचार-विमर्श करेगा और यदि न्यायालय अपने पूर्व निष्कर्ष पर दृढ़ नहीं रहता है तो वह निष्कर्ष और दण्डादेश का प्रतिसंहरण करेगा और नया निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और यदि ऐसे निष्कर्ष में दण्डादेश अंतर्वलित है तो नया दण्डादेश पारित करेगा ।
- (ख) जहां मूल निष्कर्ष "दोषी न होने" का हो, वहां न्यायालय दण्डादेश पारित करने से पूर्व नियम 102 और 103 का अनुपालन करेगा ।
- (4) (क) जहां केवल दण्डादेश ही पुनरीक्षण के लिए वापस भेजा जाता है, वहां पुनरीक्षण आदेश खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया जाएगा और अभियुक्त को पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट विषयों की बाबत न्यायालयों को संबोधित करने का अवसर दिया जाएगा ।
- (ख) तब न्यायालय अपने दण्डादेश पर बंद न्यायालय में पुनः विचार करेगा और यदि वह दण्डादेश पर दृढ़ नहीं रहता है तो दण्डादेश का प्रतिसंहरण करेगा और नया दण्डादेश पारित करेगा ।
- (5) जहां केवल दण्डादेश ही पुनरीक्षण के लिए भेजा जाता है, वहां न्यायालय निष्कर्ष का पुनरीक्षण नहीं करेगा ।

108. पुष्टि और प्रख्यापन.—(1) जब पुष्टिकर्ता प्राधिकारी न्यायालय की कार्यवाहियों का अभिलेख प्राप्त करता है, तब वह उस पर और किसी ऐसे दण्डादेश और आदेश पर जो न्यायालय से परिशिष्ट-8 में दिए गए समुचित प्ररूप में कार्यवाहियों के अभिलेख पर धारा 117 के अधीन किया है, अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और उसके विनिश्चय का ऐसा अभिलेख कार्यवाहियों के अभिलेख का भाग होगा ।

(2) जब न्यायालय ने नियम 80 के अधीन दोषी होने के अभिवचन को स्वीकार कर लिखा है तब पुष्टिकर्ता प्राधिकारी इस बात के होते हुए भी कि न्यायालय ने संयोजक आफिसर की सहमति के बिना अभिवचन स्वीकार किया है, यदि उसकी राय में ऐसा करना न्याय के हित में है तो, उसके निष्कर्ष की पुष्टि कर सकेगा ।

(3) (क) जब न्यायालय ने न्यायालय की अधिकारिता के बारे में अभिवचन या विचारण के वर्जन का अभिवचन नामंजूर कर दिया है या आरोप के बारे में किसी आक्षेप को उलट दिया है तब पुष्टिकर्ता प्राधिकारी के लिए न्यायालय के विनिश्चय का विनिर्दिष्ट रूप से अनुमोदन करना आवश्यक नहीं होगा किंतु अभिवचन या आक्षेप से संबंधित आरोप के निष्कर्ष की उसके द्वारा पुष्टि किए जाने में उसके विनिश्चय का अनुमोदन विवक्षित होगा ।

(ख) जहां वह अभिवचन नामंजूर करने या आक्षेप उलटने के न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन नहीं करता है, वहां वह अभिवचन या आक्षेप से संबंधित आरोप के निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करेगा ।

(4) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी किसी मामले में पुष्टि न करने के कारण कथित कर सकेगा किंतु यदि वह वहां, जहां न्यायालय ने अधिकारिता के बारे में अभिवचन को या विचारण के वर्जन के अभिवचन को नामंजूर कर दिया है, या उसने आरोपों की बाबत किसी आक्षेप को उलट दिया है, इस कारण पुष्टि नहीं करता है कि वह न्यायालय के इस विनिश्चय का अनुमोदन नहीं करता है तो पुष्टिकर्ता प्राधिकारी पुष्टि रोक लेने के कारण को कथित करते हुए उपनियम (1) के अधीन अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा ।

(5) जहां न्यायालय का दण्डादेश अनुचित रूप से अभिव्यक्त किया गया है, वहां पुष्टिकर्ता प्राधिकारी दण्डादेश की पुष्टि करने में उसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकेगा जिससे कि वह उचित रूप से अभिव्यक्त किया जाए ।

(6) जब कभी यह प्रतीत होता है कि नियम 80 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन दोषी होंगे के अभिवचन पर न्यायालय के निष्कर्ष को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है तब ऐसे निष्कर्ष और उसके परिणामस्वरूप विधिपूर्ण दण्डादेश की पुष्टि की जा सकेगी और यदि पुष्टि की जाती है तो, इस बात के होते हुए भी कि इन नियमों से विचलन हुआ है, ऐसा निष्कर्ष या दण्डादेश उस में अधिमान्य होगा, जब ऐसे विचलन से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(7) निष्कर्ष की पुष्टि करते समय पुष्टिकर्ता प्राधिकारी या तो बिना शर्त या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अभियुक्त स्वीकार करता है, दण्डादेश को कम या उसके किसी भाग का परिहार कर सकेगा या दण्ड की धारा 51 में दण्डों के मापमान में निम्नतम दण्ड में लघुकृत कर सकेगा ।

(8) (क) जब पुष्टिकर्ता प्राधिकारी ने न्यायालय के निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि कर दी है या उसकी पुष्टि नहीं की है तब वह, यथास्थिति, निष्कर्ष और दण्डादेश या इस तथ्य को कि पुष्टि नहीं की गई है, अभियुक्त को प्रख्यापित करने के लिए कार्यवाहियों के अभिलेख को अभियुक्त के कमान आफिसर को भेजेगा।

(ख) प्रख्यापन के तथ्य, परिशिष्ट 9 में दिए गए प्ररूप में कार्यवाहियों के अभिलेख में अभिलिखित किए जाएंगे।

(ग) जहां पुष्टि इस कारण नहीं की है कि पुष्टिकर्ता प्राधिकारी अधिकारिता के अभिवचन को या विचारण के वर्जन के अभिवचन को नामंजूर करने या आरोप के प्रति किसी आक्षेप को उलटने के न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन नहीं करता है, वहां अभियुक्त को इसकी सूचना दी जाएगी।

अध्याय 10

बल न्यायालयों की प्रक्रिया और आनुषंगिक विषय

109. सदस्यों का स्थान ग्रहण करना :- न्यायालय के सदस्य अपने रैंक के अनुसार स्थान ग्रहण करेंगे।

110. पीठासीन आफिसर का उत्तरदायित्व :- (1) पीठासीन आफिसर विचारण को उचित ढंग से और अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार और न्यायालय के लिए जो रीति उचित हो उससे संचालित किए जाने के कारण उत्तरदायी है।

(2) पीठासीन आफिसर का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि अभियुक्त का विचारण ऋजुतापूर्वक किया जाता है और यह कि विचारण के अधीन व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति या उसकी अनभिज्ञता या साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने में उसकी अयोग्यता के कारण या अन्यथा उसका कोई अहित नहीं होता है।

111. अभियोजक और अभियुक्त के संबोधन की बाबत न्यायालय की शक्ति :- (1) अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह न्याय प्रशासन में न्यायालय की सहायता करे, पक्षपात रहित व्यवहार करे, संपूर्ण संव्यवहार न्यायालय के समक्ष लाए और अभियुक्त के पक्ष में किसी साक्ष्य का कोई अनुचित फायदा न उठाए या उसे न दबाए।

(2) अभियोजक किसी ऐसे विषय को, जो न्यायालय के समक्ष आरोप या आरोपों से सुसंगत नहीं है, निर्दिष्ट नहीं कर सकेगा और उसे ऐसा करने से रोकना और अभियोजक की ओर से प्रयुक्त भाषा की किसी अनुचित तीक्ष्णता तथा निष्पक्षता या संयतता की कमी को रोकना न्यायालय का कर्तव्य होगा।

(3) न्यायालय अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा करने में युक्तियुक्त सुविधाएं देगा, अभियुक्त को न्यायालय के प्रति अवमानपूर्ण या अनादरपूर्ण टिप्पणियां करने से और अन्य व्यक्तियों के प्रति अशिष्ट और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से प्रवृत्त रहना चाहिए, किंतु वह अपनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए साक्ष्य को अधिक्षिप्त कर सकेगा और अन्य व्यक्तियों पर दोषारोपण कर सकेगा और अपराधिकता का आरोप भी लगा सकेगा किंतु यह वह ऐसा करता है तो वह उसके कारण उपगत दायित्व के अधीन होगा। न्यायालय अभियुक्त को उसकी प्रतिरक्षा की विसंगति के बारे में चेतावनी दे सकेगा, किंतु जब तक कि विशेष मामला न हो उसकी प्रतिरक्षा एक मात्र ऐसी विसंगति के आधार पर नहीं रोकेगा।

112. बंद न्यायालय में अधिविष्ट होना :- (1) न्यायालय, जहां इन नियमों द्वारा ऐसा निर्दिष्ट किया जाए, बंद न्यायालय में अधिविष्ट होगा और अन्य मामले में सदस्यों के बीच विचार विमर्श के संबंध में बंद न्यायालय में अधिविष्ट हो सकेगा।

(2) बंद न्यायालय में न्यायालय के सदस्यों जज अटर्नी (यदि कोई है) और अनुदेशाधीन किसी आफिसर के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं होगा।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, न्यायालय या तो एकांत में जा सकेगा या उस स्थान को जहां वह अधिविष्ट होगा, ऐसे सभी अन्य व्यक्तियों से खाली करा सकेगा जो वहां उपस्थित होने के हकदार नहीं हैं।

(4) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में उल्लिखित के सिवाय सभी कार्यवाहियां, जिनके अंतर्गत किसी स्थान का अवलोकन भी है, खुले न्यायालय में और उपनियम (5) के अधीन रहते हुए, अभियुक्त की उपस्थिति में की जाएगी।

(5) न्यायालय को किसी ऐसे साक्षी को, जिसे अभी साक्ष्य देना है, या अभियुक्त से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को, जो उसकी कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करता है, न्यायालय से अपवर्जित करने की शक्ति होगी।

113. विचारण का जारी रखा जाना और न्यायालय का स्थगन :- (1) जब किसी न्यायालय को समवेत कर दिया जाता है और अभियुक्त पर दोषारोपण कर दिया जाता है, न्यायालय विचारण दिन-प्रति-दिन तब तक जारी रखेगा जब तक कि

न्यायालय को यह प्रतीत नहीं होता है कि न्याय के उद्देश्य के लिए स्थगन आवश्यक है या विचारण का इस प्रकार जारी रखना असाध्य है ।

- (2) (क) न्यायालय अपनी कार्यवाहियों को समय-समय पर स्थगित कर सकेगा और अपनी बैठक किसी ऐसे स्थान पर कर सकेगा जो सुविधाजनक हो, और
- (ख) जहां-जहां आवश्यक हो घटनास्थल का निरीक्षण कर सकेगा ।
- (3) स्थल पर ज्येष्ठ आफिसर भी, सेवा की आवश्यकताओं के कारण न्यायालय का स्थगन कर सकेगा या स्थगन को बढ़ा सकेगा ।
- (4) न्यायालय जज अटर्नी की अनुपस्थिति में (यदि उस न्यायालय के लिए जज अटर्नी नियुक्त किया गया है) कार्यवाही नहीं करेगा और उसे स्थगित कर सकेगा ।
- (5) यदि वह समय विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है जिसके लिए स्थगन किया जाता है तो स्थगन बल प्राधिकारी का आगे आदेश होने तक के लिए होगा, और वह स्थान, जिसके लिए स्थगन किया गया है विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो स्थगन उसी स्थान या ऐसे अन्य स्थान के लिए होगा जो बल प्राधिकारी के अगले आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

114. विचारण का निलंबन.—जहां न्यायालय की बैठक के दौरान उद्भूत किसी बात के परिणामस्वरूप न्यायालय धारा 83 में विनिर्दिष्ट विघटन के कारण या अन्यथा विचारण जारी रखने में असमर्थ है वहां पीठासीन आफिसर या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित ज्येष्ठ सदस्य तत्काल संयोजक प्राधिकारी को तथ्यों की रिपोर्ट देगा ।

115. अभियुक्त की मृत्यु या ऐसी रुग्णता की दशा में कार्यवाहियां.—अभियुक्त की मृत्यु या रुग्णता की दशा में जिसके कारण विचारण जारी रखना असंभव हो जाए न्यायालय साक्ष्य लेकर मृत्यु या रुग्णता का तथ्य अभिनिश्चित करेगा और उसे अभिलिखित करेगा और कार्यवाहियां स्थगित कर देगा और उन्हें संयोजक प्राधिकारी को पारंपरिक करेगा ।

116. पीठासीन आफिसर की मृत्यु निवृत्ति या अनुपस्थिति.—पीठासीन आफिसर की मृत्यु आक्षेप के कारण निवृत्ति या अपरिहार्य अनुपस्थिति की दशा में अगला ज्येष्ठ आफिसर पीठासीन आफिसर का स्थान ग्रहण करेगा और यदि न्यायालय में अभी भी आफिसरों की न्यूनतम संख्या उतने से कम नहीं है जितना विधि के अनुसार होना अपेक्षित है तो विचारण आगे चलेगा ।

117. न्यायालय के सभी सदस्यों का उपस्थित रहना.—(1) न्यायालय के सभी सदस्य अभियुक्त के विचारण के दौरान उपस्थित रहेंगे, न्यायालय का कोई सदस्य, जो अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में साक्ष्य के किसी भाग को ग्रहण किए जाने के दौरान अनुपस्थित रहा है उस व्यक्ति के विचारण में आगे कोई भाग नहीं लेगा, किंतु न्यायालय पर इसका तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि उसकी संख्या न्यूनतम विधिक संख्या से कम नहीं हो जाती ।

(2) किसी अभियुक्त के दोषारोपण के पश्चात् किसी आफिसर को न्यायालय में नहीं जोड़ा जाएगा ।

118. न्यायालय के सदस्यों की राय लेना.—(1) न्यायालय के प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक ऐसे प्रश्न पर, जिसका न्यायालय को विनिश्चय करना है, मौखिक रूप में अपनी राय अवश्य देनी चाहिए और इस बात के होते हुए भी कि उसने दोषमुक्ति के पक्ष में अपनी राय दी है, उसे दण्डादेश के बारे में अपनी राय अवश्य देनी चाहिए ।

(2) न्यायालय के सदस्यों की राय, रैंक में निम्नतम सदस्य से आरंभ करके, क्रमानुसार ली जाएगी ।

119. आनुषंगिक प्रश्नों की बाबत प्रक्रिया.—यदि विचारण के दौरान विधि साक्ष्य या प्रक्रिया के किसी विषय पर अभियोजक द्वारा या अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर से कोई आक्षेप किया जाता है तो यथास्थिति अभियोजक या अभियुक्त या काउंसेल या प्रतिवाद आफिसर का उसका उत्तर देने का अधिकार होगा और आक्षेप करने वाले व्यक्ति को उसका उत्तर देने का अधिकार होगा ।

120. साक्ष्य का कब अनुवाद किया जाएगा.—जब कोई साक्ष्य किसी ऐसी भाषा में दिया जाता है जिसे न्यायालय में समाविष्ट आफिसरों में से कोई आफिसर, अभियुक्त या जज अटर्नी नहीं समझता है, तो उसका उस भाषा में अनुवाद किया जाएगा जिसे वह समझता है ।

121. बल न्यायालय के संव्यवहार की कार्यवाहियों का अभिलेख.—(1) न्यायालय में जज अटर्नी या यदि कोई जज अटर्नी नहीं है तो पीठासीन आफिसर न्यायालय के सभी संव्यवहार अभिलिखित करेगा या कराएगा और अभिलेख की (जिसे इन नियमों में कार्यवाहियां कहा गया है) यथार्थता के लिए उत्तरदायी होगा, और यदि जज अटर्नी को अभियुक्त ने साक्षी के रूप में बुलाया है तो पीठासीन आफिसर जज अटर्नी के साक्ष्य की कार्यवाहियों के अभिलेख की यथार्थता के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) साक्ष्य, यथासंभव निकटतम रूप से प्रयुक्त शब्दों में वृत्तांत रूप में लिखा जाएगा किंतु किसी ऐसे मामले में जहां अभियोजक अभियुक्त जज अटर्नी या न्यायालय उसे तात्त्विक समझता है वहां प्रश्न और उत्तर शब्दशः लिखे जाएंगे।

(3) जहां किसी प्रश्न पर या किसी साक्ष्य को ग्रहण किए जाने पर या न्यायालय की प्रक्रिया पर आक्षेप किया जाता है, वहां ऐसा आक्षेप, यदि अभियोजक या अभियुक्त ऐसा निवेदन करता है या न्यायालय उचित समझता है तो, आक्षेप के आधारों और उन पर न्यायालय के विनिश्चयों के साथ कार्यवाहियों में दर्ज किया जाएगा।

(4) जहां अभियोजक या अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर से किया गया कोई संबोधन लिखित रूप में नहीं है, वहां उसे आगे, या न्यायालय जैसा उचित समझता है उससे अन्यथा, कार्यवाहियों में अभिलिखित करना आवश्यक नहीं होगा, सिवाय इसके कि :-

(क) न्यायालय प्रत्येक मामले में अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिरक्षा का ऐसा अभिलेख तैयार करेगा जो पुष्टिकर्ता आफिसर को अभियुक्त द्वारा, या उसकी ओर से, उसके विरुद्ध प्रत्येक आरोप की बाबत दिए गए उत्तर का निर्णय करने में समर्थ बना सके, और

(ख) न्यायालय अभियोजक या अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर से किए गए संबोधन में से किन्हीं ऐसे विशिष्ट विषयों को भी अभिलिखित करेगा, जिनकी, यथास्थिति, अभियोजक या अभियुक्त अपेक्षा करे।

(5) न्यायालय कोई टीका-टिप्पणी या ऐसी कोई बात जो न्यायालय के समक्ष नहीं है या किसी ऐसे तथ्य की कोई रिपोर्ट जो विचारण का भाग नहीं है, कार्यवाहियों में दर्ज नहीं करेगा, किंतु यदि कोई ऐसी टीका-टिप्पणी या रिपोर्ट न्यायालय को आवश्यक प्रतीत होती है तो न्यायालय उसे पीठासीन आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित पृथक दस्तावेज के रूप में समुचित प्राधिकारी को भेज सकेगा।

122. कार्यवाहियों की अभिरक्षा और निरीक्षण:—कार्यवाहियां जज अटर्नी की (यदि कोई हो), या यदि कोई जज अटर्नी नहीं है, तो पीठासीन आफिसर की अभिरक्षा में समझी जाएगी, किंतु उनकी सुरक्षा के लिए उचित पूर्वविधानी बरतते हुए, न्यायालय के सदस्य, अभियोजक या अभियुक्त, निष्कर्ष पर विचार करने के लिए न्यायालय के बंद होने से पूर्व किसी भी उचित समय पर निरीक्षण कर सकेंगे।

123. जनरल/पेटी बल न्यायालय की कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन:—जनरल बल न्यायालय और पेटी बल न्यायालय की कार्यवाहियों को उस व्यक्ति द्वारा जिसकी अभिरक्षा में वे कार्यवाहियां हैं जज अटर्नी जनरल को पुनर्विलोकन के लिए भेजा जाएगा, जो तदुपरि उन्हें पुष्टिकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा।

124. प्रतिवाद आफिसर, अभियुक्त का मित्र और काउंसेल:—(1) किसी जनरल या पेटी बल न्यायालय में अभियुक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी काउंसेल द्वारा या अधिनियम के अधीन रहते हुए किसी आफिसर द्वारा, जिसे "प्रतिवाद आफिसर" कहा जाएगा, किया जा सकेगा या उसकी सहायता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जिसकी सेवाएं समाप्त करने में वह समर्थ हो सके और उसे "अभियुक्त का मित्र" कहा जाएगा।

(2) प्रतिवाद आफिसर के वही अधिकार और कर्तव्य होंगे जो इन नियमों के अधीन काउंसेल के हैं और वह समान बाध्यताओं के अधीन होगा।

(3) अभियुक्त का मित्र अभियुक्त को सभी विषय-बिंदुओं पर सलाह दे सकेगा और साक्षियों से किए जाने वाले प्रश्न सुझा सकेगा, किंतु वह साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा नहीं करेगा, न ही न्यायालय को संबोधित करेगा।

125. काउंसेल की हाजिरी के लिए अपेक्षा:—(1) किसी काउंसेल द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का आशय रखने वाला अभियुक्त अपने कमान आफिसर या संयोजक आफिसर को ऐसा आशय की यथासाध्य शीघ्र सूचना देगा यदि पर्याप्त सूचना नहीं दी गई है और यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह अभियोजक के आवेदन पर, विचारण में अभियोजक की ओर से कोई काउंसेल अभिप्राप्त करने में उसे समर्थ बनाने के लिए स्थगित कर सकेगा।

(2) जहां संयोजक आफिसर ऐसा निदेश दे वहां काउंसेल अभियोजक के साथ हाजिर हो सकेगा, किंतु उस दशा में, जब तक कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना अभियुक्त द्वारा न दे दी गई हो काउंसेल के हाजिर होने के निदेश की सूचना अभियुक्त को, ऐसे समय पर दी जाएगी किंतु किसी भी दशा में सूचना विचारण से पूर्व सात दिन से कम नहीं होगी, जिससे कि न्यायालय की राय में, अभियुक्त विचारण में सहायता प्राप्त करने के लिए काउंसेल अभिप्राप्त करने में समर्थ हो सके।

(3) काउंसेल को जो अभियोजक या अभियुक्त की ओर से न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है, साक्षियों को बुलाने, उनकी मौखिक परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा करने, कोई अभिवाक् करने और कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के वही अधिकार होंगे जो उस अभियोजक या अभियुक्त को प्राप्त है, जिसके लिए वह हाजिर होता है और उस व्यक्ति के स्थान पर,

जिसकी ओर से वह हाजिर होता है, विचारण के अनुक्रम में अन्यथा कार्य करने का उसे अधिकार होगा। वह इन नियमों का पालन उसी प्रकार करेगा मानो वह स्वयं वह व्यक्ति हो और ऐसी दशा में उस व्यक्ति को स्वयं पूर्वोक्त कार्यों में से कोई कार्य करने का अधिकार नहीं होगा, सिवाय नियम 96 के उपनियम (2) और नियम 103 के उपनियम (4) द्वारा अनुज्ञात कथन के संबंध में या न्यायालय उसके सिवाय जहां तक उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात करे।

(4) जब काउंसिल अभियोजक की ओर से हाजिर होता है, तो अभियोजक की, उसे साक्षी के रूप में बुलाया जाए, किसी अन्य साक्षी की भांति परीक्षा की जा सकेगी।

126. जज अटर्नी की निरर्हता:—ऐसा आफिसर, जो न्यायालय में आसीन होने के लिए निरर्हित है, उस न्यायालय में जज अटर्नी के रूप में कार्य करने के लिए निरर्हित होगा।

127. जज अटर्नी की मृत्यु, रुग्णता या अनुपस्थित होने पर प्रतिस्थापन:—जज अटर्नी की मृत्यु हो जाने पर या रुग्णता की दशा में या किसी अन्य कारण से जिससे जज अटर्नी हाजिर होने में असमर्थ है, उस दशा में न्यायालय स्थगित हो जाएगा और पीठासीन आफिसर तदनुसार संयोजक आफिसर को रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट की प्राप्ति पर, संयोजक आफिसर अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा जिसे शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा और वह यथास्थिति शेष विचारण के लिए या तब तक के लिए जब तक कि जज अटर्नी वापस नहीं आ जाता है, जज अटर्नी के रूप में कार्य करेगा।

128. जज अटर्नी की शक्तियां और कर्तव्य:—जहां किसी जज अटर्नी को न्यायालय में कार्य करने के लिए नामित किया गया है, वहां वह —

(क) जब कभी न्यायालय, अभियोजक, या अभियुक्त द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, आरोप या विचारण से संबंधित विधि के प्रश्न पर अपनी राय देगा।

(ख) कार्यवाहियों में किसी अनियमितता या अन्य शैथिल्यता के बारे में न्यायालय को सूचित करेगा।

(ग) आरोप में या न्यायालय के गठन में किसी शैथिल्यता या त्रुटि के बारे में संयोजक आफिसर और न्यायालय को सूचित करेगा।

(घ) साक्ष्य का उपसंहार करेगा और न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष पर विचार-विमर्श करने से पूर्व विधि के किसी प्रश्न पर अपनी राय देगा।

(2) जज अटर्नी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अभियुक्त की उस रूप में उसकी स्थिति के परिणामस्वरूप, या साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने में उसकी अनभिज्ञता या उसकी असमर्थता के कारण उसका कोई अहित न हो और इस प्रयोजन के लिए जज अटर्नी, न्यायालय की अनुज्ञा से, साक्षी बुला सकेगा और उनसे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो उसे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों।

(3) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, जज अटर्नी पूर्णतः निष्पक्षता का रुख रखेगा।

(4) जहां जज अटर्नी द्वारा न्यायालय को उसके समक्ष किसी विषय पर कोई राय दी गई है, वहां यदि जज अटर्नी या न्यायालय उसे दर्ज करना चाहे, कार्यवाहियों में दर्ज किया जा सकेगा।

(5) जज अटर्नी बल न्यायालय में जज अटर्नी जनरल का प्रतिनिधित्व करेगा।

129. उन्मत्तता का निष्कर्ष:—जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त चित्त-विकृति के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है या उसने अभिकथित कार्य तो किया है, किंतु चित्त-विकृति के कारण कार्यवाही प्रकृति को या यह समझने में असमर्थ था कि वह कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल था, वहां पीठासीन आफिसर या समरी बल न्यायालय की दशा में, विचारण करने वाला आफिसर निष्कर्ष पर अपने हस्ताक्षर करेगा और तारीख डालेगा तथा उस पर जज अटर्नी भी (यदि कोई है) हस्ताक्षर करेगा और तब कार्यवाही तुरंत पुष्टिकर्ता प्राधिकारी को या समरी बल न्यायालय की दशा में, उस पर प्रति हस्ताक्षर करने के लिए सशक्त उपमहानिरीक्षक, या अपर उपमहानिरीक्षक को भेजी जाएगी।

130. कार्यवाहियों का परिरक्षण:—प्रत्येक न्यायालय की कार्यवाहियां प्रख्यापन के पश्चात् जज अटर्नी जनरल के कार्यालय को भेजी जाएंगी और वे वहां तीन वर्ष से अन्यून तक या तब तक जब तक कि न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दण्ड का अवसान नहीं हो जाता है, इनमें से जो पश्चातवर्ती हो, परिरक्षित रखी जाएंगी।

131. विचारण किए गए व्यक्ति का कार्यवाहियों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार:—बल न्यायालय द्वारा विचारण किया गया प्रत्येक व्यक्ति निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि, जहां ऐसी पुष्टि अपेक्षित हो, की जाने के पश्चात् और कार्यवाहियों को नष्ट किए जाने से पूर्व किसी समय उसकी एक प्रति, जिसके अंतर्गत पुनरीक्षण यदि कोई है, की कार्यवाहियां भी हैं, मांग करने पर, जज अटर्नी जनरल से प्राप्त करने का हकदार होगा।

132. कतिपय दशाओं में कार्यवाहियों की प्रति न दिया जाना :—नियम, 131 में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार का, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि उक्त नियम के अधीन, कार्यवाहियों या उनके किसी भाग की प्रति देना राज्य की सुरक्षा के हितों या विदेशी राज्यों के साथ मैत्री-पूर्ण संबंधों के विरुद्ध है, उसे ऐसी प्रति नहीं दी जाएगी :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रति की मांग करने वाला व्यक्ति निष्कर्ष या दण्डादेश के संबंध में अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अर्जी प्रस्तुत करने या किसी न्यायालय में कोई कार्यवाई संस्थित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे व्यक्ति या उसके विधि सलाहकार को, यदि कोई हो, निम्नलिखित शर्तों पर, कार्यवाहियों का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा, अर्थात्:—

(क) निरीक्षण ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी निर्दिष्ट करें, और

(ख) कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात व्यक्ति ऐसा निरीक्षण करने से पूर्व :—

(i) लिखित रूप में यह वचनबंध पेश करेगा कि वह कार्यवाहियों या उनके किसी भाग की प्रतियां नहीं बनाएगा और ऐसी कार्यवाहियों में अंतर्विष्ट जानकारी या दस्तावेजों का, उक्त निष्कर्ष या दंडादेश के संबंध में अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अर्जी प्रस्तुत करने या न्यायालय में कार्यवाई संस्थित करने के प्रयोजन से भिन्न किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं करेगा ; और

(ii) एक प्रमाणपत्र पेश करेगा कि वह इस बात से अवगत है कि यदि वह उक्त कार्यवाहियों में अंतर्विष्ट दस्तावेजों या जानकारी के संबंध में भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 3 और धारा 5 में विनिर्दिष्ट कोई कार्य करता है, तो वह उक्त धाराओं के अधीन अभियोजन के लिए आपको भागी बनाएगा ।

133. कार्यवाहियों के अभिलेख का खो जाना:—(1) यदि, पुष्टि के पूर्व न्यायालय की उन मूल कार्यवाहियों का, जिसकी पुष्टि अपेक्षित है, अभिलेख या उनका कोई भाग खो जाता है, तो न्यायालय के पीठासीन आफिसर या जज अटर्नी द्वारा प्रमाणित उसकी प्रति, यदि कोई है, मूल के स्थान पर स्वीकार की जा सकेगी ।

(2) यदि कोई ऐसी प्रति नहीं है और आरोप, निष्कर्ष दण्डादेश और न्यायालय के संव्यवहारों का पर्याप्त साक्ष्य उपाप्त किया जा सकता है, तो वह साक्ष्य अभियुक्त की सहमति से मूल कार्यवाहियों के अभिलेख या उस भाग के, जो खो गया है, स्थान पर ग्रहण किया जा सकेगा ।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) में वर्णित किसी दशा में निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि की जा सकेगी, और वह वैसे ही विधिमान्य होगा, मानो मूल कार्यवाहियां या उनका भाग खोया ही नहीं था ।

(4) यदि अभियुक्त उपनियम (2) में निर्दिष्ट सहमति से इंकार करता है, तो उसका पुनः विचारण किया जा सकेगा, और पूर्व न्यायालय का जिसकी कार्यवाहियां खो गई हैं, निष्कर्ष और दण्डादेश शून्य होगा ।

(5) यदि, पुष्टि के पश्चात् या किसी ऐसे मामले में, जहां पुष्टि अपेक्षित नहीं है, मूल कार्यवाहियां या उनका कोई भाग खो जाता है तथा आरोप, निष्कर्ष, दण्डादेश और न्यायालय के संव्यवहारों तथा निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि का (यदि अपेक्षित हो) पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है, तो वह साक्ष्य सभी प्रयोजनों के लिए विचारण का विधिमान्य और पर्याप्त अभिलेख होगा ।

134. साक्षियों और अन्य द्वारा अपराध:—जब किसी न्यायालय की राय है कि धारा 40 और 41 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध की, जो उसके समक्ष किया गया है या उसकी कार्यवाहियों के दौरान उसकी जानकारी में लाया गया है, जो, यदि अधिनियम के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता तो, ऐसा अपराध गठित हुआ हो तो जांच करने के लिए आधार है, तो ऐसा न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही कर सकेगा अर्थात् —

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसने अपराध किया है, अधिनियम के अधीन है, न्यायालय उसके आचरण की सूचना उसे कमान आफिसर को दे सकेगा ।

(ख) यदि वह व्यक्ति, जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसने वह कार्य किया है, किसी सशस्त्र बल विधि से संबंधित है, तो न्यायालय उसके आचरण के बारे में बल प्राधिकारी की जानकारी में ला सकेगा ।

(ग) अन्य मामलों, यथास्थिति वह आफिसर, जिसने साक्षी को हाजिर होने के लिए समन किया है, या पीठासीन आफिसर या न्यायालय का पद धारण करने वाला आफिसर अधिकारिता रखने वाले निकटतम प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को लिखित परिवाद भेज सकेगा और उन कार्यों के मामले में, जो यदि अधिनियम के अधीन रहते हुए व्यक्ति द्वारा किए गए होते तो धारा

40 के खंड (ड.) या धारा 41 के अधीन अपराध गठित हुए होते, न्यायालय ऐसी प्रारम्भिक जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, मामले की अधिकारिता रखने वाले निकटतम प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 340 के अनुसार जांच या विचारण के लिए भेज सकेगा।

अध्याय 11

समरी बल न्यायालय

135. कार्यवाहियां:—(1) विचारण करने वाला आफिसर (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में न्यायालय कहा गया है) प्रत्येक समरी न्यायालय के संव्यवहार अभिलिखित करेगा या कराएगा।

(2) न्यायालय, न्यायालय की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने के लिए आशुलिपिक की नियुक्ति कर सकेगा। ऐसे आशुलिपिक को नियम 71 में दिए गए प्ररूप के अनुसार सम्यक् रूप से शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा।

136. साक्ष्य का कब अनुवाद किया जाएगा:—(1) जब कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाता है जिसे न्यायालय या अभियुक्त नहीं समझता है तो उस साक्ष्य का अनुवाद यथास्थिति न्यायालय या अभियुक्त के लिए ऐसी भाषा में किया जाएगा जिसे वह न्यायालय या अभियुक्त समझता है।

(2) न्यायालय इस प्रयोजन के लिए या तो एक दुभाषिया नियुक्त करेगा या स्वयं समरी बल न्यायालय में दुभाषिए के लिए विहित शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

(3) जब दस्तावेज औपचारिक सबूत के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं तब उसके उतने भाग का जितना आवश्यक प्रतीत हो निर्वचन कराना न्यायालय के विवेक पर होगा।

137. समवेत होना:—जब न्यायालय दुभाषिया (यदि कोई है) और विचारण में हाजिर होने वाले आफिसर और अधीनस्थ आफिसर समवेत हो जाते हैं तब अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और उसमें उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा नियम 138 में विहित शपथ ली जाएगी या प्रतिज्ञान किया जाएगा।

138. न्यायालय और दुभाषिए द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान:—न्यायालय निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में या समान तात्पर्य के ऐसे अन्य प्ररूप में जो न्यायालय का गठन करने वाले आफिसर के धर्म के अनुसार या अन्यथा अंतःकरण पर आबद्धकर हो, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

शपथ का प्रारूप

“मैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं पक्षपात अनुग्रह या स्नेह के बिना सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से न्याय करूंगा।

प्रतिज्ञान का प्रारूप

“मैं, सत्यनिष्ठा, शुद्ध हृदय से और सच्चाई से घोषणा करता हूँ कि मैं पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से न्याय करूंगा।

(2) न्यायालय या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अन्य व्यक्ति दुभाषिए को (यदि कोई है) निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में या समान तात्पर्य के ऐसे अन्य प्ररूप में जो न्यायालय उस व्यक्ति के जिसे दुभाषिये के रूप में कार्य करना है, धर्म के अनुसार या अन्यथा उसके अंतःकरण पर आबद्धकर अभिनिश्चित करे शपथ दिलाएगा या प्रतिज्ञान कराएगा।

शपथ का प्रारूप

“मैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं इस न्यायालय के समक्ष विषय के संबंध में मुझसे अपेक्षा किए जाने पर निष्ठापूर्वक भाषांतर और अनुवाद करूंगा।

प्रतिज्ञान का प्रारूप

“मैं, सत्यनिष्ठा, शुद्ध हृदय से और सच्चाई से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं इस न्यायालय के समक्ष विषय के संबंध में मुझ से अपेक्षा किए जाने पर निष्ठापूर्वक भाषांतर और अनुवाद करूंगा।”

(3) शपथ दिलाने और प्रतिज्ञान कराने के पश्चात् साक्षी न्यायालय से बाहर चले जाएंगे।

139. अनेक अभियुक्तों के विचारण के लिए न्यायालय को शपथ दिलाना :—(1) समरी बल न्यायालय को एक ही समय पर उसके समक्ष उस समय उपस्थित कितने ही अभियुक्तों के विचारण के लिए शपथ दिलाई जा सकेगी या प्रतिज्ञान कराया जा सकेगा चाहे उन अभियुक्तों का संयुक्त या पृथकतः विचारण किया जाना हो।

(2) पृथक-पृथक विचारण किए जाने वाले कई अभियुक्त व्यक्तियों की दशा में न्यायालय शपथ दिलाए जाने या प्रतिज्ञान कराए जाने पर अन्य मामलों को मुलतवी करते हुए एक मामले में कार्यवाही करेगा और तत्पश्चात् क्रमानुसार अन्य मामलों को लेगा।

(3) जहां एक ही संव्यवहार से उत्पन्न होने वाले आरोपों पर कई अभियुक्तों का पृथक-पृथक विचारण किया जाता है, वहां यदि न्यायालय यह समझता है कि यह न्याय के हित में वांछनीय है तो वह ऐसे अभियुक्तों में से किसी एक या अधिक को अधिनिर्णीत किए जाने वाले किसी दंडादेश पर विचार तब तक के लिए मुलतवी कर सकेगा जब तक ऐसे सभी अभियुक्तों के विचारण पूरे नहीं हो जाते हैं।

140. अभियुक्त को दोषारोपित किया जाना :- (1) न्यायालय और दुभाषिए को (यदि कोई है) ऊपर वर्णित शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के पश्चात् अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपों से दोषारोपित किया जाएगा।

(2) वे आरोप जिनसे अभियुक्त को दोषारोपित किया गया है, उसे पढ़कर सुनाये जाएंगे और यदि आवश्यक हो तो उसे उनका अनुवाद करके सुनाया जाएगा तथा उन्हें स्पष्ट किया जाएगा और उससे प्रत्येक आरोप पर पृथक रूप से अभिवचन करने की अपेक्षा की जाएगी।

141. आरोप के बारे में अभियुक्त द्वारा आक्षेप :- अभियुक्त, जब किसी आरोप पर अभिवचन करने की अपेक्षा की जाए तब, इस आधार पर आरोप के प्रति आक्षेप कर सकेगा कि उससे अधिनियम के अधीन कोई अपराध प्रकट नहीं होता है या वह इन नियमों के अनुसार नहीं है।

142. आरोप का संशोधन :- (1) यदि विचारण के दौरान किसी भी समय न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि आरोप पत्र में अभियुक्त के नाम या वर्णन में भूल है तो वह उस भूल को शुद्ध करने के लिए आरोप पत्र का संशोधन कर सकेगा।

(2) यदि किसी आरोप के विचारण में न्यायालय को साक्षियों की परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व किसी समय यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में आरोप में कोई परिवर्धन उसमें से कोई लोप या उसमें कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो वह ऐसे आरोप का संशोधन कर सकेगा और अभियुक्त को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् और यदि संशोधित आरोप के लिए ऐसी मंजूरी अपेक्षित है तो अभियुक्त के विचारण के लिए पैटी बल न्यायालय का संयोजन करने के लिए सशक्त आफिसर की मंजूरी से ऐसे संशोधित आरोप पर विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

143. विशेष अभिवचन :- यदि अभियुक्त ने न्यायालय की साधारण अधिकारिता के बारे में विशेष अभिवचन या विचारण के वर्जन के बारे में अभिवचन किया है तो ऐसे अभिवचनों को निपटाने के लिए अध्याय 9 में अधिकथित प्रक्रिया का जहां तक वह लागू हो अनुसरण किया जाएगा।

144. “दोषी होने” या “दोषी न होने” का साधारण अभिवचन :- (1) अभियुक्त का “दोषी होने” या “दोषी न होने” का (अभिवचन या यदि वह अभिवचन करने से इनकार करता है या किसी आरोप पर बोधगम्य रूप से अभिवचन नहीं करता है तो “दोषी न होने” का अभिवचन) प्रत्येक आरोप की बाबत अभिलिखित किया जाएगा।

(2) यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति “दोषी होने” का अभिवचन करता है तो वह अभिवचन न्यायालय के निष्कर्ष के रूप में अभिलिखित किया जाए किंतु उसे अभिलिखित किए जाने से पूर्व न्यायालय यह अभिनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस आरोप की प्रकृति को समझता है जिसके बारे में उसने दोषी होने का अभिवचन किया है और उसे उस अभिवचन का साधारण प्रभाव और विशिष्टतया उस आरोप का अर्थ जिसके लिए उसने दोषी होने का अभिवचन किया है और प्रक्रिया का वह अंतर जो दोषी होने के अभिवचन के कारण होगा सूचित करेगा और यदि अभिलेख या साक्ष्य के सार से (यदि कोई है) या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को दोषी न होने का अभिवचन करना चाहिए या तो उसे अभिवचन को वापिस लेने की सलाह देगा।

(3) जहां अभियुक्त अनुकल्पतः लगाये गए दो या अधिक आरोपों में से प्रथम के लिए दोषी होने का अभिवचन करता है वहां न्यायालय उपनियम (2) का अनुपालन किए जाने के पश्चात् और अभियुक्त को अनुकल्पी आरोप या आरोपों पर दोषारोपित किए जाने के पूर्व ऐसा/ऐसे अनुकल्पी आरोप वापस ले लेगा और उस आरोप का जिसके लिए उस अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन किया है अभियुक्त से उसका अभिवचन करने की अपेक्षा किए बिना अनुसरण करेगा और न्यायालय की कार्यवाहियों में उस आशय का अभिलेख किया जाएगा।

145. “दोषी होने” के अभिवचन के पश्चात् प्रक्रिया :- (1) “दोषी होने” का अभिवचन अभिलिखित किए जाने पर यदि उसी आरोप-पत्र में अन्य आरोप है जिनका अभिवचन “दोषी न होने” का है तो प्रथमतः विचारण कार्यवाही उन अन्य आरोपों के संबंध में होगी और उन आरोपों पर निष्कर्ष के पश्चात् उन आरोपों पर कार्यवाही होगी जिनकी बाबत “दोषी होने” का अभिवचन दर्ज किया गया है किंतु यदि अनुकल्पी आरोप है तो न्यायालय या तो सभी आरोपों के बारे में ऐसे कार्यवाही करेगा मानो अभियुक्त ने किसी भी आरोप की बाबत “दोषी होने” का अभिवचन नहीं किया है या उसका विचारण करने की बजाए

उन अनुकल्पी आरोपों में से किसी एक पर जिसकी बाबत उसने "दोषी होने" का अभिवचन किया है "दोषी होने" का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा और ऐसे अन्य सभी अनुकल्पी आरोपों की बाबत जो ऐसे आरोप से पहले आते हैं "दोषी न होने" का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा ।

(2) (क) किसी आरोप की बाबत "दोषी होने" का अभिवचन अभिलिखित करने के पश्चात् (यदि किन्हीं अन्य आरोपों पर विचार कार्यवाही नहीं होती है तो) न्यायालय अभिलेख या साक्ष्य का सार पढ़ कर सुनायेगा और उसे कार्यवाहियों में संलग्न करेगा अथवा यदि कोई ऐसा अभिलेख या सार नहीं है तो पर्याप्त साक्ष्य लेगा और अभिलिखित करेगा जिससे कि वह दंडादेश अवधारित करने में समर्थ हो सके और पुनर्विलोकन करने में समर्थ हो सके और पुनर्विलोकन आफिसर की अपराध से संबंधित सभी परिस्थितियों की जानकारी हो सके ।

(ख) साक्ष्य उसी रीति से लिया जाएगा जो इन नियमों द्वारा "दोषी न होने" के अभिवचन की दशा में निर्दिष्ट किया गया है ।

(3) अभियुक्त यथास्थिति ऐसा साक्ष्य लिए जाने का अभिलेख या साक्ष्य का सार पढ़कर सुनाए जाने के पश्चात् आरोप के बारे में और दंड कम करने के बारे में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अपने चरित्र के बारे में साक्षी बुला सकेगा ।

(4) (क) यदि अभियुक्त के कथन से, या साक्ष्य के अभिलेख से या अन्यथा न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त "दोषी होने" के अपने अभिवचन का प्रभाव नहीं समझता है तो न्यायालय अभिलेख में परिवर्तन करेगा और "दोषी न होने" का अभिवचन दर्ज करेगा और तदनुसार विचारण अग्रसर करेगा ।

(ख) उपनियम (1) के अधीन वापस लिए गए किन्हीं अनुकल्पी आरोपों को आरोप-पत्र में पुनः स्थापित किया जाएगा और विचारण इस प्रकार किया जाएगा मानो वे कभी वापस नहीं लिए गए थे ।

(5) यदि उसी आरोप-पत्र के कुछ आरोपों की बाबत "दोषी होने" का अभिवचन अभिलिखित किया गया है और अन्य आरोपों की बाबत विचारण की कार्यवाही की जाती है, तो उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन कार्यवाहियां उसी आरोप-पत्र के अन्य आरोपों की बाबत निष्कर्ष अभिलिखित किए जाने के पश्चात् की जाएगी ।

(6) जब अभियुक्त दंड को कम करने के संबंध में किसी बात का कथन करता है, जिसका न्यायालय की राय में साबित किया जाना अपेक्षित है, और यदि उसके साबित कर देने से दंड की मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा, तो न्यायालय अभियुक्त को उसे साबित करने के लिए साक्षी बुलाने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

146. "दोषी न होने" का अभिवचन वापस लिया जाना :- यदि अभियुक्त विचारण के दौरान किसी भी समय उचित समझता है तो वह "दोषी न होने" के अपने अभिवचन को वापस ले सकेगा तथा "दोषी होने" का अभिवचन कर सकेगा और ऐसी दशा में न्यायालय तुरंत, नियम 144 के उपनियम (2) के अनुपालन के अधीन रहते हुए "दोषी होने" का अभिवचन और निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और जहां तक आवश्यक हो, नियम 145 में विनिर्दिष्ट रीति से कार्यवाही करेगा ।

147. "दोषी न होने" के अभिवचन के पश्चात् प्रक्रिया :- (1) किसी आरोप के संबंध में "दोषी न होने" का अभिवचन अभिलिखित किए जाने के पश्चात् अभियोजन के लिए साक्ष्य लिया जाएगा ।

(2) अभियोजन के लिए साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्त से पूछा जाएगा कि क्या उसे अपनी प्रतिरक्षा में कुछ कहना है या वह, अपने साक्षी बुलाए जाने तक के लिए ऐसा संबोधन आस्थगित कर सकेगा ।

(3) तब अभियुक्त अपने साक्षी जिनके अंतर्गत चरित्र के बारे में साक्षी भी है, बुला सकेगा ।

148. प्रतिरक्षा के उत्तर में साक्षी :- यदि न्यायालय, न्याय के हित में आवश्यक समझता है तो वह प्रतिरक्षा के उत्तर में साक्षी बुला सकेगा ।

149. साक्षियों का साक्ष्य :- नियम 91, नियम 92 और नियम 93 के उपबंध जहां तक हो सके समरी बल न्यायालय में साक्षियों के साक्ष्य को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे साधारण बल न्यायालय या पैटी बल न्यायालय में साक्षियों के साक्ष्य को लागू होते हैं ।

150. निष्कर्ष का अभिलेखन और घोषणा :- (1) न्यायालय, अभियोजन और प्रतिरक्षा की ओर से साक्ष्य सुने जाने के पश्चात् अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

(2) ऐसे प्रत्येक आरोप की बाबत जिससे अभियुक्त को दोषारोपित किया गया है निष्कर्ष अभिलिखित किया जाएगा और इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, "दोषी होने" या "दोषी न होने" के निष्कर्ष के रूप में ही अभिलिखित किया जाएगा ।

(3) जहां किसी आरोप की बाबत न्यायालय की राय है कि साबित किए गए तथ्यों से आरोपित अपराध या ऐसा कोई अपराध जिसके संबंध में वह लगाए गए आरोप के बाबत अधिनियम के अधीन विधिक रूप से दोषी पाया जाए प्रकट नहीं होता है, वहां न्यायालय यह निष्कर्ष निकालेगा कि अभियुक्त उस आरोप का "दोषी नहीं" है।

(4) किसी आरोप के संबंध में जहां न्यायालय की राय है कि साक्ष्य में साबित किए जाने के लिए पाए गए तथ्य आरोप में विशिष्टियों के कथन में अभिकथित तथ्यों से तात्त्विक रूप से भिन्न हैं, किंतु फिर भी आरोप में कथित अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त हैं, और भिन्नता ऐसी तात्त्विक नहीं है कि उससे अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े वहां न्यायालय "दोषी न होने" के निष्कर्ष के स्थान पर विशेष निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा।

(5) जहां अनुकल्पिक आरोप हैं और साबित किए गए तथ्य न्यायालय को ऐसे प्रतीत होते हैं कि उन अनुकल्पिक आरोपों में से किसी में वर्णित आरोप गठित नहीं होता है वहां न्यायालय उस आरोप पर "दोषी न होने" का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(6) विशेष निष्कर्ष में अभियुक्त को किसी आरोप की बाबत उसमें विनिर्दिष्ट अपवादों या भिन्नताओं के कथन के अधीन रहते हुए दोषी ठहराया जा सकेगा।

(7) न्यायालय अभियुक्त को आनुकल्पिक रूप से लगाए गए दो या अधिक आरोपों में से एक से अधिक की बाबत दोषी नहीं ठहराएगा यद्यपि एक आरोप पर दोषसिद्धि के अनिवार्य रूप से अनुकल्पिक आरोप या आरोपों की बाबत दोषी होने का संकेत मिलता हो।

151. दोषमुक्ति के संबंध में प्रक्रिया :- जहां आरोप-पत्र के आरोपों में से प्रत्येक की बाबत "दोषी न होने" का निष्कर्ष है वहां न्यायालय कार्यवाही पर हस्ताक्षर करेगा और तारीख डालेगा। निष्कर्ष खुले न्यायालय में घोषित किया जाएगा और यदि अभियुक्त इन आरोपों की बाबत गिरफ्तार है तो उसे निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

152. "दोषी होने" के निष्कर्ष के संबंध में प्रक्रिया :- (1) जहां किसी आरोप की बाबत "दोषी होने" का निष्कर्ष है वहां न्यायालय अभियुक्त के साधारण चरित्र आयु, सेवा रैंक और वीरता के मान्यताप्राप्त कार्यों या उसके विशिष्ट आचरण को और बल न्यायालय या दंड न्यायालय द्वारा अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धियों को, धारा 56 के अधीन अधिकार का प्रयोग करने वाले किसी आफिसर द्वारा उसको अधिनिर्णीत किए गए किसी पूर्व दंड को, उस अवधि को, जिसमें वह किसी पूर्व दंड के संबंध में गिरफ्तार या परिरुद्ध रहा है, और किसी अलंकरण या इनाम को, जो उसके कब्जे में है या जिसका वह हकदार है, अपनी स्वयं की जानकारी के आधार पर अभिलिखित करेगा या किसी अभिलेख से साक्ष्य लेगा।

(2) जहां न्यायालय अपनी जानकारी के आधार पर इस नियम में वर्णित बातें अभिलिखित नहीं करता है वहां इन विषयों पर साक्ष्य उसी प्रकार के साक्ष्य के लिए नियम 103 में निर्दिष्ट रीति से लिया जा सकेगा।

153. दंडादेश :- न्यायालय उन सभी अपराधों की बाबत, जिनके लिए अभियुक्त को दोषी पाया गया है, एक दंडादेश अधिनिर्णीत करेगा।

154. कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करना :- न्यायालय, दंडादेश पर हस्ताक्षर करके तारीख डालेगा और ऐसे हस्ताक्षर से संपूर्ण कार्यवाही अधिप्रमाणित हो जाएगी।

155. भिन्न-भिन्न आरोप-पत्रों में आरोप :- (1) जब समरी बल न्यायालय द्वारा विचारण में आरोप भिन्न-भिन्न आरोप-पत्रों में अंतर्विष्ट है, तब अभियुक्त का विचारण, निष्कर्ष के प्रक्रमों को सम्मिलित करते हुए निष्कर्ष के प्रक्रम तक प्रत्येक आरोप पर पृथक् रूप से किया जाएगा।

(2) तत्पश्चात् न्यायालय, यथास्थिति, नियम 151 या नियम 152 का अनुपालन करेगा।

156. न्यायालय का खाली किया जाना :- (1) विचारण करने वाला आफिसर साक्ष्य पर विचार करने और विचारण में हाजिर रहने वाले आफिसरों और अधीनस्थ आफिसरों से परामर्श करने के लिए न्यायालय को खाली करा सकेगा।

(2) उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी कार्यवाहियां, जिनके अंतर्गत किसी स्थान का अवलोकन भी है, खुले न्यायालय में और अभियुक्त की उपस्थिति में की जाएगी।

157. स्थगन :- न्यायालय,—

(क) अपनी कार्यवाहियों को समय-समय पर स्थगित कर सकेगा और ऐसे स्थान और समय पर बैठक कर सकेगा जो सुविधाजनक हो, और

(ख) जहां-जहां आवश्यक हो, घटनास्थल का निरीक्षण कर सकेगा।

158. अभियुक्त का मित्र :- समरी बल न्यायालय में विचारण के दौरान, अभियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके अंतर्गत विधि व्यवसायी भी है, जिसे वह आवश्यक समझे, सहायता ले सकेगा :

परंतु ऐसा व्यक्ति साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा नहीं करेगा या न्यायालय को संबोधित नहीं करेगा ।

159. कार्यवाहियों से संलग्न किया जाने वाला ज्ञापन :- जहां समरी बल न्यायालय किसी ऐसे अपराध का विचारण करता है, जिसका विचारण धारा 86 की उपधारा (2) में उल्लिखित किसी प्राधिकारी को निर्देश किए बिना साधारणतया नहीं किया जाएगा, वहां कार्यवाहियों के साथ एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न किया जाएगा ।

160. प्रख्यापन :- समरी बल न्यायालय, का दंडादेश सुनाए जाने के पश्चात् शीघ्रतम अवसर पर सेवा की सामान्य रीति से प्रख्यापित किया जाएगा और अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रख्यापन के पश्चात् अविलंब कार्यान्वित किया जाएगा ।

161. कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन :- समरी बल न्यायालय की कार्यवाहियां प्रख्यापन के तुरंत पश्चात् जज अटर्नी जनरल या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नाम निर्दिष्ट आफिसर की मार्फत उस उपमहानिरीक्षक या अपर उपमहानिरीक्षक को भेजी जाएंगी जिसके अधीन अभियुक्त सेवा कर रहा हो ।

162. उपमहानिरीक्षक द्वारा कार्रवाई :- (1) जहां उस उपमहानिरीक्षक, जिसे नियम 161 के अधीन समरी बल न्यायालय की कार्यवाहियां भेजी गई हैं, का यह समाधान हो जाता है कि कार्यवाहियों में गंभीर अनियमितता के कारण या अन्यथा अभियुक्त के साथ अन्याय हुआ है, वहां वह -

(क) न्यायालय की कार्यवाहियों को अपास्त कर सकेगा,

या

(ख) दंडादेश को कम या अधिनिर्णीत दंड को धारा 51 में दिए गए दंड के निचले मापमान में लघुकृत कर सकेगा ।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की गई है, वहां वह कार्यवाही पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे प्रख्यापन के लिए अभियुक्त की यूनिट को वापस कर देगा ।

(3) कार्यवाही, प्रख्यापित किए जाने के पश्चात् जज अटर्नी जनरल को अभिरक्षा के लिए भेजी जाएगी ।

163. नियम जो समरी बल न्यायालय द्वारा विचारण में लागू नहीं होंगे - इन नियमों के अध्याय 9 और 10 के उपबंध समरी बल न्यायालय द्वारा विचारण को, जहां तक वे समरी बल न्यायालय से संबंधित इस अध्याय में अंतर्विष्ट किन्हीं उपबंधों से असंगत हैं, लागू होंगे ।

अध्याय 12

दंडादेश का निष्पादन

164. कारावास के दंडादेश के बारे में निदेश :- (1) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी, या समरी बल न्यायालय की दशा में, न्यायालय यह निदेश देगा कि कारावास या तो सिविल कारावास में या बल अभिरक्षा में परिरुद्ध रह कर भुगता जाएगा ।

(2) ऐसे निदेश में किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा ।

165. वारंट :- (1) कारावास का दंडादेश भुगतने के लिए, सिविल कारावास को किसी व्यक्ति की सुपुर्दगी के लिए या, यदि ऐसा अपेक्षित हो तो, ऐसे व्यक्ति को बल अभिरक्षा में वापस लेने के लिए या ऐसे व्यक्ति को सिविल कारावास से छोड़े जाने का आदेश करने के लिए या किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा किए गए किसी परिवर्तन के लिए वारंट ऐसे प्ररूप में होगा जो परिशिष्ट 10 में उपवर्णित प्रत्येक मामले में उपयुक्त हो ।

(2) ऐसे वारंट पर अभियुक्त के कमान आफिसर द्वारा उपमहानिरीक्षक, महानिरीक्षक या महानिदेशक की ओर से स्टाफ आफिसर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

166. मृत्यु के दंडादेश की दशा में वारंट :- (1) जहां किसी व्यक्ति को फांसी लगाकर मृत्यु का दंडादेश दिया जाता है, वहां परिशिष्ट 11 में उपवर्णित प्ररूप में वारंट, केंद्रीय सरकार द्वारा दंडादेश की पुष्टि किए जाने के पश्चात् महानिदेशक द्वारा ऐसे कारागार के अधीक्षक को जहां ऐसे दंडादेश के कार्यान्वयन की सुविधाएं विद्यमान हैं, भेजा जाएगा और आयुक्त का कमान आफिसर अभियुक्त को समुचित वारंट पर उसी कारागार के सुपुर्द करेगा ।

(2) जहां किसी अभियुक्त व्यक्ति को गोली मार कर मृत्यु दंडादेश दिया जाता है वहां केंद्रीय सरकार द्वारा उसकी पुष्टि कर दिए जाने के पश्चात् महानिदेशक द्वारा परिशिष्ट 11 में उपवर्णित समुचित प्ररूप में उस उपमहानिरीक्षक को जिसके अधीन सेवा कर रहा हो, वारंट जारी किया जाएगा और उपमहानिरीक्षक दंडादेश के निष्पादन की व्यवस्था करेगा ।

167. दंडादेश में परिवर्तन :- जहां किसी सिविल कारागार को पहले से ही सुपुर्द, किसी व्यक्ति के दंडादेश में कोई परिवर्तन किया जाता है, वहां ऐसे परिवर्तन की संसूचना परिशिष्ट 12 में उपवर्णित प्ररूप में कमान आफिसर द्वारा या नियम 165 में उल्लिखित अन्य व्यक्ति द्वारा उस कारागार के अधीक्षक को दी जाएगी जिसे ऐसा व्यक्ति सुपुर्द किया गया है।

168. पदच्युति का दंडादेश :- (1) पदच्युति का दंडादेश ऐसे दंडादेश के प्रख्यापन की तारीख से या ऐसी किसी पश्चात्तर्ती तारीख से, जो प्रख्यापन के समय विनिर्दिष्ट की जाए, प्रभावी होगा।

(2) सिविल कारागार में भुगते जाने वाले कारावास के साथ संयोजित पदच्युति का दंडादेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक ऐसा व्यक्ति सिविल कारागार को सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है।

अध्याय 13

याचिकाएं

169. न्यायालय के निष्कर्ष और दंडादेश के विरुद्ध याचिकाएं :- (1) किसी व्यक्ति को जो अधिनियम के अधीन है और जिसका न्यायालय द्वारा विचारण किया गया है, पुष्टि से पूर्व पुष्टिकरण प्राधिकारी को एक याचिका देने के लिए और पुष्टि के पश्चात् धारा 131 में उल्लिखित किसी आफिसर या प्राधिकारी को एक याचिका देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) समरी बल न्यायालय की दशा में उसे केवल धारा 131 में उल्लिखित किसी आफिसर को याचिका देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

170. परिसीमा अवधि :- (1) याचिका पुष्टि से पूर्व विचारण की समाप्ति के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(2) पुष्टि के पश्चात् याचिका उस तारीख से तीन मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी जिसको दंडादेश प्रख्यापित किया गया था :

परंतु कार्यवाहियों की प्रतिलिपि प्राप्त करने में ऐसे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय तीन मास की इस अवधि की गणना में अपवर्जित किया जाएगा।

171. याचिकाएं प्रस्तुत करने का ढंग :- (1) (क) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अभी भी बल का सदस्य है याचिका उसके कमान आफिसर के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी,

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो बल का सदस्य नहीं रहा याचिका उस यूनिट के कमान आफिसर को प्रस्तुत की जा सकेगी जिसमें विचारण किया गया था।

(2) वह आफिसर, जिसे याचिका प्रस्तुत की जाती है या जिसे याचिका भेजी जाती है, उसे एक सप्ताह की अवधि के भीतर अपने से अगले वरिष्ठ आफिसर को भेजेगा -

परंतु ऐसा आफिसर किसी याचिका को नहीं भेज सकता है यदि वह मांगे गए प्रतितोष को देने के लिए सक्षम है और ऐसा करने का विनिश्चय करता है।

(3) याचिका प्राप्त करने वाला आफिसर याचिका को जज अटर्नी जनरल या उसके द्वारा अनुमोदित आफिसर को सलाह के लिए भेजेगा।

अध्याय 14

जांच- न्यायालय

172. संरचना :- (1) जांच-न्यायालय एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बन सकेगा। यदि केवल एक ही सदस्य नियुक्त किया जाता है, तो वह आफिसर होगा। यदि एक से अधिक सदस्य नियुक्त किए जाते हैं तो उनमें से कम से कम एक आफिसर होना चाहिए। जब न्यायालय का ऐसे विशिष्ट प्रकृति के ऐसे मामलों का अन्वेषण करना हो जिसके समुचित अन्वेषण के लिए विशिष्ट व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता हो तब ऐसे व्यक्तियों को जो अधिनियम के अधीन नहीं है, अतिरिक्त सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(2) जांच न्यायालय के सदस्य या सदस्यों के रैंक ऐसे आफिसर के रैंक से निम्न रैंक का नहीं होगा जिन के आचरण के बारे में जांच के आदेश किए गए हैं। यदि उसी या उच्चतर रैंक के सभी आफिसरों की नियुक्ति संभव नहीं है तो कम से कम ऐसे जांच न्यायालय का पीठासीन आफिसर ऐसे आफिसर के, रैंक से जिसके आचरण के बारे में जांच की जा रही है, उच्चतर रैंक का होगा।

173. समवेत आदेश :- (1) जांच न्यायालय कमान आफिसर के जो कमांडेंट के रैंक से नीचे के रैंक का न हो आदेश से या उससे वरिष्ठ किसी आफिसर या प्राधिकारी के आदेश से समवेत हो सकेगा।

(2) जांच न्यायालय को समवेत करने वाले आदेश में न्यायालय की, संरचना उसके समवेत होने के समय और स्थान का उल्लेख किया जाएगा और उसमें उन विषयों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा जिनका अन्वेषण न्यायालय करेगा। इसमें न्यायालय की प्रशासनिक आवश्यकताओं के बारे में भी उपबंध किया जाएगा।

174. न्यायालय के सदस्यों का शपथ न लेना या प्रतिज्ञान न करना :- न्यायालय के सदस्यों को शपथ नहीं दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान नहीं कराया जाएगा परंतु जब कोई न्यायालय पुनःप्राप्त युद्धबंदियों पर जांच न्यायालय है तो सदस्य निम्नलिखित घोषणा करेंगे :-

“मैं सादर घोषणा करता हूँ कि मैं बल के स्थायी आदेश की सही भावना और अर्थ के अनुसार उन परिस्थितियों की बाबत सम्यक् और निष्पक्ष रूप से जांच करूंगा और अपनी राय दूंगा जिनमें ...युद्धबंदी बना, और मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं अपने स्वयं के मत या राय को अथवा न्यायालय के किसी विशिष्ट सदस्य के मत या राय को किसी भी बाबत या किसी समय तक प्रकट नहीं करूंगा या पता नहीं चलने दूंगा जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।”

175. जांच न्यायालय की प्रक्रिया :-(1) जांच न्यायालय की कार्यवाहियां जनता के लिए खुली नहीं होगी। कार्यवाहियों में केवल वे ही व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे जिन्हें ऐसा करने के लिए न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया जाए।

(2) सभी साक्षियों का साक्ष्य शपथ या प्रतिज्ञान पर लिया जाएगा और उन पर उन्हें सुनाने और उन्हें स्पष्ट करने के पश्चात् उनके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण - न्यायालय साक्षियों को शपथ या प्रतिज्ञान उस रूप में कराएगा मानो यह न्यायालय बल न्यायालय हो।

(3) साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य वृत्तांत के रूप में लेखबद्ध किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय का यह विचारण हो कि किन्हीं प्रश्नों और उत्तरों को उसी रूप में लेखबद्ध किया जाए।

(4) न्यायालय उनके कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् किन्हीं दस्तावेजों पर विचार कर सकता है भले हो वे औपचारिक रूप से साबित न किए गए हों।

(5) न्यायालय किसी भी रूप में साक्षियों से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें वह सच्चाई उगलवाने के लिए अवश्य समझे और वह किसी साक्ष्य पर विचार कर सकेगा चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के अधीन ग्राह्य हो या न हो।

(6) किसी काउंसेल या विधि व्यवसायी की जांच को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(7) जांच-न्यायालय के समक्ष साक्षियों की हाजिरी उपाप्त करने के लिए धारा 101 के उपबंध लागू होंगे। साक्षियों को परिशिष्ट 15 में उपवर्णित नमूनों के अनुसार सम्मन किया जाएगा।

(8) (क) ऐसे युद्धबंदी की दशा के सिवाय जो अभी भी गायब हैं, जहां जांच की विषयवस्तु किसी विशिष्ट व्यक्ति का आचरण या चरित्र है, वहां ऐसे व्यक्ति को पूरी जांच में सहयुक्त रखा जाएगा और उसे कोई ऐसा कथन करने या ऐसा साक्ष्य देने को जिसे वह करना चाहे या देना चाहे, किसी साक्षी को, जिसका साक्ष्य उसकी राय में, उसके चरित्र या ख्याति पर प्रभाव डालता है, प्रतिपरीक्षा करने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

(ख) अन्य मामलों में अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई राय देने से पूर्व न्यायालय उस व्यक्ति को वे सब बातें जानने का जो उसके विरुद्ध कही गई हैं, ऐसे साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का जिन्होंने उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया है और अपनी प्रतिरक्षा में कथन करने और साक्षी बुलाने का अवसर प्रदान करेगा।

(9) न्यायालय के समक्ष पूछे गए किसी प्रश्न का साक्षी द्वारा दिया गया उत्तर ऐसे न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने के किसी आरोप के सिवाय, किसी पश्चात्वर्ती अवसर पर किसी आरोप में ऐसे साक्षी के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगा।

(10) जहां किसी जांच की कार्यवाहियों को, नियम 177 के अधीन आदेशों के लिए किसी उच्चतर प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, वहां ऐसा प्राधिकारी, न्यायालय की राय से सहमत न होने से पूर्व, ऐसा करने के कारण अभिलिखित करेगा, ऐसी दशा में, उपनियम (8) के खंड (ख) के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जा सकेगा।

(11) न्यायालय उतनी बार पुनः समवेत हो सकेगा जितनी बार वह आफिसर, जिसने न्यायालय को समवेत किया, अतिरिक्त साक्षियों की परीक्षा करने के लिए या किसी साक्षी की और परीक्षा करने के लिए या और जानकारी अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए निदेश दे। ऐसी दशा में, न्यायालय यदि वह आवश्यक समझे तो, उपनियम (8) के खंड (ख) के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् नई राय अभिलिखित कर सकेगा।

176. जांच न्यायालय कब अधिविष्ट होगा :- (1) जांच-न्यायालय किसी अनुशासनिक विषय का या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय का अन्वेषण करने के लिए अधिविष्ट किया जा सकेगा।

(2) धारा 60 और धारा 65 या धारा 74 के अधीन अधिविष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित जांच-न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित मामलों में जांच न्यायालय अधिविष्ट किया जाएगा -

- (क) (i) अधिनियम के अधीन व्यक्तियों की या बल लाइनों के भीतर अन्य व्यक्तियों की अप्राकृतिक मृत्यु के सब मामलों की तत्काल एक रिपोर्ट संदेशवाहक के माध्यम में उस पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर को भेजी जाएगी जिसकी अधिकारिता में वह स्थान है जिसमें ऐसी अप्राकृतिक मृत्यु हुई है:
- (ii) उन दशाओं में, जहां ऐसी रिपोर्ट किन्हीं कारणों से व्यक्तिगत समय के भीतर परिदत्त नहीं की जा सकती है वहां उपस्थित कमान आफिसर या यूनिट का ज्येष्ठतम आफिसर परिशिष्ट 13 में उपवर्णित प्ररूप में एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(ख) अधिनियम के अधीन व्यक्तियों को हुई ऐसी सब क्षतियों, जिनसे पूर्ण या आंशिक निःशक्तता होने को संभावना है। न्यायालय ऐसे मामलों में यह अवधारित करेगा कि ऐसी क्षतियां ऐसी सेवा से हुई मानी जा सकती है या नहीं।

(ग) लोक या बल संपत्ति की सब वित्तीय अनियमितताएं, हानि, चोरी, या दुर्विनियोग, जहां ऐसी अनियमितताओं, हानि, चोरी या दुर्विनियोग के बारे में वरिष्ठ आफिसर का आदेश प्राप्त करना आवश्यक है।

(घ) गोपनीय दस्तावेजों और गोपनीय या ऊपर सुरक्षा वर्गीकरण की अन्य सामग्री के खो जाने के सभी मामले ऐसे जांच न्यायालय के लिए आदेश उस यूनिट के किसी आफिसर या कमान आफिसर के वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा जिसके प्रभार में खो गया दस्तावेज या सामग्री थी।

(ङ) प्राईवेट व्यक्तियों को हुई सभी क्षतियां या उनकी संपत्ति को हुए सब नुकसान जिनकी बाबत सरकार या बल के विरुद्ध दावा किए जाने की संभावना है।

177. जांच-न्यायालय की कार्यवाहियों पर कार्रवाई :- जांच-न्यायालय की कार्यवाहियां पीठासीन आफिसर द्वारा उस आफिसर या प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसने न्यायालय का आदेश दिया था। ऐसा आफिसर या प्राधिकारी कार्यवाहियां प्राप्त होने पर यदि ऐसा करने के लिए सशक्त है तो कार्यवाहियों पर अंतिम आदेश स्वयं पारित कर सकेगा या उन्हें वरिष्ठ प्राधिकारी को निर्देशित कर सकेगा।

178. जांच न्यायालय की कार्यवाहियों की प्रतियां :- अधिनियम के अधीन का वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध जांच-न्यायालय ने कोई राय दी है या जिसके विरुद्ध जांच न्यायालय द्वारा अन्वेषण किए गए विषयों से संबंधित आरोप पर बल न्यायालय द्वारा विचारण किया जा रहा है, जांच न्यायालय की कार्यवाहियों की प्रतियों का तब तक हकदार होगा, जब तक कि महानिदेशक अन्यथा आदेश न करे।

स्पष्टीकरण : इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए न्यायालय से "जांच न्यायालय" अभिप्रेत है।

अध्याय - 15

प्रकीर्ण

179. धारा 11 के अधीन विहित आफिसर :- ऐसा आफिसर जो कमांडेंट के रैंक से नीचे का न हो, अपने कमान के अधीन किसी आफिसर या अधीनस्थ आफिसर से भिन्न किसी व्यक्ति को धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन पदच्युत कर सकेगा या हटा सकेगा।

180. धारा 13(1) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी :- धारा 13 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे -

- (i) आफिसरों से भिन्न अधिनियम के अधीन सभी कार्मिकों की बाबत महानिदेशक।
- (ii) आफिसरों की बाबत केंद्रीय सरकार।

181. धारा 61 और 62 के अधीन विहित आफिसर :- धारा 61 की उपधारा (2) के खंड (i) और 62 के प्रयोजन के लिए विहित आफिसर निम्नलिखित होंगे -

- (i) अधीनस्थ आफिसर और अभ्यावेशित व्यक्तियों की बाबत कमांडेंट।
- (ii) आफिसरों की बाबत महानिदेशक।

(2) इन नियम के अधीन पूर्वोक्त आफिसर को किसी शक्ति का प्रयोग उससे वरिष्ठ आफिसर भी कर सकेगा।

182. धारा 66 के अधीन विहित प्राधिकारी :- ऐसा प्राधिकारी जो अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन किसी कटौती को अधिनिर्णीत करने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ हो, उक्त कटौतियों को पूरा या आंशिक रूप से परिहार करने के लिए सक्षम होगा।

183. धारा 75 के अधीन विहित प्राधिकारी :- धारा 75 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए जोन, सेक्टर प्रशिक्षण संस्थान का कमान आफिसर या क्षेत्र में बलों को कमान करने वाला आफिसर, विहित आफिसर होगा।

दंडादेश का निष्पादन

184. धारा 111 और 112 के अधीन अभिरक्षा की निहित रीति और विहित आफिसर :- (1) धारा 112 के प्रयोजनों के लिए विहित आफिसर निम्नलिखित होंगे :-

(क) समरी बल न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने की दशा में, उस यूनिट का कमान आफिसर जिससे अभियुक्त संबंधित है या ऐसे कमान आफिसर से वरिष्ठ कोई आफिसर।

(ख) किसी अन्य न्यायालय द्वारा विचारण की दशा में संयोजक आफिसर या उससे वरिष्ठ कोई प्राधिकारी।

(2) जहां कोई आफिसर जो उपनियम (1) के अधीन विहित आफिसर के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव करता है किसी ऐसे आफिसर के कमान के अधीन है जिसने उप मामलों में धारा 111 की उपधारा (4) के अधीन कोई कार्रवाई की है, तो वह कार्रवाई करने से पूर्व सामान्यतः ऐसे आफिसर का अनुमोदन प्राप्त होगा। किंतु यदि उसकी यह राय है कि सेवा की अत्यावश्यकताओं या अनुशासनिक आवश्यकताओं के कारण ऐसा अनुमोदन प्राप्त करना असंभव या असमीचीन है तो वह ऐसा अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही कार्रवाई कर सकेगा, किंतु वह ऐसी कार्रवाई और इसके कारणों के बारे में ऐसे आफिसर को रिपोर्ट देगा।

(3) धारा 111 की उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए अभियुक्त को ऐसी रीति से निरुद्ध रखा जाएगा जैसा बल प्राधिकारी की राय में बिना अनावश्यक कठोरता के, उसे सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी समझी जाए क्योंकि उसे अपराधी नहीं माना जाएगा किंतु उसे ऐसा व्यक्ति माना जाएगा जो किसी रोग के कारण कष्ट में है।

185. धारा 132 के अधीन विहित आफिसर :- किसी जोन, सेक्टर या प्रशिक्षण संस्थान का कमान आफिसर उन कार्रवाइयों के लिए जिनकी पुष्टि उसने या उसकी कमान के अधीन किसी व्यक्ति ने की हो धारा 132 के प्रयोजन के लिए विहित आफिसर होगा।

186. प्राधिकृत कटौतियां :- इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय वेतन और सभी अन्य परिलब्धियों से निम्नलिखित कटौतियां की जा सकेंगी अर्थात्-

(क) केंद्रीय सरकार के साधारण और विशेष आदेश पर किसी लोक दावे को पूरा करने के लिए अपेक्षित कोई धनराशि जो उसके नाम हो।

(ख) किसी भविष्य निधि, कल्याण निधि या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य निधि में अनिवार्य अभिदाय को पूरा करने के लिए या किसी बल की संस्था जैसे मेस, कैंटीन और वैसी ही किसी संस्था को उसके द्वारा देय किसी ऋण को पूरा करने के लिए अपेक्षित कोई धनराशि।

स्पष्टीकरण : (i) "लोक दावे" से ऐसा लोक ऋण या गैर भत्ता निषेधन अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत लोक धन या भंडार से अत्यधिक निर्गमन या कमी या अनियमित व्यय है, जिसके बारे में सम्यक अन्वेषण के पश्चात् उस व्यक्ति द्वारा जो उसके लिए उत्तरदायी है, केंद्रीय सरकार को समाधानप्रद रूप में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

(ii) पूर्वोक्त कटौतियां अधिनियम में विनिर्दिष्ट कटौतियों के अतिरिक्त है।

187. निरसन और व्यावृत्ति :- (1) इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित सभी नियम और आदेश जहां तक कि वे इन नियमों के उपबंधों से असंगत हैं निरसित हो जाएंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित नियमों या आदेशों के उपबंधों से अधीन की गई कोई भी बात या कार्रवाई जहां तक कि ऐसी बात या कार्रवाई इन नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं है इन नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार की गई समझी जाएगी मानो उक्त उपबंध उस समय प्रवृत्त थे जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी और तदनुसार तब तक प्रदत्त रहेगी जब तक कि वह इन नियमों के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई से अतिरिक्त नहीं कर दी जाती।

188. अस्थायी उपबंध :- इन नियमों के प्रारंभ होने पर बल को लागू कोई नियम या आदेश जब तक कि वह इन नियमों के विरुद्ध न हो तब तक लागू बना रहेगा जब तक कि वह केंद्रीय सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निराकृत या उपांतरित नहीं कर दिया जाता है

परिशिष्ट 1

(नियम 16 देखिए)

सशस्त्र सीमा बल भर्ती प्रारूप

संख्या	रक्त वर्ग
1. नाम	बटालियन/यूनिट
3. जाति/जनजाति/वर्ग (केवल अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की दशा में)	2. धर्म
5. उत्तराधिकारी	4. पिता का नाम
6. जन्म की तारीख ईसवी सन् के अनुसार (जहां तक अभिनिश्चित की जा सकती है उनके निकटतम)	
7. ऊंचाई सें.मी.	8. सीना से.मी.
9. पहचान चिह्न	
10. निवास स्थान : नगर/ग्राम	थाना
जिला	राज्य
11. चरित्र और पूर्ववृत्त	द्वारा सत्यापित किया गया ।
12. भर्ती होने से पूर्व उपजीविका	
13. शैक्षिक अर्हताएं यदि कोई हैं	
14. अभ्यावेशन की तारीख	
15. किस रूप में अभ्यावेशन किया गया	

नवीनतम फोटो

अभ्यावेशन का प्रारूप

.....का अभ्यावेशन

सं. नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

..... का सशस्त्र सीमा बल में

..... के रूप में अभ्यावेशन ।

भाग - 1

(अभ्यावेशन के पूर्व पूछे जाने वाले प्रश्न)

आपको चेतावनी दी जाती है कि यदि अभ्यावेशन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आपने निम्नलिखित प्रश्नों में से पहले बारह प्रश्नों में से किसी का उत्तर जानबूझकर मिथ्या दिया है तो आप सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 में यथा उपबंधित के अधीन दंडनीय होंगे ।

(सभी उत्तर स्पष्ट अक्षरों में लिखे जाने हैं)

प्रश्न :

1. आपका नाम क्या है ?
(उपनाम रेखांकित कीजिए)

2. (क) आपका जन्म स्थान कौन सा है ?
(ग्राम/नगर, जिला तथा राज्य बताइए जहां आपका जन्म हुआ है)
(ख) आपके जन्म की तारीख क्या है ?
(ईसवी सन् में लिखिए)

विशेष टिप्पणी : अभ्यावेष्टित किए जाने वाले व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह जन्म की तारीख के समर्थन में समय-समय पर सरकार के आदेशों में विनिर्दिष्ट मूल प्रमाण पत्र तथा उसकी अनुप्रमाणित प्रति पेश करें ।

3. आपके स्थायी घर का पता क्या है ?
(क) ग्राम/नगर
(ख) थाना
(ग) परगना/तहसील
(घ) जिला/ताल्लुका
(ङ) राज्य
4. (क) आपका धर्म क्या है ?
(ख) क्या आप अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं ?
(यदि हैं तो जाति, जनजाति या वर्ग बताइए और समय-समय पर सरकार द्वारा विहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र और उसकी अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें)
5. (क) क्या आप भारत के नागरिक हैं ? यदि हां तो क्या ऐसे नागरिक आप जन्म से हैं या उद्भव या रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण के आधार पर हैं या अन्यथा हैं ?
(ख) यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आपकी राष्ट्रियता क्या है ?
(ग) क्या आप किसी क्षेत्र से प्रवासी हैं जो अब पाकिस्तान में है ? यदि हां तो अपने प्रवास की तारीख बताइए ।
6. आपकी शैक्षिक अर्हताएं क्या हैं ?
(मूल प्रमाण पत्र, उनकी एक-एक अनुप्रमाणित प्रति के साथ पेश किए जाने चाहिए)
7. क्या आप विवाहित हैं ? यदि हैं तो बताइए -
(i) विवाह (विवाहों) की तारीख
(ii) पति/पत्नी का नाम
(iii) पति/पत्नी की राष्ट्रियता
((इसके अंतर्गत विधवा/विधुर/विच्छिन्न-विवाह व्यक्ति नहीं हैं))
8. (क) आपके पिता का नाम तथा पता क्या है ? यदि उनकी मृत्यु हो गई है तो उनका अंतिम पता, जिला और राज्य बताइए ।
(ख) आपके पिता की राष्ट्रियता क्या है या थी ? यदि वह भारतीय नागरिक हैं या थे तो बताइए कि क्या वे जन्म से या उद्भव या रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण के आधार पर या अन्यथा ऐसे नागरिक हैं या थे ।
9. क्या आप किसी राजनैतिक, साम्प्रदायिक या सांस्कृतिक स्वरूप के किसी दल या संगठन के सदस्य हैं या कभी रहे हैं ? यदि हां तो उस दल या संगठन का नाम और उसमें अपनी सदस्यता की अवधि या अवधियां बताइए ।
10. (क) क्या आप सरकारी सेवा में हैं या आप सरकारी सेवक रहे हैं ? यदि हां तो पूरी विशिष्टता दीजिए और उन्मोचन का कारण बताइए और इस बात की पुष्टि कीजिए कि आपको सरकारी सेवा से कभी पदच्युत नहीं किया गया है ।
(ख) क्या आपको सरकार से कोई भत्ता और/या पेंशन मिलती है ? यदि हां तो किस कारण से मिलती है ?

11. (क) क्या आप सेना, नौसेना या वायु सेना तीनों सेवाओं में से किसी के रिजर्व, सहायक वायु सेना, प्रादेशिक सेना, भारत में किसी पुलिस बल या नेपाल राज्य सेना या किसी विदेश के किसी बल के हैं ?
- (ख) क्या आपने कभी भारत में सेना, नौसेना या वायुसेना, बल तीनों सेवाओं में से किसी के रिजर्व, सहायक वायु सेना प्रादेशिक सेना, भारत में किसी पुलिस बल या नेपाल राज्य सेना या विदेश के किसी बल में सेवा की है ? यदि हां तो बताइए किस में और सेवानुवृत्त होने का कारण क्या है ? यदि आपने ऊपर नामित बलों में से एक से अधिक में सेवा की है या यदि आपने उसी बल में दो या अधिक सुभिन्न अवधियों में सेवा की है, तो प्रत्येक दशा में सेवानुवृत्त होने का कारण पृथक-पृथक बताइए ।
12. (क) क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं ?
- (ख) क्या आप कभी अभियोजित किए गए हैं ?
- (ग) क्या आप कभी निरोध में रखे गए या कारावास में रहे हैं ?
- (घ) क्या आप किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए हैं ?
- (ङ) क्या आप कभी आबद्ध किए गए हैं ?
- (च) क्या आप पर कभी किसी विधि के न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया है ?
- (छ) क्या आप कभी भारत या भारत के बाहर प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नजरबंद, निष्कासित या अन्यथा रहे हैं ? यदि हां तो विशिष्टताएं बताएं ।
- (ज) क्या आपके विरुद्ध भारत या विदेश के किसी न्यायालय में कोई अभियोजन है ?
- (झ) क्या आपको किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा परीक्षा से विवर्जित या निष्कासित किया गया है ?
- (ञ) क्या आपको किसी लोक सेवा आयोग द्वारा उसकी परीक्षा में बैठने/चयन किए जाने से विवर्जित/निरहित किया गया है ?
- (ट) क्या इस अभ्यावेशन प्रारूप के भरते समय आपके विरुद्ध किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान में कोई मामला लंबित है ?
- (ठ) क्या आपको सरकार के अधीन या अन्यथा किसी प्रशिक्षण संस्थान से उन्मोचित, निष्कासित किया गया है, अथवा बुलाया गया है ?
13. क्या आप सशस्त्र सीमा बल में योद्धक के रूप में अभ्यावेशित होने के लिए रजामंद हैं ?
14. क्या आप भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से जहां कहीं जाने के लिए आदेश दिया जाए, वहां जाने के लिए रजामंद हैं ? आप उन कर्तव्यों के पालन में, जिनके लिए आपको अभ्यावेशित किया गया है, किसी जातिगत या सामाजिक प्रथा बाधक नहीं बनने देंगे ।
15. क्या आप इस अभ्यावेशन प्रारूप के भाग 2 में विनिर्दिष्ट सेवा की शर्तों के अनुसार सशस्त्र सीमा बल में सेवामुक्त होने तक सेवा करने के लिए रजामंद हैं ?
16. क्या आपका आपके अनुप्रमाणन के समय निम्नलिखित शपथ लेने या निम्नलिखित प्रतिज्ञान के प्रति कोई आक्षेप है ?

व्यक्ति के हस्ताक्षर

शपथ का प्रारूप

मैं..... ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सशस्त्र सीमा बल में कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में, ईमानदारी से और श्रद्धापूर्वक सेवा करूंगा और वायु, भूमि या समुद्र मार्ग से जहां कहीं जाने का आदेश दिया जाएगा, वहां जाऊंगा और भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी समादेशों और मेरे ऊपर नियुक्त किसी भी आफिसर के सभी समादेशों का अपने जीवन का जोखिम उठाकर भी पालन तथा अनुपालन करूंगा ।

प्रतिज्ञान का प्रारम्भ

मैं सत्यनिष्ठा, शुद्ध हृदय और सच्चाई से घोषणा करता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं सशस्त्र सीमा बल में कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में, ईमानदारी से और अज्ञापूर्वक सेवा करूँगा और वायु, भूमि या समुद्र मार्ग से जहाँ कहीं जाने का आदेश दिया जाएगा, वहाँ जाऊँगा और भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी समादेशों और मेरे ऊपर नियुक्त किसी भी आफिसर के सभी समादेशों का अपने जीवन का जोखिम उठाकर भी पालन तथा अनुपालन करूँगा।

प्रमाणपत्र

मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त उत्तर सही हैं।

स्थान

तारीख

* (.....)

अभ्यावेशित व्यक्ति के हस्ताक्षर

अभ्यावेशित आफिसर की उपस्थिति में लिया

गया अभ्यावेशित व्यक्ति के बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान

हस्ताक्षर

नाम

साक्षी का पता

* (नाम स्पष्ट अक्षरों में)

प्रतिज्ञान कराने वाले अधिकारी

के हस्ताक्षर

भाग 2**सेवा की शर्तें**

1. सशस्त्र सीमा बल अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह अवधि जिसके लिए आप अभ्यावेशित किए गए हैं, वर्ष की होगी। यह अवधि आपसी करार द्वारा बढ़ाई जा सकती है।
2. यदि आप छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहते हैं या अभित्यजन करते हैं तो ऐसी अनुपस्थिति की कुल अवधि उक्त अवधि की गणना में नहीं ली जाएगी।
3. सेवा का उक्त वर्ष की अवधि के या आगे बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने पर आप अपनी सेवोन्मुक्त दावा करने के हकदार होंगे और यदि देश संघर्ष न हो या आपात स्थिति की घोषणा न की गई हो या उस यूनिट या संस्था जिसके आप हैं पन्द्रह प्रतिशत से अधिक की कमी न हो तो, आपको सुविधानुसार शीघ्रता से सेवोन्मुक्त कर दिया जाएगा।
4. यदि आपके बल का दक्ष सदस्य होने की संभावना नहीं है, तो आपको सेवा के प्रथम वर्ष के दौरान सेवोन्मुक्त किया जा सकेगा।
5. यदि केन्द्रीय सरकार बल या उसके किसी भाग को भंग करने का विनिश्चय करती है तो भी आपको सेवोन्मुक्त किया जा सकेगा।

अभ्यावेशित किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाण पत्र

मैंने उपरोक्त शर्तों को समझ लिया है और मैं उनका पालन करने का कशर करता हूँ।

(.....)

अभ्यावेशित व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान.....

तारीख.....

मैंने उपर्युक्त शर्तें अभ्यावेशित किए जा रहे व्यक्ति को पढ़कर सुना दी हैं/स्पष्ट कर दी हैं।

स्थान.....

तारीख.....

(.....)

अभ्यावेशन आफिसर के हस्ताक्षर

भाग 3

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने सशस्त्र सीमा बल में नियोजन के लिए अभ्यर्थी.....की परीक्षा कर ली है। वह सशस्त्र सीमा बल के लिए अधिकथित स्वास्थ्य के स्तर को पूरा करता है और मुझे उसमें कोई रोग, गठन-विकृति या अंग सैधित्य दिखाई नहीं पड़ता है। उसके कथनानुसार उसकी आयु.....वर्ष है और देखने में वह.....वर्ष का लगता है।

लम्बाई.....से. मी.

सीना (क) अधिकतम.....से. मी.

(ख) न्यूनतम.....से. मी.

चिकित्सा आफिसर के

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

स्थान.....

तारीख.....

परिशिष्ट-2

[(नियम 39(1) देखिए)]

विलम्ब रिपोर्ट का प्रारूप

गोपनीय

सं.

यूनिट का पता

तारीख

सेवा में,

विषय- सशस्त्र सीमा बल अधिनियम की धारा 71 और नियम 39 के अनुसरण में, आठ दिन विलम्ब को (द्वितीय), (तृतीय), (चतुर्थ) आदि रिपोर्ट।

1. सं. रैंक नाम

2. अपराध

3. अपराध की तारीख
4. अपराध का पता चलने की तारीख
5. (खुली/बन्द) गिरफ्तारी की तारीख
6. खुली गिरफ्तारी से निर्मुक्त करके पुनः गिरफ्तारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्मुक्त करने की तारीख (यदि निर्मुक्त नहीं किया गया है तो कारण बताएं)
7. साक्ष्य अभिलिखित करने की तारीख
(यदि अभिलिखित नहीं किया गया है तो कारण बताएं)
8. विचारण के लिए आवेदन की तारीख
9. वह तारीख जिसको विचारण किया जाना है
10. विलम्ब के कारण

(कमान आफिसर)

निम्नलिखित को प्रतिलिपि:

1. महानिरीक्षक (आठवीं और पश्चात्पूर्ति रिपोर्टों की दशा में)
2. महानिदेशक (उस दशा में विशेष रिपोर्ट जब अभियुक्त विचारण के बिना तीन मास से अधिक के लिए बन्द गिरफ्तारी में है)

परिशिष्ट-3

[नियम 40 (2) (ब) देखिए]

क्र. स	तारीख	अभियुक्त का नाम	उस आफिसर या अधीनस्थ आफिसर का नाम जिसे निवेदन या अभ्यवेदन किया गया है	निवेदन या अभ्यवेदन की विशिष्टियां	कमान आफिसर के आदेश	अभियुक्त को कमान आफिसर के आदेश संसूचित करने वाले आफिसर या अधीनस्थ आफिसर के हस्ताक्षर और तारीख	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

परिशिष्ट-4

(नियम 44 देखिए)

सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 56 के अधीन अवर आफिसरों और अन्य अभ्यावेशित व्यक्तियों की समरी कार्यवाहियों के प्रयोग के लिए प्ररूप ।

अपराध की रिपोर्ट

यूनिट

क्र. सं.

.....होने वाले सप्ताह के लिए पिछली

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख

के विरुद्ध आरोप						
सं.	रैंक		नाम			
अपराध का स्थान और तारीख	अपराध	अभिवचन	साक्षियों के नाम	अधिनिर्णीत दंड	दंड अधिनिर्णीत करने वाले आफिसर के हस्ताक्षर, रैंक और पदनाम तथा अधिनिर्णय की तारीख	आचरण पत्र में दर्ज करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
टिप्पणियां						
(8)						

बटालियन/युनिट के कमान

बटालियन/यूनिट के कमान
आफिसर के हस्ताक्षर

अनुदेश :-

- स्तम्भ 1. छुट्टी के बिना अनुपस्थिति/अभित्यजन की दशा में, “अपराध की तारीख” अनुपस्थिति का पहला दिन होगा।
- स्तम्भ 2. अधिनियम की धारा और उपधारा, जिसके अधीन आरोप लगाया गया है, आरोप के कथन के ऊपर लिखी जाएगी।
- स्तम्भ 3. कोई आफिसर किसी ऐसे मामले में संक्षिप्त कार्यवाही नहीं कर सकता है जिसमें वह एकमात्र अभियोजन साक्षी है।
- स्तम्भ 4. सर्वथा शीर्षक के अनुसार भरा जाना चाहिए।
- टिप्पण : यह दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा।
एक प्रति, जहां साक्ष्य का संक्षेप तैयार किया गया है वहां उसके साथ उप-महानिरीक्षक को भेजी जाएगी।

परिशिष्ट-5

[नियम 44 और नियम 56(2) देखिए]

आरोप पत्र

अभियुक्त सं. (यदि लागू हो) रैंक

नाम बटालियन/यूनिट पर निम्नलिखित आरोप लगाया जाता है—

अपने वरिष्ठ आफिसर के विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा
सशस्त्र सीमा बल अधिनियम की धारा 23(2) के अधीन
उसने तारीख को बजे उसी बटालियन के उसके वरिष्ठ आफिसर
रैंक नाम के कमांडेंट के परेड में आने के विधिपूर्ण समादेश की उसमें न आकर अवज्ञा की।

क. ख.

कमान आफिसर — बटालियन/यूनिट

स्थान

तारीख

* जनरल/पैटी बल न्यायालय द्वारा विचारण किया जाए।

स्थान

तारीख

भ.म.

महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक

(महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक का स्टाफ आफिसर)

* जब समरी बल न्यायालय सशस्त्र सीमा बल अधिनियम की धारा 86(2) द्वारा गम्भीर अपराधों के विचारण के लिए मंजूरी दे दी जाए, तब इसी प्रकार की प्रविष्टि आरोप पत्र में की जानी चाहिए।

परिशिष्ट 6

(नियम 55 देखिए)

बल न्यायालय के लिए आवेदन का प्रारूप

स्टेशन..... बटालियन/यूनिट
तारीख.....

बल न्यायालय के लिए आवेदन

महोदय,

मैं अपने समादेश के अधीन.....यूनिट के सं.....रैंक.....नाम.....के विरुद्ध आरोप प्रस्तुत करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ किके लिए मंजूरी दें/अभिप्राप्त करें कि उसके विचारण के लिए.....(स्थान) में बल न्यायालय का समावेश किया जाए।

मामले का अन्वेषण (क).....द्वारा किया गया था।

जांच न्यायालय(ख) तारीख.....को.....स्टेशन में अधिविष्ट किया गया था।

पीठासीन आफिसर का नाम.....रैंक.....

यूनिट.....

सदस्य.....

अभियुक्त इस समय.....(स्थान) में है।

उसका साधारण चरित्र (ग).....है। मैं निम्नलिखित दस्तावेज (घ) संलग्न कर रहा हूँ।

1. आरोप पत्र (.....प्रतियाँ) (ङ.)
2. अभिलेख या साक्ष्य का सार, मूल (च) और पांच प्रतियाँ
3. मूल प्रदर्श (छ)
4. पत्राचार (ज)
5. अभियुक्त के चरित्र (.....) और आचरण पत्र के बारे में विवरण (झ)
6. अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षियों की सूची (उनके वर्तमान पते सहित)(ञ)
7. प्रदर्शों की सूची (ड)
8. अभियुक्त का यह कथन कि वह अपने विचारण में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए संयोजक आफिसर द्वारा समनुदेशित कोई आफिसर चाहता है या नहीं [(नियम 65(2))]

कमान आफिसर के हस्ताक्षर

(क) यहां निम्नलिखित के नाम लिखें :

(i) वह आफिसर जिसने आरोपों का अन्वेषण किया है।

(ii) वह आफिसर जिसने मामले में प्रारंभिक सुनवाई की है (नियम 45)

(iii) वह आफिसर जिसने साक्ष्य अभिलिखित किया है (नियम 51)

(ख) तब भरा जाए जब आरोपों से संबंधित किन्हीं विषय की बाबत कोई जांच न्यायालय कर रहा है। अन्यथा इसे काट दिया जाए [(नियम 62(iii))]

(ग) कमान आफिसर द्वारा भरा जाएगा।

(घ) जो मद लागू न हो वह काट दी जाए।

(ङ) पीठासीन आफिसर, जज अटर्नी (यदि कोई है) सदस्य, अभियोजक और अभियुक्त को एक-एक प्रति।

(च) मूल अभिलेख या साक्ष्य का सार पीठासीन आफिसर को भेजा जाए।

(छ) 3, 4, 5 और 6, विचारण की सूचना के साथ अभियुक्त के यूनिट के कमान आफिसर को वापस कर दी जाए।

(ज) 7 और 8 पीठासीन आफिसर को भेजी जाएं।

परिशिष्ट 7

[नियम 65 (क) देखिए]

बल न्यायालय के संबंध में प्रारूप

जनरल और पैटी बल न्यायालय के समवेत के लिए प्रारूप

सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 के अधीन जनरल (या पैटी) बल न्यायालय के समवेत के लिए आदेश का प्रारूप।

_____ के आदेश से

(स्थान _____ तारीख _____)

रैंक _____

नाम..... नीचे वर्णित आफिसर, पार्श्व में नामित अभियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) का (और ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का, जो उनके समक्ष लाए जाएं)..... बल न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने के प्रयोजन के लिए तारीख..... को में समवेत किया जाएगा। ज्येष्ठ आफिसर पीठासीन आफिसर के रूप में बैठेगा।

सदस्य.....

प्रतीक्षा सदस्य.....

जज अटर्नी

..... को जज अटर्नी नियुक्त किया गया है।

दुभाषिया

..... को दुभाषिया नियुक्त किया गया है।

अभियोजक

..... को अभियोजक नियुक्त किया गया है।

* अभियुक्त को चेतावनी दी जाएगी और सभी साक्षियों से हाजिर होने की सम्यक अपेक्षा की जाएगी। कार्यवाहियां (जिसकी केवल दो प्रतियां अपेक्षित हैं)..... को अग्रेषित की जाएगी। आज तारीख..... को हस्ताक्षर किए गए।

संयोजक आफिसर

* न्यायालय के गठन की बाबत संयोजक आफिसर की राय (नियम 63 देखिए) यहां इस प्रकार जोड़ी जानी चाहिए:-
“संयोजक आफिसर की राय में विभिन्न बटालियों/यूनिटों के आफिसरों को नियुक्त करना साध्य नहीं है। संयोजक आफिसर की राय में, अभियुक्त के समतुल्य या वरिष्ठ रैंक वाला आफिसर लोक सेवा को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए उपलब्ध नहीं है।”

* यहां काउंसिल की बाबत आदेश जोड़िए (नियम 65)(छ) देखिए।

परिशिष्ट 8

(नियम 108 देखिए)

मैं, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 117 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश देता हूँ कि..... का/को परिदान/संदाय..... को कर दिया जाए (अधिहृत/नष्ट किया जाए)

हस्ताक्षर

(पुष्टिकर्ता प्राधिकारी)

स्थान.....

तारीख.....

परिशिष्ट 9

[नियम 108(8) (ख) देखिए]

अभियुक्त के विचारण के लिए तारीख से तारीख तक
 (स्थान) में अधिविष्ट जनरल/पैटी बल न्यायालय का निष्कर्ष और दण्डादेश मेरे
 द्वारा अभियुक्त को तारीख को (स्थान) में प्रख्यापित किया गया था ।

बटालियन/यूनिट अभिलेखों के लिए उद्धरण ले गए हैं । * निष्कर्ष और दण्डादेश का कोई अभिलेख नहीं रखा गया है ।

हस्ताक्षर

(कमान आफिसर)

स्थान

तारीख

* सभी आरोपों पर दोषमुक्ति की दशा में प्रयोग किया जाए ।

परिशिष्ट 10

(नियम 165 देखिए)

सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 135 और धारा 139 के अधीन वारंट

प्रारूप "क"

किसी कैदी को आजीवन कारावास का दण्डादेश दिए जाने पर प्रयोग में लाया जाने वाला सुपुर्दगी वारंट (धारा 135)
 सेवा में,

अधीक्षक

..... (क) कारागार ।

तारीख को (स्थान) में अधिविष्ट जनरल बल न्यायालय ने (सं. रैंक
 नाम यूनिट) को (यहां अपराध का संक्षेप में उल्लेख किया जाए, जैसे " सक्रिय सेवा में
 होते हुए अभित्यजन", शत्रु के साथ पत्राचार आदि) के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया था । और उक्त जनरल बल न्यायालय
 ने तारीख को उक्त (नाम) को निम्नलिखित दंडादेश दिया है,
 अर्थात्

(दण्डादेश पूर्णतया लिखिए किंतु उस पर हस्ताक्षर न किए जाएं)

और उक्त दण्डादेश (ख) विधि द्वारा अपेक्षित रूप से (ग) द्वारा सम्यक् रूप से पुष्ट किया गया था ।

आपसे यह अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम) को विधि
 द्वारा अपेक्षित रूप में उक्त कारागार में इस वारंट सहित अपनी अभिरक्षा में लें, तब तक रखें जब तक आप उसे कारावास का
 पूर्वोक्त दण्डादेश भोगने के प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी को उसकी अभिरक्षा में उक्त वारंट सहित न सौंप दें । पूर्वोक्त
 दण्डादेश (घ) से प्रभावी है ।

आज (स्थान) में तारीख को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

हस्ताक्षर

(क) सिविल कारागार का नाम लिखिए ।

(ख) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी का नाम और वर्णन ।

(ग) यदि आवश्यक हो तो " का परिहार करते हुए" शब्द जोड़ें ।

- (घ) वह तारीख लिखिए जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे ।
 (ङ) कैदी के कमान आफिसर या अन्य विहित आफिसर के हस्ताक्षर ।

प्रारूप 'ख'

सिविल कारागार में भुगतने वाले कारावास से दण्डादिष्ट कैदी की दशा में प्रयोग के लिए सुपुर्दगी वारंट (धारा 135) सेवा में

अधीक्षक

.....(क) कारागार ।

तारीखको(स्थान) में अधिविष्ट (ख) बल न्यायालय ने (सं. रैंक नामयूनिट) को(यहां अपराध का संक्षेप में उल्लेख किया जाए, जैसे "अभित्यजन" "चोरी", "चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करना", "कपट" विधिपूर्ण आदेशों की अवज्ञा या यथास्थिति) के लिए सम्यक् रूप से सिद्धदोष उहराया गया था ।

और उक्त(ख) बल न्यायालय ने तारीखको उक्त (नाम.....) को निम्नलिखित दण्डादेश दिया अर्थात् -

(दण्डादेश पूर्णतया लिखिए, किंतु उस पर हस्ताक्षर न किए जाएं) और उक्त दण्डादेश (ग) विधि द्वारा अपेक्षित रूप में(घ) द्वारा पुष्ट किया गया है (ङ) के बिना विधिमान्य है ।

आपसे यह अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम.....) को अपनी अभिरक्षा में इस वारंट सहित लें और वहां कारावास के पूर्वोक्त दण्डादेश को विधि के अनुसार निष्पादित करें । दण्डादेश(घ) से प्रभावी है ।

आज(स्थान) में तारीखको मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

हस्ताक्षर (छ)

- (क) सिविल कारागार का नाम लिखिए ।
 (ख) जनरल पैटी या समरी ।
 (ग) जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।
 (घ) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी का नाम और वर्णन ।
 (ङ) यदि आवश्यक हो तो ".....का परिहार करते हुए" शब्द जोड़ें ।
 (च) वह तारीख लिखिए जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे ।
 (छ) कैदी के कमान आफिसर या अन्य विहित आफिसर के हस्ताक्षर ।

प्रारूप 'ग'

किसी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा आजीवन कारावास के दण्डादेश को कम करके कम अवधि के कारावास का दण्डादेश दिए जाने पर प्रयोग में लाया जाने वाला वारंट (धारा 139)

सेवा में,

अधीक्षक,

(क)कारागार ।

तारीखको(स्थान) में अधिविष्ट (ख)बल न्यायालय द्वारा यूनिट के (भूतपूर्व) संख्यारैंकनामको दिए गए(ग) के दण्डादेश के अनुसरण में(घ) द्वारा जारी किए गए वारंट के अधीन उक्त व्यक्ति(क) कारागार में परिरुद्ध है और(ङ) ने सशस्त्र सीमा बल अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् (च)

आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त(नाम) को विधि द्वारा अपेक्षित रूप में उक्त कारागार में अपनी अभिरक्षा में इस वारंट सहित लें और उसे वहां तब तक रखें जब तक आप उसे उक्त आदेश के अधीन आजीवन कारावास का दण्डादेश भोगने के प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी को उसकी अभिरक्षा में उक्त

वारण्ट सहित न सौंप दें। आपसे यह अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि जिस मूल वारण्ट के बदले यह वारण्ट जारी किया गया है, उसे मुझे लौटा दें।

ऐसे कारावास की अवधि की गणना.....(छ) से की जाएगी।

आज तारीख.....को.....में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (ज)

(क) सिविल कारागार का नाम लिखिए।

(ख) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) मूल दण्डादेश (यदि यह पुष्टिकर्ता आफिसर या अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा घटा कर कम कर दिया गया था तो दण्डादेश इस प्रकार लिया जाना चाहिए “पुष्टिकर्ता आफिसर ने आजीवन कारावास को घटा कर 10 वर्ष कर दिया है”।

(घ) जनरल।

(ङ) दण्डादेश में परिवर्तन करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम।

(च) पूरा आदेश उवर्णित किया जाए।

(छ) वह तारीख लिखें जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ज) विहित आफिसर के हस्ताक्षर।

प्रारूप ‘घ’

जब कैदी को बल की अभिरक्षा में सुपुर्द किया जाना है तब प्रयोग के लिए वारण्ट

सेवा में,

अधीक्षक,

(क).....कारागार।

तारीख.....को.....(स्थान)

में अधिविष्ट (ख).....बल न्यायालय द्वारा.....यूनिट के (भूतपूर्व) संख्या.....रैंक.....

नाम.....को दिए गए.....(ग) के दण्डादेश के अनुसरण में.....(घ) द्वारा जारी किए गए वारण्ट

के अधीन उक्त व्यक्ति.....(क) कारागार में परिरुद्ध है और.....

(ङ) ने सशस्त्र सीमा बल अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् (च).....

आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप अपनी अभिरक्षा से उक्त.....(नाम) के या वारण्ट लाने वाले आफिसर या अधीनस्थ आफिसर को सौंप दें।

आज तारीख.....को.....मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर

(क) सिविल कारागार का नाम लिखिए।

(ख) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) मूल दण्डादेश लिखें (यदि यह पुष्टिकर्ता आफिसर या अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा घटा कर कम कर दिया गया था तो दण्डादेश इस प्रकार लिया जाना चाहिए —“पुष्टिकर्ता आफिसर ने 2 वर्ष के कठिन कारावास को घटाकर एक वर्ष कर दिया है”।

(घ) जनरल, पटी या समरी

(ङ) आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम।

(च) विहित अधिकारी के पूर्ण हस्ताक्षर में अधिकथित हस्ताक्षर

(छ) विहित आफिसर के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट 11

(नियम 186 देखिए)

प्रारूप "क"

मृत्यु दण्डादिष्ट व्यक्ति को कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्द करने के लिए वारण्ट

सेवा में,

अधीक्षक,

(क) कारागार ।

तारीख को मैं अधिविष्ट

(ख) बल न्यायालय ने यूनिट के (सं.)

रैंक नाम को (यहां अपराध का उल्लेख करें) के अपराध के लिए

दोषसिद्ध किया था,

और उक्त (ख) बल न्यायालय ने तारीख को उक्त (नाम) फांसी लगाकर मृत्यु से दंडादिष्ट किया था और मृत्यु के उक्त दण्डादेश की केन्द्रीय सरकार ने पुष्टि कर दी है ।

आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम) को अपनी अभिरक्षा में लें और तारीख को मृत्यु के दण्डादेश का निष्पादन करें ।

आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

हस्ताक्षर (च)

(क) कारागार का नाम लिखें ।

(ख) जनरल ।

(ग) महानिदेशक के हस्ताक्षर ।

प्रारूप 'ख'

मृत्यु से दंडादिष्ट व्यक्ति को ऐसे दण्डादेश के लिए सिविल अभिरक्षा से अभिप्राप्त करने के लिए वारण्ट

सेवा में,

अधीक्षक,

(क) कारागार ।

अधिविष्ट (ख) बल न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड भोगने के लिए दण्डादिष्ट किए जाने पर यूनिट के (भूतपूर्व) (संख्या) रैंक नाम को, (ग) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त कारागार में रखा गया है ।

और उक्त दण्डादेश की (घ) द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित रूप से सम्यक्तः पुष्टि कर दी जाने पर उक्त दंडादेश का निष्पादन करने के लिए मुझे (ड.) (नाम और रैंक) आदेश जारी किया गया है ।

आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम) को यह वारण्ट लाने वाले आफिसर या अधीनस्थ आफिसर/अवर आफिसर को तत्काल सौंप दें ।

आज तारीख को मैं मेरे हस्ताक्षर से दिया गया है ।

(क) सिविल कारागार का नाम लिखिए ।

(ख) जनरल ।

(ग) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे ।

(घ) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी का नाम और वर्णन

(ड.) उस आफिसर का नाम और पदनाम लिखें जिसे आदेश जारी किया गया है ।

(च) उस आफिसर के हस्ताक्षर जिसने आदेश जारी किया है ।

प्रारूप 'ग'

मृत्यु के दंडादेश का निष्पादन करने के लिए वारण्ट

सेवा में,

उप महानिरीक्षक.....

तारीख.....को.....में अधिविष्ट

(का).....बल न्यायालय ने.....बटालियन/यूनिट के

(सं.).....रैंक.....नाम.....को.....(यहां अपराध का संक्षेप में उल्लेख करें) के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया था,

और उक्त (ख).....बल न्यायालय ने तारीख.....को उक्त.....(नाम) की गोली मार कर मृत्यु से दण्डादिष्ट किया था और मृत्यु के उक्त दण्डादेश की केन्द्रीय सरकार ने पुष्टि कर दी है।

आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप मृत्यु के दण्डादेश की तारीख.....को निष्पादन करें।

आज तारीख.....को.....मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (ख)

(क) जनरल।

(ख) महानिरीक्षक के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट 12

(नियम 167 देखिए)

प्रारूप "क"

जब मृत्यु से दंडादिष्ट और सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्द किसी व्यक्ति का दण्डादेश आजीवन कारावास के दण्डादेश में लघुकरण कर दिया जाता है तब प्रयोग में लाया जाने वाला वारण्ट

सेवा में,

अधीक्षक,

(क).....कारागार।

तारीख.....को.....(स्थान)

में अधिविष्ट (ख).....बल न्यायालय द्वारा.....यूनिट के (भूतपूर्व) संख्या.....रैंक.....नाम.....को दिए गए.....(ग) के दण्डादेश के अनुसरण में.....(ग) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति को.....कारागार में रखा गया है और.....

(घ) ने सशस्त्र सीमा बल अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात्

(ङ).....

आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त.....(नाम) को विधि द्वारा अपेक्षित रूप में उक्त कारागार में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट सहित लें और उसे वहां तब तक रखें जब तक आप उसे उक्त आदेश के अधीन आजीवन कारावास का दण्डादेश भोगने के प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी को उसकी अभिरक्षा में उक्त वारण्ट सहित न सौंप दें। आपसे यह भी अपेक्षा है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि जिस मूल सुपुर्दगी वारण्ट के बदले में यह वारण्ट जारी किया गया है, उसे मुझे लौटा दें। ऐसे आजीवन कारावास की अवधि की गणना तारीख (च) से की जाएगी।

आज तारीख.....को.....में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (छ)

- (क) सिविल कारागार का नाम लिखिए ।
 (ख) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे ।
 (ग) जनरल ।
 (घ) दण्डादेश का लघुकरण करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम ।
 (ङ.) पूरा आदेश उपवर्णित किया जाए ।
 (च) वह तारीख लिखें जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे ।
 (छ) कमान आफिसर के हस्ताक्षर ।

प्रारूप "ख"

जब मृत्यु के दण्डादेश के अधीन और सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति का दण्डादेश, कारावास के ऐसे दण्डादेश में लघुकरण कर दिया जाता है जिसे उसी कारागार में भुगतना है तब प्रयोग में लाया जाने वाला वारण्ट । सेवा में,

अधीक्षक,

(क).....कारागार ।

तारीख.....को(स्थान)

मैं अधिविष्ट (ख).....बल न्यायालय द्वारा.....यूनिट के (भूतपूर्व) संख्या रैंक
 नाम.....को दिए गए मृत्यु के दण्डादेश के अनुसरण में(ग) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन
 उक्त व्यक्ति को.....(क) कारागार में रखा गया है और(घ) ने सशस्त्र सीमा बल
 अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात्
 (ङ.).....

आपसे और अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त.....(नाम) को वारण्ट सहित अपनी अभिरक्षा में रखें और उक्त आदेश के अधीन कारावास के दंड का निष्पादन विधि के अनुसार करें ।

और आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि सुपुर्दगी के जिस मूल वारण्ट के बदले में यह वारण्ट जारी किया गया है उसे मुझे लौटा दें । ऐसे कारावास की अवधि की गणना (च).....से की जाएगी ।

आज तारीख.....कोमें मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

हस्ताक्षर (छ)

- (क) सिविल कारागार का नाम लिखिए ।
 (ख) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे ।
 (ग) जनरल ।
 (घ) दण्डादेश का लघुकरण करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम ।
 (ङ.) पूरा आदेश उपवर्णित किया जाए ।
 (च) वह तारीख लिखें जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे ।
 (छ) कमान आफिसर के हस्ताक्षर ।

प्रारूप "ग"

जब मृत्यु से दंडादिष्ट किए जाने के पश्चात् सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्द किसी व्यक्ति को मृत्यु दण्डादेश का निष्पादन करने से भिन्न प्रयोजन के लिए बल की अभिरक्षा में सौंपा जाना है तब प्रयोग में लाया जाने वाला वारण्ट । सेवा में,

अधीक्षक,

(क).....कारागार ।

तारीख.....को(स्थान)

मैं अधिविष्ट (ख).....बल न्यायालय द्वारा.....यूनिट के (भूतपूर्व) संख्या रैंक
 नाम.....को दिए गए मृत्यु के दण्डादेश के अनुसरण में(ग) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन
 उक्त व्यक्ति को(क) कारागार में रखा गया है और

(घ) ने सशस्त्र सीमा बल अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् (ड.)

आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम) को इस वारण्ट को लाने वाले आफिसर/अधीनस्थ आफिसर को तुरंत सौंप दें।

आज तारीख को में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (च)

(क) सिविल कारागार का नाम लिखिए।

(ख) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) जनरल।

(घ) आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम।

(ड.) पूरा आदेश उपवर्णित किया जाए।

(च) कमान आफिसर के हस्ताक्षर।

प्रारूप "घ"

जब कैदी को क्षमा कर दिया जाता है या उसका विचारण अपास्त कर दिया जाता है या जब पूर्ण दण्डादेश या उसके भाग का परिहार कर दिया जाता है, तब प्रयोग में लाया जाने वाला वारण्ट (धारा 139)।

सेवा में,

अधीक्षक,

(क) कारागार।

तारीख को स्थान

में अधिविष्ट (ख) बल न्यायालय द्वारा यूनिट के (भूतपूर्व) संख्या रैंक नाम को दिए गए मृत्यु के दण्डादेश के अनुसरण में (ग) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन

उक्त व्यक्ति को (क) कारागार में परिरुद्ध है और (ड.) ने सशस्त्र सीमा बल अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् (च)

आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम) को जब तक वह किसी अन्य कारण से निरुद्ध किए जाने के दायित्वाधीन न हो, अपनी अभिरक्षा से तत्काल उन्मोचित कर दें और उसे इस प्रकार उन्मोचित करने के लिए यह आपके लिए वारण्ट होगा।

आज तारीख को में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (छ)

(क) सिविल कारागार का नाम लिखिए।

(ख) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) मूल दण्डादेश लिखें (यदि यह पुष्टिकर्ता आफिसर या अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा घटा कर कम कर दिया गया था तो दण्डादेश इस प्रकार लिया जाना चाहिए) —“पुष्टिकर्ता आफिसर ने 2 वर्ष के कठिन कारावास को घटाकर एक वर्ष कर दिया है”।

(घ) जनरल पेटी और (या) समरी।

(ड.) कैदी को क्षमा दंडादेश का कम या विचारण को अपास्त करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम।

(च) पूरा आदेश उपवर्णित किया जाए।

(छ) विहित आफिसर के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट 13

[नियम 176(2)(क)(ii) देखिए]

अप्राकृतिक मृत्यु के बारे में रिपोर्ट

1. मृत्यु का स्थान या वह स्थान जहाँ शव मिला था (ब्योरा दीजिए) ।
 2. मृत्यु की जानकारी प्राप्त होने की तारीख और समय ।
 3. शव की पहचान करने वाले दो या अधिक व्यक्तियों के नाम और वर्णन ।
 4. मृतक का नाम और उसकी विशिष्टियाँ और उसकी प्रास्थिति ।
 5. मृतक द्वारा पहने हुए कपड़ों की दशा ।
- टिप्पण:** यदि डाक्टर द्वारा परीक्षा की जानी है तो उक्त ब्योरा, मृतक के कपड़े आदि हटाए बिना एकत्र किए जाएं, और अन्य ब्योरे डाक्टर की परीक्षा के पश्चात् पूरे किए जाने चाहिए ।
6. अंग, नेत्र और मुँह की दशा ।
 7. मुख की मुद्रा ।
 8. शव पर संघर्ष के चिन्हों, यदि कोई है, क्षतियों और खरोंचों को, उनका आकार और उनकी अवस्थिति बताते हुए अभिलिखित किया जाना चाहिए ।
- टिप्पण:** क्षति की गहराई अभिलिखित की जानी चाहिए किंतु क्षतियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए । यदि डाक्टर द्वारा परीक्षा की जानी है तो उपर्युक्त जानकारी उसके द्वारा परीक्षा के पश्चात् अभिलिखित की जानी चाहिए ।
9. रक्त तरल है या स्कन्दित है । वह किस स्थान से और कितनी मात्रा में निकाला है ।
 10. किस साधन, शस्त्र या उपकरण से क्षति या संघर्ष के चिन्ह कारित किए गए प्रतीत होते हैं ।
 11. क्या कोई रस्सी गर्दन के चारों ओर बंधी हुई थी या उसके चारों ओर किसी चीज से बंधे जाने का कोई चिन्ह है ।
 12. क्या रस्सी या किसी अन्य चीज का प्रयोग गला घोटने या शव को लटकाने के लिए किया गया था, क्या वह वजन संभालने के लिए काफी मजबूत थी और क्या इसका दूसरा सिरा किसी चीज से बंधा हुआ था ?
 13. क्या घास जैसे बाहरी पदार्थ बालों में लगे हुए थे या उसके हाथ में थे या उसके शरीर के किसी अन्य भाग में चिपके हुए थे ।
 14. क्या शव किसी दृष्टपुष्ट और सुगठित आदमी का है या वह किसी कमजोर या वृद्ध आदमी का है ।
 15. क्या शव मजबूत है या कमजोर है या उसमें सड़न पैदा हो गई है ।
 16. सिर से पाँव तक शव की लम्बाई ।
 17. पहचान चिन्ह और घावों की अवस्थिति और उनका आकार ।
 18. मृत्यु का दृश्यमान कारण ।
 19. क्या कोई ऐसी अफवाह या ऐसी अन्य परिस्थितियाँ हैं जिनसे यह दर्शित होता है कि यह आत्महत्या का मामला है । शव पर या उसके समीप पड़ी हुई मिली वस्तुओं के ब्योरे ।
 20. शव पर मिली वस्तुएं (प्रत्येक वस्तु पर एक पर्ची चिपकाई जाएगी जो स्टाम्पित होगी) ।
 21. शव के समीप पड़ी हुई मिली वस्तुएं (प्रत्येक वस्तु पर सम्यक् रूप से स्टाम्पित पर्ची चिपकाई जाएगी) ।
 22. उस स्थान का नक्शा जहाँ शव मिला था

मामले का संक्षिप्त विवरण ।

परिक्षेत्र के ऐसे दो या अधिक प्रतिष्ठित साक्षियों के हस्ताक्षर जिनकी उपस्थिति में अन्वेषण किया गया था ।

मामले का अन्वेषण करने वाले आफिसर के हस्ताक्षर

रैंक.....

नाम.....

स्थान:.....

तारीख:.....

परिशिष्ट 14

(नियम 47 व 48 देखिए)

प्रारूप 1

आफिसरों और अधीनस्थ आफिसरों के संक्षिप्त विचारण में प्रयोग के लिए प्रारूप (धारा 58)

अभियुक्त
 रैंक और नाम
 यूनिट

जब मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी (अभियुक्त की लिखित सहमति से) साक्षियों को हाजिरी से अभिमुक्ति देने का विनिश्चय करता है, तब अभियुक्त से पूछे जाने वाले प्रश्न —

1. क्या आपने आरोप-पत्र और अभिलेख या साक्ष्य के सार की प्रति प्राप्त कर ली है ? उत्तर
 2. क्या आपके पास अपनी प्रतिक्षा की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय है ? उत्तर
 3. आरोप-पत्र पढ़ा जाता है। क्या आप अपने विरुद्ध लगाए गए उन आरोप/उन आरोपों के, जो आपने सुने/पढ़े हैं, दोषी हैं या दोषी नहीं हैं ? उत्तर
- अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा अनुज्ञात करते हुए साक्षी अपना साक्ष्य दे। उत्तर
4. क्या आप कोई कथन करना चाहते हैं ? उत्तर

यदि अभियुक्त कोई कथन करना चाहता है तो उसे इस समय ऐसे करना चाहिए। यदि मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी सुनवाई की समाप्ति पर यह समझता है कि आरोप खारिज नहीं किया जाना चाहिए, तो उसे अभियुक्त के सेवा अभिलेख या आचरण पत्र की जांच करनी है।

यदि मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी, धिग्दण्ड, तीव्र धिग्दण्ड या शास्तिक कटौतियों से भिन्न कोई दण्ड अधिनिर्णीत करने की प्रस्थापना करता है तो वह अभियुक्त से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा:—

5. क्या आप चाहते हैं कि आपका विचारण न्यायालय द्वारा किया जाए या मेरा अधिनिर्णय स्वीकार करेंगे ? उत्तर

निष्कर्ष.....

अधिनिर्णय.....

स्टेशन.....

तारीख.....

टिप्पण: प्रश्न 4 के उत्तर में अभियुक्त का मौखिक कथन अभिलिखित नहीं किया जाएगा। यदि अभियुक्त ने लिखित कथन प्रस्तुत किया है तो ऐसा कथन ही इस प्रारूप के साथ तब भेजा या संलग्न किया जाएगा जब अभिलेख या साक्ष्य के भार की प्रति इस प्रकार भेजी या संलग्न की जानी अपेक्षित है। यह प्रारूप अधीनस्थ आफिसर/आफिसर की गोपनीय चरित्र पुस्तिका के साथ रखा जाएगा।

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

अन्वेषण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रारूप 2

आफिसरों और अधीनस्थ आफिसरों के संक्षिप्त विचारण में प्रयोग के लिए प्रारूप (धारा 58)

अभियुक्त
 रैंक और नाम
 यूनिट

जब मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी साक्षियों को हाजिरी से अभियुक्ति देने का विनिश्चय नहीं करता है या जब अभियुक्त उनकी हाजिरी की अपेक्षा करता है, तब अभियुक्त से पूछे जाने वाले प्रश्न :

1. क्या आपने आरोप-पत्र और अभिलेख या साक्ष्य के सार की प्रति प्राप्त कर ली है ? उत्तर
2. क्या आपके पास अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय था । उत्तर
3. क्या आप अपने विरुद्ध लगाए गए उन आरोप/उन आरोपों के, जो आपने सुने/पढ़े हैं, दोषी हैं या दोषी नहीं हैं ? उत्तर
साक्षी अपना साक्ष्य देते हैं। अभियुक्त को उनकी प्रति परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है ।
4. क्या आप कोई कथन करना चाहते हैं ? उत्तर
5. क्या आप किसी साक्षी को बुलाना चाहते हैं ? उत्तर

अभियुक्त कथन करता है और उसके साक्षी देते हैं । यदि मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी सुनवाई की समाप्ति पर यह समझता है कि आरोप खारिज नहीं किया जाना चाहिए, तो उसे अभियुक्त का सेवा अभिलेख या आचरण पत्र की परीक्षा करनी है ।

यदि मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी, धिग्दण्ड, तीव्र धिग्दण्ड या शास्तिक कटौतियों से भिन्न कोई दण्ड अधिनिर्णीत करने की प्रस्थापना करता है तो वह अभियुक्त से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा:-

6. क्या आप यह चाहते हैं कि आपका विचारण न्यायालय द्वारा किया जाए, या आप मेरा अधिनिर्णय स्वीकार करेंगे ? उत्तर
निष्कर्ष.....
अधिनिर्णय.....
स्टेशन.....
तारीख.....

टिप्पण: प्रश्न 4 के उत्तर में अभियुक्त का मौखिक कथन अभिलिखित नहीं किया जाएगा । यदि अभियुक्त ने लिखित कथन प्रस्तुत किया है तो ऐसा कथन ही इस प्रारूप के साथ तब भेजा या संलग्न किया जाएगा जब अभिलेख या साक्ष्य के भार की प्रति इस प्रकार भेजी या संलग्न की जानी अपेक्षित है । यह प्रारूप अधीनस्थ आफिसर/आफिसर की गोपनीय चरित्र पुस्तिकों के साथ रखा जाएगा ।

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

अन्वेषण अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 15

[51(7), 67 और 175(7) देखिए]

साक्षियों को समन करने का प्रारूप

(क) साक्ष्य के अभिलेख की दशा में -

बल न्यायालय द्वारा विचारणीय सं. रैंक नाम

यूनिट के विरुद्ध अपराध का आरोप मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है और मैंने तारीख को बजे स्थान पर लिखित साक्ष्य का अभिलेख लेने का निदेश दिया है । मैं आपको (नाम) समन करता हूँ और उक्त स्थान और समय पर साक्षी के रूप में उपस्थिति होने की (और अपने साथ इसके पश्चात् वर्णित दस्तावेज अर्थात् लाने की) अपेक्षा करता हूँ । यदि ऐसा करने में आप असफल रहते हैं तो यह आप अपने जोखिम पर करेंगे ।

आज तारीख 20 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

हस्ताक्षर

अभियुक्त का कमान आफिसर

(ख) बल न्यायालय की दशा में —

यूनिट के श्री के विचारण के लिए तारीख को स्थान पर बजे बल न्यायालय को समवेत होने का आदेश दिया गया है। मैं आपको क ख को समन करता हूँ और उक्त न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में तारीख को बजे स्थान पर उपस्थित होने की (और अपने साथ इसमें इसके पश्चात् वर्णित दस्तावेज अर्थात् लाने की) तथा इस प्रकार दिन प्रतिदिन की कार्रवाई में तब तक उपस्थित होने की जब तक आप सम्यक् रूप से उन्मोचित नहीं कर दिए जाते, अपेक्षा करता हूँ। यदि ऐसा करने में आप असफल रहते हैं तो यह आप अपने जोखिम पर करेंगे। आज तारीख 20 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर

संयोजक आफिसर (या जज अटर्नी या
न्यायालय का पीठासीन आफिसर या
अभियुक्त का कमान आफिसर)

(ग) जांच न्यायालय की दशा में —

तारीख को स्थान पर जांच न्यायालय को उन परिस्थितियों को जिनमें जांच करने के लिए समवेत होने का आदेश दिया गया है।

मैं आपको क ख के उक्त जांच न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में तारीख को बजे उपस्थित होने की (और इसमें इसके पश्चात् वर्णित दस्तावेज अर्थात् अपने साथ लाने की) तथा इस प्रकार दिन प्रतिदिन कार्रवाई में तब तक उपस्थित होने का जब तक आप सम्यक् रूप से उन्मोचित नहीं कर दिए जाते, अपेक्षा करता हूँ। यदि ऐसा करने में आप असफल रहते हैं तो यह आप अपने जोखिम पर करेंगे।

आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर

पीठासीन आफिसर या यूनिट का
कमान आफिसर

फा. सं.

नाम

पदनाम

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2009.

G.S.R. 560(E).—In exercise of the powers conferred by Section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application.— (1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to all persons subject to the Act :

Provided that the provisions of Chapter-IV thereof shall not apply to persons belonging to the All India Services and other Government servants who are on deputation with the Sashastra Seema Bal :

Provided further that the officers on deputation shall have the option to get their trial or enquiry conducted either under the provisions of the Act and rules or the provisions of their respective service Act and rules being specific in nature.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires, —

- (a) "Act" means the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007);
- (b) "Appendix" means an Appendix annexed to these rules;
- (c) "Appointment" means appointment of a person to the Force and includes enrolment;
- (d) "Commandant" means a person appointed by the Central Government as a Commandant to the Force under section 5;
- (e) "Court" means the Force Court as defined in section 76 of the Act;
- (f) "Detachment" includes any part of a battalion or a unit of the Force required or ordered to proceed on duty away from headquarters;
- (g) "Force authority" when used in relation to any power, duty, act or matter, means such authority as, in pursuance of these rules exercises, or performs that power or duty or is concerned with that matter;
- (h) "section" means a section of the Act;
- (i) all other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

3. Reports and applications.— Any report or application required to be made under these rules to a superior authority or to a Force authority shall be made in writing through proper channel unless the said authority on account of exigencies of service or otherwise, dispenses with the writing.

4. Forms of appendixes.— (1) The Forms set forth in the appendixes, with such variations as the circumstances of each case may require, may be used for the respective purposes therein mentioned, and if used shall be sufficient, but a deviation from such Forms shall not, by reason only of such deviation, render invalid any charge, warrant, order, proceedings or any other document relevant to these rules.

(2) Any omission of any such Form shall not, by reason only of such omission, render any act or thing invalid.

(3) The directions in the notes to and the instructions in the Form shall be duly complied with in all cases to which they relate but any omission to comply with any such direction in the notes or instructions shall not, merely by reason of such omission, render any act or thing invalid.

5. Exercise of power vested in holder of an office in the Force.— Any power or jurisdiction given to any person, holding any office in the Force to any act or thing to, or before, any person, may, for the purposes of these rules, be exercised, by any other person who may, for the time being, be performing the functions of that office in accordance with the rules and practice of the Force.

6. Case un-provided for.— In regard to any matter not specifically provided for in these rules, it shall be lawful for the competent authority to do such thing or take such action as he may deem fit in accordance with exigencies and circumstances of the Case.

CHAPTER II

ORGANISATION

7. Constitution of the Force.—(1) The Sashastra Seema Bal shall consist of Sashastra Seema Bal (Regular).

(2) Officers, subordinate officers and enrolled persons appointed to or enrolled into the Sashastra Seema Bal (Regular) shall be liable for continuous service for the term mentioned in their enrolment form, letter of appointment or in the rules made in this behalf.

8. Ranks.—(1) The officers and other members of the Force shall be classified in accordance with their ranks in the following categories, namely:—

(a) Officers—

- (i) Director-General.
- (ii) Additional Director-General.
- (iii) Inspector-General.
- (iv) Deputy Inspector-General.
- (v) Commandant.
- (vi) Second-in-Command.
- (vii) Deputy Commandant.
- (viii) Assistant Commandant.

(b) Subordinate Officers—

- (i) Subedar Major
- (ii) Inspector
- (iii) Sub-Inspector.
- (iv) Assistant Sub-Inspector.

(c) Under Officers—

- (i) Head Constable
- (ii) Naik
- (iii) Lance Naik

(d) Enrolled persons other than Under Officers—

- (i) Constable.
- (ii) Enrolled followers.

(2) Matters relating to Inter-se seniority of persons belonging to the same rank shall be determined in accordance with such rules as may be made in this behalf.

(3) Notwithstanding any thing contained in these rules, the Director General may, subject to confirmation by the Central Government as provided hereinafter, grant to an officer or Inspector of the Force a rank, mentioned in clause (a) of sub-rule (1), as a local rank, whenever considered necessary by him in the interest of better functioning of the Force.

(4) An officer or Inspector of the Force holding a local rank,—

- (a) shall exercise the command and be vested with the powers of an officer holding that rank;
- (b) shall cease to hold that rank, if the grant of such rank is not confirmed within one month by the Central Government or when so ordered by the Director-General or when he ceases to hold the appointment for which the rank was granted;
- (c) shall not be entitled to any extra pay and allowances for holding such rank; and
- (d) shall not be entitled to claim any seniority over other officers of the Force by virtue of having held such rank.

9. The task of the Force, Command and Control thereto.—(1) For the purpose of sub-section (1) of section 4, the Force shall in area of its responsibility,—

- (i) safeguard the security of assigned borders of India and promote sense of security among the people living in border area;
- (ii) prevent trans-border crimes, smuggling and any other illegal activity.
- (iii) prevent unauthorised entry into or exit from the territory of India;
- (iv) to carry out civic action programme in the area of responsibility;
- (v) to perform any other duty assigned by the Central Government.

(2) In discharging the functions under sub-rule (1), the responsibility for the command, discipline, administration, morale and training shall,—

- (a) in the case of Additional Director-General extend to all battalions, units, headquarters, establishments and Force Personnel placed under him and within the area that may be assigned to him;
- (b) in the case of Inspector-General extend to all battalions, units, headquarters, establishments and the Force Personnel placed under him and within the area that may be assigned to him;
- (c) in the case of Deputy Inspector-General extend to battalions, units and other personnel placed under him and within the area that may be assigned to him;
- (d) in the case of Commandant extend to the battalion or unit placed under him and within the area assigned to him.

(3) During hostilities, the Additional Director-General, the Inspector General, the Deputy Inspector-General and the Commandant shall discharge such functions as may be assigned by their respective superiors.

(4) The command, discipline, administration, morale and training of battalion, units and establishment not placed under a Deputy Inspector-General or an Inspector-General shall be carried out by such officers and in such manner as may be laid down by the Director-General from time to time.

(5) Any member of the Force shall be liable to perform any duties in connection with the task of the Force mentioned in sub-rule (1) above, the administration, discipline, training and welfare of the Force and such other duties as he may be called upon to perform in accordance with any law for the time being in force and any order given in this behalf by a superior officer shall be a lawful command for the purpose of the Act.

10. Command.—(1) An officer appointed to command shall have the power of command over all officers and men, irrespective of seniority placed under his command.

- (2)(a) In the contingency of an officer being unable to exercise the command, to which he has been appointed, due to any reason, the command shall devolve on the second-in-command, if one has been so appointed.
- (b) If no second-in-command has been appointed, it shall devolve, on the officer who may be appointed to officiate by the immediate superior of the officer unable to exercise command.
- (c) If no such officer has been so appointed, command shall devolve on the seniormost officer present.
- (d) The inability of an officer to exercise command and its assumption by any other officer in accordance with this sub-rule shall be immediately reported to the next higher authority by the officer who has assumed command.

(3) If persons belonging to different battalions and units are working together :—

- (i) in regard to the specific task on which they are engaged, the officer appointed to command or in his absence the seniormost officer present shall exercise command over all such persons;
- (ii) in all other matters the senior officer belonging to each battalion or unit shall exercise command over persons belonging to his battalion or unit, as the case may be.

(4) When officers and other persons belonging to the Force are taken prisoner by an enemy, the existing relations of superior and subordinate and the duty of obedience shall remain unaltered and any person guilty of indiscipline or insubordination in this behalf shall, after his release, be liable for punishment.

(5) Subject to the provisions of the Act, disciplinary powers over a person subject to the Act shall be exercised by the Commandant of the battalion or unit to which such a person belongs or the officer on whom command has devolved in accordance with sub-rule (2).

(6) Where such a person is doing detachment duty, including attendance at a course of instruction the Commandant of the battalion, unit, centre or establishment with which he is doing such duty shall also have all the disciplinary power of a Commandant.

(7) The Director-General, the Additional Director-General, the Inspector-General and the Deputy Inspector-General may specify one or more officers of the staff who shall exercise the disciplinary powers of a Commandant in respect of persons belonging to or doing detachment duty at their respective Headquarters.

(8) The Director-General may also specify officers who shall exercise the disciplinary powers of an Inspector-General or Deputy Inspector-General respectively in respect of persons belonging to or doing detachment duty at his headquarters.

(9) An Inspector-General may specify an officer who shall exercise the disciplinary powers of a Deputy Inspector-General in respect of persons belonging to or doing detachment duty at his headquarters.

Explanation.— In this rule, except in sub-rule (2) the word “officer” shall include a subordinate officer and an under officer.

CHAPTER III RECRUITMENT

11. Ineligibility.— (1) No person, who has more than one wife living or who having a spouse living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment, enrolment, or employment in the Force.

(2) Any person subject to the Act, who contracts or enters into a second marriage during the life time of his first spouse shall render himself ineligible for retention in service and may be dismissed, removed or retired from service on ground of unsuitability :

Provided that the Central Government may, if satisfied that there are sufficient grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

12. Ineligibility of aliens.— No person who is not a citizen of India shall, except with the consent of the Central Government signified in writing, be appointed, enrolled or employed in the Force.

13. Appointment of officers.— The Central Government may appoint such persons as it considers to be suitable as officers in the Force in the following manner, and their conditions of service shall be such as may be provided in the rules made in this behalf by the Central Government :

- (a) by direct recruitment;
- (b) by transfer on deputation from the All India Services, Defence Forces, any other Armed Forces of the Union, State Police, any other department of the Central Government or of the State Government or autonomous bodies;
- (c) by promotion as may be prescribed from time to time;
- (d) by transfer;
- (e) by re-employment.

14. Appointment of Subordinate Officers and Enrolled Persons.— Appointment to the posts of Subedar-Majors or Inspectors may be made by the Inspector-General; Sub-Inspector or Assistant Sub-Inspector by the Deputy Inspector-General; under officers and enrolled persons by the Commandant or any other officer of the Force who may be appointed as enrolling officer by the Director-General, respectively in the following manner and their conditions of service shall be such as may be provided in the rules by the Central Government in this behalf:

- (a) by direct recruitment ;
- (b) by transfer on deputation from the Defence Forces, any other Armed Forces of the Union, State Police, any other department of the Central Government or of the State Government or autonomous bodies;
- (c) by promotion as may be prescribed from time to time;
- (d) by transfer;
- (e) by re-employment.

15. Probation.— (1) A person appointed through direct recruitment as an officer, subordinate officer, under officer or enrolled person shall be on probation for a period of two years.

(2) The Central Government in the case of officers and the authority prescribed in rule 14, in the case of subordinate officers, under officer and enrolled persons may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period of probation for such further period or periods not exceeding two years or may during the period of probation, terminate his services without assigning any reasons.

(3) The provision of sub-rules (1) and (2) shall also be applicable to a person on his initial promotion as an officer and persons who do not complete the period of probation satisfactorily are liable to be reverted to their former rank.

16. Procedure for enrolment, mode of enrolment and other matters connected therewith.— (1) Before a person is enrolled as a member of the Force, the Commandant of a unit or any other officer who may be detailed as an enrolling officer by the Director-General, shall read and explain to him, or cause to be read and explained to him in his presence, the conditions of service of the post to which he is to be enrolled and shall put to him the questions contained in the form of enrolment as set out in Appendix I and shall, after having cautioned him that if he makes a false answer to any such question he shall be liable to punishment under the Act, record or cause to be recorded his answer to each such question.

(2) If, after complying with the provisions of sub-rule (1) and such other directions as may be issued in this behalf by the Director-General from time to time, the enrolling officer is satisfied that the person desirous of being enrolled, fully understands the questions put to him and consents to the condition of service, and if the said officer is satisfied that there is no impediment, he shall sign and shall also cause such person to sign the enrolment form and such person shall thereupon be deemed to be enrolled.

(3) (a) Every person enrolled as a member of the Force under sub-rule (2) shall be administered an oath or affirmation in the form set out in Appendix I.

(b) The oath or affirmation shall as far as possible be administered by an officer not below the rank of Commandant or an officer authorised in writing by such officer in this behalf.

(c) The oath or affirmation shall be administered when the person to be attested has completed his training.

17. Liability of Service.— (1) All Officers are liable for service with any other Armed Force of the Union as may be directed by the Government and in selecting Officers for such service, preference may be given to volunteers but if the requisite number of suitable volunteers is not forthcoming Officers may be sent on transfer on deputation or detailed otherwise as considered necessary, by the Central Government.

(2) The provisions of this rule shall apply to and in relation to subordinate officers and enrolled persons as they apply to and in relation to any officer of the Force and the powers vested in the Central Government under sub-rule (1) shall be exercised by the Director-General.

CHAPTER IV TERMINATION OF SERVICE

18. Termination of service.— Authorities specified in the headings of columns (3) to (6) of the Table given below shall be competent to dismiss, remove, discharge, retire or release or any other punishment specified under the Act by a member of the Force specified in the columns, on the grounds stated in the corresponding entries in column (2), in accordance with the procedure laid down in this chapter and any power conferred by this rule or any provision of this Chapter on any of the aforesaid authorities may also be exercised by any other authority superior to it:

Provided that the provisions of this Chapter shall not apply to the persons on deputation with the Force.

TABLE

Sl. No.	Grounds on which service can be terminated	Central Government	Inspector-General	Deputy Inspector-General	Commandant
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i)	Misconduct.	Officers	Sub-Major/ Inspector.	Sub-Inspector/ Asstt. Sub-Inspector.	Under Officers/ Enrolled Person.
(ii)	Unsuitability.	Officers	Sub-Major/ Inspector.	Sub-Inspector/ Asstt. Sub-Inspector.	Under Officers/ Enrolled person.
(iii)	Unsatisfactory progress in training.	Officers	Sub-Major/ Inspector.	Sub-Inspector/ Asstt. Sub-Inspector.	Under Officers/ Enrolled person.
(iv)	Furnishing false/ wrong information at the time of appointment.	Officers	Sub-Major/ Inspector.	Sub-Inspector/ Asstt. Sub-Inspector.	Under Officers/ Enrolled person.
(v)	Physical unfitness.	Officers	Sub-Major/Inspector	Sub-Inspector/ Asstt. Sub-Inspector	Under Officers/ Enrolled person.
(vi)	On own request	Officers	Sub-Major/Inspector	Sub-Inspector/ Asstt. Sub-Inspector.	Under Officers/ Enrolled person.

19. Termination of service of officers by the Central Government on account of misconduct.—(1) When it is proposed to terminate the service of an officer under section 10 on account of misconduct, he shall be given an opportunity to show cause in the manner specified in sub-rule (2) against such action:

Provided that this sub-rule (1) shall not apply :—

- (a) where the service is terminated on the ground of misconduct which has led to his conviction by a criminal court or a Force court; or
- (b) where the Central Government is satisfied that for reasons to be recorded in writing, it is not expedient or reasonably practicable to give to the officer an opportunity of showing cause.

(2) When after considering the reports of an officer's misconduct, the Central Government or the Director-General is satisfied that the trial of the officer by a Force Court is inexpedient or impracticable, but is of the opinion, that the further retention of the said officer in the service is undesirable, the Director-General shall so inform the officer together with particulars of allegations and report of investigation (including the statement of witnesses, if any, recorded and copies of documents, if any, intended to be used against him) in cases where allegations have been investigated and he shall be called upon to submit in writing, his explanation and defence:

Provided that the Director-General may withhold disclosure of such report or portion thereof if, in his opinion, its disclosure is not in the interest of the security of the State.

(3) In the event of the explanation of the officer being considered unsatisfactory by the Director-General, or when so directed by the Central Government, the case shall be submitted to the Central Government with the officer's defence and the recommendation of the Director-General as to the termination of the Officer's service in the manner specified in sub-rule (4).

(4) When submitting a case to the Central Government under the provisions of sub-rule (2) or sub-rule (3), the Director-General shall make his recommendation whether the officer's service should be terminated, and if so, whether the officer should be :

- (a) dismissed from the service; or
- (b) removed from the service; or
- (c) retired from the service; or
- (d) called upon to resign.

(5) The Central Government, after considering the reports and the officer's defence, if any, or the judgment of the criminal court, as the case may be, and the recommendation of the Director-General, may remove or dismiss the officer or retire or get his resignation from service, and on his refusing to do so, the officer may be compulsorily retired or removed from the service.

20. Termination of service of officers by the Central Government on grounds of unsuitability.—(1) When the Director General is satisfied that an officer is unsuitable to be retained in service, the officer—

- (a) shall be so informed;
- (b) shall be furnished with the particulars of all matters adverse to him; and
- (c) shall be called upon to urge any reasons he may wish to put forward in favour of his retention in the service :

Provided that clauses (a), (b) and (c) shall not apply, if the Central Government is satisfied that for reasons, to be recorded by it in writing, it is not expedient or reasonably practicable to comply with the provisions thereof:

Provided further that the Director-General may not furnish to the officer any matter adverse to him, if in his opinion, it is not in the interest of the security of the State to do so.

(2) In the event of the explanation being considered by the Director-General unsatisfactory, the matter shall be submitted to the Central Government for orders, together with the officer's explanation and the recommendation of the Director-General.

(3) The Central Government after considering the reports, the explanation, if any, of the officer and the recommendation of the Director-General, may call upon the officer to retire or resign and on his refusing to do so, the officer may be compulsorily retired from the service.

21. Termination of service of persons, other than officers on account of misconduct.—(1) When it is proposed to terminate the service of a person subject to the Act other than an officer, he shall be given an opportunity by the authority competent to dismiss or remove him to show cause in the manner specified in sub-rule (2) against such action :

Provided that this sub-rule shall not apply :—

- (a) where the service is terminated on the ground of conduct which has led to his conviction by a criminal court or Force Court; or
- (b) where the authority as specified in rule 18 is satisfied that, for reasons to be recorded in writing, it is not expedient or reasonably practicable to give the person concerned an opportunity of showing cause.

(2) When after considering the reports on the misconduct of the person concerned, the authority as specified in rule 18 is satisfied that the trial of such a person by the Force Court is inexpedient or impracticable, but is of the opinion, that his further retention in the service is undesirable, it shall so inform him together with all reports adverse to him and he shall be called upon to submit, in writing, his explanation and defence :

Provided that the authority as specified in rule 18 may withhold from disclosure any such report or portion thereof, if in his opinion, its disclosure is not in the interest of security of the state.

(3) The authority as specified in rule 18 after considering his explanation and defence, if any, or the judgment of the criminal court, as the case may be, may dismiss or remove him from the service.

(4) All cases of dismissal or removal, under this rule, shall be reported to the Director-General.

22. Discharge from service on grounds of unsatisfactory progress in training.—(1) When it is proposed to discharge a person subject to the Act from service on account of unsatisfactory progress in training, the Commanding Officer of training establishment, where the person is undergoing training, shall make recommendation for suitable action to the Commanding Officer of the Battalion/Unit to which such person belongs for his discharge from service.

(2) In all cases of recommendations for discharge of a person, the Commanding Officer of the training establishment shall establish clearly the fact that the person has been given suitable warning and sufficient time to show progress, documentary evidence to this effect shall accompany the recommendation.

(3) The Central Government, or as the case may be, the authority as specified in rule 18, on receipt of recommendation under sub-rule (1), may discharge or release the person concerned from the service.

23. Termination of service on grounds of furnishing false or incorrect information at the time of appointment.—The Central Government, or as the case may be, the authority as specified in rule 18, may terminate the service of a person subject to the Act on grounds of furnishing false or incorrect information at the time of appointment of that person in the service and a show cause notice giving one month's time shall be issued to the individual before termination of his service.

24. Retirement or discharge or release of officers on grounds of physical unfitness.—(1) Where an officer not below the rank of Deputy Inspector-General considers that an officer of the Force is unfit to perform his duties because of his physical condition, the officer shall be brought before a medical board.

(2) The medical board shall consist of such officers and shall be constituted in such manner as may, from time to time, be laid down by the Director-General.

(3) Where the medical board considers the officer to be unfit for service, the Central Government shall, if it agrees with the findings of the medical board, communicate to the said officer the findings of the medical board and thereupon, within a period of thirty days of such communication, the officer may make a representation against it to the Central Government supported by a *prima-facie* evidence of error of judgement in the opinion expressed by the medical board and such an evidence shall be from a government doctor not below the status of civil surgeon and shall contain specific mention that he has taken into consideration the finding of the medical board before giving his opinion.

(4) The Central Government may, on receiving the representation from the officer, refer the case to be reviewed by a fresh medical board constituted for the purpose and order the retirement or discharge or release of the said officer if the decision of the fresh medical board is adverse to him.

25. Termination of service of subordinate officers by the authorities as specified in rule 18 on the grounds of unsuitability.—(1) Where a Commanding Officer not below the rank of Commandant is satisfied that a subordinate officer is unsuitable to be retained in service, the subordinate officer shall be—

- (a) so informed;
- (b) furnished with the particulars of all matters adverse to him ; and
- (c) called upon to urge any reasons he may wish to put forward in favour of his retention in the service :

Provided that clauses (a), (b) and (c) shall not apply, if the authority as specified in rule 18, is satisfied that for reasons to be recorded by it in writing, it is not expedient or reasonably practicable to comply with the provisions thereof :

Provided further that such competent authority may not furnish to the subordinate officer any matter adverse to him, if in his opinion, it is not in the interest of the security of the state to do so.

(2) In the event of the explanation being considered by the Commanding Officer not below the rank of Commandant unsatisfactory, the matter shall be submitted to the authority as specified in rule 18 for orders together with the subordinate officer's explanation and the recommendation of such Commanding Officer.

(3) The authority as prescribed in rule 18 after considering the report and the explanation, if any, of the subordinate officer and the recommendations of the Commanding Officer not below the rank of Commandant, may call upon the subordinate officer to retire or resign and on his refusing to do so, the subordinate officer may be compulsorily retired or discharged from the service.

26. Termination of service of enrolled persons on the grounds of unsuitability.— Where a Commanding Officer not below the rank of Commandant is satisfied that an enrolled person is unsuitable to be retained in the Force, the enrolled person shall be—

- (a) so informed;
- (b) furnished with the particulars of all matter adverse to him; and
- (c) called upon to urge any reasons he may wish to put forward in favour of his retention in the service :

Provided that clauses (a), (b) and (c) shall not apply, if the Commanding Officer not below the rank of Commandant is satisfied that for reasons to be recorded by it in writing, it is not expedient or reasonably practicable to comply with the provisions thereof.

Provided further that such competent authority may not furnish to the enrolled person any matter adverse to him, if in his opinion, it is not in the interest of the security of the state to do so.

(2) After considering the explanation, if any, the Commanding Officer not below the rank of Commandant, may call upon the enrolled person to retire or resign and on his refusing to do so, the enrolled person may be compulsorily retired or discharged from the service.

27. Retirement or discharge of subordinate officers and enrolled persons on grounds of physical unfitness.—

(1) Where a Commanding Officer not below the rank of Commandant is satisfied that a subordinate officer or an enrolled person is unable to perform his duties by reason of any physical disability, he may direct that the said subordinate officer or enrolled person, as the case may be, be brought before a medical board.

(2) The medical board shall consist of such officers and shall be constituted in such manner as may, from time to time, be laid down by the Director-General.

(3) Where the said subordinate officer or the enrolled person is found by the medical board to be unfit for further service in the Force, as the case may be, the authority as specified in rule 18, if he agrees with the finding of the medical board, communicate to the said person the findings of the medical board and thereupon, within a period of thirty days of such communication, the person may make a representation against it to the competent authority supported by a *prima-facie* evidence of error of judgement in the opinion expressed by the medical board and such an evidence shall be from a government doctor not below the status of Civil Surgeon and shall contain specific mention that he has taken into consideration the findings of the medical board before giving his opinion.

(4) Where the person declared to be unfit for further service makes a representation under sub-rule (3), the same shall be forwarded to the next superior officer, who shall have the case referred to be reviewed by a fresh medical board, which shall be constituted in such manner as may from time to time, be laid down by the Director-General.

The superior officer may, having regard to the findings of the fresh medical board, pass such order as he may deem fit.

(5) Where no representation is made against the decision of the medical board under sub-rule (3), the authority as specified in rule 18, as the case may be, may (if he agrees with the findings of the medical board) order the retirement or discharge of person declared to be unfit for further service in the Force.

28. Resignation.— (1) The Central Government may, having regard to the special circumstances of any case, permit any officer of the Force to resign from the Force before completing the term of engagement :

Provided that while granting such permission the Central Government may, require the officer to refund to the Government such amount as would constitute the cost of training given to that officer or three months pay and allowances, whichever is higher.

Provided further that an officer of the Force tendering resignation, for accepting a job under the Central or State Governments or local bodies, after having been granted cadre clearance for the same or who has completed ten years of service shall not be required to refund the sum as provided here in above.

(2) The Central Government may accept the resignation under sub-rule (1) with effect from such date as it may consider expedient.

(3) The Central Government may refuse to permit an officer to resign,—

- (a) if an emergency has been declared in the country either due to internal disturbance or external aggression ; or
- (b) if it considers it to be inexpedient so to do in the interest of the discipline of the Force; or
- (c) if the officer has specifically undertaken to serve for a specified period and such period has not expired.

(4) The provisions of this rule shall apply to and in relation to subordinate officers and enrolled persons as they apply to and in relation to any officer of the Force and the powers vested in the Central Government under sub-rules (1) and (2) shall be exercised in the case of a Subedar-Major or Inspector by an Inspector-General, in the case of a Sub-Inspector / or Assistant Sub-Inspector by an officer not below the rank of Deputy Inspector-General and in the case of an under officer or enrolled person by a Commandant.

29. Appeal against orders of dismissal, removal or retirement.—A person subject to the Act other than an officer who has been dismissed, removed or compulsorily retired from service, shall have the right to put in an appeal against the termination of his service to any of the authority, higher than the one who has passed the termination order within ninety days of the termination of service.

(2) In the case of officers, appeal shall lie to the Central Government and such appeal shall be filed within ninety days of the termination of service.

(3) Where the appellate authority sets aside the order of dismissal, removal or retirement under this rule, such authority shall pass such orders as may be necessary in respect of the period of absence from duty of the person whose dismissal, removal or retirement has been set aside.

30. Date of dismissal, removal, discharge or retirement.—The effective date of dismissal, removal, discharge or retirement shall be :—

- (a) the date mentioned in the order of dismissal or removal or discharge or retirement, or
 - (b) if no such date is mentioned, the date on which the person concerned is relieved from duties.
- (2) The dismissal, removal, discharge or retirement of a person subject to the Act shall not be from retrospective effect.

CHAPTER V

ARREST AND SUSPENSION

31. Forms of arrest.— (1) Arrest may be either open or close arrest.

(2) An arrest, unless otherwise specified, shall mean an open arrest.

(3) An order imposing arrest may be communicated to the person to be arrested either orally or in writing.

32. Authority to order arrest.— (1) No person subject to the Act shall be arrested on a charge under the Act except under and in accordance with the orders of a superior officer having power of command over him.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) any person subject to the Act may be placed under arrest by any superior officer :—

- (a) if he commits an offence against such superior officer; or
- (b) if he commits an offence in the view of such superior officer; or
- (c) if he is behaving in a disorderly manner and the said superior officer considers it necessary to place such a person under arrest with a view to stop such disorderly behaviour.

(3) A superior officer effecting arrest under sub-rule (2) shall as soon as possible, and in any case within twenty four hours of such arrest send a report to the Commanding Officer of the battalion or unit of which the person arrested is a member and in case of the arrest of an officer of and above the rank of Commandant, to his immediate superior officer.

33. Arrest, how imposed.— (A) Close arrest.— (1)(a) Close arrest in the case of enrolled persons shall be imposed by informing the person to be arrested and ordering him to be marched to the place of confinement under an escort of person of similar or superior rank.

(b) Where no such escort is available the person arrested shall be ordered to report himself immediately to the quarter guard or other place of confinement.

(2)(a) Close arrest in the case of officers, subordinate officers and under officers, shall be imposed by placing such officer, subordinate officer or under officer under the custody of another person of similar or superior rank and wherever considered necessary such officer, subordinate officer, or under officer may be confined under charge of a guard.

(b) The person under arrest shall not leave the place of his confinement without permission of his Commanding officer or a superior officer designated by the Commanding Officer in this behalf.

(B) Open arrest.— (3) (a) Open arrest shall be imposed by informing the person to be arrested that he is under open arrest and that he shall confine himself within such limits as may be specified in this behalf by the concerned superior officer effecting such arrest.

(b) The Commanding Officer may, from time to time, vary the limits referred to in clause (a) above.

34. Release from arrest during investigation.— Any person arrested under rule 32 may be released from arrest under the order of an officer :

Provided that in case of a person placed under arrest by an officer, such person shall be released from arrest under the order of an officer superior to the officer ordering arrest.

35. Release without prejudice to re-arrest.— Pending the completion of the investigation or convening of a Court, any person, who has been placed under arrest, may without prejudice to re-arrest be released by his Commanding Officer or by any officer superior to such Commanding Officer.

36. Arrest, when to be imposed.— (1) Any person charged with :

- (i) an offence under section 16 or clause (a) or clause (b) of section 18 or section 19 or section 22 or sub-section (1) of section 23;
- (ii) a civil offence punishable with death or imprisonment for life;
- (iii) any other offence under the Act—
 - (a) if the interest of discipline so require; or
 - (b) if the person concerned deliberately undermines discipline; or
 - (c) if the person concerned is of violent disposition; or
 - (d) if the person concerned is likely to absent himself with a view to avoid trial; or
 - (e) if the person concerned is likely to interfere with witnesses or tamper with evidence;

shall be placed under arrest.

(2) Where any person arrested shows symptoms of sickness, medical assistance shall be provided for such person.

37. Special provision in case of arrest of an intoxicated person.— (1) Where an intoxicated person has been arrested, he shall, as far as possible, be confined separately and shall be visited by duty officer or duty subordinate officer or duty under officer or under officer in-charge of the guard, once in every two hours.

(2) An intoxicated person shall not be taken before a superior officer for investigation of his case until he has become sober.

38. Arrest in case of persons whose trial has been ordered.— (1) Unless the convening officer has otherwise directed, on the commencement of the trial of a person by the Court, the said person shall be placed under arrest by his commanding Officer and shall remain under arrest during the trial.

(2) Where a sentence lower than that of imprisonment is passed by a Court, the arrested person may be released by his Commanding Officer pending confirmation of the finding and sentence :

Provided that the convening officer may rescind, vary or modify the order passed by a Commanding Officer under sub-rule (1) or sub-rule (2) and where no such order is passed by a Commanding Officer, the convening officer may pass such order as it may deem proper :

Provided further that a person who has been sentenced to be dismissed shall not, except while on active duty, be put on any duty.

39. Delay Report.— (1) (a) The report on reason for delay as required under section 71 of the Act shall be in the Form set out in Appendix II and it shall be sent by the Commanding Officer to the Deputy Inspector-General under whom the accused may be serving.

(b) A copy of the eighth delay report and every succeeding report thereof shall also be sent to the Inspector-General under whom the accused may be serving.

(2) Where the accused is kept under arrest for a period exceeding three months without being brought to trial, a special report regarding the action taken and the reasons for the delay shall be sent by the Commanding Officer to the Director-General with a copy each to the Deputy Inspector-General and the Inspector-General concerned.

40. Rights of a person under arrest.— (1) (a) Any person placed under arrest shall, at the time of being placed under arrest, be given in writing by the officer effecting the arrest of the particulars of the charges against him.

(b) The said particulars shall be rendered in simple language and also explained to the accused.

(c) Notwithstanding anything contained in clause (a), where during the investigation other offences committed by the accused are discovered, it shall be lawful to charge such person with those offences.

(2) (a) The duty officer or duty subordinate officer shall every day make a visit to the person under arrest and take the orders of the Commanding Officer on any request or representation made by the person under arrest.

(b) The request or representation made by the person under arrest shall be entered in the Form set out in Appendix III.

41. Suspension.— (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority or any other authority empowered in that behalf by the President by general or special order, may, at its discretion, place a person serving under him, under suspension in the following circumstances, namely :—

(i) where disciplinary action under the Act against him is contemplated or is pending; or

(ii) where in the opinion of the authority aforesaid, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the State; or

(iii) where a case against him in respect of any civil offence is under investigation, inquiry or trial:

Provided that the Director-General may exercise the power of suspension in respect of officers of the Force up to the rank of Deputy Commandant :

Provided further that the Director-General shall report the facts of each case immediately to the Central Government and all such orders of suspension shall be void *ab-initio* unless confirmed by the Central Government within a period of one month from the date of the said orders, irrespective of the fact that the suspension is revoked by the said authority within that period.

(2) A person subject to the Act shall be deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing authority: —

(i) with effect from the date of his detention by civil police on a criminal charge or otherwise for a period exceeding forty-eight hours, or

(ii) with effect from the date of his conviction by a criminal court on a criminal charge, if the sentence awarded is imprisonment for a term exceeding forty-eight hours.

(3) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.

(4) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule, may, at any time, be modified or revoked, by the authority which made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

(5) During the period of suspension powers vested in a person shall be in abeyance, but he shall be subject to same responsibilities, discipline, penalties and all other conditions of service to which he would have been subject if he was on duty and cannot leave headquarters declared by the competent authority without prior permission.

(6) When a person remains under suspension for more than ninety days, a report giving reasons for delay in the finalisation of his case shall be submitted to the Director-General by the Commanding Officer of the accused, and thereafter, subsequent reports shall be submitted every month till the case is finalised or the order of suspension is revoked, whichever is earlier.

CHAPTER VI

CHOICE OF JURISDICTION BETWEEN FORCE COURT AND CRIMINAL COURT

42. Trial of cases either by Force Court or Criminal Court.— (1) Where an offence is triable both by a Criminal Court and a Force Court, an officer referred to in section 92 may,—

(i) (a) where the offence is committed by the accused in the course of the performance of his duty as a member of the Force; or

(b) where the offence is committed in relation to property belonging to the Government or the Force, or a person subject to the Act; or

(c) where the offence is committed against a person subject to the Act, direct that any person subject to the Act who is alleged to have committed such an offence, be tried by a Force Court; and

- (ii) in any other case, decide whether or not it would be necessary in the interests of discipline to claim for trial by a Force Court any person subject to the Act who is alleged to have committed such an offence.
- (2) In taking a decision to claim an offender for trial by a Force Court an officer referred to in section 92 may take into account all or any of the following factors, namely:—

- (a) the offender is on active duty or has been warned for active duty and it is felt that he is trying to avoid such duty;
- (b) the offender is a young person undergoing training the offence is not a serious one and the trial of the offender by a Criminal Court would materially affect his training;
- (c) The offender can, in view of the nature of the case, be dealt with summarily under the Act.

43. Cases which may not be tried by Force Court.— Without prejudice to the provisions of sub-rule (1) of rule 42, an offender may not normally be claimed for trial by a Force Court,—

- (a) where the offence is committed by him alongwith any other person not subject to the Act whose identity is known;
- (b) where the offence is committed by him while on leave or during absence without leave; or
- (c) where the offence is committed by him which has no relation with the performance of his duty.

CHAPTER VII

INVESTIGATION AND SUMMARY DISPOSAL

44. Statement of allegations.—Where it is alleged that a person subject to the Act has committed an offence punishable under the Act, the allegation shall be reduced to writing in the Form set out in Appendix IV in the case of persons of and below the rank of Head Constable and in the Form set out in Appendix V in the case of officers and subordinate officers.

45. Hearing by an officer not below the rank of Assistant Commandant.— (1) (a) In the case of a person, subject to the Act, other than an officer and a subordinate officer, the case may, in the first instance, be heard by an officer not below the rank of Assistant Commandant;

- (b) the witnesses shall be heard in the presence of the accused who shall have the right to cross examine them;
- (c) the accused shall have the right to call witnesses in defence and to make a statement.

(2) After hearing the accused under sub-rule (1), such officer may award any punishment which he is empowered to award, or dismiss the charge when the charge is not proved, or refer the case for disposal by the Commanding Officer:

Provided that he shall not dispose of the case which has been reserved by the Commanding Officer for disposal by himself or if the accused is under close arrest.

46. Hearing by the Commanding Officer.— (1) The Commanding Officer of and above the rank of Commandant may hear the charge against the persons under his command in accordance with the provisions of sub-rule (1) of rule 45 and may:

- (i) award any punishment which he is empowered to award in respect of persons of and below the rank of Head Constable; or
- (ii) dismiss the charge; or
- (iii) remand the case for preparing a record of evidence or an abstract of evidence against the accused; or
- (iv) in the case of an accused of and below the rank of a Head Constable remand the accused for trial by Summary Force Court:

Provided that:

- (a) in the case of an officer, the evidence of witnesses shall be reduced to writing if he so demands;
- (b) the Commanding Officer shall dismiss the charge, if in his opinion, the charge is not proved or may dismiss it if he considers that because of the previous character of the accused and the nature of the charge against him, it is not advisable to proceed further with it and in case of an officer, he shall record reasons for dismissing the charge;
- (c) where a case in respect of an officer has been referred to the Commanding Officer by a superior authority for initiation of disciplinary action, the Commanding Officer shall not dismiss the charge without reference to such authority.

(d) in case of all offences punishable with death, a record of evidence shall be prepared.

(2) Where the Commanding Officer is of the opinion that the charge against an officer or a subordinate officer is of a serious nature, he may, without hearing the charge in accordance with the provisions of sub-rule (1), straightaway order a record of evidence or an abstract of evidence to be prepared in the case.

(3) Where the Commanding Officer is of the opinion that the charge against an officer or a subordinate officer does not deserve to be dismissed, and the charge is also not so serious as may warrant trial by a Force Court, he may, in the case of a subordinate officer, either dispose of the case himself or refer it to the appropriate authority for disposal under the provisions of Section 58 and in the case of an officer, he may refer the case to the appropriate authority for summary disposal under the provisions of Section 58.

(4) Where disciplinary action is intended to be taken against a Commanding Officer of a battalion or a unit, or a headquarters, such officer shall be removed from the command of the battalion, the unit, or the headquarters, as the case may be, and for the purpose, shall be attached to or posted to a battalion, unit or a headquarters under the command of an officer senior to the officer to be so attached or posted.

47. Procedure for summary disposal of charge against officers.—(1) Where an officer is remanded for the summary disposal of a charge against him, he shall be provided substance of evidence available against him or a copy of the record or abstract of evidence, if prepared, along with a copy of the charge-sheet as soon as practicable and in any case not less than twenty four hours before the commencement of the proceedings.

(2) The officer dealing with the case under Section 58 shall, unless the accused has consented in writing to dispense with the attendance of witnesses, hear the evidence in the presence of the accused who shall have the right to cross examine witnesses and the accused shall have the right to call any witness and make a statement in his defence.

(3) Proceedings shall be recorded as far as practicable in accordance with the Form in Appendix XIV, and in every case in which the punishment is awarded, the proceedings along with substance of evidence or record or abstract of evidence as the case may be, shall be forwarded to the next higher authority through the Judge Attorney-General or any officer authorised by him who may, if the punishment awarded appears to him to be illegal, unjust, excessive or inadequate, vary or remit the punishment or set aside the proceedings or enhance the punishment, or make such other directions as may be appropriate in the circumstances of the case:

Provided that before enhancing the punishment the accused shall be given an opportunity to show cause why his punishment should not be enhanced.

(4) An officer who considers himself aggrieved by any decision given under this rule, may submit one petition through his Commanding Officer, within one month of the disposal of the case, to the Director General who may pass such order or direction as may be appropriate in the circumstances of the case.

48. Summary disposal of charges against subordinate officer.—(1) Where a subordinate officer is charged with an offence under the Act, he shall be dealt with by the authority empowered under Section 58 in the same manner as nearly as circumstances admit, as provided in rule 47.

(2) Proceedings shall be recorded as soon as practicable in accordance with the Form in Appendix XIV and in every case in which the punishment is awarded, the proceedings along with substance of evidence or record or abstract of evidence, as the case may be, shall be forwarded to the next higher authority through the Judge Attorney-General or any officer authorised by him who may, if the punishment awarded appears to him to be illegal, unjust, excessive or inadequate vary or remit the punishment or set-aside the proceedings or enhance the punishment or make such other directions as may be appropriate in the circumstances of the case:

Provided that before enhancing the punishment the accused shall be given an opportunity to show cause why his punishment should not be enhanced.

(3) An subordinate officer who considers himself aggrieved by any decision given under this rule, may submit one petition through his Commanding Officer, within one month of the disposal of the case, to the authority superior to the one who awarded the punishment, and such authority may pass such order or direction as may be appropriate in the circumstances of the case.

49. Attachment to another Unit.—The Commanding officer shall not deal with any case:

- (i) where the offence with which the accused is charged is against the Commanding officer himself, or
- (ii) where the Commanding Officer is himself a witness in the case against the accused, or
- (iii) where the Commanding Officer is otherwise personally interested in the case.

The accused shall be attached to another battalion or unit or a headquarter for disposal of the case under the order of the competent authority:

Provided that a Commanding Officer shall not be disqualified from hearing a charge merely because the offence was committed against the property of a Force mess, band or institution of which the Commanding Officer is a member or trustee or because the offence is one of disobedience of such Commanding Officer's orders.

50. Charges not to be dealt with summarily.—A charge for an offence under Section 16 or clauses (a) and (b) of Section 18 or Section 19 or clause (a) of sub-section (1) of Section 20 or clause (a) of Section 22 or clause (a) of Section 27 or Section 49 (other than that for simple hurt or theft) or a charge for abetment of or an attempt to commit any of these offences, shall not be dealt with summarily.

51. Record of evidence.—(1) The officer ordering the record of evidence may either prepare the record of evidence himself or detail another officer to do so.

(2) The witnesses shall give their evidence in the presence of the accused and the accused shall have right to cross-examine all witnesses who give evidence against him:

Provided that where statement of any witness at a court of inquiry is available, examination of such a witness may be dispensed with and the original copy of the said statement may be taken on record and a copy thereof shall be given to the accused and he shall have the right to cross-examine if he was not afforded an opportunity to cross-examine the witness at the Court of Inquiry:

Provided further that if a person subject to the Act absconds or deserts the force after commission of offences under Sections 16, 17, 19, 20 and offence of 'murder' punishable under Section 49 of the Act and there is no immediate prospect of his apprehension, the officer detailed to prepare the record of evidence shall examine the witnesses in the absence of the accused and such evidence may, on the apprehension of such accused, be given in evidence against him at the trial by a Security Force Court, even if such witness is dead or incapable of giving evidence or cannot be found or his presence cannot be procured without an amount of delay, expenses or inconvenience which, under the circumstances of the case would be unreasonable.

(3) After all the witnesses against the accused have been examined, he shall be cautioned in the following terms; "You may make a statement if you wish to do so, you are not bound to make one and whatever you state shall be taken down in writing and may be used in evidence". After having been cautioned in the aforesaid manner whatever the accused states shall be taken down in writing.

(4) The accused may call witnesses in defence and the officer recording the evidence may ask any question that may be necessary to clarify the evidence given by such witnesses.

(5) All witnesses shall give evidence on oath or affirmation:

provided that no oath or affirmation shall be given to the accused nor shall he be cross-examined.

(6) (a) The statements given by witnesses shall ordinarily be recorded in narrative form and the officer recording the evidence may, at the request of the accused, permit any portion of the evidence to be recorded in the form of question and answer.

(b) The witnesses shall sign their statements after the same have been read over and explained to them.

(7) The provision of section 101 shall apply for procuring the attendance of witnesses before the officer preparing the record of evidence and the witnesses shall be summoned as per Forms given in Appendix XV.

(8) Where a witness cannot be compelled to attend or is not available or his attendance cannot be procured without an undue wastage of time or expenditure of money and after the officer recording the evidence has given a certificate in this behalf, a written statement signed by such witness may be read to the accused and included in the record of evidence.

(9) After the recording of evidence is completed the officer recording the evidence shall give a certificate in the following Form:

"Certified that the record of evidence ordered by..... was made in the presence and hearing of the accused and the provisions of rule 51 have been complied with".

(10) No counsel or legal practitioner shall be permitted to appear before the officer making the record of evidence.

52. Abstract of evidence.—(1) An abstract of evidence shall be prepared either by the Commanding officer or an officer detailed by him.

(2) (a) The abstract of evidence, shall include :

- (i) signed statements of witnesses wherever available or a précis thereof, and
- (ii) copies of all documents intended to be produced at the trial.

(b) where signed statements of any witnesses are not available, a précis of the evidence that the witnesses are likely to give shall be included.

(3) A copy of the abstract of evidence shall be given by the officer making the same available to the accused and the accused shall be given an opportunity to make a statement if he so desires after he has been cautioned in the manner laid down in sub-rule (3) of rule 51:

Provided that the accused shall be given such time as may be reasonable in the circumstances but in no case less than twenty four hours after receiving the abstract of evidence to make his statement:

53. Investigation of cases by Police.—Where the commanding officer considers it necessary so to do, he may lodge a report with the Police for investigation of any case.

54. Disposal of case by Commanding Officer after record or abstract of evidence.—(1) Where an officer has been detailed to prepare the record of evidence or to make an abstract thereof he shall forward the same to the Commanding Officer.

(2) The Commanding Officer may, after going through the record or abstract of evidence prepared by him or by another officer,—

- (i) remand the case for recording additional evidence, if required; or
- (ii) dismiss the charge provided that where disciplinary action has been initiated against an officer on a reference from a superior authority, the charge shall not be dismissed without reference to such an authority, or
- (iii) rehear the charge and award one of the Summary/minor punishments; or
- (iv) try the accused summarily under section 56 or by a Summary Force Court where he is empowered to do so; or
- (v) remand the case for summary disposal by the competent authority in the case of an officer or a subordinate officer; or
- (vi) apply to a competent officer or authority to convene a Court for the trial of the accused.

55. Application for a Court.—An application for a Court shall, as far as possible be made by the Commanding Officer in the Form set out in Appendix VI and shall be accompanied by five copies of the record or abstract of evidence and charge-sheet and such other documents as are mentioned in that application form.

CHAPTER VIII

ON CHARGES AND MATTERS ANTECEDENT TO TRIAL

56. Charge-sheet.—(1) A charge-sheet shall contain the whole of the issue or issues to be tried one time and may contain more than one charge, if the charges are founded on the same facts or form part of a series of offences of same or similar character :

Provided that a charge under sections 20, 21, 32 and 35 may be included in any charge sheet, notwithstanding that other charges in that charge-sheet are not founded on the same facts or do not form part of a series of offences of the same or similar character.

(2) Every charge-sheet shall, as far as possible be prepared as per Form set out in Appendix V.

57. Charges.—(1) There shall be a separate charge for each offence.

(2) (a) If a single act or series of acts is of such a nature that it is doubtful which of several offences, the facts which can be proved, will constitute, the accused may be charged with having committed all or any of such offences, and any number of such charges may be tried at once or he may be charged in the alternative with having committed some one of the said offences.

(b) The charge for the more serious offence shall precede the one for the less serious offence.

(3) Each charge shall consist of two parts, namely :

- (a) statement of the offence, and

(b) particulars of the offence.

(4) The offence shall be stated, if not a civil offence, as merely as practicable, in the words of the Act, and if a civil offence, in such words as would be sufficient to describe that offence.

(5) (a) The particulars shall state the time and place of the alleged offence and the person (if any) against whom, or the thing (if any), in respect of which it was committed and these should be sufficient to give the accused notice of the matter with which he is so charged.

(b) In case such particulars are not sufficient to give the accused notice of the matter with which he is charged, the charge shall also contain such particulars of the manner in which the offence was committed as will be sufficient for that purpose.

58. Joint Charges.—(1) Any number of accused may be charged jointly and tried together for an offence averred to have been committed jointly by them.

(2) Any number of accused though not charged jointly may also be tried together for an offence averred to have been committed by one or more of them and abetted by other or others.

(3) Where the accused are so charged under sub-rule (1) or sub-rule (2), any one or more of them may be charged with, and tried for, any other offence with which they could have been charged under sub-rule (1) of rule 56.

59. Validity of charge-sheet.—A charge-sheet shall not be invalid merely by reasons of the fact that, it contains any mistake in the name or description of the accused, and in the construction of a charge-sheet there shall be presumed in favour of supporting it every proposition which may reasonably be presumed to be impliedly, included, though not expressed therein, and the statement of the offence and the particulars of the offence shall be read and construed together.

60. Amendment of the charge by the Force Court.—(1) At any time during a trial, if it appears to the Court that there is in the charge-sheet, —

(a) a mistake in the name or description of the accused; or

(b) a mistake which is attributable to a clerical error or omission, the Court may amend the charge-sheet so as to correct the mistake.

(2) If at any time during a trial, at which there is a Judge Attorney, it appears to the Court, before it closes to deliberate on its findings, that it is desirable in the interest of justice to make any addition to, omission from or alteration in, a charge which cannot be made under sub-rule (1), it may, if such addition, omission, or alteration can be made without unfairness to the accused, and with the concurrence of the Judge Attorney, so amend the charge-sheet.

(3) If at any time during a trial, at which there is no Judge Attorney, it appears to the Court, before it closes to deliberate on its findings, that in the interest of justice, it is desirable to make any addition to, omission from or alteration in a charge, which cannot be made under sub-rule (1), it may adjourn and report its opinion to the convening officer, who may :

(a) amend the charge if permissible under this rule and direct the Court to try it as amended after due notice of the amendment has been given to the accused; or

(b) direct the Court to proceed with the trial of the charge without amending it; or

(c) convene a fresh Court to try the accused.

61. Amendment of Charge by Convening Officer.—When a Force Court reports to the convening officer either under rule 60 or rule 76 he may amend the charge in respect of which the Court has reported to him, by making any addition to, omission from or alteration in the charge which, in his opinion, is desirable in the interest of justice and which he is satisfied can be made without unfairness to the accused.

62. Action by a Superior Authority on receiving an application for convening a Court.—(1) As soon as a superior officer receives an application for convening a court, he shall scrutinise the charge and the evidence against the accused, where necessary, in consultation with the Judge Attorney-General or an officer detailed for the purpose, by the Judge Attorney-General and he, —

(i) shall direct the Commanding Officer to dismiss the charge where the evidence against the accused is insufficient and further evidence is not likely to be available and may direct him to do so if he considers it inadvisable to proceed with the trial; or

(ii) may return the case to the Commanding Officer for being tried by a Summary Force Court or being dealt with summarily if he considers that the same can be adequately so tried or dealt with; or

(iii) may dispose of the case administratively and if he is not competent to do so, may forward the case to higher authority with his recommendation; or

- (iv) may return the case for recording further evidence, if he considers the evidence recorded insufficient but considers that further evidence may be available.
- (2) (a) In any other case he may either himself convene a Court or if he considers that a higher type of Court should be convened, and he is not empowered to convene such a Court, forward the case to a higher authority with recommendation that, such Court may be convened.
- (b) The higher authority on receiving the case may exercise any of the powers given in sub-rule (1):

Provided that a superior officer or higher authority before convening a General Force Court or a Petty Force Court shall take the advice of the Judge Attorney-General or an officer detailed for the purpose of the Judge Attorney General:

Provided further that the superior authority or higher authority while convening a Court may reframe the charge sheet on which the accused is to be tried.

63. Disqualification of officers for serving on General and Petty Force Courts.—An Officer shall be disqualified from serving on a Court, if he, —

- (i) is an officer who convened the court; or
- (ii) is the prosecutor or a witness for the prosecution; or
- (iii) has taken any part in the investigation of the case, which would have necessitated applying his mind to any part of the evidence or to the facts of the case; or
- (iv) is the Commanding Officer of the accused, Deputy Inspector-General or the under whose command the unit in which the accused was serving at the time the alleged offence was committed; or
- (v) has a personal interest in the case.

64. Composition of General and Petty Force Courts.—(1) A Court shall consist as far as practicable, of officers of different units.

(2) The members of a Court for the trial of an officer shall be of a rank not lower than the rank of that officer, unless in the opinion of the convening officer, officers of such rank are not, having due regard to the exigencies of public service, available and such opinion shall be recorded in the convening order.

65. Duties of convening officer when convening courts.—When an officer convenes a Court he shall—

- (a) issue a convening order in the appropriate Form set out in Appendix-VII;
- (b) direct upon what charges the accused is to be tried and ensure that the accused has been remanded for trial by a Court upon these charges, by his Commanding Officer;
- (c) if he is of the opinion that charges shall be put in separate charge sheets, so direct and shall also direct the order in which they are to be tried;
- (d) direct, if there is more than one accused whether the accused are to be tried jointly or separately;
- (e) appoint members of the Court and any waiting members;
- (f) If convening a General Force Court, or a Petty Force Court which he considers should be attended by the Judge Attorney, take the necessary steps to procure the appointment of Judge Attorney by or on behalf of the Judge Attorney-General and may also appoint an officer to be under his instructions at the trial;
- (g) appoint an officer, subject to the Act or a counsel assigned by such an officer to prosecute:
Provided that the convening officer may appoint more than one such officer or counsel to prosecute if he thinks fit;
- (h) appoint an interpreter wherever necessary;
- (i) send to the senior member the charge-sheet, the convening order a copy of the record or abstract of evidence from which any evidence which in his opinion would be inadmissible at the trial, has been expurgated;
- (j) forward to each member of the Court and to each waiting member a copy of charge sheet and the convening order;
- (k) forward to the prosecutor copies of the charge-sheet and convening order and the original record or abstract of evidence together with an unexpurgated copy thereof showing the passages (if any) which have been expurgated in the copy sent to the senior member;

- (l) forward to the Judge Attorney (if any) copies of the charge sheet and convening order and an unexpurgated copy of the record or abstract of evidence showing the passages (if any) which have been expurgated in the copy sent to the senior member;
- (m) ensure that the Commanding Officer has summoned all the prosecution witnesses and such defence witnesses as the accused may have requested to be summoned under rule 67.

66. Preparation of defence by the accused.—(1) An accused, who has been remanded for trial, shall be afforded proper opportunity for preparing his defence and shall be allowed proper communication with his defending officer or counsel and with his witnesses.

(2) A defending officer, as far as possible of the choice of the accused, shall be appointed to defend an accused who has been remanded for trial unless the accused states in writing that he does not wish such an appointment to be made.

(3) If the prosecution is to be undertaken by a legally qualified officer or by a counsel the accused shall be notified of this fact in sufficient time to enable him, if he so desires, to make arrangements for a legally qualified officer or counsel to defend him.

(4) As soon as practicable after a decision has been taken to place the accused on trial and in any case not less than four days before his trial he shall be given:

- (a) a copy of the charge-sheet;
- (b) an unexpurgated copy of the record or abstract of evidence showing the passages (if any) within, which have been expurgated in the copy sent to the senior member;
- (c) notice of any additional evidence which the prosecution intends to adduce; and
- (d) if the accused so requires, a list of the ranks, names, and units of the members who are to form the Court and of any waiting members.

(5) When an accused is given a copy of the charge-sheet and of the record or abstract of evidence in accordance with this rule, he shall:

- (a) have the charge explained to him; and
- (b) be informed that, upon his making a written request to his Commanding Officer not less than twenty four hours before his trial requiring the attendance at his trial of a witness (other than a witness for the prosecution) whom he desires to call in his defence (such witness to be named by him), reasonable steps will be taken in accordance with these rules to procure the attendance of any such witness at his trial.

(6) The provisions of sub-rules (2) and (3) shall not apply in relation to a trial before a Summary Force Court and in relation to such a trial the period of four days referred to in sub-rule (4) shall be construed as twenty four hours.

67. Summoning of defence witnesses.—(1) Subject to the provisions of sub-rules (2) and (3), the Commanding Officer shall, on a request made in this behalf by the accused, summon such witnesses as are specified by the accused.

(2) Where the Commanding Officer is satisfied that the evidence to be given by any witness is not likely to be of material assistance at the trial, he may refuse to summon such witness and while doing so shall record in writing the reasons for not calling the witness.

(3) The Commanding Officer may, before summoning any witness, require the accused to defray or undertake to defray the cost of attendance of such witness and if the accused refuses to defray or undertake to defray the cost aforesaid, the Commanding Officer may refuse to procure the attendance of that witness.

(4) Where the Commanding Officer has refused to summon the witness under sub-rule (2) or sub-rule (3), the accused may make an application to the Court for the summoning of such witness and the Court may, if it considers it to be expedient in the interests of justice, order the summoning of such witness and, if necessary, adjourn the proceedings for the attendance of such witness and for summoning witnesses, summons as per Form given in Appendix XV shall be issued.

CHAPTER IX

PROCEDURE FOR GENERAL AND PETTY FORCE COURTS

68. Assembly and swearing of Court.—(i) Upon a Force Court assembling, the Court shall, before beginning the trial, satisfy itself in closed Court.—

- (a) that the Court has been convened in accordance with the Act and these rules;
- (b) that the Court consists of not less than the minimum number of officers required by law;
- (c) that the members are of the required rank;

- (d) that the members have been duly appointed and are not disqualified under the Act;
- (e) that if there is a Judge Attorney, he has been duly appointed;
- (f) that the accused appears, from the charge-sheet, to be subject to the Act and to be subject to the jurisdiction of the Court; and
- (g) that each charge is correct in law and framed in accordance with these rules.

(2) (a) Where a vacancy occurs through a member of the Court being disqualified under the Act, or being absent when the Court assembles, the presiding officer may appoint a duly qualified waiting member to fill that vacancy.

(b) Where a vacancy occurs through a member of the court so require, substitute a duly qualified waiting member for a member appointed by the convening officer.

(3) If the Court is not satisfied on any of the matters mentioned in sub-rule (1) and is not competent to rectify, such matter itself under the Act or these rules, it shall, before commencing the trial, report thereon to the convening officer.

(4) When the Court has complied with this rule and is ready to proceed with the trial, the presiding officer shall open the Court and the trial shall begin.

69. Commencement of trial.—(1) The order convening the Court and the names of the officers appointed to try the accused shall be read in the hearing of the accused who shall be given an opportunity to object to any of those officers in accordance with the provisions of section 96.

(2) When a Court is to try more than one accused whether separately or jointly, each accused shall be given an opportunity to object to any officer on the Court in accordance with sub-rule (1) and shall be asked separately whether he has any such objection.

(3) An accused shall state the names of all the officers to whom he objects before any objection is disposed of.

(4) If more than one officer is objected to, the objection to each officer shall be disposed of separately and the objection to the lowest in rank shall be disposed of first.

(5) An accused may make a statement and call any person to make a statement in support of his objection.

(6) An officer to whom the accused has objected may state in open Court any thing relevant to the objection of the accused whether in support or in rebuttal thereof.

(7) An objection to any officer shall be considered in closed Court by all the other officers of the Court and the officer objected to shall not be present at that time.

(8) When an objection to an officer is allowed under sub-section (3) of section 96 that officer shall forthwith retire and take no further part in the proceedings.

(9) When an officer objected to retires and there is duly qualified waiting member in attendance, the presiding officer shall immediately appoint him to take the place of the officer who has retired.

(10) The Court shall satisfy itself that a waiting member who takes the place of a member of the Court is of the required rank and not disqualified under the Act and shall give the accused an opportunity to object to him and shall deal with any such objection in accordance with the Act and these rules.

(11) If as the result of the allowing of an objection to a member there are insufficient officers available to form a Court in compliance with the provisions of the Act, the Court shall report to the convening officer without proceeding further with the trial and the convening officer may either appoint an officer as a member to fill the vacancy or convene a fresh Court to try the accused.

70. Swearing or affirming of members.— As soon as the Court is constituted with the proper number of officers who are not objected to or objections in respect of whom have been overruled on oath or affirmation shall be administered to every member in presence of the accused in one of the following Forms or in such other form to the same purport as the Court ascertains to be according to his religion or otherwise binding on his conscience.

FORM OF OATH

I, swear by Almighty God, that I will, well and truly, try the accused (or accused persons), before the Court, according to the evidence, and that I will, duly administer justice, in accordance with the provisions of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 without partiality, favour or affection; and I do further swear that I will not, on any account, at any time, whatsoever, disclose or discover, the vote or opinion of any particular member of the Court unless required to give evidence there of by a court of law.

FORM OF AFFIRMATION

I,.....do, solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will, well and truly, try the accused (or accused persons), before the Court according to the evidence, and that I will, duly administer justice in accordance with the provisions of the Sashastra Seema Bal Act, 2007, without partiality, favour or affection; and I do further solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will not, on any account, at any time, whatsoever, disclose or discover, the vote or opinion of any particular member of this Court unless required to give evidence thereof by a Court of Law.

71. Swearing or affirmation of Judge Attorney and other officers.— After the members of the Court are all sworn or have made affirmation, on oath or affirmation, shall be administered to the following persons or such of them as are present at the Court in such of the following Forms as shall be appropriate, or in such other Form to the same purport as the Court ascertains to be according to the religion or otherwise binding on the conscience of the person to be sworn or affirmed.

(A) JUDGE ATTORNEY**FORM OF OATH**

I,.....swear by Almighty God that I will, to the best of my ability, carry out the duties of Judge Attorney, in accordance with the provisions of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 and the rules made there under without partiality, favour or affection, and I do further swear that I will not, on any account, at any time, whatsoever, disclose or discover the vote or opinion on any matter of any particular member of this Court, unless required to give evidence thereof by a Court of Law.

FORM OF AFFIRMATION

I,.....do hereby, solemnly, sincerely and truly declare and affirm, that I will, to the best of my ability, carry out the duties of Judge Attorney in accordance with the provisions of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 and the rules made there under without partiality, favour or affection, and I do further solemnly, sincerely and truly declare and affirm, that I will not, on any account, at any time., whatsoever, disclose or discover the vote or opinion, on any matter of any particular member of this Court, unless required to give evidence thereof by a Court of Law.

(B) OFFICER ATTENDING FOR THE PURPOSE OF INSTRUCTION**FORM OF OATH**

I,....., swear by Almighty God that I will not on any account, at any time, whatsoever, disclose or discover the vote or opinion of any particular member of this Court unless required to give evidence thereof by a Court of Law.

FORM OF AFFIRMATION

I,....., do solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will not on any account, at any time, whatsoever, disclose or discover the vote or opinion of any particular member of this Court unless required to give evidence thereof by a Court of Law.

(C) SHORTHAND WRITER**FORM OF OATH**

I,....., swear by Almighty God that I will truly take down to the best of my power, the evidence to be given before this Court and such other matters as I may be required to take down and will, when required, deliver to the Court a true transcript of the same.

FORM OF AFFIRMATION

I,....., do solemnly, sincerely and truly declare and affirm, that I will truly take down to the best of my power the evidence to be given before this Court and such other matters as I may be required to take down and will, when required and deliver to the Court a true transcript of the same.

(D) INTERPRETER**FORM OF OATH**

I,....., swear by Almighty God that I will faithfully, interpret and translate, as I shall be required to do, touching the matter before this Court.

FORM OF AFFIRMATION

I,.....do solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will faithfully interpret and translate, as I shall be required to do, touching the matter before this Court.

72. Objection to Interpreter or Shorthand Writer.— A person shall not be sworn or affirmed as an interpreter or shorthand writer, if he is objected to by the accused unless the Court, after hearing the accused and the prosecutor, disallows such objections as being unreasonable.

73. Objection to Judge-Attorney and prosecutor.— The accused shall not be permitted to object to the Judge Attorney or the prosecutor.

74. Arraignment.— (1) When the Court and the Judge Attorney (if any) have been sworn, the charge will be read to the accused and he shall be asked whether he pleads guilty or not guilty to the charge or charges.

(2) If there is more than one charge against the accused he shall be required to plead separately to each charge.

(3) If there is more than one charge-sheet against the accused before the Court, the Court shall proceed with the charges in the first of such charge-sheets and shall announce its finding thereon and if the accused has pleaded guilty, comply with rule 81, before it arraigns him upon the charges in any subsequent charge-sheet.

75. Plea to jurisdiction.—(1) The accused, before pleading to the charge, may offer a plea regarding the jurisdiction of the Court, and in such a case,—

(a) the accused may adduce evidence in support of the plea and the prosecutor may adduce evidence in answer thereto: and

(b) the prosecutor may address the Court in answer to the plea and the accused may reply to the prosecutor's address.

(2) If the Court allows the plea it shall adjourn and report to the convening officer.

(3) When the Court reports to the convening officer under this rule, the convening officer shall —

(a) if he approves the decision of the Court to allow the plea, dissolve the Court;

(b) if he disapproves the decision of the Court; either,—

(i) refer the matter back to the Court and direct them to proceed with the trial; or

(ii) convene a fresh Court to try the accused.

76. Objection to the charge.— (1) An accused before pleading may object to the charge framed against him on the grounds that it is not correct in law or is not framed in accordance with the provisions of these rules and if he does so, the prosecutor may address the Court in answer to the objection and the accused may reply to the prosecutor's address.

(2) If the Court upholds the objection, it shall either amend the charge-sheet in accordance with the provisions of rule 60 or adjourn and report to the convening officer :

Provided that if there is another charge or another charge-sheet before the Court, the Court may, before adjourning proceed with the trial of the accused for such other charge or other charge-sheet.

(3) When the Court reports to the convening officer under sub-rule (2) the convening officer shall —

(a) if he approves the decision of the Court to allow the objection, —

(i) dissolve the Court; or

(ii) where there is another charge or another charge-sheet before the Court which the Court has not tried, direct the Court to proceed with the trial or such other charge or charge-sheet only; or

(iii) amend the charge to which the objection relates in accordance with the provisions of rule 61 and direct the Court to try the accused accordingly;

(b) if he disapproves the decision of the Court to allow the objection,— -

(i) direct the Court to try the accused for the charge; or

(ii) where there is another charge or another charge-sheet before the Court to which the objection does not relate and which the Court has not tried, direct the Court to proceed with the trial of the accused for such other charge or charge-sheet only ; or

(iii) convene a fresh Court to try the accused.

77. Plea in bar of trial.— (1) An accused before pleading to charge may offer a plea that the trial is barred under Section 87 or Section 88 and if he does so—

(a) the accused may adduce evidence in support of the plea and the prosecutor may adduce evidence in answer thereto, and

(b) the prosecutor may address the Court in answer to the plea and the accused may reply to the prosecutor's address.

(2) If the Court allows the plea it shall adjourn and report to the convening officer :

Provided that if there is another charge or another charge sheet before the Court, the Court may, before adjourning under this rule, proceed with the trial of the accused for such other charge or other charge-sheet.

(3) When a Court reports to the convening officer under this rule, the convening officer shall —

(a) if he approves the decision of the Court to allow the plea,—

(i) dissolve the Court; or

(ii) where there is another charge or another charge-sheet before the Court to which the plea does not relate and which the Court has not tried may direct the Court to proceed with the trial of the accused for such other charge or charge-sheet only.

(b) If he disapproves the decision of the Court to allow the plea,—

(i) direct the Court to try the accused for the charge; or

(ii) where there is another charge or another charge-sheet before the Court, to which the plea does not relate and which the Court has not tried, direct the Court to proceed with the trial of the accused for such other charge or charge-sheet only; or

(iii) convene a fresh Court to try the accused.

78. Application for separate trial.— (1) Where two or more accused are charged jointly, anyone of the accused may, before pleading to the charge, apply to the Court to be tried separately on the ground that he would be prejudiced in his defence if he were not tried separately.

(2) Where the accused makes such an application, the prosecutor may address the Court in answer thereto and the accused may reply to the prosecutor's address.

(3) Where the Court is of the opinion that the interests of justice so require, it shall allow the application and try separately the accused who made it.

79. Application for trial on separate charge-sheet.— (1) Where a charge-sheet contains more than one charge, the accused may, before pleading to the charges, apply to the Court to be tried separately on any charge in that charge-sheet on the ground that he would be prejudiced in his defence if he were not tried separately on that charge.

(2) Where the accused makes such an application, the prosecutor may address the Court in answer thereto and the accused may reply to the prosecutor's address.

(3) Where the Court is of the opinion that interests of justice so require, it shall allow the application and try the accused separately on the charge to which it relates as if that charge has been framed in a separate charge-sheet.

80. Pleading to the charge.— (1) After any plea under rules 75 and 77, any objection under rule 76 and any application under rules 78 and 79 have been dealt with, the accused shall be required subject to sub-rule (2) to plead either guilty or not guilty to each charge on which he is arraigned.

(2) Where a Court is empowered by section 105 to find an accused guilty of an offence other than that charged or guilty of committing the offence in circumstances involving a less degree of punishment or where it could after hearing the evidence, make a special finding of guilty, subject to exceptions or variations in accordance with rule 101, the accused may plead guilty to such other offence or to the offence charged as having been committed in circumstances involving a less degree of punishment or to the offence charged subject to such exceptions and variations.

81. Acceptance of plea of guilty.— (1) Where an accused pleads guilty to a charge under either sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 80 the presiding officer or Judge Attorney shall, before the Court decides to accept the plea, explain to the accused the nature of the charge and the general effect of his plea and in particular to difference in procedure when an accused pleads guilty and when an accused pleads not guilty.

(2) The Court shall then cause the prosecutor to read the record or abstract of evidence to the Court or inform the Court of the facts contained therein:

Provided that if an expurgated copy of the record or abstract of evidence was sent to the presiding officer, the prosecutor shall not read to the Court those parts of the record or abstract of evidence which have been expurgated or inform the Court of the facts contained in those parts, and shall not hand over the original record or abstract of evidence to the Court until the trial is concluded. Where there is no record or abstract of evidence, the Court shall record, in accordance with these rules sufficient evidence to enable it to determine the sentence.

- (3) A Court shall not accept a plea of guilty under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 83, if,—
- (a) the Court is not satisfied that the accused understands the nature of the charge or the effect of his plea; or
 - (b) the presiding officer having regard to the evidence contained in the record of evidence or the abstract of evidence and all the circumstances. Considers that the accused should plead not guilty; or
 - (c) the accused is liable, if convicted, to be sentenced to death.
- (4) (a) In the case of a plea of guilty under rule 82, a Court shall not accept the plea unless the convening officer concurs and it is satisfied of the justice of such course.
- (b) The concurrence of the convening officer may be signified by the prosecutor.
- (5) When a plea of guilty under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 80 is not accepted by the Court or the accused either refuses to plead to the charge or does not plead to it intelligibly, the Court shall record a plea of not guilty.
- (6) When a Court is satisfied that it can properly accept a plea of guilty under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 80 it shall record a finding of guilty in respect thereof.
- (7) After the Court has recorded its findings, it shall give an opportunity to the accused to adduce evidence of character and to make a statement in mitigation of punishment.
- (8) If, from the evidence adduced by the accused and his statement made under sub-rule (7), the Court is satisfied that the accused did not understand the effect of the plea of guilty, it should alter the record and enter a plea of not guilty and proceed with the trial accordingly.
- (9) After sub-rule (7) has been complied with and the Court has decided to accept the plea of guilty the Court shall proceed as directed in rule 103:
- 82. Plea on alternative charge.**— (1) When an accused pleads guilty to the first of two or more alternative charges, the Court if it accepts the accused's plea of guilty, shall record a finding of guilty in respect of the first charge and the prosecutor shall withdraw any of the alternative charge before the accused is arraigned on it.
- (2) When an accused pleads guilty to one or two or more charges which are laid in the alternative other than the first of such charges, the Court may,—
- (a) proceed as if the accused had pleaded not guilty to all the charges; or
 - (b) (i) with concurrence of the convening officer (which may be signified by the prosecutor) record a finding of guilty on the charge to which the accused has pleaded guilty and a finding of not guilty on any alternative charge which is placed before it in the charge-sheet;
 - (ii) where the court records such finding the prosecutor shall before the accused is arraigned on it withdraw any charge which is alternative to the charge of which the court has found the accused guilty and which is placed after it in the charge sheet.
- 83. Order of trial where plea of guilty and not guilty.**— (1) After the Court has recorded a finding of guilty, if there is no other charge in the same charge-sheet to which the accused has pleaded not guilty and no other accused who has pleaded not guilty to a charge in that charge-sheet, it shall proceed with the trial as directed by rule 81.
- (2) Where there is another charge in the charge-sheet which the accused has pleaded not guilty or there is another accused who has pleaded guilty to a charge sheet in that accused who has pleaded not guilty to a charge in that charge-sheet, the Court shall not comply with rule 81 until after it has dealt with such other charge or tried such other accused and has announced and recorded its finding in respect thereof.
- 84. Charge of plea.**— (1) An accused who has pleaded not guilty may at any time before the Court closes to deliberate on its finding withdraw his plea of not guilty and substitute a plea of guilty (including a plea of guilty under rule 82) and in such a case the Court shall, if it is satisfied that it can accept the accused's changed plea, record a finding in accordance with the accused's changed plea and so far as is necessary proceed as directed by rule 81.
- (2) Where at any time during the trial it appears to the Court that an accused who has pleaded guilty does not understand the effect of his plea or the nature of the charge the Court shall enter a plea of not guilty and proceed with the trial accordingly.
- (3) When the Court records a plea of not guilty in respect of any charge under sub-rule (2) it shall, if there was a charge laid in the alternative thereto which the prosecutor withdrew under rule 82 reinstate such alternative charge, arraign the accused thereof and proceed with the trial as if it had never been withdrawn.
- 85. Procedure on plea of not guilty.**— After a plea of not guilty to any charge has been recorded :

(i) the court shall ask the accused whether he wishes to apply for an adjournment on the ground that any of these rules relating to procedure before trial have not been complied with and that he has been prejudiced thereby or on the ground that he has not sufficient opportunity for preparing his defence,—

(ii) where the accused applies for an adjournment,—

(a) the accused may adduce evidence in support of his application and the prosecutor may adduce evidence in answer thereto; and

(b) the prosecutor may address the Court in answer to the application and the accused may reply to the prosecutor's address;

(iii) the Court may grant an adjournment if it thinks the interests of justice so require.

86. Opening address.— (1) The prosecutor may, if he so desires, and shall, if required by the Court, make an opening address explaining the charge and the nature and general effect of the evidence which he proposes to adduce.

(2) The witnesses for the prosecution shall then be called to give their evidence.

87. Additional witness.— Where the prosecutor intends to adduce evidence which is not contained in any record to abstract of evidence given to the accused, notice of such intention together with the particulars of the evidence shall, when practicable, be given to the accused at a reasonable time before the evidence is adduced and if such evidence is adduced without such notice or particulars having been given, the Court may, if the accused so desires, either adjourn after receiving the evidence or allow any cross-examination arising out of that evidence to be postponed, and the Court shall inform the accused of his right to apply for such an adjournment or postponement.

88. Dropping witnesses.— The prosecutor shall not be bound to call all the witnesses against the accused whose evidence is contained in the record or abstract of evidence, nor a witness when he had notified the accused that he intends to call under rule 86, but if the prosecutor does not intend to call such witness to give evidence, he shall give the accused reasonable notice that he does not intend to call the witness and that the accused will be allowed to communicate with him and to call him as a witness and that the accused will be allowed to communicate with him and to call him as a witness for the defence, if he so desires.

89. Withdrawal of witnesses.— During a trial, a witness other than the prosecutor or accused shall not, except by leave of the Court, be in Court while not under examination and if while he is under examination, a discussion arises as to whether a question is to be allowed or not with regard to his evidence the Court may direct the witness to withdraw during such discussion.

90. Examination of witness.— (1) A witness may be examined by the person calling him and may be cross-examined by the opposite party during the proceedings and on the conclusion of any such cross examination may be re-examined by the person who called him on matters arising out of the cross-examination.

(2) (a) The person examining a witness shall put his questions to the witness orally and unless an objection is made by the witness, the Court, the Judge Attorney, the prosecutor or by the accused, the witness shall reply forthwith.

(b) Where such an objection is made, the witness shall not reply until the objection has been disposed of.

(3) The Court may allow the cross-examination or re-examination of a witness to be postponed.

(4) Before the examination of a witness, he shall be administered an oath or affirmation in the following Form or in such other form to the same purport as the Court ascertains to be in accordance with his religion or otherwise binding on his conscience.

FORM OF OATH

I, swear by Almighty God that whatever I shall state, shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth.

FORM OF AFFIRMATION

I, do, solemnly, truly and sincerely declare and affirm that whatever I shall state, shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth.

91. Questioning by the Court.— (1) The presiding officer, the Judge Attorney and any member of the court may put questions to a witness.

(2) Upon any such question being answered, the prosecutor and the accused may put to the witness such questions arising from the answer which he has given as seem proper to the Court.

92. Reading over of evidence.— (1) (a) The record which has been made of the evidence given by a witness shall be read back to him before he leaves the Court and when this is done he may ask for the record to be corrected or explain the evidence which he has given.

(b) Where any such correction is made or explanation given, the prosecutor and the accused may put such questions to the witness respecting the correction or explanation as seem proper to the Court.

(2) When a shorthand writer is employed it shall not be necessary to comply with sub-rule (1), if, in the opinion of the Court and the Judge Attorney (if any), it is necessary to do so :

Provided that if any witness so demands, sub-rule (1) shall be complied with.

93. Calling or recalling witnesses by the Court.—(1) (a) The Court may at any time before it closes to deliberate in its finding or if there is Judge Attorney before he begins to sum up, call a witness or recall a witness, if in the opinion of the Court it is in the interest of justice to do so.

(b) Where the Court calls a witness or recalls a witness under this rule, the prosecutor and the accused may put such questions to the witness as seem proper to the Court.

(2) The prosecutor and the accused may, at any time before the Court closes to deliberate on its finding or if, there is a Judge Attorney before he begins to sum up, recall a witness by leave of the Court and the prosecutor and the accused may put such questions to the witness as seem proper to the Court.

94. Submission of no case to answer and stopping of cases.—(1) (a) At the close of the case for the prosecution the accused may submit to the Court in respect of any charge that the prosecution has failed to establish a prima facie case for him to answer and that he should not be called upon to make his defence to that charge.

(b) Where the accused makes such submission that prosecutor may address the Court in answer thereto and the accused may reply to the prosecutor's address.

(2) The Court shall not allow the submission unless it is satisfied that,—

(a) the prosecution has not established a prima facie case on the charge as laid; and

(b) it is not open to it on the evidence to make a special finding under either section 105 or sub-rule (4) of rule 101.

(3) (a) Where the Court allows the submission, it shall find the accused not guilty of the charge to which it relates and subject to confirmation the finding shall forthwith be announced in open Court.

(b) Where the Court disallows the submission it shall proceed with the trial of the offence as charged.

(4) The Court may, of its own motion, after the close of the hearing of the case of the prosecution, and after hearing the prosecutor find the accused not guilty of the charge and subject to confirmation the finding shall forthwith be announced in open Court.

95. Case for the defence.—(1) After the close of the case for the prosecution, the presiding officer or the Judge Attorney (if any) shall explain to the accused that,—

(a) if he wishes, he may give evidence on oath as a witness or make a statement without being sworn but that he is not obliged to do either;

(b) if he gives evidence on oath, he shall be liable to be cross-examined by the prosecutor and to be questioned by the Court.

(2) For the purpose of enabling the accused to explain any circumstances appearing in the evidence against him, the Court may, at any stage of the trial, without previously warning the accused, put such questions to him as the Court considers necessary, and shall for the purpose aforesaid, question him generally on the case after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called on for his defence.

(3) The accused shall not render himself liable to punishment by refusing to answer such questions, or by giving false answers to them.

(4) The answers given by the accused may be taken into consideration in such trial and put in evidence, for or against him in any other inquiry into or trial for, any other offence which such answers may tend to show he has committed.

(5) If the accused intends to call a witness to the facts of the case other than himself, he may make an opening address outlining the case for the defence before the evidence for the defence is given.

96. Witnesses for defence.—(1) After rule 95 has been complied with the witnesses for the defence (if any) shall be called to give their evidence.

(2) The provisions of rules 90, 91 and 92 shall apply to the witnesses for the defence as they apply to the evidence of witnesses for the prosecution.

97. Witness in reply.— After the witnesses for the defence have given their evidence, the prosecutor may by leave of the Court call a witness or recall a witness to give evidence on any matter raised by the accused in his defence which the prosecution could not properly have mentioned to the Court before the accused disclosed his defence or which the prosecution could not reasonably have foreseen.

98. Closing address.—(1) After all the evidence has been given the prosecutor and the accused may each make a closing address to the Court.

(2) The accused shall be entitled to make his closing address after the closing address by the prosecutor unless the accused has called a witness to facts other than himself, in which case the prosecutor shall be entitled, subject to sub-rules (3) and (4) to make his closing address after the accused has made the closing address.

(3) Where two or more accused are tried jointly anyone of them who has called no witness shall be entitled to make his closing address after the prosecutor has made the closing address.

(4) (a) Where two or more accused are represented by the same defending officer or counsel he may make one closing address only.

(b) Where anyone of the accused for whom he appears has called no witness to facts other than himself such defending officer or counsel shall be entitled to make his closing address after the prosecutor has made the closing address.

99. Summing up by Judge Attorney.— After the closing address, if there is a Judge Attorney, he shall sum up the evidence and advise the Court on the law relating to the case in open Court.

100. Deliberation on finding.—(1) The Court shall deliberate on its finding in closed Court in the presence of the Judge Attorney.

(2) The opinion of each member of the Court as to the finding shall be given by word of mouth on each charge separately starting with the juniormost in rank.

101. Record and announcement of finding.—(1) The finding on every charge upon which the accused is arraigned shall be recorded and, except as provided in these rules, shall be recorded simply as a finding of "Guilty" or of "Not Guilty":

Provided that the Court shall record brief reasons for such findings which shall be signed and dated by the presiding officer and the Judge-Attorney, if any.

(2) Where the Court is of opinion as regards any charge that the facts proved do not disclose the offence charged or any offence of which he might under the Act legally be found guilty on the Charge as laid, the Court shall acquit the accused of that charge.

(3) If the Court has doubts as regards any charge whether the facts proved show the accused to be guilty of the charge as laid, it may, before recording a finding on that charge refer to the confirming authority for an opinion, setting out the facts which it finds to be proved and may, if necessary, adjourn for that purpose.

(4) Where the Court is of opinion as regards any charge that the facts which it finds to be proved in evidence differ materially from the facts alleged in the statement of particulars in the charge but are nevertheless sufficient to prove the offence stated in the charge, and that the difference is not so material as to have prejudiced the accused in his defence, it may, instead of a finding of "Not Guilty" record a special finding.

(5) The special finding may find the accused guilty on a charge subject to the statement of exceptions or variation specified therein.

(6) Where there are alternative charges and the facts proved appear to the Court not to constitute the offence mentioned in any of those alternative charges, the Court shall record a finding of "Not Guilty" on that charge.

(7) The Court shall not find the accused guilty on more than one of two or more charges laid in the alternative, even if conviction upon one charge necessarily connotes guilty upon the alternative charge or charges.

(8) If the Court thinks that the facts proved constitute one of the offences stated in two or more of the alternative charges, but doubts which of those offences the facts do at law constitute, it may, before recording a finding on those charges, refer to the confirming authority for an opinion, setting out the facts which it finds to be proved and stating that it doubts whether those facts constitute in law the offence stated in one or other of such charges and may, if necessary, adjourn for that purpose.

(9) The finding on each charge shall be announced forthwith in open Court as subject to confirmation.

102. Procedure on acquittal.— If the finding on all the charges is "Not Guilty" the presiding officer shall affix his signature and date on the finding and such signature shall authenticate the whole of the proceedings, and the proceedings upon being signed by the Judge-Attorney (if any) shall be at once transmitted for confirmation.

103. Procedure on conviction.—(1) If the finding on any charge is "Guilty", then, for the guidance of the Court in determining its sentence, and of the confirming authority in considering its sentence, the Court, before deliberating on the sentence, shall whenever possible take evidence of and record the general Character, age, service, rank, any recognised acts of gallantry or distinguished conduct of the accused, any previous convictions of the accused either by Force Court

or a Criminal Court, any previous punishment awarded to him by an Officer exercising authority under section 56 or as the case may be, section 58, the length of time he has been in arrest or in confinement on any previous sentence, and any decoration, or reward, of which he may be in possession or to which he is entitled.

(2) Evidence of the above matter may be given by a witness verifying a statement which contains a summary of the entries in the service book respecting the accused and identifying the accused as the person referred to in that summary.

(3) The accused may cross-examine any such witness and may call witnesses to rebut such evidence and if the accused so requests, the service book or a duly certified copy of the material entries therein, shall be produced and if the accused alleges that the summary is in any respect not in accordance with the service book or such certified copy, as the case may be, the Court shall compare the summary with the service book or with copy of the material entries and if it finds that it is not in accordance therewith, shall cause summary to be corrected or the objection of the accused to be recorded.

(4) When all the evidence on the above matter has been given, the accused may address the Court thereon and in mitigation of punishment.

104. Sentence.— The Court shall award a single sentence in respect of all the offences of which the accused is found guilty, and such sentence shall be deemed to be awarded in respect of which it can be legally given and not to be awarded in respect of which it can not be legally given.

105. Recommendation for mercy.— (1) Where the Court makes a recommendation to mercy it shall give its reasons for such recommendation.

(2) The number of the members of the Court making recommendations to mercy mentioned in this rule or any question relating thereto, may be entered in the proceedings.

106. Announcement of sentence and signing and transmission of proceedings.— (1) The sentence together with any recommendation to mercy and the reasons for any such recommendation shall be announced forthwith in open Court and the sentence shall be announced subject to confirmation.

(2) Upon the Court awarding the sentence, the presiding officer shall affix his signature and date to the sentence and such signatures shall authenticate the whole of the proceedings and the proceedings upon being signed by the Judge-Attorney (if any) ; shall at once be transmitted for confirmation.

107. Revision.— (1) (a) Where the finding is sent back for revision under section 127, the Court shall re-assemble in open Court, the revision order shall be read and if the Court is directed to take fresh evidence, such evidence shall be taken in open Court.

(b) Where such fresh evidence is recorded, otherwise than that at the instance of the accused, the accused shall be given a further opportunity to lead evidence in respect of matters brought out in such fresh evidence.

(c) The prosecutor and the accused shall be given a further opportunity to address the Court in respect of the fresh evidence led.

(d) The Judge-Attorney may also give a further summing up.

(2) Where the revision of finding does not involve taking of fresh evidence the accused shall be given an opportunity to address the Court in respect of matter raised in the revision order.

(3) (a) The Court shall then deliberate on its finding in closed Court and if the Court does not adhere to its former finding, it shall revoke the finding and sentence and record a new finding and if such new finding involves a sentence, pass the sentence, afresh.

(b) Where the original finding was one of "Not Guilty", the Court shall, before passing sentence comply with rules 102 and 103.

(4) (a) Where the sentence alone is sent back for revision, the revision order shall be read in open Court and the accused be given an opportunity to address the Court in regard to matters referred to in the revision order.

(b) The Court shall then reconsider its sentence in closed Court and if it does not adhere to the sentence, revoke the sentence and pass the sentence afresh.

(5) Where the sentence alone is sent for revision the Court shall not revise the finding.

108. Confirmation and promulgation.— (1) When a confirming authority receives the record of the proceedings of a Court, it shall record its decision thereon and on any sentence and any order which the Court may have made under section 117 on the record of the proceedings in the appropriate Form set out in Appendix VIII and such record of his decision shall form part of the record of the proceedings.

(2) When a Court has accepted a plea of guilty made under rule 80 the confirming authority may confirm its finding notwithstanding that the Court has accepted the plea without the concurrence of the convening officer, if, in the opinion of the confirming authority, it is in the interest of justice to do so.

(3) (a) When a court has rejected a plea to the jurisdiction of the court or a plea in bar of trial or has over-ruled an objection to a charge it shall not be necessary for the confirming authority to approve specifically the decision of the Court, but its approval shall be implied from its confirming the finding on the charge to which the plea or objection relates.

(b) Where it disapproves the decision of the Court to reject the plea or to over-rule the objection it shall withhold confirmation of the finding on the charge to which the plea or objection relates.

(4) A confirming authority may state its reasons for withholding confirmation in any case, but if it withholds confirmation where a Court has rejected a plea to the jurisdiction or plea in bar of trial or has over-ruled an objection to the charges because it disapproves the decision of the Court, the confirming authority shall record its decision under sub-rule (1) stating the reason to withhold its confirmation.

(5) Where the sentence of a Court is improperly expressed, the confirming authority may in confirming the sentence vary the form thereof so that it shall be properly expressed.

(6) Whenever it appears that there is sufficient evidence on a plea of guilty under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 80 to justify the finding of the Court, such finding and any lawful sentence consequent thereon may be confirmed, and if confirmed, shall be valid, notwithstanding any deviation from these rules, if the accused has not been prejudiced by such deviation.

(7) While confirming the finding, the confirming authority may either unconditionally or subject to conditions which the accused accepts, reduce or remit a portion of the sentence or commute the punishment to one lower in the scale of punishments in section 51.

(8) (a) When a confirming authority has confirmed a finding and a sentence of a Court or has withheld confirmation thereof, it shall send the record of the proceedings to the Commanding Officer of the accused for promulgation to the accused of the finding and sentence or the fact that confirmation has been withheld as the case may be.

(b) The fact of promulgation shall be recorded on the record of the proceedings in the Form set out in Appendix IX.

(c) Where confirmation has been withheld because the confirming authority disapproves the Court's decision to reject a plea to the jurisdiction of a plea in bar of trial or to over-rule an objection to the charge, the accused shall be so informed.

CHAPTER X

PROCEDURE OF FORCE COURTS AND INCIDENTAL MATTERS

109. **Seating of members.**— The members of a Court shall take their seats according to their rank.

110. **Responsibility of presiding officer.**— (1) The presiding officer is responsible for the trial being conducted in proper order, and in accordance with the provisions of the Act, and rules made thereunder and in a manner befitting a court of justice.

(2) It is the duty of the presiding officer to see that the accused has a fair trial, and that he does not suffer from any disadvantage in consequence of his position as a person under trial, or of his ignorance, or of his incapacity to examine or cross-examine witnesses, or otherwise.

111. **Power of Court over address of prosecutor and accused.**— (1) It is the duty of the prosecutor to assist the Court in the administration of justice, to behave impartially, to bring the whole of the transaction before the Court and not to take any unfair advantage of, or suppress any evidence in favour of the accused.

(2) The prosecutor may not refer to any matter not relevant to the charge or charges, before the Court, and it is the duty of the Court to stop him from so doing and also to restrain any undue violence of language or want of fairness or moderation on the part of the prosecutor.

(3) The Court shall give reasonable facilities to the accused in making his defence and the accused must abstain from making any remarks contemptuous or disrespectful towards the Court, and from coarse and insulting language towards others, but he may for the purpose of his defence impeach the evidence and charge other persons with blame and even criminality and if he does so, he shall be responsible for any liability which he may thereby incur and the Court may caution the accused as to the irrelevance of his defence, but shall not unless in special case, stop his defence solely on ground of such irrelevance.

112. Sitting in closed Court.— (1) A Court shall, where it is so directed by these rules and may in other case on any deliberation amongst the members, sit in closed Court.

(2) No person shall be present in closed Court except the members of the Court, the Judge Attorney (if any) and any officer under instruction.

(3) For the purpose of giving effect to the provisions of sub-rules (1) and (2) a Court may either retire or cause the place where it sits to be cleared of all other persons not entitled to be present.

(4) Except as mentioned in sub-rules (1), (2) and (3) all proceedings, including the view of any place, shall be in open Court and in the presence of the accused subject to sub rule (5).

(5) The Court shall have the power to exclude from the Court any witness who has yet to give evidence or any other person, other than the accused, who interferes with its proceedings.

113. Continuity of trial and adjournment of Court.— (1) Once the Court is assembled and the accused has been arraigned, the Court shall continue the trial from day to day unless it appears to the Court that an adjournment is necessary for the ends of justice or that such continuance is impracticable.

(2) (a) A Court may from time to time adjourn its proceedings and meet at such place as may be convenient, and

(b) Wherever necessary, visit the scene of occurrence.

(3) The senior officer on the Spot may also for exigencies of service adjourn or prolong the adjournment of the Court.

(4) A Court in the absence of a Judge Attorney (if one has been appointed for that Court) shall not proceed, and shall adjourn.

(5) If the time to which an adjournment is made is not specified, the adjournment shall be until further orders from the Force authority, and, if the place to which an adjournment is made is not specified, the adjournment shall be to the same place or to such other place as may be specified in further orders from the Force authority.

114. Suspension of trial.— (1) Where in consequence of anything arising while the Court is sitting, the Court is unable by reason of dissolution as specified in section 83 or otherwise, to continue the trial, the presiding officer or, in his absence the senior member present, shall immediately report the facts to the convening authority.

115. Proceedings on death or illness of accused.— In case of the death of the accused or of such illness of the accused as renders it impossible to continue the trial, the Court shall ascertain the fact of the death or illness by evidence and record the same and adjourn and transmit the proceedings to the convening authority.

116. Death, retirement or absence of presiding officer.— In the case of the death, retirement, on challenge or unavoidable absence of the presiding officer, the next senior officer shall take the place of the presiding officer and the trial shall proceed if the Court is still composed of not less the minimum number of officers of which it is required by law to consist.

117. Presence of all members of Court.— (1) All the members of the Court shall remain present during the trial of an accused and any member of a Court who has been absent while any part of the evidence on the trial of an accused person is taken, shall take no further part in the trial of that person but the Court will not be affected unless it is reduced below the legal minimum.

(2) An officer shall not be added to a Court after accused has been arraigned.

118. Taking of opinions of members of Court.— (1) Every member of a Court must give his opinion by word of mouth on every question which the Court has to decide, and must give his opinion as to the sentence notwithstanding that he has given his opinion in favour of acquittal.

(2) The opinions of the members of the Court shall be taken in succession, beginning with the member lowest in rank.

119. Procedure on incidental questions.— If any objections is raised on any matter of law, evidence, or procedure, by the prosecutor or by or on behalf of the accused during the trial, the prosecutor or the accused or counsel or the defending officer, as the case may be, shall have a right to answer the same and the person raising the objection shall have a right to reply.

120. Evidence when to be translated.— When any evidence is given in a language, which any of the officers comprising the Court, the accused, or the Judge Attorney does not understand, it shall be translated into a language which he understands.

121. Record in Proceedings of transactions of a Force Court.— (1) At a Court, the Judge Attorney or, if there is none, the presiding officer shall record or cause to be recorded all transactions of the Court, and shall be responsible for the accuracy of the record (in these rules referred to as the proceedings), and if the Judge Attorney is called as a witness by the accused, the presiding officer shall be responsible for the accuracy of the record in the proceedings of the evidence of the Judge Attorney.

(2) The evidence shall be taken down in a narrative form in, as nearly as possible, the words used, but in any case where the prosecutor, the accused, the Judge Attorney or the Court considers it material, the question and answer shall be taken down verbatim.

(3) Where an objection has been taken to any question or to the admission of any evidence or to the procedure of the Court such objection shall if the prosecutor or accused so requests or the Court thinks fit, be entered upon the proceedings together with the grounds of the objection and the decision of the Court thereon.

(4) Where any address by, or on behalf of the prosecutor or the accused, is not in writing, it shall not be necessary to record the same in the proceedings further or otherwise than the Court thinks proper, except that,—

(a) the Court shall in every case make such record of the defence, made by the accused as will enable the confirming officer to judge of the reply made by, or on behalf of, the accused to each charge against him; and

(b) the Court shall also record any particular matters in the address by or on behalf of the prosecutor or the accused when the prosecutor or the accused; as the case may be, may require.

(5) The Court shall not enter in the proceedings any comment or anything not before the Court, or any report or any fact not forming part of the trial, but if any such comment or report seems to the Court necessary, the Court may forward it to the proper authority in a separate document, signed by the presiding officer.

122. Custody and inspection of proceedings.— The proceedings shall be deemed to be in the custody of the Judge Attorney (if any), or, if there is none with the presiding officer, but may, with proper precaution for their safety, be inspected by the members of the Court, the prosecutor and accused, at all reasonable times before the Court is closed to consider the findings.

123. Review of General/Petty Force Court proceedings.— The proceedings of a General Force Court and Petty Force Court shall be sent by the person having the custody thereof to the Judge Attorney-General for review, who shall then forward the same to the confirming authority.

124. Defending Officer, friend of accused and counsel.— (i) At any General or Petty Force Court an accused person may be represented by a counsel or by any officer subject to the Act who shall be called "the defending officer" or assisted by any person whose services may be able to procure and who shall be called "the friend of the accused".

(2) The defending officer shall have the same rights and duties as appertain to a counsel under these rules and shall be under the like obligations.

(3) The friend of an accused may advise the accused on all points and suggest the questions to be put to the witnesses, but he shall not examine or cross-examine the witnesses, address the Court.

125. Requirement for appearance of counsel.— (1) An accused person intending to be represented by a counsel shall give to his Commanding Officer or to the convening officer the earliest practicable notice of such intention, and, if no sufficient notice has been given, the Court may, if it thinks fit, on the application of the prosecutor, adjourn to enable him to obtain a counsel on behalf of the prosecutor at the trial.

(2) Where the convening officer so directs counsel may appear along with the prosecutor but in that case, unless the notice referred to in sub-rule (1) has been given by the accused, notice of the direction for counsel to appear shall be given to the accused at such time, but in any case the notice shall not be less than seven days before the trial as would, in the opinion of the Court, have enabled the accused to obtain counsel to assist him at the trial.

(3) The counsel, who appears before a Court on behalf of the, prosecutor or accused, shall have the same rights as the prosecutor or accused, for whom he appears to call, and orally examine, cross-examine and re-examine witnesses, to put in any plea, and to inspect the proceedings and shall have the right otherwise to act in the course of the trial in place of the person on whose behalf he appears and he shall comply with the provisions of these rules as if he was that person and in such a case that person shall have no right himself to do any of the aforesaid matters except as regards the statement allowed by sub-rule (2) of rule 96 and sub-rule (4) of rule 103 or except so far as the Court permits him to do so.

(4) When counsel appears on behalf of the prosecutor, the prosecutor if called as witness may be examined as any other witness.

126. Disqualification of Judge Attorney.— An officer who is disqualified for sitting on a Court, shall be disqualified for acting as a Judge Attorney at that Court.

127. Substitution on death, illness or absence of Judge Attorney.— In the case of death or illness or any other cause which makes the Judge Attorney unable to attend, in that case the Court shall adjourn, and the presiding officer shall report accordingly to the convening officer and on receipt of the report the convening officer may appoint another person who shall be sworn or affirmed, and act as Judge Attorney for the residue of the trial, or until the Judge Attorney returns as the case may be.

128. Power and duties of Judge Attorney.— Where a Judge Attorney has been named to act on the Court, he shall,—

- (a) give his opinion on any question of law relating to the charge or trial whenever so required by the Court, prosecutor or the accused;
- (b) inform the Court of any irregularity or other infirmity in the proceedings;
- (c) inform the convening officer and the Court of any infirmity or defect in the charge or in the constitution of the Court;
- (d) sum up the evidence and give his opinion on any question of law, before the Court proceeds to deliberate upon its findings.

(2) It shall be the duty of the Judge Attorney to ensure that the accused does not suffer any disadvantage in consequence of his position as such, or because of ignorance or incapacity to examine or cross-examine witnesses and for this purpose the Judge Attorney may, with the permission of the Court, call witness and put questions to them which appear to him to be necessary or desirable.

(3) In the discharge of his duties, the Judge Attorney shall maintain an attitude of strict impartiality.

(4) Where any opinion has been given by the Judge Attorney to the Court on any matter before it, it may be entered in the proceedings, if the Judge Attorney or the Court desires it to be entered.

(5) The Judge Attorney shall represent the Judge Attorney-General at a Force Court.

129. Finding of insanity.— Where the Court finds either that an accused, by reason of unsoundness of mind, is incapable of making his defence, or that he committed the act alleged but was by reason of un-soundness of mind incapable of knowing the nature of the act or that it was wrong or contrary to law, the presiding officer or in the case of Summary Force Court, the officer holding the trial, shall affix his signature and the date on the finding which shall also be signed by the Judge-Attorney (if any) and thereupon the proceedings shall, at once, be transmitted to the confirming authority or in the case of Summary Force Court to the Deputy Inspector-General or the empowered to countersign them.

130. Preservation of proceedings.— The proceedings of every Court shall, after promulgation, be forwarded to the office of the Judge Attorney-General and be preserved there for not less than three years, or until the sentence awarded by the Court has expired whichever is later.

131. Right of person tried to copies of proceedings.— Every person tried by a Force Court shall be entitled to obtain on demand, at any time after the confirmation of the finding and sentence, when such confirmation is required and before the proceedings are destroyed, from the Judge Attorney-General a copy thereof, including the proceedings upon revision, if any.

132. Copy of proceedings not to be given in certain cases.— Notwithstanding anything contained in rule 131, if the Central Government is satisfied for reasons to be recorded that it is against the interests of the security of the State or friendly relations with foreign states to supply a copy of the proceedings or any part thereof under the said rule, he shall not be furnished with such a copy :

Provided that if the Central Government is satisfied that the person demanding the copy is desirous of submitting a petition in accordance with the provisions of the Act or instituting any action in a court of law in relation to the finding or sentence, it shall permit inspection of the proceedings by such a person, or his legal advisor, if any, on the following conditions, namely :—

- (a) the inspection shall be made at such time and such times and such places as the Central Government or any authority authorised by it may direct; and
- (b) the person allowed to inspect the proceedings shall before such inspection, furnish,—
 - (i) an undertaking, in writing, that he shall not make copies of the proceedings or any part thereof and that the information or documents contained in such proceedings shall not be used by him, for any purpose whatsoever, other than for the purpose of submitting a petition in accordance with the provisions of the Act or instituting an action in a court of law in relation to the said finding or sentence; and

- (ii) a certificate that he is aware that he may render himself liable to prosecution under sections 3 and 5 of the Indian Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) if he commits any act specified in the said sections in relation to the documents or information contained in the said proceedings.

133. Loss of proceedings.—(1) If, before confirmation, the original proceedings of a Court which require confirmation or any part thereof, are lost, a copy thereof, if any, certified by the Presiding Officer or the Judge Attorney at the Court may be accepted in lieu of the original.

(2) If there is no such copy, and sufficient evidence of the charge, finding, sentence, and transactions of the court can be procured, that evidence may, with the assent of the accused, be accepted in lieu of the original proceedings, or part which have been lost.

(3) In any case mentioned in sub-rules (1) and (2) the finding and sentence may be confirmed, and shall be valid as if the original proceedings or part thereof had not been lost.

(4) If the accused refuses the assent referred to in sub-rule (2), he may be tried again, and the finding and sentence of the previous Court to which the proceedings have been lost shall be void.

(5) If, after confirmation or in any case where confirmation is not required, the original proceedings or any part thereof are lost, and there is sufficient evidence of the charge, finding, sentence, and transactions of the Court and of the confirmation (if required) of the finding and sentence, that evidence shall be valid and sufficient record of the trial for all purposes.

134. Offences by witnesses and others.— When a Court is of opinion that there is ground for inquiring into any offence specified in sections 40 and 41 and committed before it or brought to its notice in the course of its proceedings, which would if done by a person subject to the Act, have constituted such an offence, such Court may proceed as follows :

(a) if the person who appears to have committed the offence is subject to the Act, the Court may bring his conduct to the notice of his Commanding Officer;

(b) if the person who appears to have done the act is amenable to a law relating to any Armed Force, the Court may bring his conduct to the notice of the Force authority, as the case may be;

(c) in other cases the officer who summoned the witness to appear or the Presiding Officer or officer holding the Court, as the case may be, may forward a written complaint to the nearest Magistrate of the first class having jurisdiction, and in the case of acts which would, if done by a person subject to this Act have constituted an offence under clause (e) of section 40 or section 41, the Court, after making any preliminary inquiry that may be necessary may send the case to the nearest Magistrate of the first class having jurisdiction for inquiry or trial in accordance with section 340 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

CHAPTER XI

SUMMARY FORCE COURT

135. Proceedings.—(1) The officer holding the trial (hereinafter in this chapter called the Court) shall record, or cause to be recorded the transactions of every Summary Force Court.

(2) The Court may appoint a shorthand writer to record the proceedings of the Court. Such shorthand writer shall be duly sworn or affirmed as per Form given in rule 71.

136. Evidence when to be translated.—(1) When any evidence is given in a language which the Court or the accused does not understand, that evidence shall be translated to the Court or accused as the case may be in a language which it or he does understand.

(2) The Court shall for this purpose either appoint an interpreter or shall itself take the oath or affirmation prescribed for the interpreter at a Summary Force Court.

(3) When documents are produced for the purpose of formal proof, it shall be in the discretion of the Court to cause as much to be interpreted as appears necessary.

137. Assembly.— When the Court, the interpreter (in any) and the officers and subordinate officers attending the trial are assembled, the accused shall be brought before the Court and the oath or affirmation prescribed in rule 138 shall be taken by the persons mentioned therein.

138. Swearing or affirming of court and interpreter.— The Court shall take oath or affirmation in anyone of the following forms or in such other form to the same purport which would according to the religion or otherwise be binding on the conscience of the officer constituting the Court.

FORM OF OATH

I, swear by Almighty God that I will duly administer justice, in accordance with the provisions of the Sashashtra Seema Bal Act, 2007, without partiality, favour or affection.

FORM OF AFFIRMATION

I, do solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will duly administer justice, in accordance with the provisions of the Sashashtra Seema Bal Act, 2007, without partiality, favour or affection.

(2) The Court, or any other person empowered by it in this behalf shall administer to the interpreter (if any) an oath or affirmation in any of the following forms, or in such other form to the same purport as the Court ascertains to be according to the religion or otherwise binding on the conscience of the person who is to act as interpreter.

FORM OF OATH

I, swear by Almighty God that I will faithfully interpret and translate, as I shall be required to do touching the matter before this Court.

FORM OF AFFIRMATION

I, do solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will faithfully interpret and translate, as I shall be required to do touching the matter before this Court.

(3) The witnesses shall, after the administration of the oath and the affirmation, withdraw from the Court.

139. Swearing of Court to try several accused persons.—(1) A Summary Force Court may be sworn or affirmed at the same time to try any number of accused persons then present before it whether those persons are to be tried collectively or separately.

(2) In the case of several accused persons to be tried separately, the Court, when sworn or affirmed shall proceed with one case postponing the other cases and taking them afterwards in succession.

(3) Where several accused persons are tried separately upon charges arising out of the transaction, the Court may, if it considers it to be desirable in the interests of justice, postpone consideration of any sentence to be awarded to any one or more such accused persons until the trials of all such accused persons have been completed.

140. Arraignment of accused.—(1) After the Court and interpreter (if any) are sworn or affirmed as mentioned above, the accused shall be arraigned on the charges framed against him.

(2) The charges on which the accused is arraigned shall be read and, if necessary, translated to him, and explained and he shall be required to plead separately to each charge.

141. Objection by accused to charge.—The accused, when required to plead any charge, may object to the charge on the ground that it does not disclose an offence under the Act, or is not in accordance with these rules.

142. Amendment of charge.—(1) At any time during the trial if it appears to the Court that there is mistake in the name or description of the accused in the charge-sheet, it shall amend the charge-sheet so as to correct that mistake.

(2) If on the trial of a charge it appears to the court at any time before it has begun to examine the witnesses, that in the interests of justice any addition to, omission from, or alteration in, the charge is required, it may amend such charge and may, after due notice to the accused, and with the sanction of the officer empowered to convene a Petty Force Court for the trial of the accused, if the amended charge require such sanction, proceed with the trial on such amended charge.

143. Special pleas.—If a special plea to the general jurisdiction of the Court, or a plea in bar of trial is offered by the accused the procedure laid down in Chapter IX for disposing of such pleas shall, so far as may be applicable, be followed.

144. General plea of "Guilty" or "Not Guilty".—(1) The accused persons' plea of "Guilty" or "Not Guilty" (or if he refuses to plead or does not plead intelligibly, either one or the other a plea of "Not Guilty") shall be recorded on each charge.

(2) If an accused person pleads "Guilty" that plea shall be recorded as the finding of the Court, but before it is recorded the Court shall ascertain that the accused understands the nature of the charge to which he has pleaded guilty and shall inform him of the general effect of that plea and in particular of the meaning of the charge to which he has pleaded guilty and of the difference in procedure which will be made by the plea of guilty and shall advise him to withdraw that plea if it appears from the record or abstract of evidence (if any) or otherwise that the accused ought to plead not guilty.

(3) Where an accused person pleads guilty to the first two or more charges laid in the alternative, the Court may after sub-rule (2) has been complied with and before the accused is arraigned on the alternative charge or charges, withdraw such alternative charge or charges and follow the charge to which the accused has pleaded guilty without requiring the accused to plead thereto, and a record to that effect shall be made in the proceedings of the Court.

145. Procedure after plea of "Guilty".—(1) Upon the record of the plea of "Guilty" if there are other charges in the same charge-sheet to which the plea is "Not Guilty", the trial shall first proceed with respect to those other charges. and, after the finding on those charges, shall proceed with the charges on which a plea of "Guilty" has been entered, but if there are alternative charges, the Court may either proceed with respect to all the charges as if the accused had not pleaded "Guilty to any charge or may, instead of trying him, record a finding of "Guilty" upon anyone of the alternative charges to which he had pleaded "Guilty" and finding of "Not Guilty" upon all the other alternative charges which precede such charge.

(2) (a) After the record of the plea of "Guilty" on a charge (if the trial does not proceed on any other charges) the Court shall read the record or abstract of evidence and annex it to the proceedings or if there is no such record, or abstract shall take and record sufficient evidence to enable it, to determine the sentence, and the reviewing officer to know all the circumstances connected with the offence.

(b) The evidence shall be taken in like manner as is directed by these rules in the case of a plea of "Not Guilty".

(3) The accused may, after such evidence has been taken or as the case may be, the record or abstract of evidence has been read, address the court with reference to the charge and in mitigation of punishment and may call witnesses as to his character.

(4) (a) If from the statement of the accused or from the record of evidence or otherwise it appears to the Court that the accused did not understand the effect of his plea of "Guilty", the Court shall alter the record and enter a plea of "Not Guilty", and proceed with the trial accordingly.

(b) Any alternative charges withdrawn under sub-rule (1) shall be reinstated in the charge-sheet and the trial shall take place as if they had never been withdrawn.

(5) If a plea of "Guilty" is recorded on some charges and the trial proceeds with respect to other charges in the same charge-sheet, the proceedings under sub-rules (2) and (3) shall take place after the finding on the other charges in the same charge-sheet are recorded.

(6) When the accused states anything in mitigation of punishment which in the opinion of the Court requires to be proved, and would if proved affect the amount of punishment, the Court may permit the accused to call witnesses to prove the same.

146. Withdrawal of plea of "Not Guilty".—The accused may, if he thinks fit at any time during trial, withdraw his plea of "Not Guilty" and plead "Guilty" and in such case the Court shall at once, subject to compliance with sub-rule (2) of rule 144, record a plea and finding of "Guilty" and shall, so far as if necessary proceed in the manner specified in rule 145.

147. Procedure after plea of "Not Guilty".—(1) After the plea of "Not Guilty" to any charge, is recorded, the evidence for the prosecution will be taken.

(2) At the close of the evidence for the prosecution the accused shall be asked if he has anything to say in his defence or may defer such address until he has called his witnesses.

(3) The accused may then call his witnesses, including witnesses to character.

148. Witnesses in reply to defence.—The Court may, if it thinks it necessary in the interests of justice, call witnesses in reply to the defence.

149. Evidence of witnesses.—The provisions of rules 91, 92 and 93 shall, so far as may be, apply to the evidence of witnesses at a Summary Force Court as they apply to the evidence of witnesses at a General Force Court or Petty Force Court.

150. Record and announcement of finding.—(1) The Court shall after the evidence for prosecution and defence has been heard, record its findings.

(2) The finding on every charge upon which the accused is arraigned shall be recorded and except as provided in these rules shall be recorded simply as a finding of "Guilty" or of "Not Guilty".

(3) Where the Court is of opinion as regards any charge that the facts proved do not disclose the offence charged or any offence of which he might under the Act legally be found guilty on the charge laid, the Court shall find the accused "Not Guilty" of that charge.

(4) Where the court is of opinion as regards any charge that the facts which it finds to be proved in evidence differ materially from the facts alleged in the statement of particulars in the charge but are nevertheless sufficient to prove the offence stated in the charge, and that the difference is not so material as to have prejudiced the accused in his defence, it may, instead of a finding of "Not Guilty" record a special finding.

(5) Where there are alternative charges, and the facts proved appear to the court not to constitute the offence mentioned in any of those alternative charges the court shall record a finding of "Not Guilty" on that charge.

(6) The special finding may find the accused guilty on a charge subject to the statement of exceptions or variations specified therein.

(7) The Court shall not find the accused guilty on more than one or two or more charges laid in the alternative, even if conviction upon one charge necessarily connotes guilty upon the alternative charge or charges.

151. Procedure on acquittal.—Where the findings on each of the charges on a charge-sheet is "Not Guilty", the Court shall affix its signature and date to the proceedings, the findings will be announced in open Court, and the accused will be released if under arrest in respect of these charges.

152. Procedure on finding of "Guilty".—(1) Where the finding on any charge is "Guilty", the Court may record of its own knowledge, or take evidence of any record, the general character age, service, rank, and any recognised acts of gallantry, or distinguished conduct of the accused, and previous convictions of the accused either by a Force Court or a Criminal Court any previous punishment awarded to him by an officer exercising authority under section 56 the length of time he has been in arrest or in confinement on any previous sentence, and any decoration, or reward, of which he may be in possession or to which he may be entitled.

(2) Where the Court does not record the matters mentioned in this rule of its own knowledge evidence on these matters may be taken in the manner specified in rule 103 for similar evidence.

153. Sentence.—The Court shall award one sentence in respect of all the offences of which the accused is found guilty.

154. Signing of proceedings.—The Court shall affix its signature and the date to the sentence and such signature shall authenticate the whole of the proceedings.

155. Charges in different charge-sheets.—(1) When the charges at a trial by Summary Force Court are contained in different charge-sheets, the accused shall be tried on each charge-sheet separately up to and including the stage of finding.

(2) The Court shall, thereafter, comply with rule 151 or as the case may be, rule 152.

156. Clearing the Court.—(1) The officer holding the trial may clear the Court to consider the evidence or to consult with the officers and subordinate officers attending the trial.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1) all the proceedings including the view of any place, shall be in open Court, and in the presence of the accused.

157. Adjournment.—A Court may,—

(a) from time to time adjourn its proceedings and meet at such place and time as may be convenient; and

(b) Wherever necessary visit the scene of occurrence.

158. Friend of the accused.—During a trial at a Summary Force Court an accused may take the assistance of any person including a legal practitioner, as he may consider necessary:

Provided that such person shall not examine or cross-examine witnesses or address the Court.

159. Memorandum to be attached to proceedings.—Where Summary Force Court tries an offence which shall not ordinarily be tried without reference to an authority mentioned in sub-section (2) of section 86, an explanatory memorandum shall be attached to the proceedings.

160. Promulgation.—The sentence of a Summary Force Court shall be promulgated in the manner usual in the service, at the earliest opportunity after it has been pronounced and shall subject to the provisions of the Act as carried out without delay after promulgation.

161. Review of proceedings.—The proceedings of a Summary Force Court shall immediately on promulgation be forwarded through the Judge Attorney-General, or an officer nominated by him for the purpose to the Deputy Inspector-General or the under whom the accused may be serving.

162. Action by the Deputy Inspector-General.—(1) Where the Deputy Inspector-General to whom the proceedings of a Summary Force Court have been forwarded under rule 161 is satisfied that injustice has been done to the accused by reason of any grave irregularity in the proceedings or otherwise, he may,—

(a) set aside the proceedings of the Court;

or

- (b) reduce the sentence or commute the punishment awarded to one lower in the scale of punishment given in section 51.
- (2) Where no action under sub-rule (1) has been taken he shall countersign the proceedings and return it to the unit of the accused for promulgation.
- (3) The proceedings shall after its promulgation, be forwarded to the Judge Attorney-General for custody.
- 163. Rules which shall not apply to trial by Summary Force Court.**—The provisions of Chapters IX and X of these rules shall not apply to trials by Summary Force Court in so far as they are in consistent with any of the provisions contained in this Chapter pertaining to Summary Force Court.

CHAPTER XII

EXECUTION OF SENTENCE

- 164. Direction about sentence of imprisonment.**—(1) A confirming authority or in the case of a Summary Force Court, the Court, shall direct that the sentence of imprisonment shall be undergone by confinement either in a civil prison or in Force custody.
- (2) Such direction may be varied by any superior officer.
- 165. Warrants.**—(1) Warrants for committing a person to a civil prison to undergo sentence of imprisonment or to get such person back into Force custody if so required or to order the release of such a person from civil prison or any variation done by any superior officer shall be in such Form as may be appropriate to each set out in Appendix -X.
- (2) Such warrants shall be signed by the Commanding Officer of the accused or by a staff officer on behalf of a Deputy Inspector-General, Inspector-General or the Director-General.
- 166. Warrant in case of sentence of death.**—(1) Where a person is sentenced to death by hanging, a warrant in the Form set out in Appendix XI shall be set by the Director-General to the Superintendent of the prison where facilities for carrying out such a sentence exist, after the sentence has been confirmed by the Central Government and the accused shall be committed to the same prison by his Commanding Officer on the appropriate warrant.
- (2) Where an accused person is sentenced to death by being shot, a warrant in the appropriate Form set out in Appendix XI shall be issued by the Director-General, to Deputy Inspector-General or under whom the accused may be serving, after the sentence has been confirmed by the Central Government and the Deputy Inspector-General shall arrange for the execution of the sentence.
- 167. Changes in sentence.**—Where any change is made in the sentence of a person already committed to a civil prison, such change shall be communicated to the Superintendent of the prison to which such person has been committed by the Commanding Officer or such other person as mentioned in rule 165 in the Form set out in Appendix XII.
- 168. Sentence of dismissal.**—(1) Sentence of dismissal shall take effect from the date of promulgation of such sentence or from any subsequent date as may be specified at the time of promulgation.
- (2) A sentence of dismissal combined with imprisonment to be undergone in a civil prison shall not take effect until such person has been committed to a civil prison.

CHAPTER XIII

PETITIONS

- 169. Petitions against finding and sentence of Court.**—(1) A person subject to the Act who has been tried by a Court shall be allowed to put in one petition before confirmation, to the confirming authority and one petition after confirmation to any officer or authority mentioned in section 131.
- (2) In the case of a Summary Force Court he shall be allowed to put in one petition only to any of the officers mentioned in section 131.
- 170. Period of Limitation.**—(1) A petition, before confirmation, shall be submitted, within two weeks of the conclusion of trial.
- (2) A petition after confirmation shall be submitted within three months of the date on which the sentence was promulgated:
- Provided that the time taken by such person to obtain a copy of the proceedings shall be excluded in computing period of three months.
- 171. Mode of submitting petitions.**—(1) (a) A petition by a person who is still a member of the Force shall be submitted through his Commanding Officer.

(b) A petition by a person who has ceased to be a member of the Force may be submitted to the Commanding Officer of the unit in which the trial was held.

(2) An officer to whom a petition is submitted or to whom a petition has been forwarded shall forward it to the next superior within a period of one week:

Provided that an officer may not forward a petition if he is competent to give the redress asked for and decides to do so.

(3) An officer receiving a petition shall send it to the Judge Attorney-General or to the officer approved by him for advice.

CHAPTER XIV COURT OF INQUIRY

172. Composition.—(1) A Court of Inquiry may consist of one or more members and if only one member is appointed he shall be an officer or if more than one member is appointed, at least one of them should be an officer and persons not subject to the Act, may also be appointed as additional members when the Court is to investigate matters of such a specialised nature as may require the assistance of specialised persons for proper investigation.

(2) The member or members of a Court of Inquiry ordered to be held into the conduct of an officer shall not be of a lower rank than the rank of such an officer and in case it is not possible to appoint all the members of the same or the higher rank, at least the presiding officer of such a Court of Inquiry shall be of a higher rank than the officer whose conduct is under inquiry.

173. Assembly order.—(1) A Court of Inquiry may be assembled by order of a Commanding Officer not below the rank of Commandant or any officer or authority superior to him.

(2) The order assembling the Court of Inquiry shall state the composition of the Court, the time and place for its assembly and clearly state the matters which the court will investigate and it will also provide for the administrative requirements of the Court.

174. Members of Court not to be sworn or affirmed.—The members of the Court shall not be sworn or affirmed, but when the Court is a Court of Inquiry or recovered prisoners of war, the members shall make the following declaration :

"I do declare upon my honour that I will duly and Impartially inquire into and give my opinion as to the circumstances in which became a prisoner of war, according to the true spirit and meaning of the Standing Order of the Force; and I do further declare, upon my honour that I will not, on any account, or at any time disclose or discover my own vote or opinion or that of any particular member of the court, unless required to do so by competent authority."

175. Procedure of Courts of Inquiry.—(1) The proceedings of a Court of Inquiry shall not be open to the public and only such persons may attend the proceedings as are permitted by the Court to do so.

(2) The evidence of all witnesses shall be taken on oath or affirmation and signed by them after the same has been read over and explained to them.

Explanation.—For the purpose of this rule, the Court shall administer the oath or affirmation to witnesses, as if the court were a Force Court.

(3) Evidence given by witnesses shall be recorded in narrative form unless the Court considers that any question and answers may be recorded as such.

(4) The court may take into consideration any documents even though they are not formally proved after recording the reasons thereof.

(5) The court may ask witnesses any questions, in any form, that they consider necessary to elicit the truth and may take into consideration any evidence, whether the same is admissible under the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) or not.

(6) No counsel; or legal practitioner shall be permitted to appear before a Court of Inquiry.

(7) Provisions of section 101 shall apply for procuring the attendance of witnesses before the Court of Inquiry and witnesses shall be summoned as per Form set out in Appendix XV.

(8) (a) Save in the case of a prisoner of war who is still absent whenever the subject matter of inquiry is the conduct or character of a particular person, such person may be associated throughout with the inquiry and be given full opportunity of making any statement, or giving any evidence, he may wish to make or give, and of cross-examination any witness whose evidence in his opinion, affects his character or reputation.

(b) In other cases, before giving opinion against any person subject to the Act, the Court shall afford that person an opportunity to know all that has been stated against him, cross-examine any witnesses who have given evidence against him, and make a statement and call witnesses in his defence.

(9) The answers given by a witness to any question asked before the Court shall not be admissible against such a witness on any charge at any subsequent occasion except a charge of giving false evidence before such Court.

(10) Where the proceedings of an inquiry are submitted to a higher authority for orders under rule 177 such authority before disagreeing with the opinion of the Court, shall record reasons for doing so. In such a case, provisions of clause (b) of sub-rule (8) may not be complied with.

(11) The Court may be re-assembled as often as the officer who assembled the court may direct, for the purpose of examining additional witnesses, or further examining any witness or recording further information and in such a case the Court may record fresh opinion if considered necessary after complying with the provisions of clause (b) of sub rule (8).

176. Courts of Inquiry, when to be held.—(1) A Court of Inquiry may be held to inquire into any disciplinary matter or any other matter of importance.

(2) In addition to a Court of Inquiry required to be held under sections 60 and 65 or section 74 of the Act, a Court of Inquiry shall be held in the following cases :

(a) (i) All unnatural deaths of persons subject to the Act or of other persons within the Force lines, an immediate report shall be sent through the messenger to the officer-in-charge of the police station within whose jurisdiction the place of such unnatural death exists.

(ii) In cases when such report cannot, for any reasons be delivered within a reasonable time, the Commanding Officer or the senior most officer of the unit present shall prepare a report in the Form set out in Appendix XIII.

(b) All injuries sustained by persons subject to the Act which are likely to cause full or partial disability, the court shall in such case determine whether such injuries were attributable to service or not.

(c) All financial irregularities, losses, theft and misappropriation of public or Force property, where it is necessary to obtain the order of a superior officer on such irregularities, loss, theft or misappropriation.

(d) All losses of secret documents and any other material of secret or above security classification, the Court of Inquiry shall be ordered by an officer or authority superior to the Commanding Officer of the Unit having the lost document or material on its charge.

(e) All injuries sustained by private persons or damages to their property in respect of which there is likely to be a claim against the Government or the Force.

177. Action on the proceedings of a Court of Inquiry.—The proceedings of a Court of Inquiry shall be submitted by the presiding officer to the officer or authority who ordered the Court and such officer or authority on receiving the proceedings may pass final orders thereon himself, if he is empowered to do so, or refer them to a superior authority.

178. Copies of Court of Inquiry proceedings.—A person subject to the Act against whom the Court of Inquiry has given an opinion or who is being tried by a Force Court on a charge relating to matter investigated by the Court of Inquiry, shall be entitled to copies of the proceedings of the Court of Inquiries unless the Director-General orders otherwise.

Explanation.—For the purposes of this chapter Court means a Court of Inquiry.

CHAPTER XV

MISCELLANEOUS

179. Prescribed officer under section 11.—Officer not below the rank of Commandant may, under sub-section (2) of Section 11, dismiss or remove from the service any person under his command other than an officer or a subordinate officer.

180. Authority prescribed for the purpose of section 13(1).—The authority for the purpose of sub-section (1) of section 13 shall be :

(i) Director-General in respect of all personnel subject to the Act other than officers.

(ii) Central Government in respect of officers.

181. Prescribed officer under sections 61 and 62.—(1) The following shall be the prescribed officers for the purpose of clause (i) of sub-section (2) of section 61 and section 62:

(i) Commandant in case of subordinate officers and enrolled persons.

(ii) Director-General in the case of officers.

(2) Any power conferred under this rule on any of the aforesaid officer may also be exercised by any officer superior to that officer.

182. Prescribed authorities under section 66.—Any authority superior to the one awarding any deductions under Chapter V of the Act shall be competent to remit the whole or part of the said deductions.

183. Prescribed officer under section 75.—The prescribed officer for the purpose of sub-section (1) of section 75 shall be the officer commanding a Frontier, sector or training institution or an officer commanding the Force in the field.

EXECUTION OF SENTENCE

184. Prescribed manner of custody and prescribed officer under sections 111 and 112.—(1) The prescribed officer for the purposes of section 112 shall be:

- (a) in the case of trial by Summary Force Court, the Commanding Officer of the Unit to which the accused person belongs, or any authority superior to such Commanding Officer;
- (b) in the case of trial by any other Court, the convening officer or any authority superior to him.

(2) When the officer who proposes to act as a prescribed officer under sub-rule (1) is under the command of the officer who has taken action in the case under sub-section (4) of section 111, he shall ordinarily obtain the approval of such officer before he acts, but if he is of the opinion that service exigencies, or the necessities of discipline, render it impossible or inexpedient to obtain such approval, he may act without obtaining such approval, but shall report his action and the reasons thereof to such officer.

(3) For the purpose of sub-section (4) of section 111 the accused shall be confined in such manner as may, in the opinion of the proper Force authority, be best calculated to keep him securely without unnecessary harshness, as he is not to be considered as a criminal but as a person labouring under a disease.

185. Prescribed officer under section 132.—The prescribed officer for the purpose of section 132 shall be the officer commanding a frontier, sector or training institution in respect of proceedings confirmed by him or by a person under his command.

186. Authorised deductions.—The following deductions may be made from the pay and all other emoluments payable to a person subject to the Act, namely:-

- (a) upon the general or special order of the Central Government, any sum required to meet any public claim, there may be against him ;
- (b) any sum required to meet compulsory contributions to any provident fund, welfare fund or any other fund approved by the Central Government or to meet any debt that may be due from him towards any Force institutions such as messes, canteens and the like.

Explanation.—(i) “Public Claim” means any public debt or disallowance including over-issue, or a deficiency or irregular expenditure of public money or store of which, after due investigation, no examination satisfactory to the Central Government, is given by the person who is responsible for the same.

(ii) The aforesaid deductions shall be in addition to those specified in the Act.

187. Repeal and Savings.—(1) All rules and orders relating to the matters covered by these rules shall stand repealed in so far as they are inconsistent with any of the provisions of these rules.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the rules or orders so repealed shall, in so far as such thing or action is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the provisions of these rules, as if the said provisions were in force when such thing was done or such action was taken and shall continue in force accordingly until superseded by anything done or any action taken under these rules.

188. Transitory provision.—Any rule or order applicable to the Force on commencement of these rules shall, unless repugnant to these rules, continue to apply unless and until abrogated or modified by the Central Government or any other competent authority.

[F. No. I-45026/1/2002/Pers-II/III-Vol. II]

ASHOK LAVASA, Jt. Secy.

APPENDIX-I

(see rule 16)

SASHASTRA SEEMA BAL RECRUITING FORM

No.	Blood Group.....
1. Name	Battalion/Unit.....
3. Caste/Tribe/Class..... (in case of Scheduled Castes, Tribes and other Backward classes only)	2. Religion
5. Heir.....	4. Father's Name
6. Date of birth by Christian Era (As nearly as can be ascertained).	
7. Height.....Cms	8. Chest.....Cms.
9. Identification Marks	
10. Residence..... Thana.....	Village/Town District.....State.....
11. Character and antecedents verified by	
12. Occupation prior to enlistment	
13. Educational qualifications, if any	
14. Date of enrolment.....	
15. Enrolled as	

Recent photograph

FORM OF ENROLMENT
ENROLMENT OF

No. Name (in Block Letters).....
as ain the Sashastra Seema Bal.

PART-I

(Questions to be put before enrolment)

You are warned that if after enrolment, it is found that you have given a willfully false answer to any of the first twelve of the following questions you will be liable to be punished as provided in the Sashastra Seema Bal Act, 2007.

(ALL ANSWERS ARE TO BE WRITTEN IN BLOCK LETTERS)

Questions:

1. What is your name?
(Underline Surname)
2. (a) What is your place of birth?
(State Village/Town, District and State of Birth)
- (b) What is your date of birth?
(State in Christian Era)

(N.B.- To support the date of birth the person being enrolled will be required to produce original, together with attested copies of the certificate specified in Government orders from time to time).

3. What is your permanent home address?
 - (a) Village/Town
 - (b) Thana
 - (c) Pargana/Tehsil
 - (d) District/Taluk
 - (e) State
4. (a) What is your religion?
- (b) Are you a member of a Scheduled Caste, a Scheduled Tribe or an other Backward Class?
(If so, state Caste, Tribe or Class and also produce original certificate together with attested copy of such certificate issued by competent authority specified by Government from time to time).
5. (a) Are you a citizen of India? If so, whether by birth or descent or registration or naturalization or otherwise?
- (b) If you are not a citizen of India, what is your Nationality?
- (c) Have you migrated from areas now in Pakistan? If so, state the date of your migration.
6. What are your educational qualifications? (Original certificates. with one attested copy of each, are to be produced).
7. Are you married? * If so state
 - (i) Date of marriage(s).
 - (ii) Name(s) of Spouse(s)
 - (iii) Nationality of spouse(s)

*(This does not include widow/widower/divorced).
8. (a) What is your father's name and address? If dead, state last address, district and state.
- (b) What is or was the nationality of your father? If he is or was an Indian citizen, state whether by birth, descent, registration, naturalization or otherwise.
9. Are you or have you ever been member of a party or organisation of a political, communal or cultural nature? If so, state the name of the party or organisation with the period/periods of your membership therein.
10. (a) Are you in Government service or have you ever been a Government servant? If so, state full particulars and the reasons for discharge and confirm that you were never dismissed from any Government service.
- (b) Are you in receipt of any allowance and/or pension from the Government? If so, on what account?
11. (a) Do you belong to Army, Navy or Air Force, the reserves of any of the three services, the Auxiliary Air Force, the Territorial Army and Police Force in India or the Nepal State Army or any of the Force of a foreign country?
- (b) Have you ever served in any of the Army, Navy or Air Force in India, the Reserves of any of the three services, the Auxiliary Air Force, the Territorial Army, or any Police Force in India or Nepal State Army or any of the force of a foreign country? If so, state in which and the cause of discharge. If you have served in more than one of the above named forces, or if you have served the same force in two or more distinct periods, state the cause of discharge separately in each case.

12. (a) Have you ever been arrested?
 (b) Have you ever been prosecuted?
 (c) Have you ever been kept under detention or imprisoned?
 (d) Have you ever been convicted by court of law for any offence?
 (e) Have you ever been bound down?
 (f) Have you ever been fined by a court of law?
 (g) Have you ever been interned, externed or otherwise dealt with under any law in force in India or outside? If so, state particulars.
 (h) Are you facing any prosecution in any court in India or abroad?
 (i) Have you ever been debarred from any examination or rusticated by any University or any other educational authority/Institution?
 (j) Have you ever been debarred/disqualified by any public service commission from appearing at its examination/selection?
 (k) Is any case pending against you in any University or other educational authority/institution at the time of filling up this enrolment form?
 (l) Whether discharged/expelled/withdrawn from any training institution under the Government or otherwise.
13. Are you willing to be enrolled as a combatant in the Sashastra Seema Bal ?
14. Are you willing to go wherever ordered by land, sea or air and not to allow any caste or social usages to interfere with the duties for which you are enrolled?
15. Are you willing to serve in Sashastra Seema Bal until discharged, in accordance with the conditions of service as specified in Part II of this form of Enrolment?
16. Do you have any objections to take the following oath or to make the following affirmation at the time of your attestation?

Signature of Individual

FORM OF OATH

I,....., do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will as in duty bound, honestly and faithfully serve in the Sashastra Seema Bal, and go wherever ordered, by air, land or sea and that I will observe and obey all commands of the President of the Union of India and the commands of any officer set over me even to the peril of my life.

FORM OF AFFIRMATION

I,....., do solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will, as in duty bound, honestly and faithfully serve in the Sashastra Seema Bal and go wherever ordered by air, land or sea and that I will observe and obey all commands of the President of India and the commands of any officer set over me even to peril of my life.

CERTIFICATE

I,....., do solemnly declare that the answers furnished by me above are true.

Place.....

Date.....

*()

Signature of person enrolled

Left thumb impression of the person enrolled
 taken in the presence of the Enrolling Officer

.....Signature

.....Name

.....Address of witness.

(*Name in Block letters)

Signature of officer who administer

Oath of Affirmation

PART II

CONDITIONS OF SERVICE

1. Subject to the provisions of the Sashastra Seema Bal Act, and the Rules made there under, the period for which you are enrolled shall be. years which may be extended by mutual agreement.
2. If you absent without leave, or desert, the total period of such absence shall not count towards that said period of. years.
3. On completion of the said period of. years of service or further extension of tenure you will be entitled to claim your discharge and you will be discharged with all convenient speed, unless the country is engaged in hostilities, or a state of emergency has been declared or the unit or institution to which you belong is more than 15 % under strength.
4. You are liable to be discharged during the first year of the service if you are not likely to become an efficient member of the Force.
5. You will also be liable to be discharged if the Central Government decides to disband the Force or a portion of it.

Certificate by the person to be enrolled

I have understood the above conditions and agree to abide by them.

(.....)

Signature of the person enrolled

Place.

Date.....

The above conditions have been read/explained to the person being enrolled by me.

(.....)

Signature of the Enrolling Officer

Place.

Date

PART III

HEALTH CERTIFICATE

I do hereby certify that I have examined candidate for employment in the Sashastra Seema Bal. He fulfils medical standards laid down for the Sashastra Seema Bal and I cannot discover that he has any disease, constitutional affliction or bodily infirmity. His age according to his own statement is..... Years and by appearance..... years.

Height Cms

Chest (a) Maximum..... Cms

(b) Minimum Cms

Place.

Date

Signature of Medical Officer

Designation

APPENDIX-II

[See rule 39(1)]

FORM OF DELAY REPORT

Confidential

No.....

Unit address

Date.....

To

.....

Subject: [(1st) (2nd), (3rd), (4th), etc. Eight day delay report pursuance to the
Section 71 and rule 39 of the Sashastra Seema Bal Act.]

1. No..... Rank..... Name.....
2. Offence
3. Date of Offence
4. Date when offence was discovered
5. Date of (open/close) arrest.....
6. Date of release to open arrest/release without prejudice to re-arrest (if not released, reason).....
7. Record of evidence made on (If not recorded, reasons)
8. Application for trial made on
9. Date due to be tried
10. Reason for delay

(COMMANDING OFFICER)

Copy to:

1. Inspector-General (In the case of the 8th and subsequent reports).
2. Director-General (Special report in case the accused is under close arrest for more than 3 months without a trial).

APPENDIX III

[See rule 40(2)(b)]

Sl.No	Date	Name of the Accused	Name of the Officer or Subordinate Officer to whom request or representation made	Particulars of the request or Representation	Orders of the Commanding Officer	Signature and date of the Officer or Subordinate Officer who conveys the orders of the Commanding Officer to the accused	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

APPENDIX IV

(See rule 44)

Form for use at summary proceedings of under-officers and other enrolled persons under Section 56 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007

OFFENCE REPORT

Unit.....

Serial No.....

For week ending

Last report submitted on

Charges against No..... Rank..... Name.....

Place and date of offence	Offence	Plea	Name of witness	Punishment awarded	Signature Rank and designation of officer by whom awarded and date of award	Date of entry in conduct sheet	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

Signature of Commanding Officer
of the Battalion/Unit

Instructions:

- Col. 1 In cases of absence without leave or desertion, "the date of offence" will be the first day of absence.
- Col. 2 The Section and sub-section of the Act under which the charge is preferred will be inserted above the statement of offence.
- Col. 4 An officer cannot deal summarily with a case in which he is the sole prosecution witness.
- Col. 5 Must be completed strictly in accordance with the heading.
- NOTE: This will be prepared in duplicate.

A copy along with a precis of evidence where made shall be sent to the Deputy Inspector-General.

APPENDIX V

[See rules 44 and 56(2)]

CHARGE-SHEET

The accused No. (if applicable) Rank.

Name Battalion/Unit is charged with
disobeying the lawful command of his superior officer under Section 23 (2) of the Sashastra Seema Bal Act in that he,
at on disobeyed the lawful
command of his superior officer, Rank Name of the same
Battalion, to turn out for Commandant's parade, by not turning out.

Place.....

Date

AB

Commanding Officer..... Bn/Unit

*To be tried by a General/Petty Force Court

Place.....

Date

XY

Inspector-General/Dy. Inspector-General

(Or Staff Officer to IG/DIG)

*When the sanction is accorded for the trial of the grave offences by Summary Force Court (Sashastra Seema Bal Act section 86 (2), a similar entry should be made on the charge sheet.

APPENDIX VI

(See rule 55)

FORM OF APPLICATION FOR A FORCE COURT

Battalion/Unit

Date.....20.....

Station.....

Application for a Force Court

Sir,

I have the honour to submit charge(s) against No.....Rank.....
Name..... of the..... Unit under my command, and request
you to accord/obtain sanction, of.....that a Force Court may be
assembled for his trial at.....

The case was investigated by (a).....

A Court of Inquiry was held on (b).....date.....at.....

.....at.....(Station).

Presiding Officer Rank, Name and Unit.

Members.....

The accused is now at His general character is (c) I enclose the following documents (d) . .

1. Charge-sheet[..... copies(e).]
2. Record or abstract of evidence original (f) and 5 copies.
3. Original exhibits (g).
4. Correspondence (g).
5. Statement as to character (and the) conduct-sheet of the accused (g).
6. List of witnesses for the prosecution and defence (with their present addresses) (g).
7. List of Exhibits (h).
8. Statement by accused as to whether or not he desires to have an officer assigned by the convening officer to represent him at the trial [rule 65(2)].

Signature of Commanding Officer

- (a) Here insert name of.....
- (i) Officer who investigated the charges.
 - (ii) Officer who made preliminary hearing into the case (Rule 45).
 - (iii) Officer who made the record of evidence (Rule 51).
- (b) To be filled in if there has been a Court of Inquiry respecting any matters connected with the charges; otherwise to be struck out [Rule 62(iii)]
- (c) To be filled in by the Commanding Officer
- (d) Any items not applicable to be struck out.
- (e) One copy each to presiding officer, Judge-Attorney (if any), members, Prosecutor and the accused.
- (f) Original record or abstract of Evidence to be sent to presiding officer.
- (g) 3, 4, 5 and 6 to be returned to the Commanding Officer of the Unit of the accused with the notice of trial.
- (h) 7 and 8 to be sent to the presiding officer.

APPENDIX VII

[See rule 65 (a)]

FORMS AS TO FORCE COURT

FORMS FOR ASSEMBLY OF FORCE COURT

GENERAL NDA PETTY

Forms or order for the Assembly of a General (or Petty) Court under the Sashastra Seema Bal Act, 2007.

Orders by.....

(PlaceDate)

No.....

Rank

Name

at.....on the.....day of.....for the purpose of trying by a.....Bn./Unit
Force Court the accused person (persons) named in the margin (and such other person or persons as may be brought before them)*

The senior officer to sit as Presiding Officer.

MEMBERS..... WAITING MEMBERS
..... is appointed Judge Attorney

INTERPRETER

..... is appointed Interpreter.

PROSECUTOR

..... Is appointed Prosecutor.

*The accused will be warned, and all witnesses duly required to attend. The proceedings (of which only two copies are required) will be forwarded to.....

Signed this..... day of.....

Convening Officer

*The opinion of the Convening Officer with respect to the composition of the Court (see Rule 63) should be added here, thus :—

“In the opinion of the convening officer it is not practicable to appoint officers of different Battalions/Units”.

“In the opinion of the convening officer, officer of equal or superior rank to the accused are not available, having due regard to the public service.”

*Add here any order regarding Counsel. [See rule 65(g).

APPENDIX VIII

[See rule 108]

In exercise of the powers conferred on me by Section 117 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007, I, hereby order that be delivered/paid to (be confiscated/destroyed).

Signature

(Confirming authority)

Place,.....

Date.....

APPENDIX IX

[(See rule 108(8)(b))]

The finding and sentence of the General/Petty Force Court held at (place). were promulgated to the accused by me at (Place) on day of.....20....

Extract for Battalion/Unit records have been taken/* . No record has been kept of the finding and sentence.

Signature

(Commanding Officer)

Place.....

Date.....

*To be used in case of acquittal on all charges.

APPENDIX—X

[See rule 165]

WARRANTS UNDER SECTIONS 135 AND 139 OF THE
SASHASTRA SEEMABAL ACT, 2007
FORM 'A'

Warrant of commitment for use when a prisoner is sentenced to imprisonment for life (Section 135).

To

The Superintendent

of the (a)..... Prison.

Whereas at a General Force Court, held at..... on the day of..... 20....,
(No..... Rank.....) Name.....
Unit....., was convicted of (the offence to be briefly stated here, as "desertion on active duty", "correspondence
with the enemy", "or as the case may be").

And whereas the said General Force Court on the..... day of..... 20.... passed the following
sentence upon the said (Name.....) that is to say.....
(Sentence to be entered in full, but without signature)

And whereas the said sentence had been duly confirmed by (b) as required by law (c).

This is to require and authorise you to receive the said (Name.....) into your custody in the said
prison as by law is required together with this warrant, until he shall be delivered over by you with the said warrant to the
proper authority and custody for the purpose of undergoing the aforesaid sentence of imprisonment. The aforesaid
sentence has effected from (d).

Given under my hand at... this the..... Day of..... 20....

Signature(s)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Name and description of confirming authority.
- (c) Add if necessary "with a remission of....."
- (d) Enter date on which the original sentence was signed.
- (e) Signature of Commanding Officer of the prisoner or other prescribed officer.

FORM 'B'

Warrant of commitment for use when a prisoner is sentenced to imprisonment which is to be undergone in a civil
prison (Section 135).

To

The Superintendent

of the (a)..... Prison.

Whereas at a (b)..... Force Court held at..... on the..... day of..... 20....
(No..... Rank..... Name..... Unit.....) was duly convicted of
(the offence to be briefly stated here, as 'desertion', 'theft', 'receiving stolen goods', 'Fraud', 'disobedience of lawful
command' or as the case may be).

And whereas the said (b)..... Force Court on the day of 20... passed the following sentence upon the said (Name.....) that is to say.....

(Sentence to be entered in full, but without signature)

And whereas the said sentence..... (c) has been confirmed by (d) as required by law (e) is by law valid without confirmation.

This is to require and authorise you to receive the said (Name.....) into your custody together with the warrant and to carry the aforesaid sentence of imprisonment into execution according to law. The sentence has effect from the (f),.....

Given under my hand at this the..... day of 20....

..... Signature (g)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) General, Petty or Summary.
- (c) Strike out inapplicable words.
- (d) Name and description of confirming authority.
- (e) Add if necessary with a remission of.
- (f) Enter date on which the original sentence was signed.
- (g) Signature of Commanding Officer of Prisoner or other prescribed officer.

FORM 'C'

Warrant for use when a sentence of imprisonment for life is reduced by superior authority to one of a shorter period (section 139)

To

The Superintendent

of the (a). Prison

Whereas..... (No..... Rank Name.....)

(late) of the unit is confined in the (a).. (prison under a warrant issued by (b) in pursuance of a sentence of (c).... passed upon him by a (d). Sashastra Seema Bal Act Force Court held at on..... And whereas (e)..... has, in the exercise of the power conferred upon him by the SSB Act, passed the following order regarding the aforesaid sentence, that..... is to..... say (1).....

This is to require and authorise you to keep the said (Name)..... in your custody together with this warrant in the said prison as by law is required until he shall be delivered over by you with the said warrant to the proper authority and custody, for the purpose of his undergoing the punishment of imprisonment for life under the said order. And this is further to require and authorise you to return to me the original warrant of commitment in lieu whereof this warrant is issued.

*The period of such imprisonment will reckon from the (g).

Given under my hand at this the..... day of 20.....

Signature (h)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Enter name or designation of officer who signed original warrant.
- (c) Enter original sentence (if this was reduced by the confirming officer or other superior authority the sentence should be entered thus:- "Life imprisonment reduced by confirming officer to 10 Years".
- (d) General.

- (e) Name and designation of authority varying the sentence.
- (f) Order to be set out in full.
- (g) Enter date on which original sentence was signed.
- (h) Signature of prescribed officer.

FORM 'D'

Warrant for use when prisoner is to be delivered into force custody.

To

The Superintendent
of the (a) Prison.

Whereas (No. Rank Name) (late) of the unit is confined in the (a) prison under a warrant issued by (b) in pursuance of sentence of (c) passed upon him by a (d) Force Court held at on and whereas (e) has, in exercise of the powers conferred upon him by the Sashastra Seema Bal Act passed, the following order regarding the aforesaid sentence; that is to say (f)

'This is to require and authorise you to deliver forthwith the said (name) in your custody to the officer or subordinate officer bringing this warrant.

Given under my hand at, this the day of 20.....

Signature(g)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Enter name or designation of officer who signed original warrant.
- (c) Enter original sentence (if this was reduced by the confirming officer or the other superior authority the sentence should be entered thus:—"2 years rigorous imprisonment reduced by confirming officer to 1 year".
- (d) General, Petty or Summary.
- (e) Name and designation of authority issuing the order.
- (f) Order to be set out in full (g) Signature of prescribed officer.
- (g) Signature of prescribed officer.

APPENDIX XI

(See rule 166)

FORM 'A'

Warrant committing to civil prison custody a person sentenced to death.

To

The Superintendent of the (a) Prison

Whereas at a (b) Force Court held at On the day of 20....., (No. Rank Name) of the Unit was convicted of (offence to be briefly stated);

And whereas the said (b) Force Court on the day of 20....., passed sentence of death by being hanged, on the said

(NAME):—

and the said sentence of death has been confirmed by the Central Government.

This is to require and authorise you to receive the said (Name) into your custody and to carry out the sentence of death on

Given under my hand at ..., this day of 20...

Signature (c)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) General.
- (c) Signature of the Director-General.

FORM 'B'

Warrant to obtain in person sentenced to death from civil custody in order to carry out such sentence.

To

The Superintendent
of the (a) Prison,

Whereas (No. Rank Name)

(late) of the Unit having been sentenced to suffer death on the day of 20 by a (b) Force Court held at is held in the said prison under a warrant by (c).

And whereas the said sentence having been duly confirmed by (d) as by Law required an Order to carry out the said sentence has been issued to me (e) (Name and Rank)

This is to require and authorise you to deliver forthwith the said (Name) to the officer/Subordinate officer/Under officer bringing the warrant.

Given under my hand at this day of

Signature (f)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) General.
- (c) Enter name or designation of officer who signed original warrant.
- (d) Name and description of confirming authority.
- (e) Name and designation of the officer to whom the order is issued.
- (f) Signature of the officer by whom the order is issued.

FORM 'C'

Warrant to carry out sentence of death

To

The Deputy Inspector General,

Whereas at a(a) by Force Court held at on the day of 20 . (No. Rank. Name

(.....) of the Battalion/Unit was convicted of (offence to be briefly stated).

And whereas the said (a) Force Court on the day of 20, passed sentence of death by being shot on the said (Name) and the sentence of death has been confirmed by the Central Government.

This is to require and authorise you to carry out the sentence of death on

Given under my hand at this the day of 20

Signature (b)

- (a) General.
- (b) Signature of the Director-General.

APPENDIX XII

(See rule 167)

FORM 'A'

Warrant for use when the sentence of a person under sentence of death and committed to custody in a civil prison is commuted to a sentence of imprisonment for life.

To

The Superintendent of the (a)..... Prison.

Whereas (No. Rank Name) (late) of the unit is held in the (a) Prison under a warrant issued by (b) in pursuance of a sentence of death passed upon him by (c) Force Court held at on and whereas (d) has in exercise of the powers conferred upon him by the Sashastra Seema Bal Act passed the following order regarding the aforesaid sentence:

That is to say (e).....

This is require, and authorise you to keep the said (Name)..... in your custody together with this warrant in the said prison as by law is required until he shall be delivered over by you with the said warrant to the proper authority and custody for the purpose of his undergoing the punishment of imprisonment for life under the said order. And this is further to require and authorise you to return to me the original warrant of commitment in lieu whereof this warrant is issued. This period of such imprisonment for life will reckon from the

(f).....

Given under my hand at this the day of 20....

Signature (g)

(a) Enter name of civil prison.

(b) Enter name or designation of the officer who signed original warrant.

(c) General

(d) Name and designation of authority commuting the sentence.

(e) Order to be set out in full.

(f) Enter date on which original sentence was signed.

(g) Signature of Commanding Officer.

FORM 'B'

Warrant for use when the sentence of a person under sentence of death and committed to custody in a civil prison is commuted to a sentence of imprisonment to be served in the same prison.

To

The Superintendent of the (a)..... Prison

Whereas (No. Rank Name) (late) of the, ... Unit is held in the (a) Prison under a warrant Issue By (b) in pursuance of a sentence of death passed upon him by a (e) Force Court held at on and whereas (d) has in exercise of the Powers conferred upon him by the Sashastra Seema Bal Act, passed the following order regarding the aforesaid sentence that is to say :

(e).....

This is to require and authorise you to keep the said (Name)..... in your custody together, with this warrant, and there to carry into execution the punishment of imprisonment under the said order according to law.

And this is further to require and authorise you to return to me the original warrant of commitment in lieu whereof this warrant is issued. This period of such imprisonment will reckon from the (f).....

Given under my hand at this the day of 20....

Signature (g)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Enter name or designation of officer who signed original warrant.
- (c) General.
- (d) Name and designation of authority commuting the sentence.
- (e) Order to be set out in full.
- (f) Enter date on which original sentence signed.
- (g) Signature of Commanding Officer.

FORM 'C'

Warrant for use when a person, who after having been sentenced to death has been committed to custody in a civil prison is to be delivered into the Force custody for a purpose other than carrying out the sentence of death.

To

The Superintendent of the (a)..... Prison.

Whereas (No..... Rank..... Name.....) (late) of the
Unit is held in the (a)..... prison under a warrant issued by (b)..... in pursuance
of a sentence of death passed upon him by a (c)..... Force Court held at
..... on..... and whereas (d).....
..... has in exercise of the powers conferred upon him by the Sashastra Seema Bal Act passed the following
order regarding the aforesaid sentence; that is to say (e).....

This is to require and authorise you to forthwith deliver the said (Name)..... to the
officer/subordinate officer or under officer bringing this warrant.

Given under my hand at this the day of 20....

Signature (f)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Enter name or designation of officer who signed original warrant.
- (c) General.
- (d) Name and designation of authority issuing order.
- (e) Order to be set out in full.
- (f) Signature of Commanding Officer.

FORM 'D'

Warrant for use when a prisoner is pardoned or his trial set aside, or when the whole sentence or the unexpired portion thereof is remitted (Section 139).

To

The Superintendent of the (a)..... Prison.

Whereas (No..... Rank..... Name.....) of the
Unit is confined in the (a)..... Prison under a warrant issued by (b)..... in
pursuance of a sentence of (c)..... passed upon him by a (d)..... Force Court held at.....
..... on..... and whereas (e)..... has,
in exercise of the powers conferred upon him by the Sashastra Seema Bal Act, passed the following order regarding the
aforesaid sentence; this is to say (f).....

This is to require and authorise you to forthwith discharge the said (Name)..... from your
custody unless he is liable to be detained for some other cause, and for your so discharging his this shall be your sufficient
warrant.

2807 GI/09-9

Given under my hand atthis the.....day of20...

Signature (g),

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Enter name or designation of officer who signed original warrant.
- (c) Enter original sentence (if this was reduced by the confirming officer or other superior authority the sentence should be entered thus: "2 years rigorous imprisonment reduced by confirming officer to 1 year".
- (d) General, Petty and (or) Summary.
- (e) Name and designation of authority pardoning prisoner, mitigating sentence or setting aside trial.
- (f) Order to be set out in full.
- (g) Signature of prescribed officer.

APPENDIX XIII

[See rule 176(2)(a) (ii)]

REPORT ON UNNATURAL DEATH

1. Place of death, or the place where dead body was found (give details).
2. Date and time at which information of death was received.
3. Name and description of two or more persons who identify the dead body.
4. Name and particulars of the deceased and his status.
5. Condition of clothes worn by the deceased.

Note.—In case, examination by Doctor is awaited, above details should be collected without removing the clothes etc. of the deceased, the other details should be completed after the Doctor's examination.

6. Condition of limbs, eyes and mouth.
7. Expression of face.
8. Marks of struggle on the dead body, if any, injuries and abrasions, should be recorded showing their size and location.

Note.—Depth of injury should be recorded but injuries should not be touched. If examination by Doctor is awaited the above information should be recorded after his examination.

9. Whether blood is fluid or coagulated. The place from which it came out and its quantity.
10. By which means, weapon or instrument, the injury or marks of struggle appear to have been caused?
11. Was any rope tied around the neck or is there any mark of it being tied by anything?
12. Was the rope or any other thing used to strangle or hang dead body, was it strong enough to sustain the weight and whether its other end was tied to anything?
13. Was any external article like grass etc. sticking to hairs or held in his hand or sticking to any other part of the body?
14. Is the dead body that of a strong and well-built man or it is that of a weak or old man?
15. Is the dead body strong or weak or is it in decomposed state?
16. Length of the dead body from head to feet.
17. Identification marks and location and appearance of the wounds.
18. Apparent cause of death.
19. Is there any rumour or other circumstances showing that it is a case of suicide? Details of articles found on the dead body or lying near it.
20. Those found on the dead body (A slip will be fixed on each article which will be stamped).
21. Those found lying near the dead body (a slip duly stamped will be affixed on each article). Description of the seal.
22. Map of the place where the dead body was found.

Brief history of the case

Signature of two or more respectable witnesses of the locality in whose presence investigation was carried out

Place

Signature of the Officer Investigating the case

Date

Name

Rank

APPENDIX XIV

[See rules 47 and 48]

FORM I

FORM FOR USE AT SUMMARY TRIALS OF OFFICERS AND SUBORDINATE OFFICERS (Section 58)

Accused

Rank and Name

Unit

When the authority dealing summarily with the case decides (with the written consent of the accused) to dispense with the attendance of witness.

Question to accuse

- | | |
|---|--------|
| 1. Have you received a copy of the charge sheet, and recorded or abstract of evidence | Answer |
| 2. Have you had sufficient time to prepare your defence ? | Answer |
| 3. The charge sheet is read.
Are you guilty or not guilty of the charges against you which you have heard/read | Answer |
| 4. Do you wish to make a statement? | Answer |

If the accused desires to make a statement he should do so now. If at the conclusion of the hearing the authority dealing summarily with the case considers that the charge should not be dismissed, he is to examine the accused's record of service or conduct sheet.

If the authority dealing summarily with the case proposes to award a punishment other than a reprimand /severe reprimand or penal deductions, he shall put the following question to the accused.

5. Do you elect to be tried by Court or will you accept my award?

Finding

Award

Station

Date

Note.—Oral statement of the accused made in answer to question 4 will not be recorded. If the accused has submitted a written statement such statement is only to be forwarded with or attached to this form when a copy of the Record or Abstract of Evidence is also required to be so forwarded or attached. This form will be kept with Confidential Character Roll of the Officer/Subordinate Officer.

Signature of Investigating Officer

Signature of Charged Officer

FORM II

FORM FOR USE AT SUMMARY TRIALS OF OFFICERS AND SUBORDINATE OFFICERS (Section 58)

Accused

Rank and Name

Unit

When the authority dealing summarily with the case do not decide to dispense with the attendance of witnesses or when the accused requires their attendance.

Question to Accused :

1. Have you received a copy of the charge-sheet and the record Or abstract of evidence ? Answer
 2. Have you had sufficient time to prepare your defence? Answer
 3. Are you guilty or not guilty of the charge/s against you which you have heard/read? Answer
- The witness give their evidence, accused being permitted to cross-examine.
4. Do you wish to make a statement? Answer
 5. Do you desire to call any witness? Answer

The accused makes a statement and his witnesses give evidence.

If at the conclusion of the hearing, the authority dealing summarily with the case considers that the charge should not be dismissed, he is to examine the accused's record of service or conduct sheet.

If the authority dealing summarily with the case proposes to award a punishment other than a reprimand, severe reprimand or penal deductions, he shall put the following question to the accused.

6. Do you elect to be tried by Court or will you accept my award? Answer

FINDING.....

AWARD.....

STATION.....

DATE.....

NOTE :— Oral statement of the accused made in answer to question will not be recorded. If the accused has submitted a written statement such statement is only to be forwarded with or attached to this form when a copy of the Record or Abstract of Evidence is also required to be forwarded or attached. This form will be kept with Confidential Character Roll of the Officer/Subordinate Officer.

Signature of Investigating Officer

Signature of Charged Officer

APPENDIX-XV

[See rules 51(7), 67 and 175(7)]

FORMS OF SUMMONS TO WITNESSES

(a) In the case of Record of Evidence.

Whereas charge of having committed an offence triable by Force Court has been preferred before me against (No..... Rank..... Name..... Unit.....) and whereas I have directed a record of the evidence to be taken in writing at (place) on the day of.....20.....at.....hours.

I do hereby summon and require you (name) to attend as a witness at the said place and hour (and bring with you the documents hereinafter mentioned, namely.....)

Whereof you fail at your peril.

Given under my hand at..... on the..... day of.....20.....

Commanding Officer of the accused

Signature

(b) In the case of Force Court

Whereas a Force Court has been ordered to assemble at..... on the day of.....20..... for the trial of..... of the..... Unit. I do hereby summon and require you A,.....B.....to attend, as a witness before the said

Court at.....on the.....day of.....20..... at hours (and to bring with you the documents hereafter mentioned, namely.....) and so to attend from day to day until you shall be duly discharged, whereof you shall fail at your peril.

Given under my hand at.....on the.....day of.....20.....

Signature
Convening Officer (or Judge Attorney
or Presiding Officer of the Court
or Commanding Officer of the accused)

(c) In the case of a Court of Inquiry

Whereas a Court of Inquiry has been ordered to assemble at.....on the day of 20.....to inquire.....into.....the.....circumstances.....unde.....which.....I do hereby summon and require you A..... B.....to attend as a witness before the said Court Of Inquiry at.....on the.....day of.....20 athours (and to bring with you the documents here after mentioned, namely.....) and so to attend from day to day until you shall be duly discharged, whereof you shall fail at your peril.

Given under my hand at.....on the.....day of.....20.....

(Signature)

Presiding Officer or
Commanding Officer of the Unit

F.No.....

Name.....

Designation.....